भारतीय रिज़र्व बैंक

बुलेटिन

मई 2019

खंड 73 अंक 5

संपादन समिति

राजीव रंजन
डी. पी. रथ
सितीकांत पट्टनाईक
जी. पी. सामंता
एस. गंगाधरन
पल्लवी चव्हाण
स्नेहल हेरवडकर

संपादक

शशीधर एम. लोकरे

भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन संपादकीय समिति के निर्देशन में आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग द्वारा मासिक आधार पर प्रकाशित किया जाता है। इसमें व्यक्त व्याख्याओं और विचारों के लिए बैंक का केंद्रीय निदेशक मंडल उत्तरदायी नहीं है। हस्ताक्षरित लेखों में व्यक्त विचारों के लिए लेखक स्वयं उत्तरदायी हैं।

© भारतीय रिज़र्व बैंक 2019

सर्वाधिकार सुरक्षित।
सामग्री के पुन: प्रयोग की अनुमति है,
बशर्ते स्रोत का उल्लेख किया जाए।

बुलेटिन के सदस्यता शुल्क के लिए कृपया ‘‘भारतीय रिज़र्व बैंक के हाल के महत्वपूर्ण प्रकाशन’’ खंड देखें।

भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन को इंटरनेट के माध्यम से **http://www.bulletin.rbi.org.in** पर भी देखा जा सकता है।

विषय-वस्तु

भाषण

उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के समक्ष वैश्विक जोखिम एवं नीतिगत चुनौतियां 1
शक्तिकान्त दास

17 वाँ सी.डी.देशमुख स्मारक व्याख्यान: उद्घाटन उद्बोधन 5
शक्तिकान्त दास

केंद्रीय बैंक और नवोन्मेष : वित्तीय समावेशन के अनुसंधान में भागीदार
अगस्टीन कार्सटेंस 7

वैश्विक पटल पर भारत का बढ़ता महत्व क्या यह लंबे समय तक बना रहेगा और क्या हम इसके लिए तैयार हैं?
बी. पी. कानूनगो 17

लेख

भारत में नवीकरणीय ऊर्जा तथा बिजली की कीमतों की गत्यातमक स्थिति 25

बैंक जमाराशियां: अंतर्निहित समीकरण 35

वर्तमान सांख्यिकी **47**

हाल के प्रकाशन **91**

भाषण

उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के समक्ष वैश्विक जोखिम एवं नीतिगत चुनौतियां
शक्तिकान्त दास

17 वाँ सी.डी.देशमुख स्मारक व्याख्यान: उद्घाटन उद्बोधन
शक्तिकान्त दास

केंद्रीय बैंक और नवोन्मेष :
वित्तीय समावेशन के अनुसंधान में भागीदार
अगस्टीन कार्सटेंस

वैश्विक पटल पर भारत का बढ़ता महत्व क्या यह लंबे समय तक बना रहेगा और क्या हम इसके लिए तैयार हैं?
बी. पी. कानूनगो

उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के समक्ष वैश्विक जोखिम एवं नीतिगत चुनौतियां*

शक्तिकान्त दास

इस मंच पर मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद ।

मैं उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) के परिप्रेक्ष्य से कुछ वैश्विक जोखिम एवं नीतिगत चुनौतियों पर बोलने वाला हूँ। हमे मालूम है कि हलचल भरे 2018 से गुजरने के बाद ज्यादातर ईएमई अधिक सुदृढ़ होकर उभरी हैं। 2018 में अधिकांश समय ईएमई ने वैश्विक प्रभाव-प्रसार-जनित जोख़िम की कई लहरों का सामना किया है जिससे पूंजी के चले जाने, मुद्रा व आस्ति मूल्य अस्थिरता तथा तंग वित्तीय हलात पैदा हुए हैं। इन घटनाक्रमों से वृद्धि एवं मुद्रास्फीति के लिए जोखिम उत्पन्न हुए हैं। तथापि, आधारभूत पक्षों के सुदृढ़ होने, विदेशी मुद्रा भंडार बफर, बैंकिंग प्रणाली में पूंजी एवं विवेकसम्मत समष्टि आर्थिक नीतियों ने इन अर्थव्यवस्थाओं को वैश्विक प्रभाव-प्रसार को सहने की क्षमता दी है। फिर भी, जैसा कि अगस्टीन कार्स्टन तथा ह्यून सांग शिन ने गंभीरता से कहा है, 'ईएमएई अभी भी
1 संकट से बाहर नहीं निकल पाए हैं।'[1]

वैश्विक जोखिम

मैं उन तीन बड़े जोख़िमों पर प्रकाश डालना चाहता हूँ जो 2019 में ईएमईज़ के सामने हैं।

इन अर्थव्यस्थाओं के सामने सबसे बड़ा खतरा यह है कि वैश्विक वृद्धि और व्यापार के कमजोर होने के साक्ष्य बढ़ रहे हैं। ब्रेक्सिट के आस-पास के व्यापार-तनावों व घटनाक्रमों का निपटारा नहीं होने के कारण परिदृश्य में वृद्धि के नीचे जाने का जोख़िम और बढ़ रहा है। इस बात को लेकर काफ़ी अनिश्चितता है कि यह कमजोरी कुछ ही समय के लिए है या विकसित अर्थव्यवस्थाओं में किसी मंदी की शुरुआत। 2019 में वैश्विक वृद्धि के संबंध में आईएमएफ द्वारा अपने अनुमानों को कई बार घटाने में भी इस अनिश्चितता की छाया झलकती है। इसके अलावा केंद्रीय बैंक दुनिया भर में कसाव वाली मौद्रिक नीति से पीछे हट रहे हैं और उनमें से कुछ उधार देने में सुगम परिस्थितियों को बढ़ावा दे रहे हैं। कुछ अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि के लिए राजकोषीय प्रोत्साहन का अवलंब लिया जा रहा है।

दूसरा जोख़िम है ईएमईज़ का वित्तीय बाजार अस्थिरता के प्रभाव में बने रहना जैसा कि 2018 में देखने को मिला। पूँजी-प्रवाह के अचानक थमने और उल्टे पाँव लौटने के जोख़िम बढ़ गए हैं। इसके फलस्वरूप बाह्य वित्तपोषण में आने वाले अंतराल व मुद्रा मूल्यह्रास से इन अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि और समष्टिगत स्थिरता के परिदृश्य को नुकसान पहुँच सकता है, ठीक जब वैश्विक वित्तीय संकट के एक दशक के बाद वैश्विक वृद्धि में समवेत पुनरुत्थान के संकेत दिखने शुरु हुए थे। आगे, प्रतिकूल वित्तीय माहौल से कुछ ईएमईज़ में उधार देने वाले संस्थानों में वर्तमान तनाव और बढ़ सकता है और उनकी पूँजीगत आवश्यकताएं भी बढ़ सकती हैं।

ईएमईज़ के लिए तीसरा जोख़िम अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों में बड़ी अस्थिरता है। भारत जैसे निवल ऊर्जा आयातकों के लिए, प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं द्वारा उत्पादन में कटौती के बाद हाल में तेल की कीमतों में आई मजबूती चालू खाते घाटे व मुद्रा स्फ़ीति के लिए जोखिम है। ऊर्जा बाजारों का वित्तीयकरण और वैश्विक तेल बाजार में बदलते हुए अंतर्निहित समीकरण कीमतों के ऊपर ले जाने का जोखिम बढ़ा रहे हैं, जबकि माँग दबी हुई है। यद्यपि शेल उत्पादन की ब्रेक-इवन लागत बढ़ी हुई प्रतीत होती है, निवेशक जोख़िम-विमुख हो गए हैं और नकद प्रवाह और वित्तीय आमद पर ध्यान दे रहे हैं। इससे ओपेक और उत्पादन कटौती द्वारा बनाई गई कमियों को पूरा करने में शेल उत्पादन का लचीलापन घट सकता है।

नीतिगत चुनौतियां

तो, इस माहौल में ईएमईज़ के लिए नीतिगत चुनौतियां क्या हैं?

वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफ़सी) के बाद, कई ईएमईज़ ने अपनी अर्थव्यवस्थाओं को फिर से दिशा देने के लिए संरचनात्मक सुधार शुरू किए हैं। अल्पावधि में, वैसे, इन सुधारों में वृद्धि की गति में कमी जैसे बलिदान अपरिहार्यत: शामिल होते हैं। पारंपरिक दृष्टि से, ये सुधार तब सबसे अच्छे होते

---

* भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास का 12 अप्रैल 2019 को वाशिंगटन डीसी में फंड-बैंक स्प्रिंग मीटिंग्स, 2019 के अवसर पर 'गवर्नर वार्ता' ('गवर्नर टॉक्स') कार्यक्रम में दिया गया भाषण ।

[1] विदेशी मामले, 15 मार्च 2019 ।

हैं, जब आर्थिक चक्र विस्तार के दौर में हो। जब देश-विदेश में एक साथ वृद्धि की गति धीमी पड़ रही हो, तब संरचनागत सुधार हाथ में लेने और/या लागू करने का अवकाश बहुत कम होता है अथवा बाधित भी होता है। लेकिन यह तथ्य है कि हमें संरचनात्मक सुधारों की आवश्यकता ठीक तभी अधिक होती है, जब अर्थव्यवस्था धीमी पड़ रही होती है ताकि वृद्धि की गति को बनाए रखा जा सके। यह एक बिंदु है, जिस पर मैं ज़ोर देना चाहूँगा।

वैश्विक अर्थव्यस्था की रफ्तार धीमी पड़ने और राजकोषीय अवकाश के संकुचित होते जाने की स्थिति में, ईएमई और विकसित दोनों अर्थव्यवस्थाओं में बचाव की पहली पंक्ति के रूप में मौद्रिक नीति पर ध्यान जाएगा। एक बार फिर प्रत्याशा होगी कि केंद्रीय बैंक विश्व अर्थव्यवस्था के अभिभावक की भूमिका निभाएं। वैसे, वैश्विक वित्तीय संकट ने मौद्रिक नीति के पारंपरिक व अपारंपरिक नीतिगत औजारों की कई कमियां उजागर कर दी हैं। हताशा में कुछ लोगों ने अपारंपरिक विचारों का रुख़ किया है जिसे आधुनिक मौद्रिक सिद्धांत का नाम दिया गया है। वैसे तो इसका मूल्यांकन अभी नहीं हुआ है, नीचे ले जाने वाले इसके गंभीर जोख़िम को देखते हुए, मेरे मन में इसे लेकर काफ़ी संदेह है। अंततः मौद्रिक नीति को वास्तविक अर्थव्यवस्था से जुड़ना होगा, निवेश को बढ़ावा देना होगा और मौद्रिक व वित्तीय स्थिरता कायम करनी होगी।

तथापि, मैं यह महसूस करता हूँ कि लीक से हटकर सोचने का समय आ गया है जिसमें पारंपरिक विचाराधारा को चुनौती भी देनी होगी। आइए जरा ऐसे ही एक वैचारिक प्रयोग से आपको कुछ झटका सा देने की कोशिश करूँ। सामान्यतः, आधुनिक केंद्रीय बैंक ब्याज दर को अपने मुख्य उपकरण के रूप में लेते हुए छोटे-छोटे कदम उठाते हैं – 25 आधार अंक या उनके गुणजों में – और नीति की संभावित भावी दिशा पर बाज़ारों व जनता को दिशा देने के लिए कसाव, तटस्थता या निभाव का रुख़ घोषित करते हैं। एक विचार जो मेरे मन में आता है, वह यह है कि यदि 25 आधार अंकों की इकाई कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है और महज एक परिपाटी है, तो परिस्थिति के अनुसार नीतिगत दर के आकार को समायोजित करने से मौद्रिक नीति को फ़ायदा होगा और स्वयं परिवर्तन का आकार ही नीति का रुख़ बता देगा। उदाहरण के लिए, यदि मौद्रिक नीति को ढीला करने की जरूरत हो लेकिन केंद्रीय बैंक अपने निभाव में सतर्क रहना चाहता है, तो नीतिगत दर में 10 आधार अंकों की एक कटौती प्राधिकारियों की प्रतिबद्धता को शायद अधिक स्पष्टता से जाहिर करे, बजाय दो अलग कदमों के – एक नीतिगत दर पर, पूर्णांकन के लिए मूल्यवान दर कार्रवाई के 15 आधार अंकों की बर्बादी, और दूसरा रुख़ पर, जो एक तरह से भावी नीतिगत कार्रवाई को एक पूर्व-प्रतिबद्ध दिशा से बाँध देता है। इसी प्रकार, ऐसी दशा में जब केंद्रीय बैंक की प्राथमिकता तो निभाव की है पर बहुत ज्यादा नहीं तो यदि बैंक का आकलन यह है कि मानक 25 आधार अंक बहुत कम है और लेकिन इसका गुणक, अर्थात् 50 आधार अंक बहुत अधिक तो बैंक 35 आधार अंकों की कटौती की घोषणा कर पाए। यह तरीका तब भी उपयोगी होगा जब केंद्रीय बैंक कसाव की मुद्रा में हो और सुदूर भविष्य के रुख़ द्वारा भावी मार्गदर्शन (फॉरवर्ड गाइडेंस) से नीति के पलट जाने को टालने में भी सहायक हो जो कि हो सकता है बड़ी अस्थिरता वाले वैश्विक परिदृश्य में एक वर्ष का भी न हो। मैं किसी सिद्धांत की खोज में यह विचार नहीं रख रहा हूँ, बल्कि इस क्षेत्र के विशेषज्ञों से और विशेष रूप से केंद्रीय बैंकर का कार्य करने वालों से इस बिंदु की स्वीकार्यता की तलाश में कह रहा हूँ जिनको अपने दैनिक जीवन में इस दुविधा से दो-चार होना पड़ता है।

एक अन्य स्तर जिस पर, ईएमईज़ के लिए एक बड़ी चुनौती बनी रहेगी, वह है वैश्विक प्रभाव-प्रसारों का प्रबंधन। हम चलायमान पूँजी प्रवाहों वाली दुनिया में रहते हैं जहाँ पूँजी के आने, अचानक रुक जाने और पलट जाने के असर को राष्ट्रीय स्तर पर वहन करना होगा। इस पृष्ठभूमि में, एक वास्तविक वैश्विक सुरक्षा कवच मरीचिका बना हुआ है। जब भी हम स्प्रिंग या वार्षिक बैठकों में मिलते हैं, आईएमएफ़ के संसाधनों का सुदृढ़ीकरण भविष्य में किसी उपयुक्त समय के लिए टल जाता है। इन परिस्थितयों में ईएमईज़, जिनके हिस्से में प्रायः वैश्विक घटनाक्रमों का प्रतिकूल प्रभाव ही आता है, के पास विदेशी मुद्रा भंडार के अपने बफ़र तैयार करने के अलावा कोई उपाय नहीं रह जाता। विरोधाभास ये है कि रिज़र्व जमा करने को 'मुद्रा का हेर-फेर' जैसे लेबल लगाकर बदनाम कर दिया गया है। मुझे ऐसा लगता है कि हम अनजाने ही कई ईएमई मुद्राओं के बाहर निकलने और प्रमुख रिज़र्व मुद्राओं के प्रभुत्व को चुनौती देने

का मंच तैयार कर रहे हैं। दोनों पक्षों में और बेहतर समझ की आवश्यकता है। इस बीच, जहाँ तक भारतीय रिज़र्व बैंक का प्रश्न है, हम इस खेल के वर्तमान नियमों के अनुसार खेलते रहेंगे।

मौद्रिक नीति के संचरण के लिए केंद्रीय बैंकों को वित्तीय बाजारों से गहन आदान-प्रदान की जरूरत होती है। इसके लिए एक ठोस और कार्यकुशल भुगतान व निपटान प्रणाली का आधार आवश्यक है। भारत में डिजीटलीकरण और ऑनलाइन कॉमर्स की उत्तरोत्तर वृद्धि को देखते हुए, हाल के वर्षों में एक अत्याधुनिक राष्ट्रीय भुगतान संरचना व तकनीक का प्लेटफॉर्म स्थापित करने की कोशिश की गई है। इसने देश के खुदरा भुगतान परिदृश्य को बदल दिया है। अपनी भुगतान प्रणाली के विनियमन और विकास में हमने संरक्षा, सुरक्षा, सुविधा, पहुँच और तकनीकी साधनों के लाभ का ध्येय रखा है। फिनटेक का सुसंगत विकास और वित्तीय प्रणाली में उनके प्रभाव को सुव्यवस्थित करने के लिए, एक सुपरिभाषित स्थान व अवधि में फिनटेक सॉल्यूशन्स से प्रयोग करने के लिए हम एक 'विनियामक प्रयोग-क्षेत्र/नवोन्मेष केंद्र' ('रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स/ इनोवेशन हब') लाने से संबंधित दिशा-निर्देशों पर कार्य कर रहे हैं।

इस परिवर्तनशील और अनिश्चित परिवेश में, ईएमईज़ की बेहतरी इसी में है कि वे बहु-ध्रुवीयता को स्वीकारते हुए सभी मोर्चों पर सहयोग बढ़ाएं। सहयोग का एक क्षेत्र यह हो सकता है कि ऐसी संस्थागत व्यवस्था कायम की जाए जो तेल का निर्यात व आयात करने वाले देशों की प्राथमिकताओं में संतुलन लाए ताकि ऊर्जा कीमतों में स्थिरता आए। विकल्पों की तलाश भी ईएमईज़ के लिए आवश्यक है जिससे पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों पर निर्भरता घटे और नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों व ऊर्जा के कुशल उपयोग पर अधिक ध्यान दिया जाए। द इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसका मुख्यालय दिल्ली में है, इसका एक जीता-जागता उदाहरण है। यह वित्तीय व सौर संसाधन से समृद्ध देशों में सहयोग का एक समर्पित मंच उपलब्ध कराने का प्रयास है जिससे सौर ऊर्जा का लाभ विश्व समुदाय को मिले।

अंत में मैं भारत के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूँ। 2019-20 में 7.2 प्रतिशत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि प्रत्याशित है, जो कि विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज होगी, तथा हाल के वर्षों में इसकी औसत वार्षिक वृद्धि दर लगभग 7.5 प्रतिशत रही है। मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढाँचे के अंतर्गत आने वाली अवधि में अब तक (अक्टूबर 2016 से फरवरी 2019 तक) मुद्रा स्फीति का औसत, लक्ष्य से कम, 3.6 प्रतिशत रहा है; 2018-19 में चालू खाता घाटाजीडीपी के 2.5 प्रतिशत के आस-पास रहने की संभावना है; और सकल राजकोषीय घाटा बजट के लक्ष्य के अनुकूल रहा है।

आने वाले समय में, हमारी प्राथमिकता है कि हम सजग रहें और वृद्धि को पुनरुज्जीवित करें और समष्टि-आर्थिक, वित्तीय व मूल्य स्थिरता बनाए रखें।

धन्यवाद।

*17 वाँ सी.डी.देशमुख स्मारक व्याख्यान: उद्घाटन उद्बोधन**

शक्तिकांत दास

भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से मैं श्री ऑगस्टिन कर्स्टेन्स (Mr. Agustin Carstens), महाप्रबंधक, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेट्टलमेंट्स का सी.डी. देशमुख स्मारक व्याख्यानमाला में आज 17वाँ व्याख्यान देने के लिए सहर्ष स्वागत करता हूँ। हम आज स्व.सी.डी.देशमुख के परिवार के श्री अतुल देशमुख एवं श्रीमती देशमुख को भी अपने बीच पाकर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक के सभी गणमान्य अतिथियों का भी हार्दिक स्वागत है।

आरंभ में, मैं इस अवसर पर श्री सी.डी.देशमुख को याद करते हुए उनके बारे में कुछ कहना चाहूँगा। श्री चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख का जन्म 14 जनवरी 1896 को महाराष्ट्र में रायगढ़ फोर्ट के निकट नाटा में हुआ था। उनका शैक्षणिक करियर अप्रतिम था। उन्होंने 1912 में यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे से मैट्रिकुलेशन की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उन्होंने 1917 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जीसस कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और 1918 में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा, जो उस समय केवल लंदन में आयोजित होती थी, में प्रथम स्थान प्राप्त किया। 1920 में भारत वापस लौटने पर उन्होंने बिहार सरकार और भारत सरकार में संयुक्त सचिव के रूप में कार्य किया।

भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ उनका संबंध जुलाई 1939 में आरंभ हुआ जब उन्हें बैंक के मामलों के संदर्भ में भारत सरकार से संपर्क बनाए रखने के लिए संपर्क अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। तीन महीने बाद उन्हें बैंक के केंद्रीय बोर्ड का सचिव नियुक्त किया गया और दो वर्ष बाद दिसंबर 1941 में उनको बैंक के उप गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया। 11 अगस्त 1949 को भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर के रूप में नियुक्त होने वाले वे प्रथम भारतीय थे और वे 30 जून 1949 तक इस पद पर सुशोभित रहे। उन्होंने औद्योगिक वित्त निगम बनाए जाने और ग्रामीण ऋण को बढ़ावा देने में प्रमुख भूमिका निभायी। अपने कार्यकाल के दौरान भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग कंपनी अधिनियम, 1949 बनते हुए देखा जिसने भारत में बैंकिंग क्षेत्र के विनियमन की आधारशिला रखी। उनके कार्यकाल के दौरान ही भारतीय रिज़र्व बैंक का 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण हुआ।

श्री देशमुख भारतीय रिज़र्व बैंक में अपने कार्यकाल की समाप्ति के बाद योजना आयोग के सदस्य बने जब योजना आयोग का गठन 1950 में किया गया। इसके बाद वे 1950 में वित्त मंत्री बनाए गए और जुलाई 1956 तक देश को अपनी विशिष्ट सेवा प्रदान की। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने देश की प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण और उनके कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। वे नये कंपनी अधिनियम बनाए जाने और इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया तथा जीवन बीमा कंपनियों के राष्ट्रीयकरण के प्रमुख कारक थे। केंद्रीय कैबिनेट से इस्तीफा देने के बाद वे उन्होंने 1956 से 1961 तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के अध्यक्ष और 1962 से 1967 तक दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में कार्य किया। 1975 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। विशिष्ट सरकारी सेवा के लिए 1959 में दिए गए प्रतिष्ठित मैग्सेसे पुरस्कार के भी वे सह विजेता रहे।

श्री सी.डी.देशमुख के सम्मान में इस वर्ष के स्मारक व्याख्यान में श्री ऑगस्टिन कर्स्टेन्स को अपने बीच पाकर हमें अत्यंत प्रसन्नता है। ये 2010 से 2017 तक सेन्ट्रल बैंक ऑफ मेक्सिको के गवर्नर रहे और 2011 से 2017 तक बीआईएस बोर्ड के सदस्य रहे। बीआईएस बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में इन्होंने वैश्विक आर्थिक बैठकों और आर्थिक सलाहकार परिषद की बैठकों की अध्यक्षता की। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की परामर्शदात्री समिति अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक और वित्तीय समिति (इंटरनेशनल मॉनेटरी ऐंड फायनान्शियल कमिटी) की भी अध्यक्षता की।

श्री कर्स्टेन्स ने अपने करियर की शुरुआत 1980 में बैंक ऑफ मेक्सिको से की जहाँ इन्होंने विभिन्न पदों पर कार्य किया। बाद में इन्होंने मेक्सिको के उप वित्त मंत्री और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) में उप प्रबंध निदेशक के रूप में सेवा प्रदान की। ये 2006 से 2009 तक मेक्सिको के वित्तमंत्री रहे।

ये 2010 तक वित्तीय स्थिरता बोर्ड के सदस्य भी रहे हैं तथा समूह 30 (ग्रुप ऑफ थर्टी) के सदस्य हैं।

श्री कर्स्टेन्स ने शिकागो यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है तथा इन्हें मैक्रोइकोनॉमिक मुद्दों

* 25 अप्रैल 2019 को मुंबई में सत्राहवें सी. डी. देशमुख मेमोरियल व्याख्यान में श्री शक्तिकांत दास, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए उदघाटन उद्बोधन।

और वित्त के क्षेत्र में गहन शोध का अनुभव है। 'लैटिन अमेरिकन सेन्ट्रल बैंक रिफॉर्म : प्रोग्रेस ऐंड चैलेंजेज ' पर किया गया उनका कार्य जो लैटिन अमेरिका में मौद्रिक नीति में 1990 के आरंभिक वर्षों से किए गए संस्थागत सुधारों का जायजा लेता है, की व्यापक स्तर पर सराहना हुई।

आज श्री कर्स्टेन्स "Central Banking and Innovation : Partners in Quest for Financial Inclusion" विषय पर बोलेंगे जो आज की परिस्थिति में अत्यंत प्रासंगिक विषय हो सकता है। हाल ही में वित्त के क्षेत्र में उभर कर सामने आए फिनटेक अथवा डिज़िटल नवाचार वैश्विक स्तर पर वित्तीय क्षेत्र को आकार देने की दिशा में संभावनाओं से भरी एक मजबूत रूपांतरणकारी शक्ति बन गए हैं। इस प्रौद्योगिकीगत विकास का एक बड़ा लाभ यह है कि इससे वहनीय लागत पर वित्तीय पहुँच के विस्तार की गुंजाइश बढ़ी है। लेकिन इसके साथ ही विनियामक और पर्यवेक्षी चुनौतियाँ भी बढ़ी हैं जिनको वैश्विक स्तर पर सभी केंद्रीय बैंकों द्वारा ठीक किए जाने की जरूरत है।

रिज़र्व बैंक भारत में वित्तीय समावेशन अभियान को बढ़ावा देने तथा इसकी गति तेज़ करने के लिए प्रतिबद्ध है। हाल ही में फिनटेक में हुए विकास ने देश में वित्तीय समावेशन प्रक्रिया को एक नयी गति दी है। भारत में डिज़िटाइजेशन की आई तीव्र वृद्धि और ऑनलाइन व्यापार का संज्ञान लेते हुए हाल के दिनों में एक नवोन्नत राष्ट्रीय भुगतान आधारभूत संरचना एवं प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म बनाए जाने की दिशा में नीतिगत प्रयास किए गए हैं। रिज़र्व बैंक अपने विनियामक और पर्यवेक्षी ढाँचे को निरंतर एक दूसरे के अनुकूल बना रहा है ताकि वंचित जनसामान्य तक वित्तीय पहुँच को विस्तार देने और उसे आसान बनाने में मदद देने के लिए फिनटेक के विकास को और सशक्त बनया जा सके। फिनटेक नवाचारों के बढ़ते महत्व और वित्तीय क्षेत्र तथा वित्तीय क्षेत्र की संस्थाओं के साथ उसके अंतर्संबंधों की दृष्टि से रिज़र्व बैंक अपने निगरानी ढाँचे को मजबूत कर रहा है तथा बैंक द्वारा हितधारकों से अभिमत प्राप्त करने के लिए "Enabling Framework for Regulatory Sandbox" पर दिशानिर्देश का प्रारूप भी जारी किया गया है। आज श्री कर्स्टेन्स के वक्तव्य से हमें इस दिशा में निश्चित रूप से प्रासंगिक जानकारी प्राप्त होगी।

मैं श्री कर्स्टेन्स को व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित करता हूँ।

*केंद्रीय बैंक और नवोन्मेष : वित्तीय समावेशन के अनुसंधान में भागीदार**

अगस्टीन कार्सटेंस

देवियो और सज्जनो,नमस्कार। मेरे लिए यह सौभाग्य की बात है कि मैं 17वें सी डी देशमुख मेमोरियल व्याख्यान के लिए मुंबई में हूँ। इस आमंत्रण के लिए मैं गवर्नर दास को धन्यवाद देता हूँ।

गवर्नर देशमुख एक असाधारण राजनीतिज्ञ और भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। एक निजी शेयरधारकों के स्वामित्व वाली संस्था से एकआधुनिक केंद्रीय बैंक के रूप में रूपांतरण को नेतृत्व प्रदान करने के साथ-साथ उन्होंने ग्रामीण ऋण के समर्थन में अनेक पहल की, जिसमें कृषि के विकास के लिए रिज़र्व बैंक की निधि को सही दिशा में लगाना शामिल है। ये उपाय गवर्नर देशमुख की वित्तीय समझ की गहरी समझ को दर्शाते हैं और आज उनके सम्मान में, मैं इस सवाल पर फिर से विचार करना चाहूंगा कि क्यों वित्तीय समावेशन केंद्रीय बैंक के अधिदेश के अंतर्गत आता है।

मेरा मुख्य शोध यह है कि केंद्रीय बैंक और वित्तीय प्राधिकरण अपने प्रथम और मुख्य उद्देश्यों को पूरा करते हुए वित्तीय समावेशन का समर्थन और प्रचार कर सकते हैं। मूल्य स्थिरता को बनाये रखने के पश्चात वे यह सुनिश्चित करते हैं कि मुद्रा का मूल्य बना रहे। वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करके, वे वित्तीय संस्थानों को विफल होने से बचाते हैं जिससे लोगों की बचत संस्थाओं के पास आती है। लेकिन सबसे बढ़कर, केंद्रीय बैंक विश्वास को बढ़ावा देते हैं। वित्तीय प्रणाली और इसके संस्थानों में विश्वास को मजबूत करके, केंद्रीय बैंक आम लोगों को बैंकिंग की मुख्यधारा में लाते हैं और उन्हें इसका फायदा उठाने में मदद करते हैं। इस तरह से , केंद्रीय बैंक अधिक समावेशी और जीवंत अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है।

* 25 अप्रैल 2019 को मुंबई में सत्राहवें सी डी देशमुख मेमोरियल व्याख्यान में श्री अगस्टीन कार्सटेंस, महाप्रबंधक, अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (बीआईएस) द्वारा दिया गया व्याख्यान

इस प्रकार वित्तीय समावेशन के लिए यह एक आवश्यक शर्त यह है कि केंद्रीय बैंक अपने मुख्य अधिदेश पर खरा उतरे। लेकिन यही पर्याप्त नहीं है। अन्य घटक भी महत्वपूर्ण हैं। नई तकनीक नागरिकों और वित्तीय संस्थानों दोनों के लिए बाधाओं को तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इस प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए, केंद्रीय बैंकों और वित्तीय प्राधिकारियों को अनिवार्य रूप से सही बुनियादी ढाँचा प्रदान करना होगा। इसमें भौतिक बुनियादी ढाँचा जैसे भुगतान और निपटान प्रणाली के साथ-साथ सॉफ्ट या 'संदर्भगत' बुनियादी ढाँचा जैसे नियम और दिशा-निर्देश शामिल हैं जिससे अपने उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा करते हुए तकनीक का पूर्ण लाभ प्राप्त किया जा सकेगा। केंद्रीय बैंक और नवोन्मेषक महत्वपूर्ण साझेदार होते हैं तथा एक-दूसरे के सहयोग के बिना वित्तीय समावेशन को प्राप्त नहीं किया जा सकता।

आज मैं वित्तीय समावेशन के लाभ पर ज़ोर देते हुए अपनी बात आरंभ करूंगा कि आज हम इस दौर में कहाँ खड़े हैं। इसके बाद मैं उस भूमिका के बारे में बात करूंगा जो केंद्रीय बैंक और वित्तीय प्राधिकारी सफलता के लिए आवश्यक शर्तें प्रदान करने में निभाते हैं। और मैं इस सफलता के निर्माण के लिए फिनटेक के साथ साझेदारी के लिए सुझाव दूंगा क्योंकि अब हम सब वित्तीय सेवाओं में तकनीक संचालित नवोन्मेष को अपना रहे है। अंत में मैं यह कहना चाहूँगा कि कैसे बीआईएस इस क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग में तेजी लाने के लिए मदद कर सकता है।

वित्तीय समावेशन क्यों महत्वपूर्ण है?

वित्तीय समावेशन वित्तीय सेवाओं तक पहुँच बनाता है जो आधुनिक अर्थव्यवस्था में भाग लेने की कुंजी है। इसमें भुगतान, क्रेडिट, बीमा और बचत शामिल है। दक्ष भुगतान प्रणाली की पहुंच के बिना कारोबार रुक जाता है। एक आधुनिक अर्थव्यवस्था दक्ष, विश्वासनीय तथा किफ़ायती भुगतान प्रणाली के बिना नहीं चल सकती।

क्रेडिट, संसाधनों के और बेहतर ढंग से उपयोग को सुनिश्चित करता है। ऋणदाताओं के अल्पाधिकार और ऋण पात्रता संबंधी सभी संदेह युक्त समस्याओं के साथ औपचारिक वित्तीय क्षेत्र का ऋण आमतौर पर सस्ता होता है और इसमें अनौपचारिक ऋण की तुलना में बेहतर शर्तें होती हैं। ऋण बाजार में ऐसी समस्याएं होती ही हैं, कि बाजार की शक्ति को प्रभावित किया जा सकता है। काला बाजारी ऋणदाता अक्सर इसे एकाधिकार के रूप में चलाते हैं और अत्यधिक ब्याज दर

लगाते हैं। अनौपचारिक बाजार बीमा उत्पाद प्रदान करने में भी असमर्थ हैं, जो खराब फसल, बीमारी, या कमाने वाले सदस्य के मृत्यु जैसे झटके से बचाने का कार्य करता है।

औपचारिक बचत सुविधाएं कम जोखिम वाली ब्याज आय प्राप्त करने में मदद कर सकती हैं। औपचारिक ऋण सुविधाओं के साथ, ये आय में कमी की वजह उपभोक्ता खर्च में होने ने वाले उतार-चढ़ाव को कम करने में मदद कर सकती हैं। बढ़ी हुई आय स्थिरता और ऋण तक बेहतर पहुंच से गरीबों को फायदा होगा।

जबकि वित्तीय पहुंच वित्तीय जुड़ाव की गारंटी नहीं देती है, लेकिन यह प्रोत्साहन के रूप में कार्य करता है। एक बुनियादी जमा खाता भुगतान और क्रेडिट जैसी अन्य बैंकिंग सेवाओं को आज़माने का द्वार खोल देती है।

इसके अलावा, वित्तीय समावेशन 'सामाजिक समावेशन' को बढ़ावा देता है। उदाहरण के लिए, एक चालू खाते में बचत जमा करके, व्यक्ति संपत्ति के अधिकारों द्वारा संरक्षित हो जाता है। यदि वे अपनी बचत राशि से आभूषण बनवाते हैं या उसे सिर्फ गद्दे के नीचे छिपा कर रखते हैं तो वे चोरी के शिकार हो सकते हैं या उसका अवमूल्यन हो सकता है । इसके अलावा, वित्तीय समावेशन कल्याण योजनाओं से संबंधित लाभ का हस्तांतरण तेज, सस्ता हो जाता है और राशि के रिसाव की संभावना में कमी आती है। इससे राज्य के साथ-साथ प्राप्तकर्ता भी लाभान्वित होते हैं। कुल मिलाकर, वित्तीय समावेशन गरीबी को कम करने में मदद कर सकती है।[1]

समावेशन में मुख्य बाधाएं

वित्तीय पहुंच के विस्तार में पर्याप्त प्रगति हुई है। वर्ष 2011 से, 1 अरब से अधिक वयस्कों की पहुंच बुनियादी लेनदेन खातों तक हुई है। इसमें समर्पित राष्ट्रीय रणनीतियों ने एक बड़ी भूमिका निभाई है। भारत में जनधन योजना ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है।[2] फिर भी पहुंच का विस्तार करने के साथ-साथ सहभागिता के लिए प्रोत्साहन देने के संदर्भ में वैश्विक स्तर पर बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है।

वित्तीय सेवाओं तक पहुँच के संदर्भ में, दुनिया की लगभग एक तिहाई वयस्क आबादी के पास अभी भी एक बुनियादी जमा खाता (चार्ट 1, बाएं हाथ का पैनल) नहीं है।[3] अफ्रीका, एशिया और अमेरिका के कुछ देशों में, दो में से केवल एक वयस्क के पास बैंक खाता है (चार्ट 2, निचला पैनल)। औसतन, महिलाएं, गरीब, बेरोजगार और कम पढ़े-लिखे पिछड़े हुए पीछे (चार्ट 1, बीच का पैनल) हैं।

चार्ट 1: समावेशन में मुख्य बाधाएँ

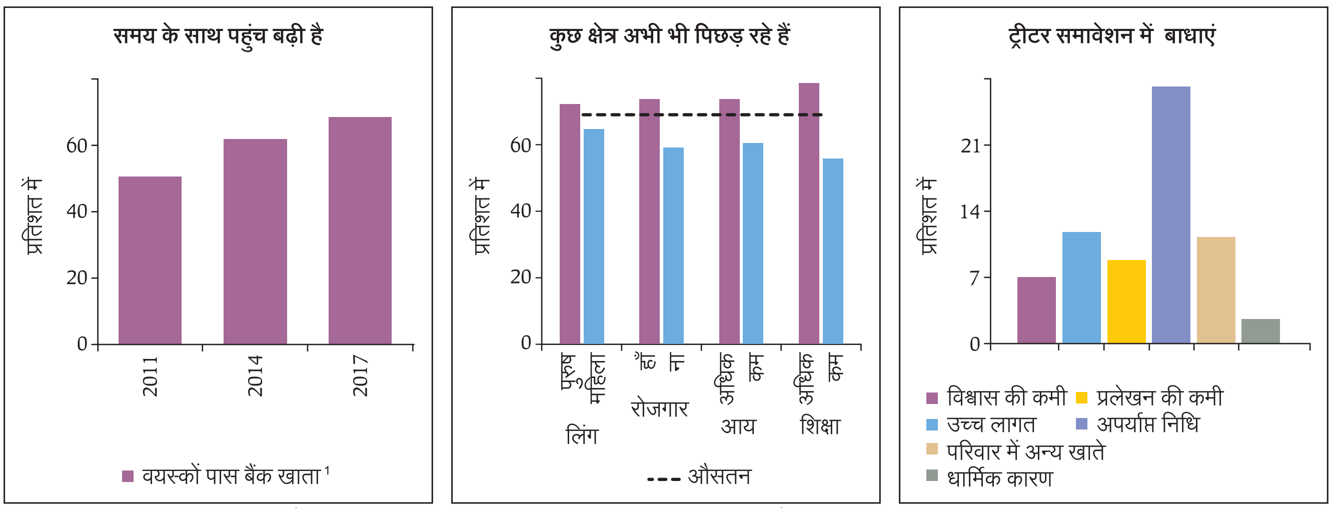

[1] 15 वर्ष से अधिक उम्र के उत्तरदाताओं ने प्रतिक्रिया दी है कि बैंक में या अन्य प्रकार के वित्तीय संस्थाओं में (एकल या संयुक्त रूप से) खाता है अथवा पिछले 12 माह में वैयक्तिक रूप से मोबाइल मनी सेवा का प्रयोग किया है।

स्रोत : वर्ल्ड बैंक ग्लोबल फिंडेक्स सर्वे 2011, 2014 और 2017; ए डेमिरग्यूक-कुंट और आर लेविन, एल क्लेप्पर, डी सेंगर,एस अंसार और जे हेस्स। *ग्लोबल फिंडेक्स डाटाबेस 2017: मेजरिंग फाइनेंशियल इनक्लूजन एंड डी फिंटेक रिवोल्यूशन,* विश्व बैंक, 2018।

[1] ए डेमिरग्यूक-कुंट और आर लेविन, 'वित्त और असमानता: सिद्धांत और साक्ष्य, वित्तीय अर्थशास्त्र 2009 की वार्षिक समीक्षा देखें। एस गुप्ता, सी पट्टिलो और एस वाघ, 'उप-सहारा अफ्रीका में गरीबी और वित्तीय विकास पर धन-प्रेषण का प्रभाव ', वर्ल्ड डेवलपमेंट, 2009 को भी देखें।

[2] एस अग्रवाल, एस आलोक, पी घोष, एस घोष, टी पिस्कोर्स्की और ए सेरू, 'बैंकिंग द अनबेंक्ड: वित्तीय पहुंच के बारे में 255 मिलियन नए बैंक खाते क्या बताते हैं?' देखें। मिमियो, 2017

[3] हालांकि इनमें से कुछ वयस्कों के पास अप्रत्यक्ष वित्तीय पहुंच हो सकती है, *उदाहरण* के लिए, एक पति या पत्नी के माध्यम से जिनके पास बैंक खाता है।

चार्ट 2: 2011-17 में वित्तीय समावेशन सूचकांक का विकास[1]

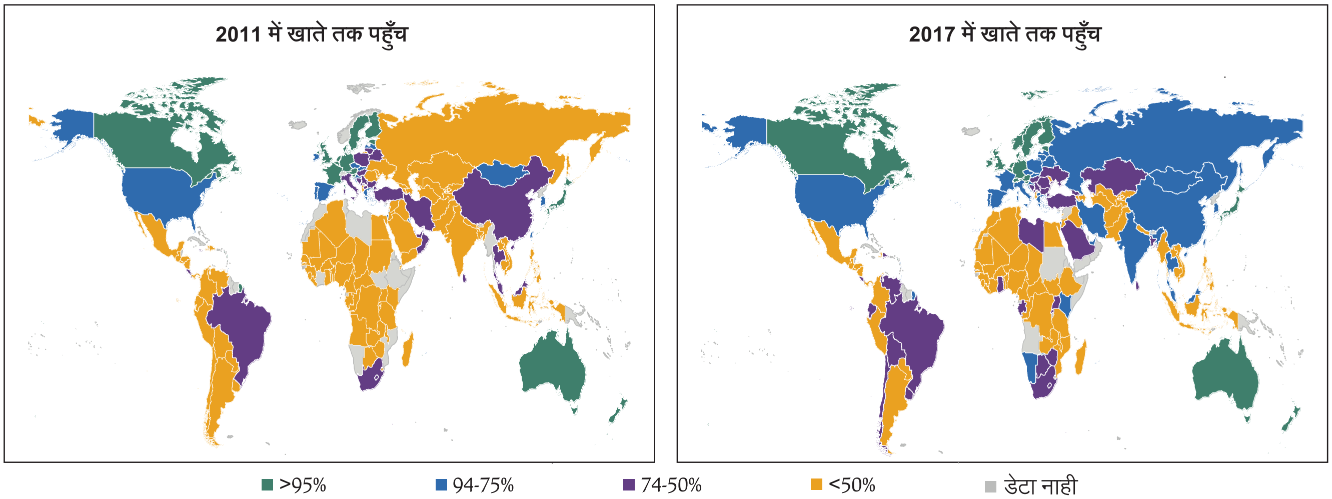

[1] 15 वर्ष से अधिक उम्र के उत्तरदाताओं ने प्रतिक्रिया दी है कि बैंक में या अन्य प्रकार के वित्तीय संस्थाओं में (एकल या संयुक्त रूप से) खाता है अथवा पिछले 12 माह में वैयक्तिक रूप से मोबाइल मनी सेवा का प्रयोग किया है।
स्रोत : वर्ल्ड बैंक ग्लोबल फिंडेक्स सर्वे 2011,2014 और 2017; ए डेमिरग्युक-कुंट और आर लेविन, एल क्लेप्पर, डी सेंगर, एस अंसार और जे हेस्स। *ग्लोबल फिंडेक्स डाटाबेस 2017: मेजरिंग फाइनेंशियल इनक्लूजन एंड डी फिंटेक रिवोल्यूशन,* विश्व बैंक, 2018।

लेकिन वित्तीय पहुंच के संतोषजनक स्तर होने के बावजूद, सक्रियता कम रह सकती है। उदाहरण के लिए, 2017 ग्लोबल फाइनडेक्स सर्वे के अनुसार, जिन वयस्कों के पास बैंक खाता था, उनमें से आधे से कम ने वास्तव में पिछले वर्ष में किसी वित्तीय संस्था में बचत राशि जमा की थी। यहां तक कि उच्च आय वाले देशों में जहां अधिकांश वयस्कों (94%) का खाता था, 10 में से एक से अधिक ने परिवार और दोस्तों से उधार लेना पसंद किया था।

समावेशन संबंधी बाधाओं का कारण उपयोगकर्ताओं के साथ सेवा प्रदाता भी हैं। चार्ट 1 का दायां पैनल उन कुछ कारणों पर प्रकाश डालता है जिनकी वजह से उपयोगकर्ता वित्तीय सेवाओं का उपयोग नहीं करते हैं। मैं उन तीन बाधाओं को उजागर करता हूँ जिन पर सार्वजनिक नीति और नवाचार की सबसे अधिक संभावना है।

पहली बाधा वित्तीय प्रणाली में **'विश्वास की कमी'** है, विशेष रूप से मुद्रा और वित्तीय संस्थाओं में। यह बैंक की विफलताओं के इतिहास और कड़ी मेहनत से अर्जित मुद्रा से जुड़े नुकसान के कारण हो सकता है जो लोगों ने पहले देखा होगा। विश्वास की कमी वित्तीय साक्षरता की कमी को भी दर्शा सकती है। वास्तव में, लोगों से ऐसी किसी चीज़ पर भरोसा करने की उम्मीद नहीं की जा सकती, जिसे वे समझते नहीं हैं।

दूसरी बाधा **'उच्च लागत'** है। यानी, कुछ उपयोगकर्ताओं के लिए वित्तीय सेवा बहुत महंगी हो सकती है। दो संभावनाएँ हो सकती हैं। या तो कीमत उचित है, लेकिन उपयोगकर्ता इसे वहन करने की स्थिति में नहीं है। या कीमत वास्तव में बहुत अधिक है क्योंकि सेवा प्रदाता को जनसंख्या के खास वर्गों को सेवा देना लाभहीन लगता है। एक छोटे, कम आय वाले वर्ग पर विचार करें। संभावित ग्राहकों की एक महत्वपूर्ण संख्या के बिना, एक पूरी तरह से कर्मचारी युक्त शाखा स्थापित करना बहुत महंगा हो सकता है। यहां तक कि अगर कोई निश्चित लागतों को नजरअंदाज करता है, तो बहुत कम वित्तीय जरूरतों वाले कम आय वाले ग्राहकों को सेवा देने से सीमांत लाभ बहुत कम हो सकता है।

तीसरी बाधा **'प्रलेखन की कमी'** है। जन्म प्रमाणपत्र या पहचान पत्र जैसे बुनियादी दस्तावेजों के बिना बैंक खाते नहीं खोले जा सकते। इस बीच, क्रेडिट रिकार्ड के न होने से ऋण या बीमा पाने के रास्ते को बंद कर सकता है।

सौभाग्य से, सार्वजनिक नीति और नवाचार इन बाधाओं को दूर करने में मदद कर सकते हैं। मैं इस बात से अपनी बात की शुरुआत करूंगा कि केंद्रीय बैंक और वित्तीय प्राधिकारी वित्तीय प्रणाली में विश्वास को कैसे बढ़ा सकते हैं।

केंद्रीय बैंक और वित्तीय अधिकारी अपने अधिदेश को पूरा करके विश्वास को बढ़ावा देते हैं

केंद्रीय बैंक और वित्तीय प्राधिकरण अपने मूल अधिदेशों – नामत: कीमत और वित्तीय स्थिरता – पर ध्यान देकर वित्तीय प्रणाली में लोगों के विश्वास को बढ़ा सकते हैं और इस प्रकार वित्तीय समावेशन के लिए आधार प्रदान कर सकते हैं। यह लिंक

चार्ट 3: अच्छा चक्र: किसी केंद्रीय बैंक के मुख्य उद्देश्य वित्तीय समावेशन का समर्थन कैसे करते हैं

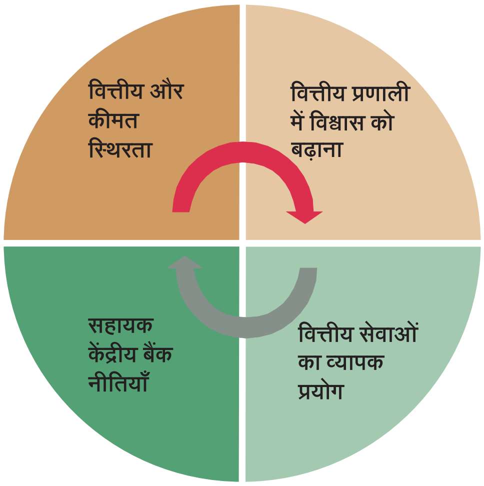

स्रोत : बीआईएस।

चार्ट 3 में लाल तीर द्वारा दिखाया गया है। मूल रूप से, लोग औपचारिक वित्तीय सेवाओं का उपयोग करना शुरू नहीं करेंगे, अगर वे मुद्रा, या बैंकों, क्रेडिट यूनियनों और सहकारी समितियों जैसी वित्तीय संस्थाओं पर भरोसा नहीं करते हैं। केंद्रीय बैंक इन दोनों आयामों में विश्वास बनाने में मदद कर सकते हैं। मूल्य स्थिरता मुद्रा में विश्वास को बढ़ाता है और एक मजबूत विवेकपूर्ण पर्यवेक्षी ढांचा संस्थाओं में विश्वास पैदा करता है।

आखिरकार, विश्वसनीय वादा करने और उसे पूरा करने पर भरोसा जगता है। और किसी का भरोसा जीतना मुश्किल है लेकिन उसे खो देना आसान है। इस प्रकार केंद्रीय बैंकों को अपने अधिदेशों पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।

कीमत स्थिरता संबंधी अधिदेश क्यों मायने रखता है, अपनी बात इससे आगे बढ़ाता हूँ।

पहला, मुद्रास्फीति के दोहरे अंकों की सीमा पार कर जाने के पहले ही बढ़ती हुई कीमतें वैध मुद्रा पर लोगों के विश्वास को कम कर सकती हैं । जैसाकि चार्ट 4 दिखाता है, विश्वास 'सामान्य' मुद्रास्फीति दरों पर भी कम हो जाता है। तथाकथित महंगाई कर का भार गरीबों पर अधिक पड़ता है, तेजी से बढ़ रही कीमतों से जिनकी बचत बुरी तरह प्रभावित होती है।[4]अमीर और अधिक प्रबुद्ध लोग ही वित्तीय साधनों तक बेहतर पहुंच रखते हैं, जो मुद्रास्फीति के प्रभाव से किसी तरह उनका बचाव करते हैं, जबकि गरीबों के पास नकदी या लेन-देन से संबंधी बड़ी राशि होने की संभावना है जिसपर वे ब्याज नहीं पाते हैं। अमीरों के सापेक्ष, गरीब न्यूनतम मजदूरी या पेंशन जैसे राज्य-निर्धारित आय पर भी अधिक निर्भर करते हैं जो पूरी तरह से मुद्रास्फीति के प्रति सूचिकांकित नहीं होते हैं।

दूसरी बात यह है कि कीमत अस्थिरता जमा और ऋण बाजार को भी कमजोर कर सकती है। जब मुद्रास्फीति बहुत तेजी से बढ़ती है तो लोग स्थिर ब्याज दरों पर बचत करने से बचते हैं क्योंकि मुद्रास्फीति में उछाल होने से उनकी बचत की

चार्ट 4: मुद्रास्फीति कम होने पर बैंकों पर विश्वास बढ़ता है[1]

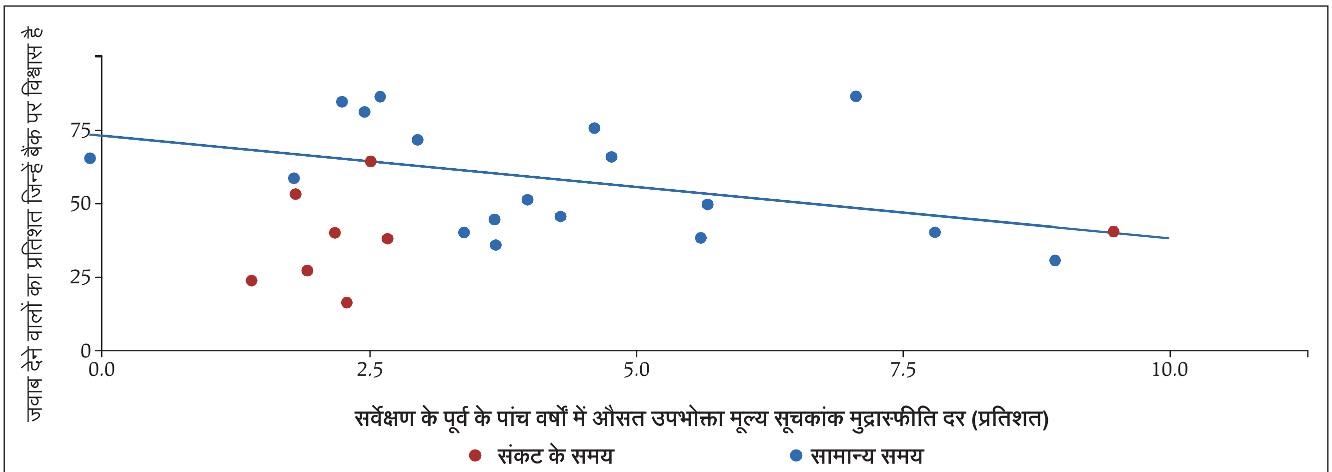

[1] "बैंकों पर विश्वास" का आकलन विश्व मूल्य सर्वेक्षण से किया गया है। वाई-ऐक्सिस, सर्वेक्षण का जवाब देने वाले उन व्यक्तियों का प्रतिशत दर्शाती है, जिन्होंने प्रश्न : ''क्या आप यह बता सकते हैं कि आपको बैंकों पर कितना विश्वास है: बहुत अधिक विश्वास है, अधिक विश्वास है, बहुत अधिक विश्वास नहीं है, या बिल्कुल विश्वास नहीं है" का उत्तर "बहुत अधिक विश्वास है" या "अधिक विश्वास है'' दिया है। एक्स ऐक्सिस, सर्वेक्षण के पूर्व के पाँच वर्षों में औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक दर्शाती हैं। लाल (नीले) बिन्दु उन देशों को दर्शाते हैं, जहां विश्व मूल्य सर्वेक्षण किए जाने के पाँच वर्ष पूर्व बैंकिंग संकट था (नहीं था)। 2010-14 के दौरान सर्वेक्षण किए गए 26 देशों का सैंपल

स्रोत : L Laeven and F Valencia, 'Systemic Banking Crises Database: An Update', IMF Working Papers, WP/12/163, 2012; World Value Survey (Wave 6); BIS.

[4] डब्ल्यू ईस्टर्ली और एस फीशर, 'इंफ्लेशन एंड द पुअर', जर्नल ऑफ मनी, क्रेडिट एंड बैंकिंग वॉल्यूम 33, न. 2, 2001, पीपी 160-78

कीमत नष्ट हो सकती है। दूसरी ओर, उधार लेने वाले अस्थिर ब्याज दर वाले ऋण नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि उच्च मुद्रास्फीति का मतलब अस्थिर मुद्रास्फीति है और ब्याज की वास्तविक दर अधिक रहने की संभावना होगी जिससे चुकौती के कार्यक्रम में अधिक अनिश्चितता होगी। चूंकि बचतकर्ता और उधारकर्ता शर्तों पर सहमत नहीं हो सकते इसलिए संबंधित बाजार धाराशायी हो सकता है जिससे वित्तीय समावेशन का कार्य कमजोर हो सकता है। यह क्षति बीमा जैसी अन्य वित्तीय सेवाओं तक तेजी से फैल सकती है। यदि कोई यह नहीं जानेगा कि भविष्य में उसके दावे के भुगतान के समय मुद्रा का क्या मूल्य होगा तो वह आज बीमा क्यों खरीदेगा?

वित्तीय स्थिरता वित्तीय समावेशन का एक अन्य स्तंभ है। संस्थाओं की आघात सहन करने की क्षमता वित्तीय प्रणाली की आघात सहन करने की क्षमता के समान ही महत्त्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए यदि कोई ग्रामीण सहकारी बैंक असफल हो जाए तो इसके ग्राहकों का विश्वास पूरी प्रणाली से उठ सकता है। ऐसी असफलताएं केवल कमजोर बैंकिंग प्रथा के कारण ही नहीं होती हैं बल्कि अपर्याप्त जमाराशि बीमा, विनियमन और पर्यवेक्षण के कारण भी होती हैं जिनसे भरोसा टूटता है।[5] फिर कल्पना करें कि पूरे प्रणालीगत संकट से लोगों के आत्मविश्वास पर क्या असर पड़ेगा।

वित्तीय संकट से उधार लेने की लागत बढ़ती है जिससे ऋण की भारी कमी और मंदी हो सकती है। उपलब्ध साक्ष्य यह संकेत करते हैं कि बैंकों ने 2007-09 के गंभीर वित्तीय संकट[6] को ध्यान में रखते हुए ऋण देने में बहुत तेजी से कटौती की। कुछ लोगों के लिए ऋण बंद किया जा सकता है और कुछ के लिए काफी महंगा हो सकता है। परिणामस्वरूप, व्यक्तियों और फर्मों को ऋण के लिए औपचारिक वित्तीय प्रणाली के बाहर देखने को मजबूर होना पड़ सकता है। इस प्रकार, वित्तीय संकट वित्तीय समावेशन की बाधाओं को और बढ़ा देते हैं।

आगे बढ़ने से पहले मैं यह जोर देकर बताना चाहता हूँ कि कीमत का एक तरफ वित्तीय स्थिरता तथा दूसरी तरफ वित्तीय समावेशन के साथ दोतरफा संबंध है। तालिका 3 में ग्रे कलर के तीर के निशान से इस लिंक को दर्शाया गया है। वित्तीय समावेशन केंद्रीय बैंकों तथा वित्तीय प्राधिकारियों को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहयोग कर सकता है। वित्तीय संस्थाएं विभिन्न क्षेत्रों और जनसांख्यिकी में जमाकर्ताओं और उधारकर्ताओं के व्यापक आधार के साथ अपने निधीयन और ऋण के अपने स्रोतों में बेहतर ढंग से विविधता ला सकती हैं।[7] इससे वे अधिक सुरक्षित होंगी।

समावेशी वित्त के लिए नवोन्मेषी उपाय

यद्यपि कीमत और वित्तीय स्थिरता वित्तीय समावेशन संबंधी विश्वास से संबंधित बाधाओं को दूर करती हैं, फिर भी वे केवल अपने बल पर वित्तीय समावेशन को बढ़ावा नहीं दे सकती हैं। अन्य कारकों में, पर्याप्त कानूनी प्रणाली, तकनीक और नवोन्मेषी उपाय की भी आवश्यकता होती है। वित्तीय सेवाओं की उच्च लागत तथा संभावित उपयोगकर्ताओं के प्रलेखीकरण और क्रेडिट हिस्ट्री की कमी जैसी वित्तीय समावेशन की अन्य बाधाओं को दूर करने में विशेष रूप से डिजिटल प्रौद्योगिकी और बिग डेटा की महत्त्वपूर्ण भूमिका है।

जब लागत में कटौती की बात आती है तो वेब और स्मार्टफोन आधारित वित्तीय सेवाएं सबसे प्रभावशाली सिद्ध हुई हैं। केन्या के एम-पेसा से लेकर चीन के अलीपे और भारत के पेटीएम तक, प्रौद्योगिकी ने वित्तीय सेवाओं को सचमुच अत्यंत सुगम बना दिया है। पहला, डिज़िटल टेक्नॉलजी वित्तीय सेवाओं की आपूर्ति के लिए सबसे सस्ता डिलीवरी चैनल मुहैया कराती है। दूसरा, डिज़िटल नेटवर्क उपयोगकर्ताओं का विस्तार करता है जिससे सकारात्मक नेटवर्क तैयार होता है। तीसरा, बड़ी संख्या में स्मार्टफोन के उपयोगकर्ताओं के कारण वित्तीय सेवा प्रदाताओं की पहुँच बड़ी संख्या में ग्राहकों तक होती है (तालिका 5, बाएं पैनल)। इस प्रकार, लगभग शून्य सीमांत लागत पर डिज़िटल वित्तीय सेवा प्लैटफार्मों का विस्तार किया जा सकता है। उदाहरण के लिए चीन में अलीपे अपने उपयोगकर्ताओं को निर्बाध रूप से बीमा खरीदने या वॉलेट की राशि को म्यूचुअल फंड में निवेश करने को सुगम बना देता है। विप्रेषण जैसी सीमापार सेवाओं में भी लागत में कमी लायी जा सकती है।

साथ ही, डेटा जेनरेशन, कलेक्शन और प्रोसेसिंग में सुधार से अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्रों में प्रलेखीकरण या क्रेडिट हिस्ट्री की कमी के कारण पैदा हुई समस्याओं को दूर किया जा सकता है। तालिका 5 के दायीं ओर का पैनल यह दर्शाता है कि इन सुधारों के कारण फिनटेक क्रेडिट का विस्तार बहुत तेजी से हुआ है। वास्तव में, बड़ी तकनीकी कंपनियाँ और बड़े प्रौद्योगिकी फर्म, पहले से ही अपने डिज़िटल प्लैटफार्मों के माध्यम से एकत्र डेटा की प्रोसेसिंग कर रहे हैं ताकि वे ऐसे उधारकर्ताओं को ऋण दे सकें जिन्हें बैंक बहुत जोखिम वाले मानते हों। एंट फाइनैंशियल

[5] जे. रेविलाक, 'द इम्पैक्ट ऑफ फाइनैंशियल क्राइसिस ऑन द पुअर', जर्नल ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट, 2018

[6] वी. इवाशिना और डी स्कार्फस्टीन, 'बैंक लेंडिंग ड्यूरिंग द फाइनैंशियल क्राइसिस ऑफ 2008', जर्नल ऑफ फाइनैंशियल इकनॉमिक्स, वॉल्यूम 97, न. 3, 2010, पीपी 319-38

[7] ओ. म्ब्यूटर, 'द इम्पैक्ट ऑफ फाइनैंशियल इंक्लूशन ऑन मॉनिटरी पॉलिसी इन नाइजेरिया', जर्नल ऑफ इकनॉमिक्स एंड इंटरनेशनल फाइनैंस, 2013. ए. मेहरोत्रा और जे. येटमैन, 'फाइनैंशियल इंक्लूशन- इश्यूस फॉर सेंट्रल बैंक्स', बीआईएस क्वार्टर्ली रिव्यू, मार्च 2015.

चार्ट 5: डिजिटल भुगतान और फिनटेक क्रेडिट

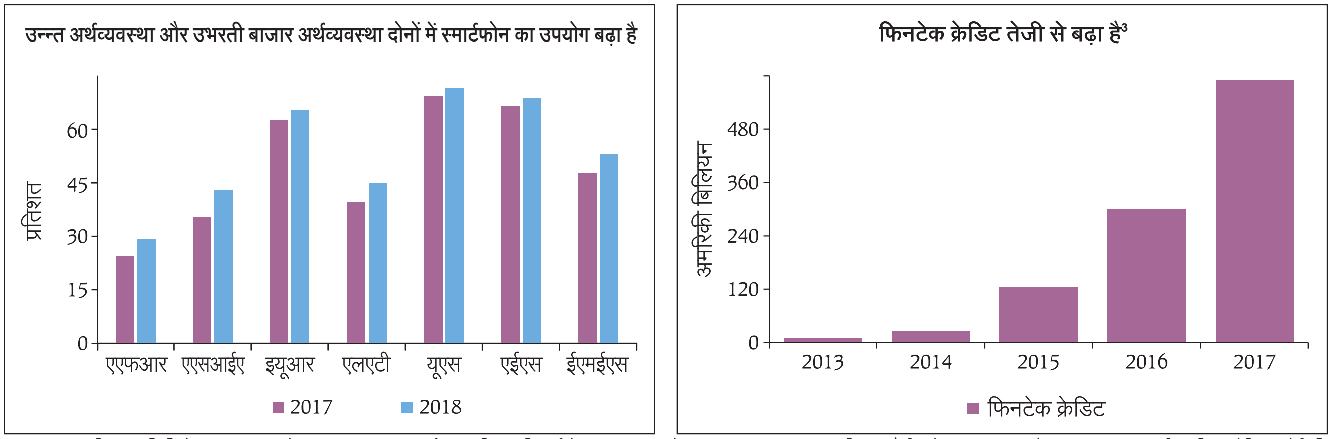

एएफआर = चुनिंदा अफ्रीकी देश, उपलब्धता के आधार पर; एएसआईए = चुनिंदा एशियाई देश, उपलब्धता के आधार पर; इयूआर = चुनिंदा यूरोपीय देश, उपलब्धता के आधार पर; एलएटी=चुनिंदा लैटिन अमेरिकी देश, उपलब्धता के आधार पर।

[1] उपलब्धता के आधार पर, एयू,बीई,सीए,सीएच,डीई,डीके,ईएस,एफआई,एफआर,जीबी, जीआर,आईटी,जेपी,एनएल,एनओ, एनजेड,पीटी,एसई,एसके और यूएस का सामान्य औसत।

[2] उपलब्धता के आधार पर, एआर,बीआर,सीएल,सीएन,सीओ,सीजेड,एचके,एचयू,आईडी, आईएन,केआर ,एमएक्स, एमवाई, पीई,पीएच,पीएल,आरयू ,एसए,एसजी, टीएच,टीआर,टी डब्ल्यू और जेडए का सामान्य औसत।

[3] यह स्तंभ वर्ष 2013-17 अवधि के दौरान फिनटेक और बिग टेक फर्म द्वारा वार्षिक वैश्विक उधार प्रवाह को दर्शाते हैं। इन आंकड़ों में अनुमानों को शामिल किया गया है।

स्रोत : जे फ्रोस्ट,एल गेम्बकोर्टा, वाई हुआंग एंड एच.एस.शिन, "बिग टेक एंड द चेंजिंग स्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंशियल इंटरमेडीएशन", बीआईएस वर्किंग पेपर नं 779, 2019, बिग टेक कंपनीज़ के वित्तीय विवरण, केंब्रिज सेंटर फॉर अलटेरनेटिव फाइनाइन्स एंड रिसर्च पार्टनर्स, न्यूज़ू।

एम वाई बैंक एक ऐसा उदाहरण है जो हाल में एक परंपरागत बैंक के साथ जुड़ा है ताकि ऑफ लाइन किसानों को बेहतर तरीके से सेवाएं उपलब्ध कराई जा सके। एम वाई बैंक ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को क्यूआर कोड वाले पोस्टर उपलब्ध कराता है जिसे स्कैन कर ग्राहक किसान को अलीपे के माध्यम से भुगतान करते हैं। इसके बाद यह बैंक लेनदेन के डेटा का उपयोग उन किसानों के क्रेडिट स्कोर तैयार करने और उन्हें ऋण उपलब्ध कराने के लिए करता है जिनके पास आम तौर पर नियमित बैंक ऋण तक पहुँच के लिए आवश्यक प्रलेखीकरण की कमी होती है। वस्तुतः 'नवसृजित डेटा संपार्श्विक प्रतिभूति का कार्य करते हैं'। यह वित्तीय समावेशन में पर्याप्त विकास को दर्शाता है।[8]

बायोमेट्रिक आधारित पहचान प्रोग्रामों में विकास से प्रलेखीकरण की बाधाओं को दूर करने में सहायता मिल रही है। ऐसी प्रगति के बाद लोग परिचय पत्र प्राप्त करने के लिए अपने फिंगर प्रिंट या रेटिना स्कैन का उपयोग कर सकते हैं। इस संबंध में, भारत का आधार कार्यक्रम एक बहुत बड़ी परिसंपत्ति है जो पहले से ही लाभ पहुँचा रहा है। आधार चालित भुगतान प्रणाली या AePS के माध्यम से, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कम बैंक शाखाएं उपलब्ध होने के बावजूद, लोग पैसे जमा कर सकते हैं, पैसे निकाल सकते हैं या पैसे भेज सकते हैं। मूलतः यह प्रणाली बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट्स को ग्रामीण क्षेत्रों में एक ऐसे माइक्रो एटीएम के साथ जाने की सुविधा प्रदान करती है जिससे ग्राहक की पहचान डिज़िटल माध्यम से की जा सकती है और उनके खातों का परिचालन किया जा सकता है।

नवोन्मेषी कदम भी जोखिम उत्पन्न कर सकते हैं

यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि नई प्रौद्योगिकी की कुछ कमियाँ भी हैं। अत्यधिक बाजार संकेंद्रीकरण बाजार की विफलता का एक संभाव्य परिणाम हो सकता है। जैसे ही एक बड़ा डिजिटल नेटवर्क स्थापित होता है, संभाव्य प्रतिद्वंदियों के पास प्रतिद्वंदी नेटवर्क बनाने और उसे चुनौती देने के अवसर कम होते हैं। एक नए नेटवर्क को स्थापित करने की निर्धारित लागत बहुत अधिक होगी। साथ ही, शक्तिशाली प्लेटफॉर्म, प्रवेश के क्षेत्र के अवरोधों को बढ़ाकर अपनी स्थिति और मजबूत करने का प्रयास कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब एक नेटवर्क ऑपरेटर एक स्मार्टफोन आधारित भुगतान प्रणाली का प्रयोग करता है, तो वह अपने संभाव्य प्रतिद्वंदियों, जैसे, बैंकों से कनेक्शन शुल्क की मांग कर सकता है, जो नए प्रवेशकों को प्रतिस्पर्धा करने से प्रभावशाली रूप से रोकने में सक्षम होगा। उनके पास एक कैप्टिव यूज़र बेस हो जाने पर, शक्तिशाली प्लेटफॉर्म अपनी वित्तीय सेवाओं की कीमत बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार, हालांकि नई तकनीक वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में आ रही कीमत संबंधी बाधाओं को दूर करती हैं, फिर भी बाजार संकेंद्रीकरण का प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है।

दूसरे प्रकार की बाजार विफलता ग्राहक संबंधी आंकड़ों से उत्पन्न होती है। जब बड़ी तकनीकी फर्में जैसे – ऐन्ट

[8] जी. डींग, जी.चांग, डी कुओ चुएन और टी. चेंग: 'फ्रॉम एंट फाइनैंशियल टु अलीबाबास रूरल तावबाव स्ट्रैटजी- हाउ फिनटेक इज़ ट्रांसफॉर्मिंग सोशल इंक्लूशन', माइमिओ, 2017

फाइनेंसियल, टेनसेंट या मर्कैडो लिब्रे – अपने ग्राहकों से संबंधित विस्तृत विवरण इकट्ठा करती हैं, वे कम से कम तब तक, उस आंकड़े के एकमात्र मालिक बन जाते हैं। इसे बड़ी तकनीकी फर्मों द्वारा दी जा रही सेवाओं का उप-उत्पाद माना जा सकता है। चूंकि ये आंकड़े निःशुल्क और गैर-प्रतिद्वंदी हैं – अर्थात् बिना कंटेंट की हानि के कई लोगों द्वारा इनका उपयोग किया जा सकता है, इसलिए सामाजिक रूप से यह अपेक्षित होगा कि इसे सभी के साथ साझा किया जाए। लेकिन ऐसा करने से बड़ी तकनीकी फर्म को कोई लाभ नहीं होगा। इसके विपरीत, ये आंकड़ें इन्हें अपने प्रतिद्वंदियों के प्रति एक सूचनात्मक लाभ देते हैं। उदाहरण के तौर पर, ऐसे विशेष आंकड़ों का उपयोग करते हुए वे एक संभाव्य उधारकर्ता की ऋण पात्रता और यहाँ तक कि, उस व्यक्ति की उधार लेने की उच्चतम क्षमता- यानि वह सबसे उच्चतम दर, जिसपर एक उधारकर्ता ऋण लेने के लिए इच्छुक हो – का मूल्यांकन कर सकती है। इसके आधार पर, एक बड़ी तकनीकी फर्म, ग्राहकों से उनके अधिशेष का अधिकांश हिस्सा लेते हुए, व्यक्तिगत उच्चतम दर तक, उच्चतर ब्याज दर की मांग कर सकती हैं। अतः आंकड़ों पर स्वामित्व नियंत्रण बड़ी तकनीकी फर्म की शक्तियों को बढ़ा देती है।

वित्तीय नवोन्मेष नए प्रकार की कठिनाइयाँ भी उत्पन्न करती है। विशेष रूप से, अपराधी, कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म द्वारा सुगम कराई गई गुमनामी और पर्यवेक्षी निगरानी न किए जाने का गलत फायदा भी उठा सकते हैं।

नीति निर्माता बाजार- विफलताओं और नवोन्मेषों द्वारा उत्पन्न जोखिमों को दूर करने में सहायता कर सकते हैं

वित्तीय नवोन्मेष द्वारा वित्तीय समावेशन को और आगे बढ़ाने के लिए वित्तीय नवोन्मेष के संभावित प्रतिकूल प्रभावों को दूर किया जाना चाहिए। इसमें नीति निर्माता, हार्ड और सॉफ्ट दोनों ही प्रकार की, बुनियादी संरचना के उन्नयन या नई बुनियादी संरचना उपलब्ध करवा कर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

हार्ड बुनियादी संरचना में वित्तीय सेवाओं का समर्थन करने वाली प्रणालियां और उपयोगिताएं शामिल हैं। उदाहरण के लिए उपयोगिताओं की स्थापना करना जैसे निपटान प्रणालियां या एक समान तकनीकी मानकों पर सहमत होना जो कि बाजार सहभागियों की क्षमता से बाहर हों। फिर भी, ऐसी बुनियादी संरचनाएं वांछनीय हैं क्योंकि ये लेन-देन की लागत को कम और प्रतिभागियों को एक समान अवसर प्रदान कर सकती हैं। जब बाजार जनता के हितों के लिए कुछ करने में विफल रहता है तो केंद्रीय बैंक और वित्तीय प्राधिकरण उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकते हैं। उदाहरण के लिए भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस को लें: यह सुविधा घरेलू और वैश्विक दोनों प्रतिभागियों को मोबाइल भुगतान एप्लीकेशनों को विकसित करने की अनुमति देता है। इस प्रकार यह इस क्षेत्र में प्रवेश के अवरोधकों, विशेष रूप से छोटी फर्मों के लिए, को कम करता है और इस प्रकार कार्य के क्षेत्र में एक समान अवसर प्रदान करता है।

प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने का एक और तरीका है – विनियामक प्रायोगिक परिवेश (सैंडबॉक्स) । ये नवोन्मेषियों को उनके नए उत्पादों को विनियामक की देखरेख में परीक्षण करने देते हैं। इस बीच में नवोन्मेष हब ज्ञान साझा करने, प्रतिस्पर्धा या निधियां जुटाने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं। इस प्रकार, हब और सैंडबॉक्स एक गतिशील वित्तीय परिदृश्य सुनिश्चित करने में मदद करते हैं- एक ऐसा परिदृश्य जिसमें यह आवश्यक नहीं है कि कुछ ही प्रतिभागी उसमें हावी हों। वे विनियामकों को नवीनतम वित्तीय नवोन्मेष में मूल्यवान अंतर्दृष्टि भी दे सकते हैं जो कि उन्हें पर्याप्त विनियामक प्रतिक्रिया डिजाइन करने में मदद कर सकती हैं। एक सुदृढ़ विनियामक ढांचा बाजार में प्रवेश के मार्ग को भी सुचारू कर सकता है। रिज़र्व बैंक सहित कई केंद्रीय बैंक ऐसी बुनियादी संरचनाएं स्थापित कर रहे हैं।

नीति निर्माता सॉफ्ट बुनियादी संरचना के लिए भी उत्तरदायी हैं जिसमें विनियम, मानक या कार्यक्रम शामिल हैं जो कि वित्तीय सेवाओं के प्रावधान को निर्देशित करते हैं, जोखिम को कम करते हैं – जैसे कि डेटा के संग्रहण और उसके उपयोग, धोखाधड़ी और धन शोधन से उत्पन्न होने वाले जोखिम।

डेटा से संबंधित मुद्दों के बारे में मैं उदाहरण के रूप में अमेजन पर क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हुए एक पुस्तक खरीदने के बारे में बात करना चाहूंगा। लेन-देन डाटा का मालिक कौन होना चाहिए- मैं, अमेजन या क्रेडिट कार्ड कंपनी ? क्या कंपनियों को मेरे लिंक्ड डिवाइसेस से मेरे लेन-देन डेटा का मिलान मेरी व्यक्तिगत जानकारी के साथ करने की अनुमति दी जानी चाहिए? उन्हें ऐसे डाटा के साथ क्या करने की अनुमति दी जानी चाहिए ? ये ऐसे प्रश्न हैं जिनके नैतिक और आर्थिक दोनों पक्ष हैं। उदाहरण के लिए, डेटा स्वामित्व पहले से ही कुछ बड़ी कंपनियों के बीच गंभीर रूप से केंद्रित है जो कि उन्हें अत्यधिक मात्रा में बाजार की शक्ति दे रहा है। और, कई मामलों में ग्राहक स्वयं ही सुखदरूप से इस बात से अनजान हैं कि उनके डेटा का उपयोग कैसे किया जा रहा है। वर्तमान नियमों की अपर्याप्तता के कारण इन मुद्दों से निपटना जटिल है।

अब तक नीतिगत प्रतिक्रिया समन्वित नहीं रही है। कुछ देशों ने डेटा गोपनीयता कानून बनाए हैं और कुछ देश इस पर विचार कर रहे हैं। इन देशों में शामिल हैं- ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय संघ, सिंगापुर और स्विट्ज़रलैंड। डेटा पोर्टेबिलिटी और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए 'मुक्त बैंकिंग' आवश्यकता के कुछ रूपों को भी अपना रहे देशों की संख्या बढ़ रही है। मूल विचार यह है कि उपभोक्ताओं को तीसरी पार्टी जैसे कि फिनटेक फर्म द्वारा उनके वित्तीय डेटा को एक्सेस करने को प्राधिकृत करने का अधिकार होना चाहिए। तब फिनटेक फर्म प्रतिस्पर्धी वित्तीय सेवाओं को प्रदान करने के लिए डेटा का उपयोग करेंगी।

एक संबंधित मुद्दा है साइबर सुरक्षा और धनशोधन। इस प्रकार के जोखिम को दूर करने में औपचारिक वित्तीय प्रणाली और सेवाओं पर जोर देने को अकसर महत्वपूर्ण रूप में देखा जाता है। एक चुनौती यह है कि मौजूदा धन शोधन प्रक्रियाओं को वित्तीय समावेशन में बाधा डाले बिना कैसे प्रभावी रूप से डिजिटल वित्तीय सेवाओं के लिए लागू किया जाए। मैक्सिको का हाल ही का 'फिनटेक कानून' इसका एक अच्छा उदाहरण है। यह 'समान जोखिम- समान विनियम' के सिद्धांत को अपनाता है और फिनटेक संस्थानों को भी बैंकों की तरह ही ऐसे लेन-देन को रोकने और उनकी पहचान करने के लिए सभी संभव उपाय किया जाना आवश्यक है जिसमें अवैध रूप से प्राप्त संसाधन या आंतकवाद को वित्तपोषण करना शामिल है।

निष्कर्ष

वित्तीय समावेशन समृद्धि में वृद्धि का प्रवेश द्वार है। केंद्रीय बैंक सिर्फ अपने मूल्य और वित्तीय स्थिरता के उद्देश्यों को पूरा करके इसमें प्रमुख भूमिका निभाते हैं । इसी के साथ नवोन्मेष और प्रौद्योगिकी की भी आवश्यकता है।

वित्तीय नवोन्मेष के प्रतिकूल प्रभाव भी हो सकते हैं इसलिए इसका निर्देशन भी होना चाहिए और समर्थन भी किया जाना चाहिए। नीति निर्माता पर्याप्त बुनियादी संरचना प्रदान करके सहायता कर सकते हैं। इसमें हार्ड बुनियादी संरचना जैसे भुगतान प्रणालियां या समाशोधन गृह और नियम, विनियमों और मानकों सहित सॉफ्ट बुनियादी संरचना दोनों ही शामिल हैं।

नीतिगत पहलों को देश की सीमाओं के पार भी समन्वित किया जाना चाहिए विशेष रूप से उन नवोन्मेषों के मामले में जो वित्तीय समावेशन के लिए महत्व रखते हैं। समन्वयन की आवश्यकता है क्योंकि नवोन्मेष और डेटा दोनों ही देश की सीमाओं के आर-पार आते-जाते हैं। नए वितरण चैनलों का लाभ उठाने वाली विप्रेषण सेवाएं इसका एक अत्यधिक प्रासंगिक उदाहरण हैं। विप्रेषण आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं, विशेष रूप से उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में। इसके अलावा चूंकि औपचारिक विप्रेषण अनौपचारिक विप्रेषणों की तुलना में सस्ता है अतः यह व्यक्तियों को वित्तीय रूप से समावेशित होने पर जोर डालने के लिए बाध्यकारक कारण प्रदान करता है। डिजिटल प्रौद्योगिकी किस प्रकार सीमा पार से भुगतान को बढ़ा सकती है इसके बारे में एक संयुक्त अध्ययन हाल ही में बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ कनाडा और सिंगापुर मौद्रिक प्राधिकरण[10] द्वारा प्रकाशित किया गया था । बड़े पैमाने की किफायतें इस प्रकार के अनुप्रयोगों का एक लाभ है।

बीआईएस इस क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में योगदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी नई मध्यम अवधि रणनीति ' नवोन्मेष बीआईएस 2025' में कई पहलों को अपनाया गया है जिनके संबंध में हमें आशा है कि वे वित्तीय प्रणाली के लिए तकनीकी विकासों में अंतर्दृष्टि प्रदान करेंगी और उन्हें प्रभावी रूप से प्रयोग करने के लिए नीति निर्माताओं की सहायता करेंगी। उदाहरण के लिए नवोन्मेष संबधित कार्य में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए हमारी एक बहु-विषयक नवोन्मेष हब स्थापित करने की योजना है। एक नई इकाई नीति इस संबंध में विश्लेषण और अनुसंधान करेगी कि कैसे नवोन्मेष और बढ़ी हुई डेटा उपलब्धता केंद्रीय बैंकों की प्रतिक्रिया को आकार दे सकते हैं।

वित्तीय नवोन्मेष द्वारा उत्पन्न चुनौतियां दर्शाती हैं कि हमें अपने सामूहिक प्रयासों को व्यापक बनाने और नीतिगत विचारों में डेटा को एकीकृत करने की आवश्यकता है। मानकों को परिभाषित करना और यह निर्णय करना कि डेटा तक किसकी पहुंच होनी चाहिए और उनका बेहतर प्रबंधन कैसे किया जाए कुछ महत्वपूर्ण और विचारणीय पहलू हैं। इन प्रश्नों के सही उत्तरों से विनियामक मध्यस्थता की व्याप्ति और प्रतिकूल प्रभाव विस्तार में कमी हो सकती है, बाजारों को प्रतिस्पर्धी बनाए रखा जा सकता है और वित्तीय समावेशन की ओर नवोन्मेष के लाभों को और अधिक भेजा जा सकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग महत्वपूर्ण है प्रौद्योगिकी वित्तीय मध्यस्थता को नया रूप प्रदान करती है।

[9] 'मुक्त बैंकिंग' एक ढांचा है जिसके तहत उपभोक्ता अपनी बैंकिंग जानकारी अन्य वित्तीय सेवा प्रदाताओं जैसे वित्तीय एग्रीगेटर या अन्य फिनटेक फर्म के साथ साझा कर सकते हैं। संक्षेप में, मुक्त बैंकिंग व्यक्तिगत बैंकिंग डेटा को पोर्टेबल बनाती है। तकनीकी पक्ष की ओर पर, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध एपीआई (एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस) के उपयोग से जानकारी का साझा किया जाना संभव हो पाता है जो कि एक एप्लीकेशन (जैसे, एऑनलाइन बैंकिंग ऐप) को दूसरे के साथ सीधे संवाद (जैसे, एक वित्तीय एग्रीगेटर ऐप) की अनुमति प्रदान करता है।

[10] बैंक ऑफ कनाडा, बैंक ऑफ इंग्लैंड और सिंगापुर मौद्रिक प्राधिकरण, "सीमापारीय अंतर बैंक भुगतान और निपटानः डिजिटल अंतरण के लिए उभरते अवसर", नवंबर 2018।

गवर्नर देशमुख और भारिबैं के अग्रणी प्रयासों के बाद से वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में भारत ने अत्यधिक प्रगति की है। इस प्रगति को आगे बढ़ाने में केंद्रीय बैंक और सरकारी नीतियों की भूमिका का महत्व सर्वविदित है। हां, और भी बहुत कुछ किया जाना है। जैसा कि एक पुरानी कहावत में कहा गया है: हम हवा का रुख तो नहीं बदल सकते पर अपनी नाव के पाल का रुख तो बदल सकते हैं।'

ध्यान देने के लिए धन्यवाद।

*वैश्विक पटल पर भारत का बढ़ता महत्व क्या यह लंबे समय तक बना रहेगा और क्या हम इसके लिए तैयार हैं?**

श्री बी. पी. कानूनगो

आज आपके बीच आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है और आपसे बात करने का यह शुअवसर प्रदान करने के लिए मैं फेडाई एवं इस सम्मेलन के आयोजकों को धन्यवाद देना चाहता हूं। फेडाई पिछले छह दशकों से भी लंबे समय से विदेशी मुद्रा बाज़ार में आम जनता के साथ-साथ सीमा-पार अंतर-बैंक लेन-देन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। याद कीजिए कि शुरुआती दिनों में जब विदेशी बैंकों की केवल चुनिंदा शाखाओं द्वारा ही ऐसे विदेशी मुद्रा लेन-देन किए जाते थे, तब इस तरह के लेन-देन को निष्पक्ष बनाने के लिए फेडाई का गठन किया गया था। समय के साथ, वैधानिक ढांचे द्वारा विदेशी मुद्रा डीलरों को अधिकृत डीलर की एक अतिरिक्त भूमिका का निर्वहन करने का आदेश दिया गया – जो इतना व्यापक है कि वे विनियामक व्यवस्था के संचालन की जिम्मेदारी साझा करते हैं। प्राधिकृत (विदेशी मुद्रा) डीलरों की संस्था के रूप में फेडाई ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और अगर आज हम विदेशी मुद्रा बाजार में भागीदारी बढ़ा रहे हैं तो इसका कुछ श्रेय फेडाई को भी जाता है जिसने विदेशी मुद्रा संबंधी कारोबार के लिए प्रचुर मात्रा में और व्यापक रूप से आवश्यक कौशल विकास किया है। मुझे यकीन है कि यह रचनात्मक भूमिका निभाता रहेगा और बाजार सहभागियों को उन चुनौतियों से निपटने में मदद करेगा जो विदेशी मुद्रा बाजार में समय-समय पर आने वाले उछाल के कारण बाजार में अस्थिरता और अनिश्चितता लाती हैं।

वर्ष 2006 से आयोजित किए जा रहे ये वार्षिक सम्मेलन महत्वपूर्ण आयोजन रहे हैं, और मैं यह मानता हूं कि यह आयोजन सबसे महत्वपूर्ण है जिसका विदशी मुद्रा बाज़ार के भागीदार बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। इससे बाज़ार के भागीदारों को नेटवर्किंग एवं विचारों के आदान-प्रदान का अवसर मिलता है। यह धूप और धूल भरे बाज़ार के माहौल से भी राहत प्रदान करता है। इस वर्ष के आयोजन की थीम को ध्यान में रखते हुए सम्मेलन हेतु इस स्थान के चयन की मैं प्रशंसा करता हूं। चीन एवं भारत सदियों से व्यापार एवं सभ्यता संबंधी जैसी बहुआयामी यात्रा के साथी रहे हैं। एंगस मैडिसन[1] मानते हैं कि 18वीं सदी की शुरुआत तक भारत और चीन दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रहे हैं। क्रय शक्ति समता (पीपीपी) के आधार पर चीन विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि भारत का स्थान तीसरा है।यदि आप निर्यात एवं आयात को जोड़ दें, तो चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार (2017-18 का डेटा) है। सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में इन दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी में आने वाले समय में अभूतपूर्व उछाल देखा जा सकता है।

इस सम्मेलन के लिए चुना गया विषय है: अंतरराष्ट्रीय पटल पर भारत का बढ़ता महत्व: *क्या यह लंबे समय तक बना रहेगा और क्या हम इसके लिए तैयार हैं?* ये दिलचस्प और महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, और जैसा कि हम देखेंगे, ये हमारे सामान्य व्यवहारिक कार्यक्षेत्र के लिए काफी प्रासंगिक हैं। अब, अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में महत्व के कई आयाम हैं: कुछ का अगर हम नाम लें तो वे हैं - सांस्कृतिक, सैन्य, नैतिक, रणनीतिक परंतु इन सबसे बढ़कर जो आयाम है वह आर्थिक है। यदि आप मानव सभ्यता के इतिहास को देखें, तो आप पाएंगे कि यह आर्थिक समृद्धि ही है जो किसी भी देश की महत्ता तय करती आई है। यदि हम 15वीं/16वीं शताब्दी के इटली के शहरी राज्यों को देखें तो हम पाएंगे कि शेक्सपियर के कई नाटकों की पृष्ठभूमि वेरोना से वेनिस तक थी - और यह सोचकर अचरज होता है कि क्या मेडिसी और अन्य के समर्थन और धन के बिना ऐसा पुनर्जागरण संभव हो पाता, अथवा 18वीं/19वीं सदी का ब्रिटेन जो दो सदियों के लिए एक महत्वपूर्ण वैश्विक शक्ति बन गया, तथा अंग्रेजी संपर्क भाषा बन गई - यह आर्थिक संवृद्धि ही है जिसने इन देशों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण बनाया। आज के समय में चीन की श्रेष्ठता बहुत हद तक उसकी अभूतपूर्व आर्थिक सफलता के कारण ही है।

हमें यह भी गौरतलब है कि आर्थिक समृद्धि लगभग हमेशा ही अभिन्न रूप से अंतरराष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य के साथ

* श्री बी.पी. कानूनगो, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक। बीजिंग में 19 अप्रैल 2019 को आयोजित FEDAI के वार्षिक सम्मेलन में दिया गया भाषण।

[1] मेडसिन एंगस " द विर्ल्ड इकोनॉमी, हस्टिोरकिल स्टैटक्सि, 2003

जुड़ी रही है (पूंजीगत आंदोलन हाल की घटनाएं हैं)। औद्योगिक क्रांति से उत्पादकता में हुई वृद्धि ने मुक्त व्यापार और वाणिज्य की आवश्यकता को रेखांकित किया। बेशक, यह उस अर्थ में नहीं था जैसा कि अब हम समझ रहे हैं। उन्नीसवीं सदी के मध्य तक, यूरोप में वाणिज्यवाद प्रमुख नीति निर्धारक की भूमिका में था। इसमें कोई संदेह नहीं कि इसने स्वर्ण को छोड़कर सभी वस्तुओं के निर्यात का समर्थन किया, लेकिन साथ ही आयात शुल्क के माध्यम से आयात को हतोत्साहित करने का भी प्रयास किया। अंततः, 1846 में कॉर्न लॉ (ब्रिटिश) को निरस्त करने के साथ ही मुक्त व्यापार का मुद्दा स्पष्ट रूप से परिभाषित हो गया। मुक्त व्यापार कल्याण को बढ़ावा देता है; इस धारणा को आगे हुए शोधों ने सैद्धांतिक धरातल पर मजबूती ही प्रदान की है। इस तथ्य के बावजूद कि पिछले दो शताब्दियों में वैश्विक आर्थिक विकास और वैश्विक व्यापार में वृद्धि साथ-साथ चली है, आयात प्रतिस्थापन, चुनिंदा संरक्षण, अनुदान के पक्ष में जबकि कम प्रतिबंध वाले व्यापार से संबंधित वैश्विक उद्देश्य बना रहेगा, तथापि अन्य समष्टि-आर्थिक कारकों, जैसे कि राजकोषीय नीति, विनिमय दर नीति, रोजगार नीति, आदि को ध्यान में रखते हुए स्थानीय परिवर्तनों पर विचार करना होगा।

वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार के विपरीत, पूंजी प्रवाह का मामला स्पष्ट नहीं रहा है। यद्यपि यह सही है कि ब्रेटन वुड्स प्रणाली में पूंजी प्रवाह पर प्रतिबंध लगाए गए थे, तथापि, सत्तर के दशक की शुरुआत में ब्रेटन वुड्स प्रणाली के असफल होने के बाद मुक्त पूंजी प्रवाह के पक्ष में मजबूत दावे सामने आए जिसे आईएमएफ का समर्थन भी मिला। 1990 के उत्तरार्ध के सुदूर पूर्वी संकट के मद्देनजर, इसकी वांछनीयता के बारे में बहस फिर छिड़ गई। वैश्विक वित्तीय संकट के बाद इस बहस ने फिर से जन्म ले लिया और उसके बाद से एक आम सहमति बनी हुई है - और मैं यहां ब्रेटन वुड्स के मुख्य निर्माताओं में से एक, हैरी डेक्सटर व्हाइट के शब्दों को दोहराना चाहूंगा, - "उपयोगी पूंजी को उन क्षेत्रों में प्रवाहित करने को प्रोत्साहित करना जहां इसे सबसे अधिक लाभप्रद रूप से उपयोग में लाया जा सके, इस पर जोर देने की कोई आवश्यकता नहीं है, परंतु ऐसा भी समय आता है जब पूंजी प्रवाह को सही मोड़ न दे पाने से गंभीर आर्थिक व्यवधान वाले परिणाम सामने आए हैं'। कीन्स इससे सहमत थे।

मैंने व्यापार और पूंजी प्रवाह से संबंधित प्रस्तावों पर जो चर्चा की है उसके पीछे मेरा मकसद यह स्पष्ट करना है कि दोनों में से किसी से संबंधित कोई भी सार्वभौमिक स्वीकार्य नीति नहीं है। सिद्धांत और अनुभववाद दोनों ही देश की विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त नीति के विशिष्ट सेटों की संभाव्यता को शामिल करते हैं और इसी पृष्ठभूमि में हम अतीत और वर्तमान के सीमा-पार लेन-देन के संबंध में अपनी नीतियों पर विचार करेंगे।

सीमापार लेन-देन व्यवस्था के कई पहलू हैं: परंतु हमारी इस चर्चा का प्रयोजन विनिमय नियंत्रण बल्कि विदेशी विनिमय प्रबंधन से संबंधित है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन नीति अंततः दो कारकों पर निर्भर है: विदेशी मुद्रा की उपलब्ध मात्रा और विनिमय दर। इसने भारत में विनिमय नियंत्रण व्यवस्था के उद्भव को दिशा प्रदान की है और देखा जाए तो वास्तव में दुनिया भर में दिशा दी है।

वर्ष 1947 में फेरा, 1947 द्वारा सांविधिक व्यवस्था में प्रशासनिक फिएट के माध्यम से युद्धकालीन समय विनिमय नियंत्रण को परिवर्तित किया गया था। 1960 में विदेशी मुद्रा की अत्यधिक कमी और अन्य विभिन्न कारकों जैसे कि खाद्यान्न की कमी, युद्ध होने आदि ने और अधिक कठोर व्यवस्था फेरा, 1973 की ओर ले गई। विदेशी मुद्रा को स्वत: महत्वपूर्ण माना जाता था और नीति व्यवस्था में विभिन्न मांगों के लिए विदेशी मुद्रा का अनिच्छित आबंटन के नियम शामिल थे। आयात नियंत्रण और आयात प्रतिस्थापन के प्रोत्साहन ने मानार्थ नीति साधन प्रदान किए हैं। सत्तर के दशक के मध्य में (फेरा, 1973 के लागू होने के तुरंत बाद लेकिन आवश्यक नहीं कि इसी कारण से) बाहरी क्षेत्र से संबंधित स्थिति के प्रारंभ में भारतीय प्रसार से बढ़ते विप्रेषण और हरित क्रांति के प्रभाव से सुधार होने लगा। इस प्रकार 1980 के दशक में, सीमापार लेन-देन में प्रगतिशील और वृद्धिशील उदारीकरण हुआ लेकिन ऐसा एक ही दृष्टांत में हुआ। यहां एक के बाद दो बातें क्रमश: इस प्रकार हैं।पहली, विनिमय नियंत्रण व्यवस्था में उदारीकरण से अन्य आर्थिक नीतियों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन शामिल नहीं था। दूसरा, हालांकि ब्रेटन-वुड्स शासन 1970 के दशक की शुरुआत में

टूट गया और कई मुद्राएं चलायमान हुईं, रुपया एक नियंत्रित विनिमय दर प्रणाली में रहा, पहले पाउंड स्टर्लिंग और फिर विविध मुद्रा समूह में। इस प्रकार, नब्बे के दशक की शुरुआत में एक बार फिर विदेशी मुद्रा संकट सामने आया। इस समय संकट के उपरांत नीतिगत प्रतिक्रिया एक व्यापक सुधार थी। जहां तक सीमापार लेनदेन को विनियमित करने का संबंध है, मैं यहां तीन ऐतिहासिक घटना का उल्लेख करना चाहूंगा: (ए) 1993 में बाजार निर्धारित विनिमय दर प्रणाली को अपनाना, (ख) आइएमएफ चार्टर के अनुच्छेद 8 के अनुरूप प्रतिबद्धता - चालू खाता परिवर्तनीयता - 1994 में और (ग) 1999 में फेमा का अधिनियमन - एक दबाववाली व्यवस्था को हटाकर। यह एक नया प्रतिमान था।

हम इस प्रतिमान में अब तक लगभग ढाई दशक रहे हैं। समय-समय पर नीति व्यवस्था में तालमेल रहा है, परंतु मूल सिद्धांत समान हैं और जो भविष्य में नीतिगत ढांचे के विकास का मार्गदर्शन करते रहेंगे। मैं आपका ध्यान फेमा, 1999 की प्रस्तावना की ओर आकर्षित करता हूं, जो बहुत ही सरलता से सीमापार लेन-देन को कैसे नियंत्रित करने के दर्शन को सारांशित करता है। यह इस प्रकार है: ***" एक अधिनियम जो भारत में विदेशी मुद्रा बाजार के क्रमिक विकास और रखरखाव को बढ़ावा देने और बाहरी व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से विदेशी मुद्रा से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करता है।"***

जहां तक चालू खाता का सवाल है, इस क़ानून में यह अधिदेश है कि रिज़र्व बैंक के परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के अतिरिक्त कोई अन्य प्रतिबंध नहीं होगा। नियम-पुस्तिका में जो प्रतिबंध दिए गए हैं, वे अधिकतर कुछ (सामाजिक रूप से अवांछनीय) गैर-प्राथमिकता प्राप्त गतिविधियों जैसे जुआ,ऐसे लेन-देन जहां पूंजीगत लेन-देन को चालू खाता लेन-देन के रूप में प्रयोग किया जाता है और कुछ का रणनीतिक निहितार्थ के लिए। कुछ विषमता भी है, अगर नियम नहीं हैं, चालू खाते के लेन-देन के मध्य जिसमें एक बाहरी प्रेषण और जिसमें एक आवक शामिल है। चालू खाता लेन-देन के लिए विनियामक ढांचा अत्यधिक स्थिर रहा है; मैं कह सकता हूं कि आउटसोर्सिंग हब के रूप में भारत की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए सेवाओं में लेन-देन लगातार बढ़ रहा है। हालांकि भुगतान संतुलन को संकलित करने हेतु सकल आंकड़ों के संग्रह के लिए एक व्यापक प्रणाली मौजूद है, संभवत: हमें जहां आवश्यकता है वहां अपनी समझ में सुधार करने और नीतिगत कार्रवाई को बेहतर बनाने के लिए वणिक व्यापार की तरह ही लेन-देन स्तर के आंकड़े एकत्रित करने के लिए एक प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता है।

अब मैं पूंजी खाता लेनदेन की ओर रुख करता हूं। यह क़ानून रिज़र्व बैंक (और 2015 के फेमा में संशोधन, 1999 को अधिसूचित किया गया था, केंद्र सरकार कुछ वर्गों के लेन-देन में) विनियमित करेगा कि किस सीमा तक और किन शर्तों के अधीन किसी पूंजी खाते के लेन-देन की अनुमति है। आंशिक रूप से इन वैधानिक प्रावधानों के कारण परंतु अधिकांशत: पिछले दो दशकों के दौरान विकसित समष्टि आर्थिक स्थितियों, पूंजी खाते से संबंधित नीतिगत कार्यवाहियों के कारण हैं।

जैसा कि मैंने पहले कहा, 1970 के आरंभ से, और 1980 के पूरे दशक और 1990 के दशक में भी मुक्त बाजार के समर्थकों ने सम्पूर्ण पूंजी संपरिवर्तनीयता की पुरजोर वकालत की थी। यह 1994 के आईएमएफ़ की मैड्रिड घोषणा में फलीभूत हुआ, जिसमें सदस्य देशों को पूंजी प्रवाहों में आने वाली बाधाओं को दूर करने हेतु प्रोत्साहित किया गया। तथापि, बाद की वैश्विक आर्थिक प्रगति ने इस अवस्थिति (स्टांस) में संशोधन कर दिया है और अब यह स्वीकार कर लिया गया है कि पूंजीगत नियंत्रणों को वस्तुतः व्यष्टिआर्थिक और वित्तीय स्थिरता हेतु एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। अब यह लक्ष्य (गोलपोस्ट) संपरिवर्तनीयता से पूंजीगत लेखा उदारीकरण यानी एक घटना से एक प्रक्रिया में बदल गया है। इससे उदारीकरण की गति और स्वरूप संबंधी मुद्दे खड़े होते हैं, जिसके संवाहक वैश्विक सिद्धांतों पर आधारित होने की बजाय, चयनवादी (एक्लेक्टिक) और देश-केन्द्रित हैं। व्यापक तौर पर, तीन निर्धारक कारक महत्वपूर्ण हैं: (क) पूंजीगत खाता खोलने हेतु पूर्वशर्त (ख) पूंजीगत लेखा प्रतिबंधों की लागत और प्रभाविता और (ग) लगातार उदार होते पूंजीगत लेखा के मौद्रिक नीति निहितार्थ।

तब भी, विदेशी मुद्रा बाजार की स्थिरता और व्यवस्थित स्थितियाँ पूंजी प्रवाहों संबंधी नीतियों की निकटस्थ निर्धारक बनी रहेंगी। हमारे मामले में, जहाँ पूंजी प्रवाह आयात-निर्यात अंतर और बचत-निवेश अंतर को पाटने के दुहरे उद्देश्य को पूरा करते हैं, वहीं उपर्युक्त विचारण विनियमन के दृष्टिकोण को निर्धारित करेंगे। पूंजीगत लेखा उदारीकरण के लिए सामान्यतः तीन पूर्वशर्तों पर चर्चा की जाती है: मूल्य स्थिरता, राजकोषीय स्थिरता और वित्तीय संस्थाओं एवं बाज़ारों की स्थिरता। जैसा कि आज हम चर्चा कर रहे हैं, उल्लिखित मानदंडों के संबंध में उपलब्धियां अलग-अलग हैं। आम सरकार के स्तर पर राजकोषीय घाटे में सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है। यह अपेक्षित है कि हम और अधिक उदार पूंजीगत खाते की ओर बड़े कदम उठाएँ, इससे पहले संवृद्धि निम्न मुद्रास्फीति और राजकोषीय विवेक के साथ अच्छी तरह तालमेल बिठा ले। इसके अलावा, दूरस्थ क्षितिज में ही सही, वैश्विक प्रतिकूलताओं (ग्लोबल हेडविंड्स) के संकेत भी दिख रहे हैं।

हालांकि पूंजीगत लेखा उदारीकरण की बारीकियाँ विस्तृत विषय हैं, पूंजी प्रवाहों के पदानुक्रम संबंधी कुछ व्यापक नीतिगत परमाधिकारों का उल्लेख किया जा सकता है। पहला, वित्तीय क्षेत्र में प्रवाहों की तुलना में, खास तौर पर रियल सैक्टर के लिए पूंजी प्रवाहों को सदैव वरीयता मिलेगी। दूसरा, ऋण अंतःप्रवाहों की तुलना में इक्विटी संबंधी पूंजीगत अंतःप्रवाहों को तरजीह मिलेगी। इक्विटी प्रवाहों में भी, पोर्टफोलियो प्रवाहों के मुक़ाबले प्रत्यक्ष निवेश प्रवाहों को तरजीह मिलेगी। और जहाँ तक ऋण प्रवाहों का मामला है तो दीर्घावधि ऋण और रुपया-नामित ऋण – चाहे द्विपक्षीय करारबद्ध हों या विपणन-योग्य प्रतिभूतियों के मार्फत- को तरजीह मिलना जारी रहेगा। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, बाह्य वाणिज्यिक उधारियों, व्यापार घाटे आदि के संबंध में हाल में हुए नीतिगत बदलावों से आप अवगत हैं। तथापि, ये बदलाव अपनी अवस्थिति (स्टांस) में किसी महत्वपूर्ण बदलाव करने की बजाय, अधिकांशतः युक्तिकरण और सुदृढ़ीकरण ही करते हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था की निवेश आवश्यकताएँ बहुत अधिक हैं और बहुत अधिक बनी रहेंगी। अपेक्षित संवृद्धि को बल देने वाले आइकोर-चालित निवेश के अलावा, भौतिक और सामाजिक अवसंरचना क्षेत्रों के लिए भारी निवेश की भी आवश्यकता है। बाद वाले इन निवेशों की लंबी और अनिश्चित निष्पादन अवधि, लंबी निवेश-वापसी अवधि आदि के रूप में अपनी चुनौतियाँ हैं। दुनिया अभी पेंशन फ़ंड के रूप में दीर्घावधि बचतों और बीमा कंपनियों की मूल निधियों से लबालब है। इसलिए हमारी नीति व्यवस्था को इतना चपल-चुस्त और समायोजी होना पड़ेगा कि इन्हें भारत में उत्पादक उपक्रमों की ओर मोड़ा जा सके। हम इस दिशा में काम कर रहे हैं।

अवसंरचना क्षेत्रों पर बात करते हुए, हम निवेशकों के एक नये वर्ग के उदय को नोटिस किए बिना नहीं रह सकते: जोखिम पूंजी और निजी इक्विटी। उपख्यान्यात्मक रिपोर्टें ऐसा बताती प्रतीत होती हैं कि पिछले कुछ वर्षों में, ऐसी निधियों द्वारा निवेश एफ़डीआई अंतःप्रवाहों का लगभग 30-40 प्रतिशत हिस्सा निर्मित कर रहा है। जहाँ एक ओर पेंशन फ़ंड, बीमा कंपनियों, राष्ट्रिक फ़ंड, ट्रस्ट, एंडोमेंट आदि जैसे दीर्घावधि निवेशकों और दूसरी ओर संभावनाशील संवृद्धि उद्योगों के बीच मध्यस्थ के रूप में वीसी और पीई फंड की भूमिका जिस तरह महत्वपूर्ण है, इन निवेशों की अलग-अलग संरचनात्मक और व्यवहारगत विशेषताएँ हैं। वर्तमान व्यवस्था सामान्य एफ़डीआई में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण लेकिन जोखिमपूर्ण माने जाने वाले कुछ चुनिंदे क्षेत्रों में वीसी निवेशकों को व्यापक स्वतंत्रता देती है। शायद यहाँ निजी इक्विटी निवेश को इसकी संपूर्णता में विचार करने और यह देखने की आवश्यकता है कि क्या नीतिगत व्यवस्था में- व्यापक और नवोन्मेषी कर्ज-निधियन, मिश्रित लिखतों आदि, खासकर जहाँ वे अवसंरचना, अपारंपरिक ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं अन्य सामाजिक प्रभाव वाले क्षेत्रों जैसे प्राथमिकता क्षेत्रों से संबन्धित हैं, सहित- फेरबदल वांछित है। यह हमारा ध्यान खींच रहा है।

स्टार्ट-अप से जुड़े मुद्दे बेहद महत्वपूर्ण हैं। कारोबार का विकास जिस प्रकार हुआ है, कुछ समय पूर्व इस प्रकार के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती थी। सबसे बड़ी परिवहन कंपनी जिसके पास खुद की कार नहीं है, सबसे बड़ी खुदरा कंपनी जिसके पास खुद की कोई दुकान नहीं है इत्यादि; मिसाल के तौर पर इसके उदाहरण है। प्रौद्योगिकी और इंटरनेट ने सेवा उद्योग में क्रांति लाने का काम जारी रखा है। अधिकांश स्टार्ट-अप ने रोजगार सृजन में बहुत अधिक योगदान दिया है (क्या हमें अर्थव्यवस्था में रोजगार को महत्व देते हुए वृहद रोजगार संभावना के क्रियाकलापों के लिए बेहतर एफ़डीआई व्यवस्था की शुरुआत करनी चाहिए?)। अपने बढ़ते चरण में स्टार्ट-अप को पूंजी की बहुत आवश्यकता होती है और इस

पूंजी का एक बड़ा हिस्सा विदेशी निवेश के माध्यम से ज्यादातर उद्यम पूंजी या निजी इक्विटी फंड के रूप में आता है। हमने पूर्व में स्टार्ट-अप्स द्वारा फंड जुटाने की सुविधा के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन हम इसके अनुपालनगत बोझ को कम करने के साथ-साथ इसकी उभरती जरूरतों के प्रति ज़िंदादिली बनाए रखेंगे।

जहां तक पूंजी के बहिर्गमन का संबंध है, हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? अब तक यह लगभग पूरी तरह से प्रत्यक्ष निवेश के प्रति रहा है। इतना ही नहीं, इक्विटी और ऋण बहिर्गमन के लिए कोई अलग नीति नहीं है। फ़ेरा काल के दौरान जो नीति दृष्टिकोण आगे चलता आ रहा था उसमें कई प्रकार की नकारात्मकता थी। एक पूंजी अभाव वाला देश पूंजी निर्यात क्यों करता है? क्या विदेशी निवेश की प्रक्रिया पर उससे प्राप्त होने वाले लाभांश के आधार पर विचार नहीं किया जाना चाहिए? शायद इस पर फिर से विचार करने का समय आ गया है। भारतीय निवासियों द्वारा विदेशी संपत्ति का निर्माण की प्रविष्टि अंतरराष्ट्रीय निवेश की स्थिति में एक क्रेडिट प्रविष्टि के रूप में की जाती है। इसलिए लाभांश अर्जन की जगह मूल्यवर्धन पर विचार करने की जरूरत है। दूसरा, रणनीतिक और आर्थिक संपत्ति का अधिग्रहण जैसे - कोयला क्षेत्र, तेल क्षेत्र, आदि एक दीर्घकालिक प्राथमिकता है। तीसरा, विदेशी निवेश को शायद निर्यात के रूप में देखा जा सकता है, जिसे पूंजी का निर्यात न मानते हुए उद्यमिता का निर्यात मानना चाहिए। अंतिम बात यह है की विदेशी निवेश स्टार्ट-अप से जुड़ा एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कई स्टार्ट-अप्स व्यक्तिगत उद्यमियों सहित विदेशी होल्डिंग कंपनी के माध्यम से भारत में निवेश करते हैं; ताकि एक विदेशी क्षेत्राधिकार में पूंजी जुटाने में आसानी हो। जबकि आर्थिक गतिविधि भारत में घटित होती है जो रोजगार, राजस्व और आर्थिक मूल्य का सृजन करती है। हम, भारत सरकार के साथ, इस संबंध में विनियामकीय शासन में मौजूद किसी भी गलतफ़हमी पर पुनः विचार करेंगे और आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करेंगे।

अब मैं विदेशी मुद्रा बाजार पर आता हूँ। मुझे पता है कि विदेशी मुद्रा बाजार में काम कर रहें ट्रेजरी प्रोफेशनल इस क्षेत्र में बड़ा स्थान रखते हैं और यह एक ऐसा विषय है जिससे आप निकटता से जुड़े हुए हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बतलाया था कि एक सुव्यवस्थित विदेशी मुद्रा बाजार का होना एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है और एक्स्चेंज प्रबन्धन व्यवस्था को आगे बढ़ाने की यह एक पूर्वशर्त है। हम 'आरबीआई मध्यवर्ती दर' के दिनों से काफी आगे आ चुके हैं। आज, भारतीय विदेशी बाजार दैनिक कारोबार के मामले और उपलब्ध उत्पादों की रेंज में बहुत अच्छी तरह विकसित है। अभी भी, यह एक विनियमित बाजार बना हुआ है। आइए अब हम यह देखें की इस बाजार की अभिप्रेरणा और विनियामकीय शासन का भविष्य क्या है।

विदेशी मुद्रा बाजार विनिमय दर को निर्धारित करता है, जो एक महत्वपूर्ण समष्टि-चर है, जिसका भुगतान संतुलन, मौद्रिक नीति, पूंजी प्रवाह, और कई अन्य व्युत्पन्न मुद्दों पर प्रभाव पड़ता है। अब, यह सर्व विदित है कि दीर्घावधि में विनिमय दर मुद्रास्फीति, ब्याज दरों, भुगतान-संतुलन आदि जैसे आर्थिक मूल सिद्धांतों पर निर्भर करती है, लेकिन अल्पावधि में विनिमय दर मूल सिद्धांतों द्वारा निर्धारित मूल्य से काफी अलग हो सकती हैं। यद्यपि विनिमय दर कई पद्धतियों से तय की जा सकती है जैसे कि विभिन्न मुद्राओं तथा विभिन्न भारांक पद्धति के संयोजन से आरईईआर (नाममात्र प्रभावी विनिमय दर) और एनईईआर (नाममात्र प्रभावी विनिमय दर) मेरी चर्चा हेडलाइन भारतीय रुपया - अमरीकी डॉलर दर के इर्दगिर्द केंद्रित रहेगी, जो मतों और निर्णयों से संचालित होती है। विनियम दर में उतार-चढ़ाव अनेक प्रकार के घटनाक्रमों की भावनाओं और धारणाओं के कारण होते हैं, ये घटनाक्रम कुल घरेलू और कुछ वैश्विक होते हैं। जैसाकि आप जैसे डीलर लोग कहते हैं, "अफवाह पर खरीदें, और ख़बर पक्की होने पर बेचें"। हमारे पास इस तरह के कई प्रकरण आए हैं। मार्च 2018 में पिछले एक साल या उसके दौरान रुपया ने 64 के स्तर को देखा, जो अक्तूबर 2018 में घटकर लगभग 75 के स्तर तक गया और फिर मार्च 2019 तक यह 68+ के स्तर तक मजबूत हुआ और तब से लगभग इसी के आसपास कारोबार कर रहा है। इस एक वर्ष के दौरान, भारतीय अर्थव्यवस्था के मूल सिद्धांतों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, और न ही वैश्विक परिस्थितियों में भी कोई नाटकीय परिवर्तन हुआ है। इसका कारण ज्यादातर पूंजी प्रवाह में तेजी या कमी रही है, जो धारणाओं और जोखिम से बचने या इसे पचा पाने की क्षमता से प्रेरित है। हालांकि, विनिमय दर में इन बदलावों को समझ लेने से भी नीति निर्माता को कोई हल नहीं मिलता है: पर एक प्रतिक्रिया जरूरी हो जाती है, ताकि बाजार में घबराहट न

हो और इसके मद्देनजर बाजार में बहुत बड़ी अव्यवस्था न हो। प्रतिरक्षा करने के रूप में पहला कदम बाजार में हस्तक्षेप करना है। लेकिन तभी असंभाव्यता का त्रिक भी अपना खेल दिखाता है: बाजार में हस्तक्षेप करना रुपये की चलनिधि को प्रभावित करता है और यह मौद्रिक नीति के रुख के विपरीत हो सकता है। निष्प्रभावीकरण की कदाचित अपनी लागत होती है। और कभी-कभी, विशेष रूप से जब रुपया का मूल्यह्रास होता है, तब हस्तक्षेप एक सीमा तक ही हो पाता है, और इस प्रकार का हस्तक्षेप कार्यनीतिक रूप से अप्रभावी होता है। प्रतिरक्षा करने के रूप में दूसरा कदम पूंजी नियंत्रण व्यवस्था को संशोधित करने का सहारा लेना है: रुपये में तेजी या मूल्यह्रास के आधार पर प्रतिबंधों को कठोर या आसान बनाना। हालांकि यह एक अंतिम उपाय होना चाहिए: क्योंकि विदेशी मुद्रा बाजार की स्थिति जहां तेजी से बदल सकती है, वहीं नियंत्रण व्यवस्था लंबी अवधि के लिए होना चाहिए भले ही ये आर्थिक एजेंटों द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हों।

दूसरा विषय, जिसपर मैं बात करना चाहता हूँ वह विदेशी मुद्रा बाजार के डेरिवेटिव से जुड़ा हुआ है। डेरिवेटिव तीव्र प्रतिक्रियात्मक होता है - 'वित्त की सबसे महत्वपूर्ण घटना' (ग्रीनस्पैन) से लेकर 'सामूहिक विनाश के हथियार' (बुफे) या 'हत्या करने के लिए अनुज्ञप्ति' (सोरोस) तक की प्रतिक्रिया होती है। डेरिवेटिव का प्राथमिक उद्देश्य भविष्य की अनिश्चितताओं के खिलाफ बचाव करना है। इस प्रकार, वे बेहतर अंतर-अस्थायी निर्णय लेने के लिए एजेंटों को सक्षम करने में आर्थिक रूप से बेहद उपयोगी कार्य करते हैं। लेकिन दूसरी ओर, उन्हें अटकलों के उपकरणों के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है जो जोखिम आबंटन को अस्पष्ट कर सकता है। गार्बर के अनुसार, 'डेरिवेटिव के उत्थान से जुड़ी समस्याओं का स्रोत अंशतः वहीं हैं जो इसके लाभ के हैं: अलग करने की बढ़ी हुई क्षमता और बाजार जोखिम का मतलब है कि कुछ प्रतिपक्षकार अतीत की तुलना में अधिक आसानी से जोखिम भरी पोजीशन ले सकते हैं। डेरिवेटिव की समस्या का स्रोत यह है कि वे अत्यंत जटिल और अपारदर्शी हो सकते हैं। हमारे बाजारों में, हमारे पास रैखिक (फॉरवर्ड और फ्यूचर्स) दोनों के साथ-साथ गैर-रैखिक (ऑप्शन, एक्सचेंज तथा ओटीसी दोनों पर कारोबार योग्य) विकल्प हैं। बाद वाले ज्यादातर सादे स्वरूप के होते हैं। कुछ समय के लिए, जटिल डेरिवेटिव्स को रुपया में शामिल नहीं होने दिया गया, लेकिन इससे वे जोखिम जिन्हें राजश्री शुगर केस में समझ नहीं पाए उनका अनुमान लगा सके। समस्या का दूसरा पहलू अरक्षित एक्सपोज़र है। हेजिंग में लागत होती है। यह वह लागत है जिसे एक एजेंट अनिश्चितता को निश्चितता में बदलने के लिए चुकाता है। इस प्रकार, यहाँ बचाव रहित रहने तथा घटनाओं को ईश्वर पर छोड़ने की प्रवृति हो सकती है। क्या बाज़ार की स्थितियां प्रतिकूल होनी चाहिए, नुकसान में कटौती करना एक सनक सी बन गई है जो बाज़ार की स्थिति को और भी बिगाड़ देती है। हमारा दृष्टिकोण एक ऐसा एजेंट रखना रहा है और रहेगा जिसे रुपए का एक्सपोज़र है चाहे वो निवासी हो या अनिवासी ताकि डेरिवेटिव उत्पादों की पहुँच के साथ उन्हें अपने विदेशी विनिमय जोखिमों को रोकने में सहायता हो सके लेकिन साथ ही उत्पादों की पहुँच का धीरे-धीरे विस्तार करना होगा।

विदेशी मुद्रा बाज़ार की चर्चा तब तक पूरी नहीं होगी जब तक रुपए के अंतरराष्ट्रीयकरण के मुद्दे की चर्चा न कर ली जाए। एक मुद्रा अंतरराष्ट्रीय अथवा आरक्षित मुद्रा तभी हो सकती है जब इसे अनिवासी द्वारा व्यापक रूप से रखा जाता है और अंतरराष्ट्रीय लेन-देन के निपटान में इसका उपयोग किया जाता है। मुद्रा के अंतरराष्ट्रीयकरण के कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। इसका प्रमुख फायदा अपनी मुद्रा में उधार लेने की असमर्थता की 'प्रमुख समस्या' से छुटकारा पाना है जो कि मुद्रा संकट के आधार में हैं। नुकसान उस देश की बाध्यता से होता है जिसकी मुद्रा इसकी वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए वैश्विक आरक्षित मुद्रा के रूप में कार्य करती है जो कि अपनी घरेलू नीतियों के साथ टकराव की स्थिति में आ सकती है। पिछले कुछ वर्षों में, वैश्विक निवेशकों ने रुपया आधारित आस्तियों -दोनों इक्विटी तथा डेट- के सक्रिय तटवर्ती बाज़ारों में अपनी दिलचस्पी दिखाई है। तथाकथित मसाला बॉन्डों में रुपया मूल्यवर्गीय बॉन्ड ने भी तटवर्तीय बाज़ारों में निवेशकों की रुचि को देखा है। जब रुपया आस्ति वैश्विक निवेशकों द्वारा व्यापक रूप से रखा जाता है, तो मुद्रा, ब्याज़ दर तथा क्रेडिट जोखिमों के बचाव हेतु रुपया डेरिवेटिव्स की आवश्यकता होगी। इसलिए यह स्वाभाविक है कि तटवर्तीय वित्तीय केन्द्रों में इस प्रकार के बाज़ारों की आवश्यकता होगी। इन बाज़ारों में चुनौती यह है कि जहां एक ओर तटवर्तीय डेरिवेटिव्स बाज़ार को कड़ाई से

विनियमित किया जाता है, वहीं अपतटीय बाज़ार नियामकीय पहुँच से परे हैं, जिससे अशांत प्रकरणों के दौरान मध्यस्थता के माध्यम से घरेलू बाज़ार प्रभावित हो सकते हैं। नियामकीय ढांचा तटवर्तीय डेरिवेटिव बाज़ारों को रुपए एक्सपोज़र के साथ सभी अनिवासियों के लिए सुलभ बनाने के प्रयास जारी रखेगा।

मुझे अब निष्कर्ष पर आना चाहिए। भारत विश्व के तेजी से बढ़ते देशों में से एक है तथा पीपीपी के आधार पर आज विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यह वैश्विक निवेशकों के पसंदीदा स्थानों में से एक है। भारतीय अर्थव्यवस्था ने प्रतिकूल वैश्विक घटनाओं के प्रति यद्यपि पूरी तरह नहीं किंतु समुत्थानशीलता दिखायी है। निरंतर आर्थिक विकास तथा बृहत आर्थिक स्थिरता, अनुकूल जनसांख्यिकी और एक बड़े बाज़ार के साथ भारत वैश्विक आर्थिक क्षेत्र में एक प्रमुख भागीदार है। इसकी वैश्विक भूमिका की निरंतरता विकास की गति तथा स्थिरता बनाए रखने पर निर्भर करेगी। जबकि इसके लिए बहुत से क्षेत्रों में उभरती चुनौतियों के लिए निरंतर नीतिगत प्रतिक्रिया की आवश्यकता होगी, साथ ही वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण भी विकास की गति को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण कारक होगा। हमें विकास और स्थिरता दोनों की चुनौतियों से सतर्क रहना होगा और अर्थव्यवस्था की जरूरतों के साथ मिलकर सीमा पार लेन-देन से संबंधित नीतिगत व्यवस्था को आगे बढ़ाना होगा। जहां तक विदेशी विनिमय डीलर अथवा विशेष कर अधिकृत डीलर ग्राहकों के साथ प्राथमिक इंटरफ़ेस तैयार करते हैं तथा विदेशी मुद्रा बाज़ार में विकास को आकार देते हैं, वे इस संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे।

मुझे विश्वास है कि आपके विचार-विमर्श और चर्चाएं काफी महत्वपूर्ण और उपयोगी सिद्ध होंगी। मैं आपको इस प्राचीन किंतु आधुनिक शहर की सुखद सैर के लिए भी शुभकामनाएं देता हूँ।

लेख

भारत में नवीकरणीय ऊर्जा तथा बिजली की कीमतों की गत्यातमक स्थिति

बैंक जमाराशियां: अंतर्निहित समीकरण

*भारत में नवीकरणीय ऊर्जा तथा बिजली की कीमतों की गत्यातमक स्थिति**

यद्यपि भारत के समग्र ऊर्जा सम्मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा के स्त्रोत अभी भी बहुत कम हैं फिर भी वे बिजली की स्पॉट कीमतों को नियंत्रित कर विद्युत परिदृश्य को काफी बदल रहे हैं। यह प्रभाव आगे जाकर और बढ़ सकता है जिसमें अंतर्निहित बिजली आपूर्ति – मांग एवं कीमतों के समीकरण में अहम बदलाव की संभावना है।

भूमिका

भारत में विद्युत उत्पादन क्षेत्र परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) की प्रमुखता बढ़ती जा रही है। यद्यपि ताप विद्युत मुख्य आधार बना हुआ है फिर भी भारत के ऊर्जा-सम्मिश्रण का झुकाव नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) की ओर है, जिसकी हिस्सेदारी कुल विद्युत उत्पादन में 2008-09 के 3.7 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 9.2 प्रतिशत हो गई है। इसके अलावा, पिछले पाँच वर्षों में सौर ऊर्जा कीमत में 64 प्रतिशत की गिरावट से नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों (आरईएस) की प्रतिस्पर्धात्मकता काफ़ी सुधरी है। ये घटनाक्रम बिजली की कीमतों के समीकरण को काफी नाटकीय रूप से बदल रहे हैं – स्पॉट मार्केट में निर्धारित बिजली की औसत कीमत पिछले पाँच वर्षों में वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) एवं विद्युत उत्पादनकर्ताओं के बीच दीर्घकालिक विद्युत क्रय करारों (पीपीए) में अंतर्निहित कीमत की तुलना में लगभग 33 प्रतिशत कम थी। ऐसे समय में जब अधिकांश ताप विद्युत संयत्र (टीपीपी) गंभीर वित्तीय दबाव में हैं, गिरती कीमतें उनकी व्यावहार्यता में सेंध लगा रही हैं। विद्युत क्रय करारों (पीपीए) के तहत बिजली खरीदने के वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) द्वारा अपने वायदे को न मानना तथा ताप विद्युत संयत्रों (टीपीपी) द्वारा पीपीए निर्धारित मूल्यों से कम मूल्य पर स्पॉट मार्केट में बिजली बेचना जैसे दृष्टांत ऊर्जा क्षेत्र में इस संकट के लक्षण हैं। यह वैसा है जैसा शेल गैस के आने से कच्चे तेल के बाजार के साथ हुआ। वैश्विक कच्चे तेल की आपूर्ति में महज 1.5 प्रतिशत की हिस्सेदारी के बावजूद शेल तेल ने कीमतों के दबाव को कम कर दिया है और सभी ओपेक (पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन) और गैर-ओपेक देशों में इस क्षेत्र में निवेश की नई योजनाओं को रोक रखा है।

आमतौर पर, ताप विद्युत संयत्र ऐसी लागत संरचना पर काम करते हैं जिसकी खासीयत होती है उच्च ऑपरेटिंग लीवरेज – एक निश्चित लागत आधार के साथ बिजली उत्पादन में न्यूनतम भार क्षमता – और, इसलिए क्षमता उपयोग और अर्जित राजस्व के पैमाने पर उनका लाभ / आय अत्यधिक संवेदनशील है। ग्रिड को बेचे जाने वाली बिजली की मात्रा (संयत्र भार क्षमता द्वारा इंगित) और बिजली की प्रति इकाई प्राप्त कीमत पर राजस्व निर्भर है, और दोनों नवीकरणीय ऊर्जा के बढ़ते महत्व से प्रभावित होते हैं। वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) के साथ दीर्घकालिक संविदाओं (पीपीए) के जरिए प्रतिबद्ध उच्च क्षमता वाले ताप विद्युत संयत्रों (टीपीपी) की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर हो सकती है, लेकिन दीर्घावधि में वितरण कंपनियाँ (डिस्कॉम्स) वर्तमान संविदाओं के समाप्त होने पर मौजूदा संविदाओं के फिर से मोल-भाव को तरजीह दे सकती हैं। ताप विद्युत उत्पादन कंपनियों को दिए जाने वाले बैंक ऋण और निवेश समेत इन गतिविधियों के व्यापक प्रभाव होते हैं।

इस लेख का उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) के क्षेत्र में होने वाले विकास के संदर्भ में भारत में बिजली की कीमतों की गत्यातमक स्थिति को गौर से देखना है। भाग II में नवीकरणीय ऊर्जा की बढ़ती प्रमुखता के बारे में सरलीकृत तथ्य और इसके लिए नीतिगत प्रोत्साहन पर चर्चा की गयी है। भाग III बिजली एक्सचेंजों के क्रमिक विकास एवं कार्य पद्धति तथा मूल्य निर्धारण व्यवस्थाओं में प्रवेश करता है। भाग IV में आंकड़ों का स्त्रोत, कार्यप्रणाली और प्रमुख परिणामों को प्रस्तुत किया गया है। भाग V में निष्कर्षी विचार तथा कुछ नीतिगत संभावनाएं प्रस्तुत की गई हैं।

II. भारत में नवीकरणीय ऊर्जा : कुछ सरलीकृत तथ्य

वृद्धिशील विद्युत उत्पादन क्षमता में लगातार तीन वर्षों तक में नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत (आरईएस) की बड़ी हिस्सेदारी रही है; वर्ष 2016-17 तथा 2018-19 के बीच इसका हिस्सा 67

* यह आलेख भारतीय रिज़र्व बैंक के आर्थिक एवं नीति अनुसंधान विभाग के राहुल अगरवाल, सार्थक गुलाटी तथा सोन्ना थंगजेसन द्वारा तैयार किया गया है। इस आलेख में व्यक्त विचार लेखकों के निजी विचार हैं और ये भारतीय रिज़र्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते।

[1] *https://www.deccanchronicle.com/nation/current-affairs/011117/centre-plans-law-against-ppa-violation.html*

प्रतिशत रहा है (चार्ट 1ए)। इस अवधि के दौरान मांग-आपूर्ति का असंतुलन एवं ताप विद्युत संयंत्रों (टीपीपी) की क्षमता का उपयोग ऐतिहासिक निम्न स्तर पर भी रहा जिससे अतिरिक्त क्षमता में निवेश को धक्का लगा (चार्ट 1बी)। अतिरिक्त आरईएस क्षमता में निवेश का कारण पारंपरिक ताप विद्युत तुलना में इसकी बेहतर प्रतिस्पर्धात्मकता है, जो प्रौद्योगिकी लागतों में भारी गिरावट से आया है, विशेषकर सौर विद्युत में (चार्ट1सी)। उत्पादन क्षमता में वृद्धि से समग्र उत्पादन में भी इसका हिस्सा बहुत बढ़ गया है (चार्ट1डी)[2]।

उन्नत प्रतिस्पर्धात्मकता के अलावा, सरकार के नीतिगत प्रोत्साहन से भी आरईएस में निवेश को लाभ मिला है। वर्ष 2015 के पेरिस समझौते में जलवायु परिवर्तन की प्रतिबद्धताओं, जिसे कान्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ (सीओपी) की परवर्ती बैठकों में दोहराया गया, को पूरा करने में कार्बन उत्सर्जन पर अंकुश लगाने एवं आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने की भारत की रणनीतिक ऊर्जा नीति के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नवीकरणीय ऊर्जा अत्यंत महत्वपूर्ण है। पेरिस समझौते में हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) के माध्यम से वैश्विक तापमान में वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तरों से 2

सारणी 1: स्त्रोत द्वारा बिजली उत्पादन की गतिशीलता

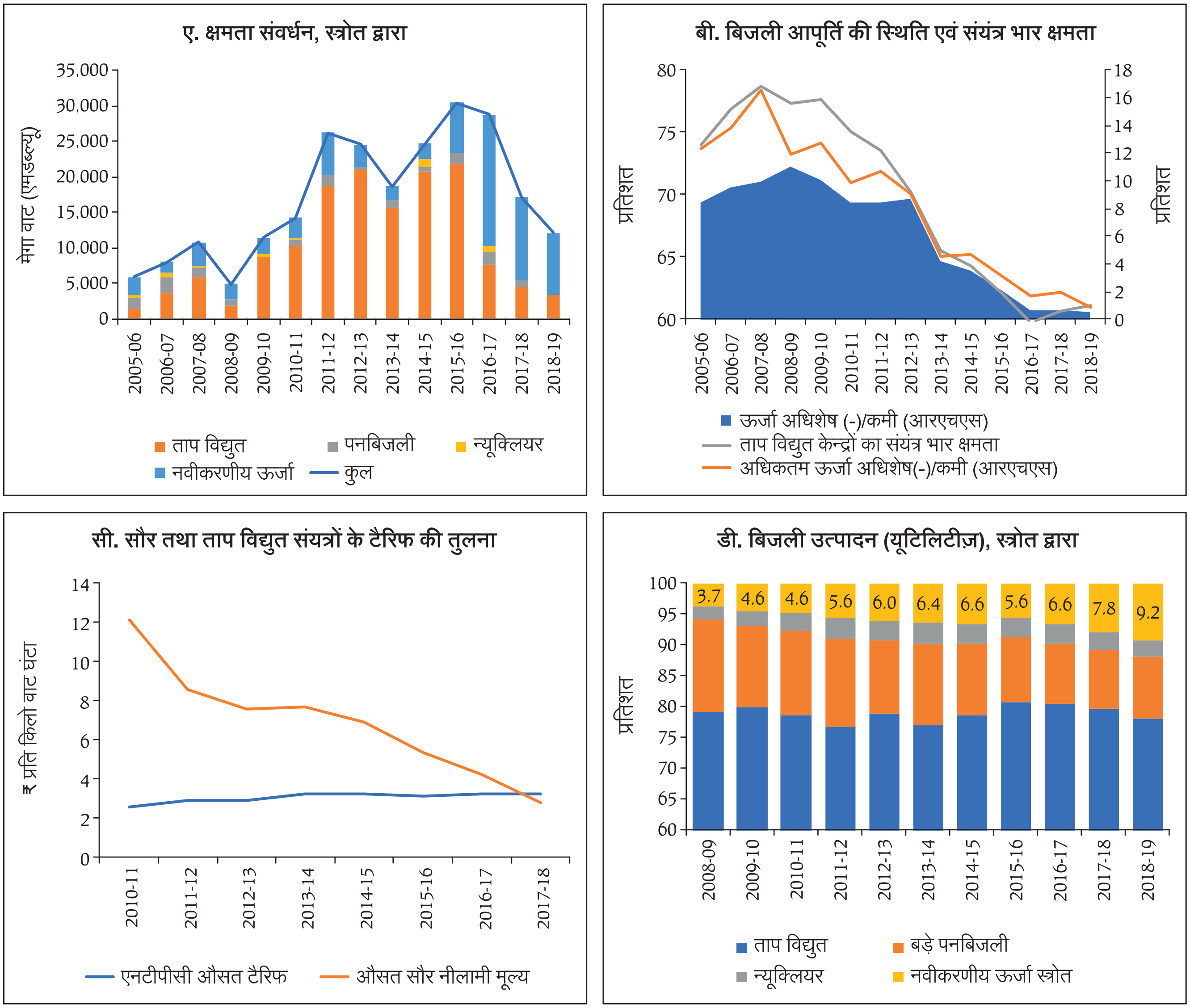

स्त्रोत : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, भारतीय अर्थव्यवस्था निगरानी केंद्र (सीएमआईई), राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी)

[2] उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी (2018-19 में 9.2 प्रतिशत) संस्थापित क्षमता में उनके हिस्से (2018-19 में 21.8 प्रतिशत) से कम है क्योंकि नवीकरणीय ऊर्जा आम तौर पर निम्न क्षमता उपयोग कारक पर परिचालित होते हैं और इसलिए संस्थापित क्षमता की प्रति मेगावाट बिजली की कम यूनिटों का उत्पादन करते हैं।

डिग्री सेल्सियस नीचे तक सीमित करने का लक्ष्य रखा गया है। 2030 तक अपने जीडीपी जन्य उत्सर्जनों को वर्ष 2005 के स्तरों की तुलना में 33-35 प्रतिशत तक कम करने, संचयी बिजली संस्थापित क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों का हिस्सा 40 प्रतिशत तक ले जाने तथा 2.5 से 3 बिलियन टन CO_2 के समतुल्य अतिरिक्त कार्बन सिंक सृजित करने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2022 तक 175 गीगा वाट(जीडब्ल्यू) के महत्वाकांक्षी लक्ष्य की घोषणा की, जिसे और बढ़ाकर 227 जीडब्ल्यू तक कर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय सौर एलायंस (आईएसए) की स्थापना के द्वारा भारत ने सौर विद्युत के विकास हेतु वित्त और प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में नेतृत्व की भूमिका भी उठाई है।

नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत (आरईएस) के लिए पारंपरिक रूप से राजकोषीय प्रोत्साहन (टैक्स ब्रेक, त्वरित मूल्यह्रास) के रूप में जो नीतिगत समर्थन दिया जाता था वह विद्युत अधिनियम, 2003 के शुभारंभ से उत्पादन आधारित प्रोत्साहन प्रदान करने की दिशा में आगे बढ़ा। विशेषकर, फीड इन टैरिफ (एफआईटी) जो उस टैरिफ जिस पर वितरण कंपनियां (डिस्कॉम्स) उत्पादक कंपनियों के साथ दीर्घकालिक पीपीए निष्पादित करती हैं, को नियंत्रित करने का लक्ष्य रखती है तथा मस्ट-रन की स्थिति जो मांग की किसी भी स्थिति में आरईएस से उत्पादन प्रेषण की गारंटी देता है। आम तौर पर एफआईटी लागतोपरि (कॉस्ट-प्लस) स्तरों पर तय किया जाता था, लेकिन समय के साथ नवीकरणीय ऊर्जा(आरई) लागत में गिरावट आने के कारण टैरिफ स्तरों का पता लगाने के लिए एफआईटी व्यवस्था को नीलामियों द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा, 2003 में नवीकरणीय खरीद दायित्व (आरपीओ) की शुरुआत की गई थी, जिसके अनुसार वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) और निर्धारित (कैप्टिव) विद्युत उपयोगकर्ताओं को अपनी बिजली की आवश्यकता का न्यूनतम हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत (आरईएस) से खरीदना अनिवार्य है, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत(आरईएस) से उत्पादन के लिए पर्याप्त मांग सुनिश्चित हो। 2010 में नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र (आरईसी) के लागू होने से एफआईटी व्यवस्था का एक विकल्प प्रदान किया गया, जिसका उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों (आरईएस) के लिए खरीदी गई ऊर्जा हेतु क्रेडिट में ट्रेड के लिए एक बाजार तंत्र स्थापित करके सभी राज्यों में नवीकरणीय ऊर्जा(आरई) क्षमता और नवीकरणीय खरीद दायित्व (आरपीओ) लक्ष्यों के बीच असंतुलन को दूर करना है[3]। हालांकि आरईसी मार्ग के जरिए अधिक सफलता हासिल नहीं हो पाई और इससे 2017-18 तक कुल आरई क्षमता का केवल 5.7 प्रतिशत ही प्राप्त हो पाया। इसकी वजह संभवत: आरपीओ अधिदेश का सुस्त अनुपालन रहा जिससे आरईसी के मांग में कमी आई।

हाल के नीतिगत पहल से नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत (आरईएस) के विकास को और गति मिलने की उम्मीद है। केंद्र सरकार ने 2018-19 के दौरान नवीकरणीय खरीद दायित्व (आरपीओ) लक्ष्यों को 17 प्रतिशत (डिस्कॉम और कैप्टिव विद्युत उपयोगकर्ताओं द्वारा खरीदी गई कुल विद्युत का) से बढ़ाकर 2021-22 तक 21 प्रतिशत कर दिया है। नवीकरणीय खरीद दायित्व (आरपीओ) लक्ष्यों को बढ़ाने के साथ तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा आरपीओ अनुपालन कक्ष के निर्माण के जरिए इसके अनुपालन पर बल देने के साथ नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र (आरईसी) मार्ग के जरिए संभवत: इसकी हिस्सेदारी बढ़ पाई। इसके अलावा, फरवरी 2016 में, सौर और पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए अंतर-राज्यीय पारेषण शुल्क[4] को 31 मार्च, 2022 तक चालू की गई सभी परियोजनाओं के लिए माफ कर दिया गया। हालांकि, ट्राफ्ट राष्ट्रीय ऊर्जा नीति 2017 की परिकल्पना है कि मस्ट-रन स्थिति की क्रमिक वापसी और अंतर-राज्यीय पारेषण लागत को नहीं लगाकर ऊर्जा का भेदभाव-रहित प्रेषण किया जाए एवं इन प्रतिस्पर्धी प्रौद्योगिकियों को बाजार के अनुशासन में छोड़ दिया जाए।

नवीकरणीय ऊर्जा में वृद्धि से भारत में बिजली की बढ़ती माँग के पूरा होने की उम्मीद है। हालांकि, मध्यावधि में जैसे-जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्थिर एवं सुदृढ़ होती है, ताप विद्युत संयत्रों को काम में लाना होगा क्योंकि प्रति व्यक्ति खपत बढ़ने के साथ मांग बढ़ती है। ग्रिड से जुड़े विद्युत की चरम मांग 2016-17 में 161.8 जीडब्ल्यू से बढ़कर 2021-22 में 225.8 जीडब्ल्यू और 2026-27 में 298.8 जीडब्ल्यू होने का अनुमान है। यद्यपि 2021-22 तक मांग में अनुमानित वृद्धि को मौजूदा क्षमता एवं नए क्षमता संवर्धन जो पाइपलाइन में है, के जरिए पूरा किया जा सकता है फिर भी 2026-27 तक चरम मांग में वृद्धि को पूरा करने के लिए 46 जीडब्ल्यू की वृद्धिशील तापीय क्षमता की आवश्यकता का अनुमान है (जीओआई, 2017)[5]।

[3] आरईसी के तहत, आरईएस से ऊर्जा की खरीद के क्रेडिट को ट्रेड किया जाता है, जिसका उपयोग क्रेता द्वारा आरपीओ आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। एक आरईसी प्रमाणपत्र धारक को आरईएस से खरीदे गए ऊर्जा का एक मेगावाट घंटा (एमडब्ल्यूएच) क्रेडिट करता है।

[4] पारंपरिक ताप बिजली परियोजनाओं की स्थापना उस स्थान के आस-पास की जा सकती है जहां इसकी खपत होती है ताकि पारेषण लागत कम की जा सके, ठीक इसके विपरीत सौर एवं पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना उन्हीं जगहों पर की जा सकती है जहाँ जलवायु परिस्थितियाँ अनुकूल हों, और इसलिए इसकी पारेषण लागत बहुत अधिक होती है।

[5] 19वीं इलेक्ट्रिक पावर सर्वेक्षण, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण

III. बिजली कीमत के समीकरण

विद्युत अधिनियम, 2003 ने बाजार निर्धारित बिजली कीमत की शुरुआत की है। यह अधिनियम स्वतंत्र बिजली उत्पादकों (आईपीपी) के लिए गैर-पक्षपाती रूप से बाजार तक पहुंच प्रदान करता है और व्यापार को कानूनी गतिविधि के रूप में मान्यता देता है। 2008 में प्रतिस्पर्धी कीमत-निर्धारण को प्रोत्साहित किया गया था जब सरकार ने एक्सचेंजों पर बिजली व्यापार की अनुमति दी थी। वर्तमान में, देश में दो पावर एक्सचेंज हैं - इंडियन एनर्जी एक्सचेंज (आईईएक्स) और पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीएक्सआईएल) जिनका क्रमशः जून 2008 और अक्तूबर 2008 में परिचालन शुरू हुआ। एक्सचेंजों (2017-18 में) के माध्यम से बिजली लेनदेन की मात्रा में इंडियन एनर्जी एक्सचेंज (आईईएक्स) की बाजार हिस्सेदारी 98.4 प्रतिशत है।

इन उपायों के परिणामस्वरूप बाजार आधारित अल्पकालिक संविदाओं का प्रसार हुआ, हालांकि डिस्काम (वितरण कंपनी) की थोक बिजली की आवश्यकता की पूर्ति के लिए दीर्घकालिक संविदाएं मुख्य आधार बनी हुई हैं। विशेषतः बिजली एक्सचेंजों (चार्ट 2 क) के माध्यम से अल्पकालिक बाजार साधनों के माध्यम से कारोबार की जाने वाली बिजली की हिस्सेदारी पिछले एक दशक से लगातार बढ़ी है। आईईएक्स पर लेन-देन की गई बिजली के आधे से अधिक हिस्से को क्रय करने और एक तिहाई से अधिक मात्रा में विक्रय करने के लिए डिस्काम बाजार में सबसे बड़ा भागीदार है। अतिरिक्त अधिभार और पावर एक्सचेंजों (चार्ज 2 ख) से खरीद पर और उच्च प्रसारण प्रभार से डिस्काम की भागीदारी बाधित होने के बावजूद क्रय मात्रा में निर्बाध पहुंच में ग्राहकों की भी महत्वपूर्ण भागीदारी है।

विशेष रूप से पावर एक्सचेंजों के माध्यम से बिजली की बढ़ी हुई मात्रा के साथ अल्पकालिक संविदा के द्वारा लेन-देन की गई बिजली की औसत कीमत में भारी गिरावट आयी है। दैनिक कीमतों की अस्थिरता[6] भी 2008-09 में 20 प्रतिशत से घटकर 2017-18 (चार्ट 3 क) में 11.1 प्रतिशत हो गई है।

चार्ट 2: बिजली का अल्पावधि बाजार लेन-देन

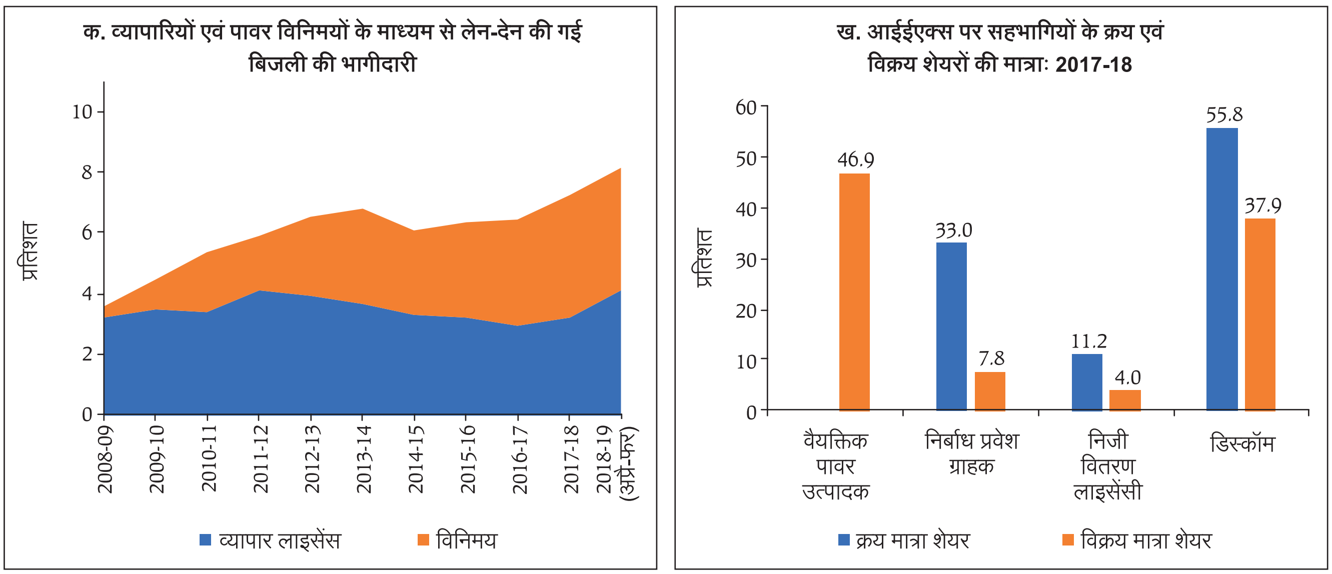

स्रोत : केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, आईईएक्स

[6] दैनिक कीमत रिटर्न का मानक विचलन के रूप में मापन,

$$\sigma = \sqrt{1/(n-1)\sum_{y=1}^{n}\left(\ln\frac{y_i}{y_{i-1}} - \mu\right)^2}$$

यहां $\mu = \frac{1}{n}\sum_{y=1}^{n}\left(\ln\frac{y_i}{y_{i-1}}\right)$ तथा दैनिक कीमत रिटर्न = $\left(\ln\frac{y_i}{y_{i-1}}\right)$

Yi आज की कीमत; Yi-1 पिछले दिन की कीमत; Ln प्राकृतिक लघुगणक; n टिप्पणियों की संख्या; μ औसत कीमत रिटर्न

चार्ट 3: बिजली की कीमतों में उतार-चढ़ाव

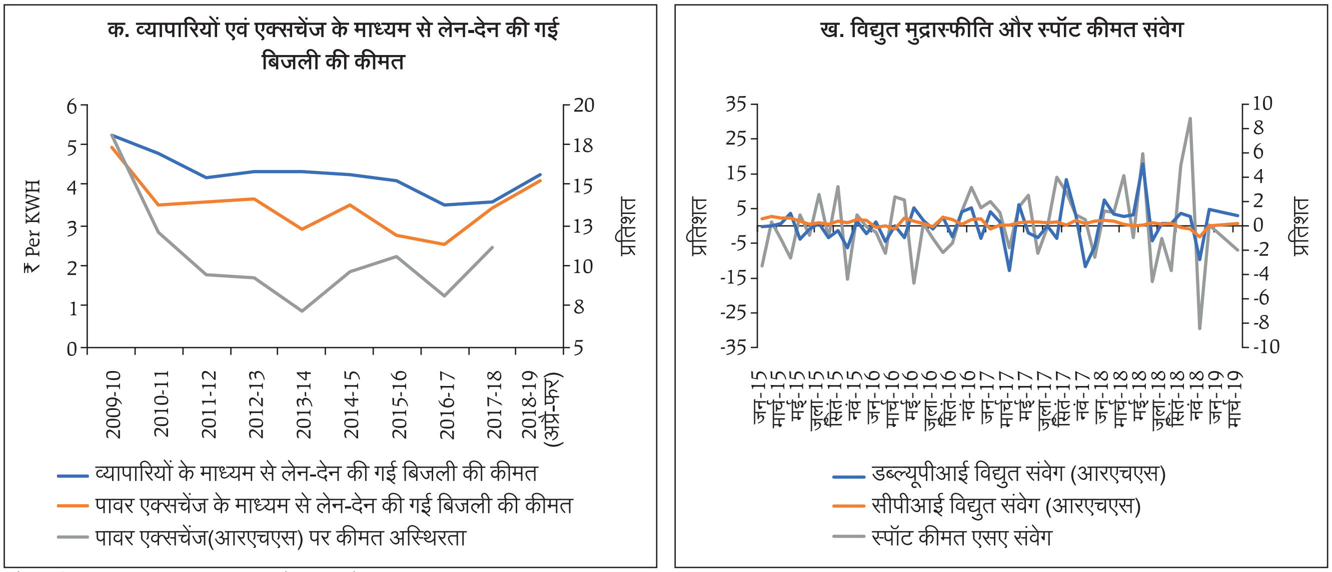

स्रोत : केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, एमओएसपीआई, आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, आईईएक्स

पावर एक्सचेंजों में व्यापार, अनुबंधों में अगला-दिन (डे-अहेड) एवं अगली-मीयाद (टर्म-अहेड) बाजारों के आधार पर किया जाता है। भौतिक व्यापार के अलावा, ऊर्जा एक्सचेंज भी आरईसी में व्यापार की सुविधा प्रदान करते हैं। अगला दिन बाजार का तात्पर्य है अगले दिन के 24 घंटों में किसी भी समय खंड (भारतीय विनिमयों के मामले में 15 मिनट) के वितरण के लिए व्यापार खिड़की है जबकि अगली मीयाद बाजार से तात्पर्य है भविष्य की तारीख (आईईएक्स के मामले में 11 दिन तक) पर मीयादी आधार पर वितरण के लिए व्यापार खिड़की है। अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंजों की तरह ही, भारत में पावर एक्सचेंज पर व्यापार की मात्रा में अगला दिन बाजार का प्रभुत्व है। अगला दिन बाजारों में, प्रत्येक 15-मिनट के ब्लॉक के लिए कीमत गणना एल्गोरिदम क्रय और विक्रय बोलियों के साथ मेल की जाती हैं। बाजार सहभागियों द्वारा प्रस्तुत बोलियों के आधार पर, कुल मांग और सप्लाई कर्व का इंटरसेक्शन, प्रत्येक व्यापार ब्लॉक के लिए बाजार समाशोधन कीमत निर्धारित करता है। नवीकरणीय ऊर्जा निर्माण में वृद्धि से विनिमय पर दोनों मांग और आपूर्ति प्रभावित होती है। नवीकरणीय ऊर्जा की अबाधित स्थिति को देखते हुए डिस्काम की मांग में कमी आ सकती है जबकि टीपीपी की न्यूनतम भार क्षमता को देखते हुए स्पॉट बाजार को आईपीपी से आपूर्ति में वृद्धि हो सकती है जिससे कीमतों पर अधोमुखी दबाव बना रहेगा।

अन्य मूल्य सूचकांकों के साथ स्पॉट की कीमतों के संबंध का विश्लेषण करते हुए, यह देखा गया है कि बिजली के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति और एक्सचेंजों में स्पॉट की कीमतों के बीच घरेलू और कृषि बिजली की कीमतों की नियंत्रित प्रकृति के परिणामस्वरूप थोड़ा सा सह-संचार[7] हुआ है। यह प्रमाण उपलब्ध है कि बिजली (चार्ट 3 ख) में सीपीआई मुद्रास्फीति और स्पॉट कीमतों के बीच सह-संचार है। स्पॉट बाजार में निर्बाध पहुंच उपभोक्ताओं द्वारा बिजली इनपुट कीमत प्रभावित होने से स्पॉट कीमत एवं डब्ल्यूपीआई विद्युत मुद्रास्फीति के बीच सह-संचार आंशिक रूप से औद्योगिक फर्मों की भागीदारी द्वारा समझाया गया है। इसके विपरीत, यहां तक कि स्पॉट कीमतों में पिछले पांच वर्षों में लगातार गिरावट आई है, सीपीआई विद्युत मुद्रास्फीति लगभग 3.0 प्रतिशत[8] की दर तक अवरुद्ध रही है।

IV. कार्यप्रणाली, अध्ययन की अवधि और परिणाम

इन शैलीगत तथ्यों की पृष्ठभूमि के परिप्रेक्ष्य में, बिजली की स्पॉट कीमत पर नवीकरणीय ऊर्जा के प्रभाव का मात्रात्मक अनुमान, निकट अवधि के ऊर्जा दृष्टिकोण और भारत में ऊर्जा मिश्रण की संभावनाओं के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। उपयोग किए जानेवाले चरों(परिवर्ती) के बीच एकीकरण के भिन्न आदेशों-I (0) तथा I (1) को समायोजित करने के नवीकरणीय ऊर्जा और

[7] समयानुकूल समायोजित चर के संवेग (एम-ओ-एम परिवर्तन) के बीच सह-संबंध के रूप में मापन।

[8] विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा घोषित अनुदान में वृद्धि के कारण डब्ल्यूपीआई में तेजी के रुझान के विपरीत अक्तूबर 2018 से विद्युत सीपीआई में असामान्य कमी आई है।

तालिका 1: प्रायोगिक परिणाम- ऑटोरिग्रेसीव डिस्ट्रिब्यूटेड लाग (एआरडीएल) संरचना

(आश्रित चर: बिजली की स्पॉट कीमत)

व्याख्यात्मक चर	गुणांक	टी-सांख्यिकी	पी-मूल्य
लॉग.स्पॉट कीमत(-1)	0.53	5.16	0.00*
लॉग.स्पॉट कीमत(-2)	0.48	4.69	0.00*
लॉग.ताप वाल्यूम	0.83	3.35	0.00*
लॉग.नवीकरणीय वाल्यूम	-0.44	-3.42	0.00*
लॉग.नवीकरणीय वाल्यूम(-1)	0.26	2.20	0.03**
लॉग.जल वाल्यूम	0.26	1.58	0.12#
स्थिर	-9.58	-2.66	0.01*
बहिर्जात चर			
लॉग.कोयला आयात	-0.22	-2.06	0.04**
अनुपात स्पॉट- कुल	0.14	2.89	0.00*

नैदानिक

$\bar{R}^2$ = 0.81; एसईई = 0.087; एफ-सांख्यिकी = 32.76 (पी-मूल्य = 0.00)

*: 1% महत्व स्तर; **: 5% महत्व स्तर; #: महत्वहीन

यहां,

स्पॉट कीमत : बिजली मात्रा लेन-देन/आईई में निर्गमित समयानुकूल समायोजित (एसए) मासिक औसत स्पॉट कीमत

ताप मात्रा : ताप स्रोतों से प्रति माह निर्मित ऊर्जा की एसए मात्रा

नवीकरणीय मात्रा : नवीकरणीय स्रोतों से प्रति माह निर्मित ऊर्जा की एसए मात्रा

कोयला आयात मात्रा : कोयला आयात की एसए मात्रा

जल मात्रा : प्रति माह निर्मित एसए जल विद्युत

अनुपात.स्पॉट_ कुल : कुल निर्मित के अनुपात में मासिक बिजली लेन-देन की मात्रा का एसए अनुपात

स्रोत : लेखक का अनुमान।

भारत में बिजली कीमत के समीकरण लिए एक ऑटोरिग्रेसीव डिस्ट्रिब्यूटेड लाग (एआरडीएल) संरचना (पेसारन, 1999 और 2001) को अपनाया गया है। अप्रैल 2013 से सितंबर 2018 की अवधि के लिए यह प्रायोगिक अभ्यास केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) और आईईएक्स के मासिक डेटा का उपयोग करता है।

परिणाम (तालिका 1 और अनुबंध I) यह दर्शाते हैं कि कोयले के आयात के साथ नवीकरणीय ऊर्जा और थर्मल पावर की मात्रा तथा बहिर्जात चर के रूप में निर्मित कुल ऊर्जा में विनिमय पर व्यापार की गई मात्रा का अनुपात सांख्यिकीय रूप में महत्वपूर्ण तरीके से बिजली की स्पॉट कीमतों को प्रभावित करती है। बिजली की कीमतों में दृढ़ता एक प्रबल प्रमाण है। कीमत निर्माण में ताप ऊर्जा उत्पादन का एक प्रमुख प्रभाव है क्योंकि यह लगभग 80 प्रतिशत बिजली उत्पादन करता है और यह अधिक महंगा है[9]। परिणाम यह बताते हैं कि निरंतर आधार पर स्पॉट कीमतों को कम करने में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन ने मदद की है और विशेष रूप से, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों की तुलना में सौर ऊर्जा सस्ती हुई है। तथापि, इसकी आपूर्ति[10] में उतार-चढ़ाव है। स्पॉट कीमतों पर जल-विद्युत का प्रभाव सांख्यिकीय रूप से महत्वहीन पाया गया है जो संभवतः कुल ऊर्जा मिश्रण में अल्प भागीदारी एवं सरकार द्वारा सीमित स्वामित्व को दर्शाती है।

स्ट्रक्चरल वेक्टर ऑटो रिग्रेशन (एसवीएआर) परिणाम यह भी दर्शाते हैं कि बिजली की दैनिक औसत आईईएक्स स्पॉट कीमत को कम करने में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का प्रभाव महत्वपूर्ण[11] है। उत्पादन की उच्च लागत के कारण ताप उत्पादन से दैनिक औसत स्पॉट कीमत में वृद्धि होती है। चोल्स्की अपघटन[12] का उपयोग करते हुए आवेग प्रतिक्रियाएं यह दर्शाती हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में एक इकाई की वृद्धि से दैनिक औसत बाजार समाशोधन कीमत (अनुबंध II) में 0.1 इकाई की चरम गिरावट की ओर ले जाती है। संयंत्र भार घटक को कम करते हुए ताप संयंत्र उच्चतम नवीकरणीय मात्रा तथा निम्न बाजार नवीकरणीय ऊर्जा और भारत में बिजली कीमत के समीकरण समाशोधन कीमतों पर प्रत्युत्तर के फलस्वरूप विनिमयों पर किए गए व्यापार मात्रा में कमी आयी है।

V. निष्कर्ष

यह आलेख कुल बिजली आपूर्ति में कम भागीदारी के बावजूद विद्युत के कीमत निर्धारण में नवीकरणीय ऊर्जा की बढ़ती भूमिका पर प्रकाश डालता है। आगे जाकर, 2022 तक लागत प्रभावी सौर पैनल, भंडारण प्रौद्योगिकियां और 227 गीगावॉट के नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता लक्ष्य की प्राप्ति संभवत: बिजली की स्पॉट कीमत को और नीचे ले जा सकती है। हालांकि, यह ताप विद्युत संयंत्र की व्यवहार्यता के लिए एक चुनौती है जो पहले से

[9] 2013-18 के दौरान आईईएक्स पर उपलब्ध बिजली की कीमत ₹3.1 प्रति किलोवाट थी, जो कि डिस्कॉम और बिजली उत्पादकों के बीच दीर्घ अवधि के औसत बिजली खरीद करारों (पीपीए) से कम है और यह इसी अवधि के दौरान ₹3.0 - 4.3 प्रति यूनिट के बीच थी।

[10] स्पॉट बाजार में नवीकरणीय ऊर्जा का प्रवेश अप्रत्याशित प्रकृति और पूर्वानुमान में कठिनाई के कारण बहुत कम है। नवीकरणीय ऊर्जा चार अलग-अलग मार्गों से स्पॉट बाजार में प्रवेश करती हैं। ये हैं: (i) आरईसी मार्ग; (ii) गैप फिलिंग मैकेनिज्म के रूप में जब बोलियाँ आंशिक रूप से निर्गमित की जाती हैं; (iii) अंतिम उपयोगकर्ता को सीधा विक्रय; और (iv) डिस्कॉम द्वारा पुनर्विक्रय।

[11] प्रायोगिक अभ्यास 1 अक्तूबर 2017 से 31 दिसंबर 2018 तक की अवधि के लिए पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन और आईईएक्स के दैनिक डेटा का उपयोग करती है।

[12] लुत्केपोहल, हेलमुट (1991), "मल्टीपल टाइम सीरीज़ एनालिसिस का परिचय", न्यूयॉर्क: स्प्रिंगर-वेर्लाग।

ही बड़े वित्तीय तनाव से जूझ रहे हैं, किन्तु भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है।

थर्मल पावर संयंत्रों के वजूद पर पहले से ही भारी वित्तीय दबाव के बादल मंडरा रहे हैं जबकि भावी ऊर्जा सुरक्षा के लिए इनकी आवश्यकता होगी। इस ओर तत्काल नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता है ताकि थर्मल क्षेत्र के समक्ष आये इस मौजूदा वित्तीय दबाव से निपटा जा सके तथा भविष्य के लिए यह क्षेत्र सक्षम बने। इस संबंध में प्रमुख अपेक्षा यह है कि मौजूदा पावर संयंत्रों की प्रौद्योगिकी को अपनाया जाए ताकि निम्नतम बेसलोड क्षमताओं पर लचीले रूप से इन्हें संचालित किया जा सके। थर्मल पावर संयंत्रों के लचीले रूप से संचालन करने के उपायों की संस्तुति करने के लिए इंडो–जर्मन ऊर्जा फोरम के तत्वाधान में विद्युत मंत्रालय द्वारा मई 2016 में एक कार्य बल का गठन किया गया था। एक दूसरा नीतिगत विकल्प यह है कि विद्युत के लिए एक क्षमतामयी बाजार बनाया जाए जो मौजूदा विद्युत बाजार के साथ-साथ कार्य करता रहे जिसमें केवल क्षमता के रख-रखाव का कारोबार हो तथा स्पष्ट रूप से पारिश्रमिक की प्राप्ति हो। इससे अक्षय ऊर्जा उत्पादन में अस्थिरता के विरुद्ध टकराव झेलते हुए, बहुत ऊंची मांग की दशा में थर्मल क्षमता के अंतिम सहारा देने की भूमिका को प्रोत्साहन मिलेगा।

संदर्भ

केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, "रिपोर्ट ऑन शॉर्ट-टर्म पावर मार्किट इन इंडिया: 2017-18", *http://www.cercind.gov.in/2018/MMC/AR18.pdf*

आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17, "स्टेट ऑफ इकोनोमी : एन एनेलिटिकल ओवरव्यू एंड आउटलुक फॉर पॉलिसी (अध्याय 1)", *https://www.indiabudget.gov.in/budget2017-2018/es2016-17/echap01_vol2.pdf*

Indian Energy exchange, day-ahead market data, *https://www.iexindia.com/*

इंडियन एनर्जी एक्सचेंज (जुलाई 2018), "आईईएक्स स्ट्राइव्स फॉर आरई इंटीग्रेशन इन्टू पावर एक्सचेंजेस–इंटरव्यू" *https://www.iexindia.com/Uploads/Articles/03_08_2018IEX%20-%20Interview%20EPR%20July%2018.pdf*

इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, "मार्किट स्नैप शॉट – स्पॉट प्राइस", *https://www.iexindia.com/marketdata/market_snapshot.aspx*

इंडो – जर्मन एनर्जी प्रोग्राम ग्रीन एनर्जी कॉरीडर्स (2015), "रिपोर्ट ऑन मार्किट डिजाइन फॉर केपेसिटी मार्किट इन इंडिया", *https://mnre.gov.in/file-manager/UserFiles/Report-on-Market-Design-for-Capacity-Market-in-India.pdf*

लुटकेपोहल, हेलमुट (1991), *"इंटरोडक्शन टू मल्टीपल टाइम सीरीज एनेलेसिस"*, न्यू यॉर्क: स्प्रिंगर–वेरलेग

मम्डौह जी सालामेह (2013), "इम्पैक्ट ऑफ यू एस शेल ऑइल रेवोल्यूशन ऑन द ग्लोबल ऑयल मार्किट, द प्राइस ऑफ ऑयल एंड पीक ऑयल", *https://www.iaee.org/en/publications/newsletterdl.aspx?id=202*

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय , भारत सरकार, सीपीआई विद्युत डाटा, *http://164.100.34.62:8080/Default1.aspx*

नीति आयोग (2017), "नई ऊर्जा नीति (एनईपी) (प्रारूप)" *http://niti.gov.in/writereaddata/files/new_initiatives/NEP-ID_27.06.2017.pdf*

आर्थिक सलाहकार का कार्यालय , भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, डब्ल्यूपीआई विद्युत डाटा, *http://eaindustry.nic.in/home.asp*

पावर सिस्टम ऑफ ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मासिक रिपोर्ट्स, *https://posoco.in/reports/monthly-reports/monthly-reports-2018-19/*

पेसारान, एम एंड शिन, वाय (1999), एन आटोरिग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूटेड लैग मॉडलिंग एप्रोच टू कोइंटीग्रेशन एनेलेसिस, इन एस स्ट्रोम,

इकोनोमेट्रिक्स एंड इकोनोमिक थेयरी इन द 20थ सेंचुरी : द रैगनर फ्रीश्च सेंटेनिएल सिंपोसियम, *कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, कैम्ब्रिज*

पेसरान, एम. एच. शिन, वाय एंड स्मिथ, आर. जे. (2001), बाउंड्स टेस्टिंग एप्रोचेस टू द एनेलेसिस ऑफ लेवेल रिलेशनशिप, *जर्नल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक्स, 16, 289-326*

टास्क फोर्स कमिटी रिपोर्ट ऑन फ्लेक्सिबिलाइजेशन ऑफ थर्मल पावर प्लांट्स (2017), *http://www.cea.nic.in/reports/others/thermal/trm/taskforce_report.pdf*

अनुबंध I

भारत में अक्षय ऊर्जा तथा विद्युत मूल्य गतिकी (डायनेमिक्स) – एआरडीएल

स्वप्रतिगामी वितरित अंतराल (ऑटोरिग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूटेड लैग) (एआरडीएल) फ्रेमवर्क को एक उचित कार्यप्रणाली के रूप में अपनाया गया था ताकि अप्रैल 2013-सितंबर 2018 के दौरान स्पॉट बाज़ारों पर व्यापार –विनिमय किए जा रहे विद्युत के मूल्य गतिकी का मूल्यांकन किया जा सके। इस प्रक्रिया में उपयोग किए गए मीयादी रूप से समायोजित चरों का ब्योरा देखने पर, बहिर्जात चरों के रूप में पैदा की गई कुल विद्युत की तुलना में आईईएक्स पर व्यापार किये कोयला आयात तथा मात्रा के अनुपात को शामिल करने के अलावा थर्मल पावर, अक्षय ऊर्जा तथा जल विद्युत की पैदा की गई मात्रा पर स्पॉट मूल्य (भारत ऊर्जा एक्सचेंज, आईईएक्स) का आश्रित चरों के रूप में रिग्रेशन हुआ है।

ऑग्मेंटेड डिकी फुलर (एडीएफ़) यूनिट मूल परीक्षण मानदंड (सारणी 1) पर आधारित, थर्मल, अक्षय तथा जल विद्युत मात्रा 1 (0) है जबकि पैदा की गई कुल विद्युत की तुलना में व्यापार किया गया स्पॉट मूल्य, कोयला आयात तथा मात्रा का अनुपात 1 (1) है। एआईसी परीक्षण के अनुसार यह दो (2) का उचित लंबा अंतराल होना चाहिए।

ये परिणाम यह पुष्टि करते हैं कि अक्षय ऊर्जा के विद्युत के स्पॉट मूल्यों में थोड़ी कमी करने के सांख्यिकीय प्रमाण मिले हैं जबकि मूल्य गतिकी बरकरार है तथा थर्मल पावर प्रमुख निर्धारक रहे हैं।

2.86 के टी-स्टैट्स के साथ एफ तथा टी-बाउंड परीक्षण, जिसका सम्पूर्ण मूल्य 1 (0) से कम था तथा 3.23 (5 प्रतिशत पर तथा नीचे) के मूल्य 1 (1) तथा 4.35 का 1 (1) ; तथा -2.57 तथा -3.46 के साथ इसका टी – स्टैट्स = 0.111, क्रमश: 1 (0) तथा 1 (1) के लिए यह पुष्टि करते हैं कि वेरिएबल्स के बीच कोई सह संघटित संबंध नहीं था। (सारणी 2)

सारणी 1: मूल यूनिट का एडीएफ़ परीक्षण – मासिक डाटा

वेरिएबल्स	प्रवृति के बिना टी-सांख्यिकीय	प्रवृति सहित टी-सांख्यिकीय
लॉग.स्पॉट मूल्य	-2.09	-2.08
लॉग.थर्मल मात्रा	-1.36	-5.32*
लॉग.अक्षय ऊर्जा मात्रा	-0.14	-3.20**
लॉग.हाइड्रो मात्रा	-3.42**	-3.57**
अनुपात स्पॉट _ कुल	-0.67	-1.74
लॉग.कोयला आयात	-2.43	-3.00

*: 1% महत्व का स्तर; **: 5% महत्व का स्तर;
***: 10% पर महत्व
स्रोत : लेखक का अनुमान।

सारणी 2: एफ तथा टी – बाउंड्स परीक्षण
अमान्य अनुमान : स्तर विहीन संबंध

परीक्षण सांख्यिकीय	मूल्य	महत्व	I(0)	I(1)
		Asymptotic: n=1000		
एफ- सांख्यिकीय के	2.8605363	10%	2.72	3.77
		5%	3.23	4.35
		2.50%	3.69	4.89
		1%	4.29	5.61
वास्तविक सैंपल आकार	62	सीमित सैंपल: n=65		
		10%	2.843	3.923
		5%	3.435	4.583
		1%	4.69	6.143
		सीमित सैंपल: n=60		
		10%	2.838	3.923
		5%	3.415	4.615
		1%	4.748	6.188
टी- बाउंड्स टेस्ट		अमान्य अनुमान : स्तर विहीन संबंध		
परीक्षण सांख्यिकीय	**मूल्य**	**महत्व**	**I(0)**	**I(1)**
टी-सांख्यिकीय	0.111304	10%	-2.57	-3.46
		5%	-2.86	-3.78
		2.50%	-3.13	-4.05
		1%	-3.43	-4.37

स्रोत : लेखक का अनुमान।

2.49 के एफ-स्टैट्स के साथ ब्रयूश्च – गोडफ्रे सीरियल कोरेलेशन एलएम परीक्षण तथा संभावना एफ (2.50)=0.093 तथा 0.064 की संभावना की साथ ची – स्क्वेयर की संभावना, 0.05 से अधिक – महत्वहीन यह पुष्टि करते हैं कि कोई क्रमिक सह संबंध नहीं था। (सारणी 3)। लगभग 5 का गणना किया वेरिएन्स मुद्रास्फीति फैक्टर (वीआईएफ़) स्वीकारे जाने योग्य सीमा के भीतर था जो यह दर्शाता है इन रिग्रेसरो के बीच कोई बहु-एकसीधरेखा (मल्टी कोलिनिएरिटी) नहीं है।

(जारी...)

सारणी 3: ब्र्युश्च-गोडफ्रे क्रमिक सह संबंध एल एम परीक्षण

एफ - सांख्यिकीय	2.48495	संभावना एफ(2,51)	0.0934
ओबीएस*आर-स्केयर्ड	5.505347	संभावना ची-स्क्वेयर(2)	0.0638

नोट : एफ-सांख्यिकीय तथा ची-स्क्वेयर की संभावनाएं जो कि 0.05 से अधिक है यह पुष्टि करते हैं कि इसमें कोई क्रमिक सह संबंध नहीं था।
स्रोत : लेखक का अनुमान।

इसी माह के स्पॉट मूल्य पर आरई मात्रा का प्रभाव जानने का संयुक्त महत्व का वाल्ड टेस्ट यह दर्शाता है कि इस वर्तमान माह आरई मात्रा का नकारात्मक प्रभाव पिछले माह के आरई मात्रा के सकारात्मक प्रभाव से खारिज नहीं हुआ है (सारणी 4)।

सारणी 4: वाल्ड परीक्षण

परीक्षण सांख्यिकीय	मूल्य	डीएफ	संभावना
टी-सांख्यिकीय	-2.58873	53	0.0124
एफ-सांख्यिकीय	6.7015	(1, 53)	0.0124
ची-स्क्वेयर	6.7015	1	0.0096
अमान्य अनुमान: सी(4)+सी(5)=0			
सामान्यीकृत रोक (= 0)		**मूल्य**	**मानक त्रुटि**
सी(4) + सी(5)		-0.17816	0.068822

उक्त रोक को-एफीसींएट्स में रेखीय है।
स्रोत : लेखक का अनुमान।

अनुलग्नक II

भारत में अक्षय ऊर्जा तथा विद्युत मूल्य गतिकी - आवेगी प्रतिक्रिया

चोलेस्कि एक एस डी (डी एफ समायोजित) इन्नोवेशन्स ± 2 एस.ई. पर प्रतिक्रिया

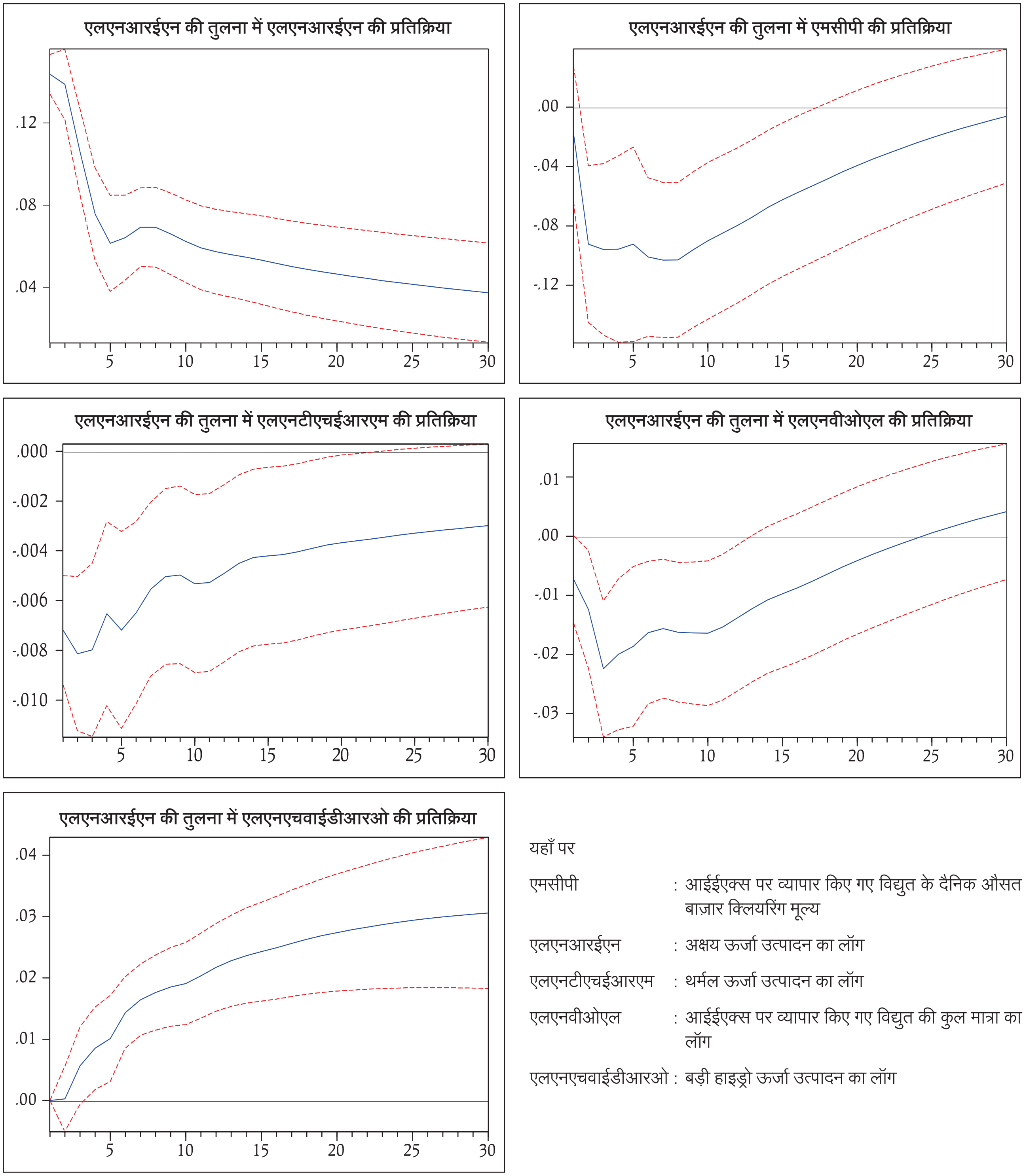

यहाँ पर

एमसीपी : आईईएक्स पर व्यापार किए गए विद्युत के दैनिक औसत बाज़ार क्लियरिंग मूल्य

एलएनआरईएन : अक्षय ऊर्जा उत्पादन का लॉग

एलएनटीएचईआरएम : थर्मल ऊर्जा उत्पादन का लॉग

एलएनवीओएल : आईईएक्स पर व्यापार किए गए विद्युत की कुल मात्रा का लॉग

एलएनएचवाईडीआरओ : बड़ी हाइड्रो ऊर्जा उत्पादन का लॉग

बैंक जमाराशियां: अंतर्निहित समीकरण*

हाल ही में,बैंक की जमाराशियों की वृद्धि में आयी गिरावट और ऋण की बढ़ी मांग के चलते बैंकिंग प्रणाली में संरचनात्मक चलनिधि अंतराल के प्रति चिंता बढ़ गई है, यह संभवत: विमुद्रीकरण के बाद बैंक की जमाराशियों की तुलना में छोटी बचत एवं म्यूचुअल फंड के प्रतिस्थापन प्रभाव के चलते और बढ़ गया है। इस लेख में बैंक जमाराशियों को प्रभावित करने वाले चक्रीय झुकाव तथा दीर्घकालिक प्रभाव की समीक्षा की गई है। अनुभवजन्य परिणामों से पता चलता है कि आय और वित्तीय समावेशन दीर्घकालिक संरचनागत वाहक हैं जबकि ब्याज दर और सेंसेक्स प्रतिफल अल्पावधि में बैंक जमाराशियों की वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं।

भूमिका

हाल की अवधि में बैंकिंग प्रणाली[1] की जमाराशियों की वृद्धि पर एक सजीव बहस देखी गई है। इस मुद्दे ने ऋण मांग बढ़ने के कारण ध्यान आकर्षित किया है जब लगातार 75 माह की गिरारवट के बाद यह नवंबर 2017 में बढ़कर 9.3 प्रतिशत हो गई जो कि फरवरी 2017 में अपने न्यूनतम स्तर अर्थात 4.4 प्रतिशत रही थी।

उधार और जमा वृद्धि के बीच बढ़े अंतराल ने बैंकिंग प्रणाली के संरचनागत चलनिधि अंतराल के प्रति चिंता बढ़ा दी है,जो वित्तीय मध्यस्थता प्रक्रिया के पहिये को जाम कर सकती है,जिसके माध्यम से उधार प्रदान करते हुए जमाराशियों को उत्पादक निवेश में परिवर्तित किया जाता है,जिससे अर्थव्यवस्था का पहिया निर्बाध बनता है। हाल के बयान ने ऋण देने योग्य निधियों की कमी पर ध्यान केंद्रित किया है,इससे निधियों की लागत ऐसे समय में बढ़ गई है, जब घरेलू आर्थिक गतिविधियां अपनी गति खो रही हैं, जैसा कि मांग और उत्पादन के उच्च आवृत्ति वाले संकेतकों से संबंधित आंकड़ों से पता चलता है।

31 मार्च 2019 को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की बकाया जमाराशियां ₹1,25,726 बिलियन रही जो कि बकाया बैंक ऋण का 128.7 प्रतिशत है (पिछले साल के 132.5 प्रतिशत से कम), जो कि जमाराशियों की कम वृद्धि के कारण वित्तीय स्थितियों को सख्त बनाने को दर्शाता है। हाल के सरोकारों के परिप्रेक्ष्य में देखें तो बैंक जमाराशियां हाउसहोल्ड की पसंदीदा वित्तीय आस्ति बनी रहीं, जो कि वैकल्पिक उच्चतम निवल लाभ (कर प्रोत्साहन समेत) युक्त वित्तीय बचत विकल्प होने के बावजूद,अर्थव्यवस्था के लिए निधियों की आपूर्ति का प्रमुख स्रोत हैं। आश्वासित लाभ, चलनिधि तथा सुरक्षा ऐसे घटक हैं जो हाउसहोल्ड के पसंदीदा वित्तीय लिखत पर निर्भर हैं। साथ ही वित्तीय समावेशन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक और भारत सरकार के निरंतर प्रयासों से अब तक बैंकिंग प्रणली के बाहर रहे हाउसहोल्डों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली के दायरे में लाने से जमाराशियां बढ़ी हैं।

तदनुसार, इस आलेख में इन प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास किया गया है कि: क्या छोटी बचत और म्यूचुअल फंड्स की तुलना में प्रतिस्थापन प्रभाव है अथवा क्या कोई गैर वित्तीय मध्यस्थीकरण प्रक्रिया है जो कि भारत की बैंक-प्रधान वित्तीय प्रणाली और अब तक ज्ञात वित्तीय मध्यस्थीकरण की प्रक्रिया की रूपरेखा को बदलने वाली है। विमुद्रीकरण के बाद जनता की बैंकिंग आदत में हुए परिवर्तन और बैंकों द्वारा किए गए तुलन-पत्र समायोजन करने के संदर्भ में यह प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है । इस लेख में उल्लेख किया गया है कि चक्रीय झुकाव को सुलझाना और हाउसहोल्ड/बैंकों के संरचनागत अथवा व्यवहारवादी परिवर्तन अत्यंत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये नीतियों पर अत्यधिक प्रभाव डालते हैं।

* यह आलेख श्री हरींद्र बेहरा और श्री दीर्घायु के रावत, आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग और श्रीमती आरती सिन्हा, सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा तैयार किया गया है। इस आलेख में व्यक्त विचार लेखकों के हैं और ये विचार भारतीय रिज़र्व बैंक के विचारों को प्रतिनिधित्व नहीं करता है।

[1] दि एकनॉमिक टाईम्स, 4 मई 2018: 'बैंक जमा की वृद्धि पिछले पांच दशकों में अत्यंत कम'; फैनान्सियल एक्सप्रेस, 10 सितंबर 2018: 'चिंता की बात: पिछले एक साल से बैंक जमा वृद्धि में गिरावट दर्ज'; लाईव मिंट, 10 जनवरी 2019: 'बैंक जमा वृद्धि में मंदी के बावजूद बैंक उधार वृद्धि में बढ़ोत्तरी'; फैनान्सियल एक्सप्रेस, 22 मार्च 2019, 'आपके पैसे: अब बैंक जमा निवेशकों का प्रिय न होने का कारण'

शेष आलेख को तीन भागों में विभाजित किया गया है। इसके तुरंत बाद भाग II में जमा व्यवहार के अंतर्निहित दीर्घावधि निर्धारिकों के अस्थायी प्रभाव को अलग करने के उद्देश्य से बैंक समूहों द्वारा जुटाई गई जमाराशियां, खातों का प्रकार और उनकी परिपक्वता अवधि तथा हाउसहोल्ड की वित्तीय बचत में वित्तीय आस्तियों के व्यवहारवादी पहलुओं पर शैली अनुरूप तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं। भाग III में अपनाई गई कार्य-प्रणाली, अध्ययन अवधि तथा अनुभवजन्य परिणाम विवरण वर्णित किए गए हैं। भाग IV में नीतिगत परिप्रेक्ष्य के साथ निष्कर्ष प्रस्तुत किया गया है।

2. कुछ शैली अनुरूप तथ्य

अन्य विविध कारकों को हाल ही में मानने के बावजूद बैंकिंग साहित्य जिसमें बैंक जमा को विशेषत: जमा ब्याज दर और आय के फलन के रूप में माना जाता है। जमा संग्रहण (माशांबा ईट अल., 2014) को बढ़ाने के लिए बैंक रहित क्षेत्रों में बैंक शाखाएं प्रारंभ करने हेतु आमतौर पर बैंक शाखाओं और बैंक जमाओं के बीच सकारात्मक संबंध की पुष्टि की गई है। शेयर बाज़ार से प्राप्त प्रतिफल, मुद्रास्फीति और लोक भविष्य निधि (पीपीएफ) पर लागू ब्याज दर आदि मीयादी जमाओं की वृद्धि पर नकरात्मक प्रभाव डालते हैं। (दास एवं अन्य, 2015, बेहरा और यादव,2019)। हाल के कार्य में विमुद्रीकरण के कारण वित्तीय बचतों को पूंजी बाज़ार में पथांतरण किए जाने और हाउसहोल्ड्स मीयादी जमाओं की जगह बचत जमाओं का विकल्प अपनाने को वरीयता देने के कारण जमा व्यवहार में हुए परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। (सक्सेना और श्रीजित, 2018)

जमाराशियों की वृद्धि में आयी गिरावट के विपरीत, नवंबर 2017 के 3 प्रतिशत जो कि पिछले 53 साल में हुई गिरावट के बाद वर्ष 2018 के प्रारंभ में, इसमें वृद्धि होने लगी। मार्च 2019 की समाप्ति पर दर्ज 10 प्रतिशत जमा वृद्धि, वस्तुत: पिछले 15 साल की प्रवृत्ति (चार्ट 1) से मामूली अधिक रही। इसके अलावा, वर्षानुवर्ष जमावृद्धि में हुआ अपघटन यह दर्शाता है कि प्रतिकूल आधारभूत प्रभाव (लाल रंग की रेखाएं) के बावजूद हाल ही में हुई बढ़ोत्तरी उसकी गति से संचालित रही। इस उल्लेखनीय सुधार के होते हुए भी, यह नोट करने योग्य है कि नवंबर–दिसंबर 2016 के दौरान विमुद्रीकरण के कारण हुए रूकावट को छोड़कर, अगस्त 2009 से हुए दीर्घकालिक गिरावट के परिप्रेक्ष्य के बावजूद हाल में सुधार ने जोड़ पकड़ा है।

चार्ट 1: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सकल जमा – आधाभूत और गति प्रभाव

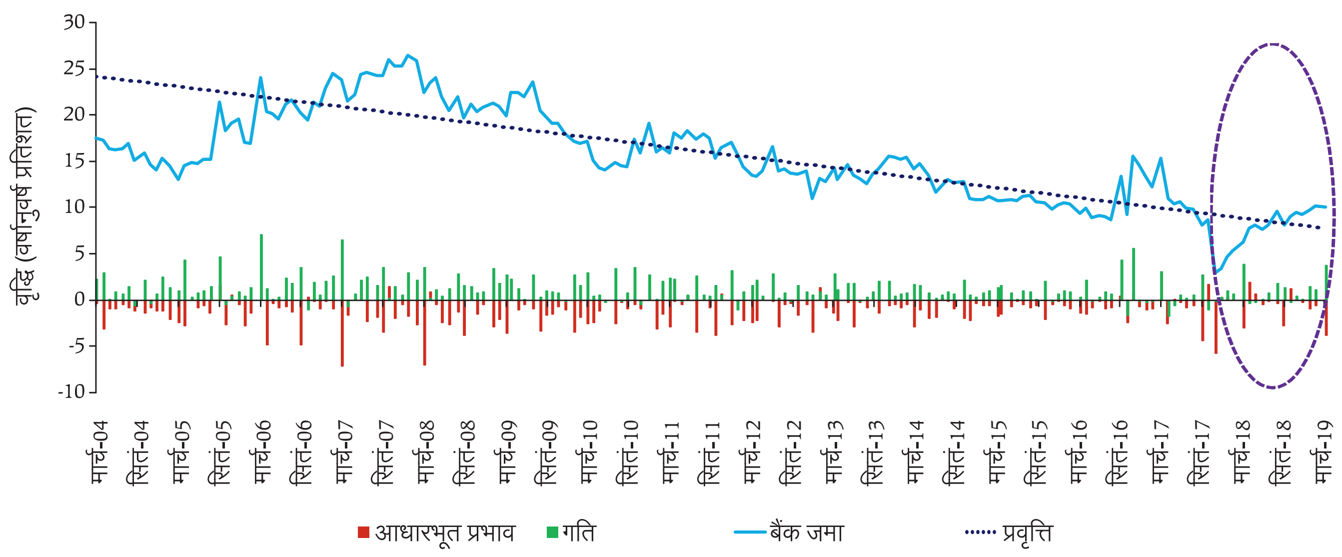

स्रोत : आरबीआई।

विशेष रूप से बैंकों द्वारा प्राप्त जमाराशियों को चालू, बचत और सावधि जमा[2] के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। बचत जमा एक संकर उत्पाद है जिसमें चालू खाता और सावधि जमा खाते की विशेषताएं मिश्रित हैं। मांग पर अदा की जाने वाली सभी जमा देयताएं यथा चालू खाता जमा तथा बचत बैंक जमाओं की मांग के घटक, मांग जमाओं के अधीन आते हैं। बैंकों की मीयादी जमाओं में सावधि जमा तथा बचत बैंक जमा की अवधि के घटक शामिल हैं। पिछले कुछ सालों से सकल जमाओं में मांग जमा का हिस्सा कम हुआ है जबकि आवधिक जमा बढ़ी हैं। आवधिक जमा, सकल जमा का लगभग 88 प्रतिशत हिस्सा थी और यह पाया गया है कि सकल जमा वृद्धि का स्वरूप प्रमुख रूप से आवधिक जमा के व्यवहार से निर्धारित किया जाता है। (चार्ट 2) दूसरी ओर, मांग जमा वृद्धि अस्थिर होती है, वर्तमान में आम जनता के पास उपलब्ध मुद्रा में हुए परिवर्तन के अनुरूप इसमें प्रतिस्थापन होता है।

बैंक समूह के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा संग्रहीत जमा, सकल जमाओं का प्रमुख अंश होती है। हाल ही में हुई जमा वृद्धि में निजी क्षेत्र तथा विदेशी बैंकों का योगदान रहा है, जबकि अक्तूबर 2011 में हुए संकुचन की तुलना में विदेशी बैंकों का अच्छा कार्यनिष्पादन है और निजी क्षेत्र के बैंक अधिक समुत्थानशील है, क्योंकि उनकी जमा वृद्धि में प्रगति सितंबर 2013 से हुई है। (चार्ट 3)। सभी वर्गों के बैंकों द्वारा जमा वृद्धि में समान दीर्घकालिक गिरावट दर्शायी गयी है, हालांकि निजी क्षेत्र के बैंकों के संबंध में गिरावट की प्रवृत्ति तुलनात्मक रूप से सपाट है। इस प्रकार यह देखने को मिलता है कि सकल जमा, प्रमुख रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की आवधिक जमा के व्यवहार को प्रतिबिंबित करती है।

जमा वृद्धि और ब्याज दर[3] में हुए परिवर्तन में निकटतम सह उतार-चढ़ाव दिखाई देता है जैसे कि नवंबर 2017 तक घटने की प्रवृत्ति और उसके बाद बढ़ने की प्रवृत्ति (चार्ट 4)। जमा वृद्धि और सांकेतिक जीडीपी वृद्धि में हुए परिवर्तन में भी

चार्ट 2: विविध प्रकार के जमा

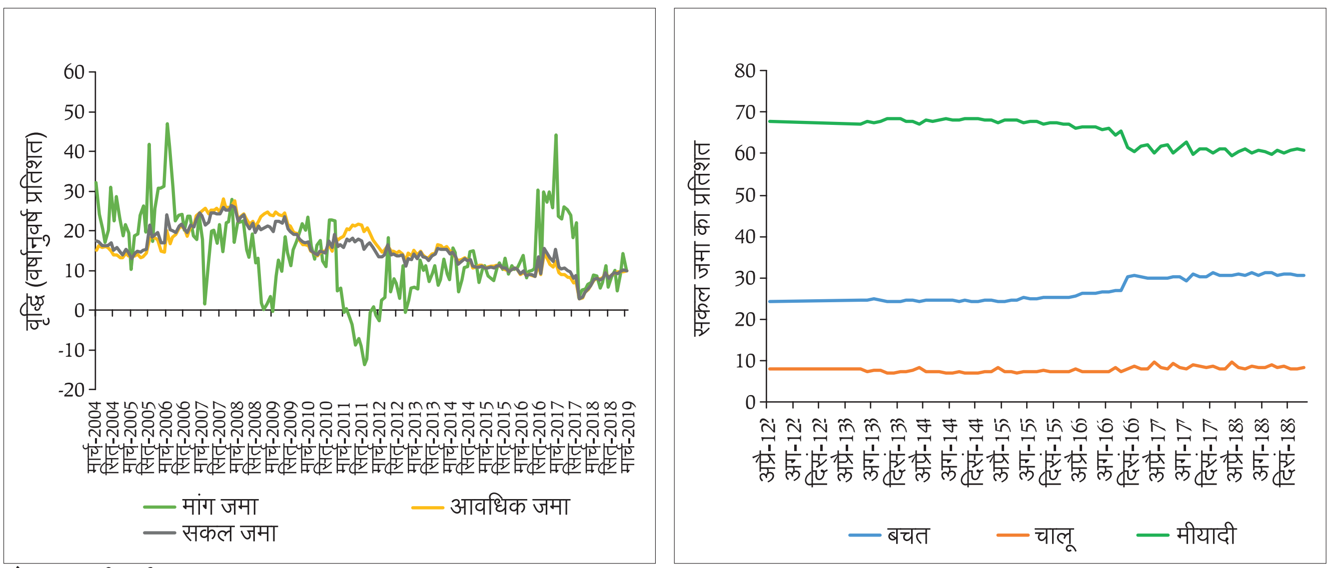

स्रोत : आरबीआई।

---

2 चालू जमाराशियों में चालू खाता की शेष राशि और मांग पर देय अन्य जमाराशियां शामिल हैं। बचत जमाराशियां किसी निर्धारित अवधि के दौरान किए गए आहरण तथा बैंक द्वारा अनुमत आहरण राशि संबंधी प्रतिबंध के अधीन है। सावधि/मीयादी जमाराशियां, किसी निर्धारित अवधि के लिए बैंक द्वारा प्राप्त जमाराशियां जो कि उस निर्धारित अवधि की समाप्ति पर आहरण करने योग्य है। मांग जमाराशियों में चालू जमाराशियां तथा बचत जमाराशियों की मांग का अंश शामिल हैं।

3 भारित औसत सावधि जमा दर, जिसमें भार विविध परिपक्वता अवधि की बकाया जमाराशियों पर आधारित है।

चार्ट 3: सकल जमाराशियां: बैंक दल वार

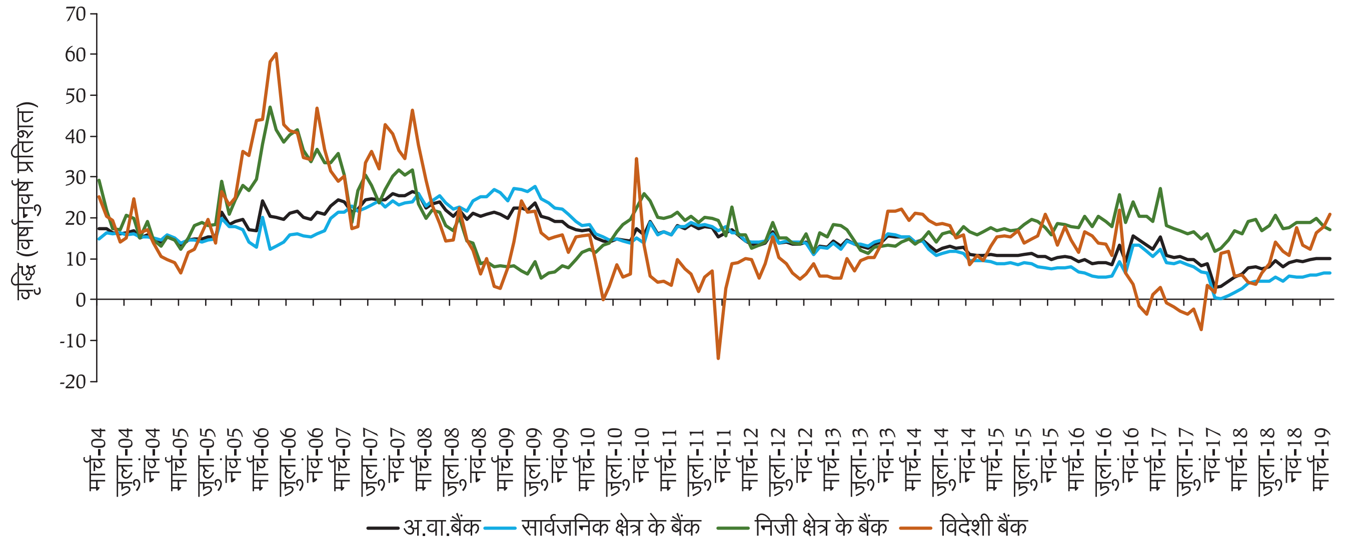

स्रोत : आरबीआई।

निकटतम सह उतार-चढ़ाव देखने को मिलते हैं जैसे कि 2003-08 के दौरान बढ़ने की और उसके बाद की अवधि में घटने की प्रवृत्ति। जमावृद्धि और सांकेतिक जीडीपी की वृद्धि के सह उतार-चढ़ाव जमा ब्याज दर की वृद्धि से अधिक है, जो यह दर्शाता है कि जमावृद्धि को बढ़ाने में आय का प्रभाव, मूल्य के प्रभाव से अधिक है।

आय और ब्याज दर के अलावा, छोटी बचत से उत्पन्न दीर्घकालिक प्रभाव द्वारा जमाराशियों का संग्रहण प्रभावित हुआ, हालांकि उसी अवधि में सकारात्मक सह-संबंध रहा, इससे ब्याज दर अंतरवाली राशियों में कमी पाई गई है। दीर्घकालीन रूप में जमावृद्धि और छोटी बचत दोनों घटती गई हैं। छोटी बचत योजनाओं को उपलब्ध कराए गए आय कर प्रोत्साहन के कारण बैंक जमाओं और छोटी बचत के बीच प्रतिस्पर्धा होने लगी (अनुबंध 1)। दीर्घकालीन रूप में छोटी बचत, विशेषत: पीपीएफ पर लागू कर रियायत सीमित किए जाने पर प्रतिस्पर्धा समाप्त हो गई। पीपीएफ पर लागू कर रियायत, समय-समय पर आयकर अधिनियम की धारा 80सी के अधीन निर्धारित निवेश सीमा के अनुरूप संशोधित की जाती है। जैसे कि पहले ही उल्लेख किया गया था कि निवेशकों के लिए उपलब्ध वित्तीय बचत लिखतों का नवोन्मेषण, जिसमें सुरक्षा और प्रतिलाभ दोनों हैं, के कारण वित्तीय आस्तियों का विपथन हुआ। इसके परिणामस्वरूप म्यूचुअल फंड्स और अन्य शेयर बाज़ार लिखतों की लोकप्रियता बढ़ी और रियल एस्टेट और स्वर्णाभूषण आदि परंपरागत विकल्प की लोकप्रियता कम हुई। इसलिए शेयर बाज़ार प्रतिलाभ और जमावृद्धि का उतार-चढ़ाव प्रतिस्थापन प्रभाव के संकेत बन गए।

III. आंकड़े, अध्ययन अवधि, कार्य-पद्धति और परिणाम

बैंक जमाराशियों पर आंकड़े वर्ष 1951 से मासिक अंतराल पर उपलब्ध हैं, लेकिन औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई – आईडबल्यू) जनवरी 1960 से ही उपलब्ध है। इसलिए वास्तविक जमाराशियों की श्रृंखला, बाद की तारीख को सीपीआई-आईडब्ल्यू द्वारा सांकेतिक सकल जमाराशियों को कम करते हुए परिकलित किया जा सकता है। तथापि, अन्य परिवर्ती कारक यथा छोटी बचत और बैंक शाखाएं आदि संबंधी आंकड़ों की उपलब्धता सीमित है, जो कि जून 2006 से सितंबर 2018 तक की तिमाही आंकड़ों के अध्ययन तक सीमित करता है।

समग्र जमाराशियों में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि के पैटर्न में संरचनात्मक विराम को बाई-पेरोन जांच[4] (बाई और पेरोन,

[4] बाई-पेरोन जांच को संरचनात्मक विराम जांचों के अन्य रूपों के मुकाबले बेहतर माना जाता है क्योंकि यह अज्ञात तिथियों में होने वाले एकाधिक संरचात्मक विरामों को चिह्नित करने में सक्षम है।

चार्ट 4: निकटस्थ सह-संचलन

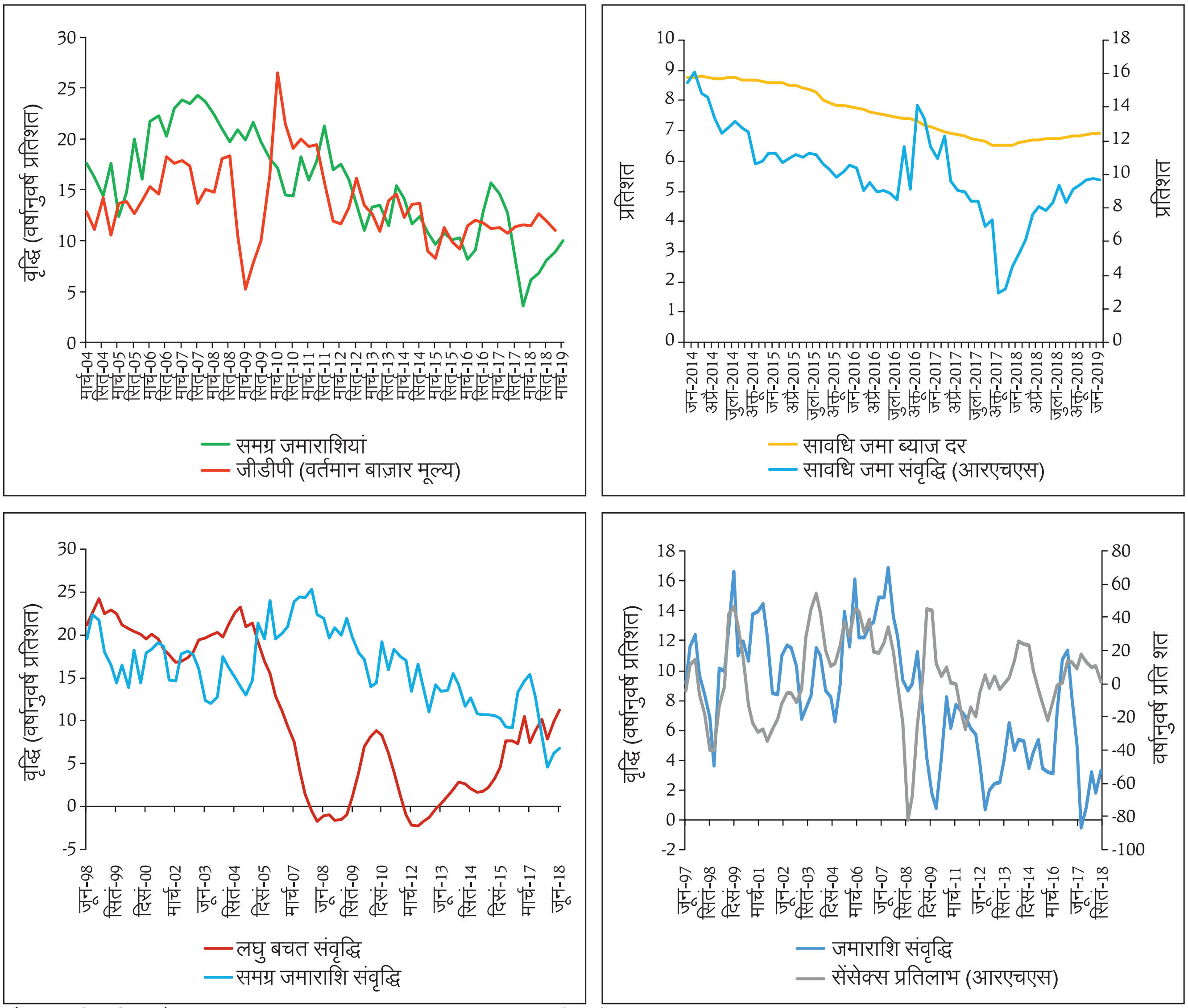

स्रोत : सांख्यिकीय और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार; आरबीआई।

1998) का उपयोग करके चिह्नित किया गया है। संवृद्धि दर के अनुसार, अक्तूबर 2009 (चार्ट 5) में जमा व्यवहार एक प्रमुख संरचनात्मक विराम से गुजरा। 2009 में विराम का रुझान जीडीपी संवृद्धि में मंदी का संकेत हो सकता है। नवम्बर 2016 में, विमुद्रीकरण से जमा संवृद्धि में क्षणिक उछाल तो उत्पन्न हुआ लेकिन आंकड़ों के नजरिए से कोई महत्वपूर्ण संरचनात्मक विराम नहीं था। इसके अलावा, जमा संवृद्धि में यह उछाल जुलाई 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण से संबंधित उछाल की तुलना में कम व्यापक थी।

जमाराशि संवृद्धि की मंदी में अंतर्निहित दीर्घकालिक और अल्पकालिक प्रतिवर्ती कारकों के बीच अंतर करने के लिए, स्तरों में सामयिक रूप से समायोजित समग्र जमाराशियां रुझान और चक्रीय घटकों (चार्ट 6) में विघटित की जाती हैं। टर्निंग पॉइंट विश्लेषण (हार्डिंग और पगान, 2002 पर आधारित) से पता चलता है कि चक्रों की अवधि औसतन लगभग 37 महीनों की है, जिसमें नवंबर 2016 में विमुद्रीकरण के अलावा कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं है, जो संभवतः अंतर्निहित कारोबारों / आर्थिक चक्रों को दर्शाता है। तदनुसार, जमा व्यवहार

चार्ट 5: जमा वृद्धि में संरचात्मक विराम

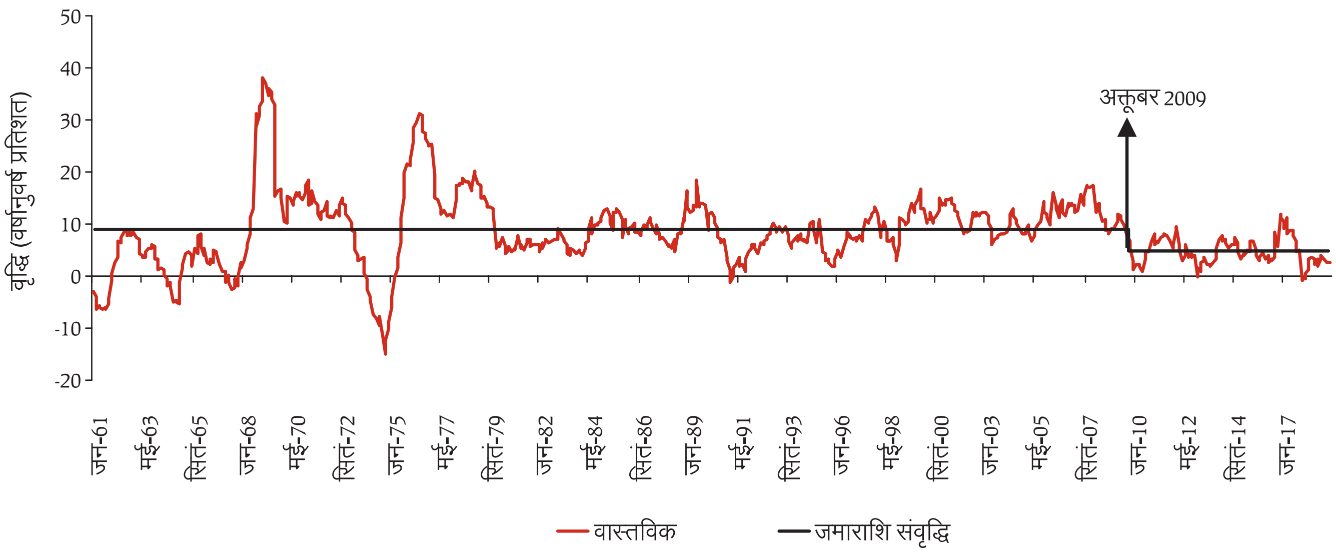

स्रोत : लेखकों के अनुमान।

और अंतर्निहित समष्टि आर्थिक (मैक्रोइकोनॉमिक) एवं वित्तीय परिवर्तियों के साथ इनके संबंध का गहन विश्लेषण आवश्यक है।

अगले चरण में, सामयिक रूप से समायोजित (sa) जमाराशियों और निकटस्थ निर्धारक तत्वों जैसे सकल घरेलू उत्पाद (sa) के बीच दीर्घकालिक सह-एकीकृत संबंध की मौजूदगी, सावधि जमा ब्याज दर का भारित औसत, लघु बचत (sa), और वैकल्पिक वित्तीय साधनों पर प्रतिलाभ जैसे म्यूचुअल फंड पर सेंसेक्स द्वारा अनुमानित प्रतिलाभ, और तमाम बैंक शाखाओं (sa) द्वारा किए गए वित्तीय समावेशन का पता लगाया जाता है। अक्तूबर 2009 में आया संरचनात्मक विराम और विमुद्रीकरण आघात को प्रतिरुपी परिवर्तियों द्वारा कैप्चर किया गया है। आंकड़ों के समय श्रृंखला गुणों को देखते हुए जो विश्लेषण के लिए चुने गए स्थिर और गैर-स्थिर परिवर्तियों

चार्ट 6: समग्र जमाराशियां: रुझान और चक्र

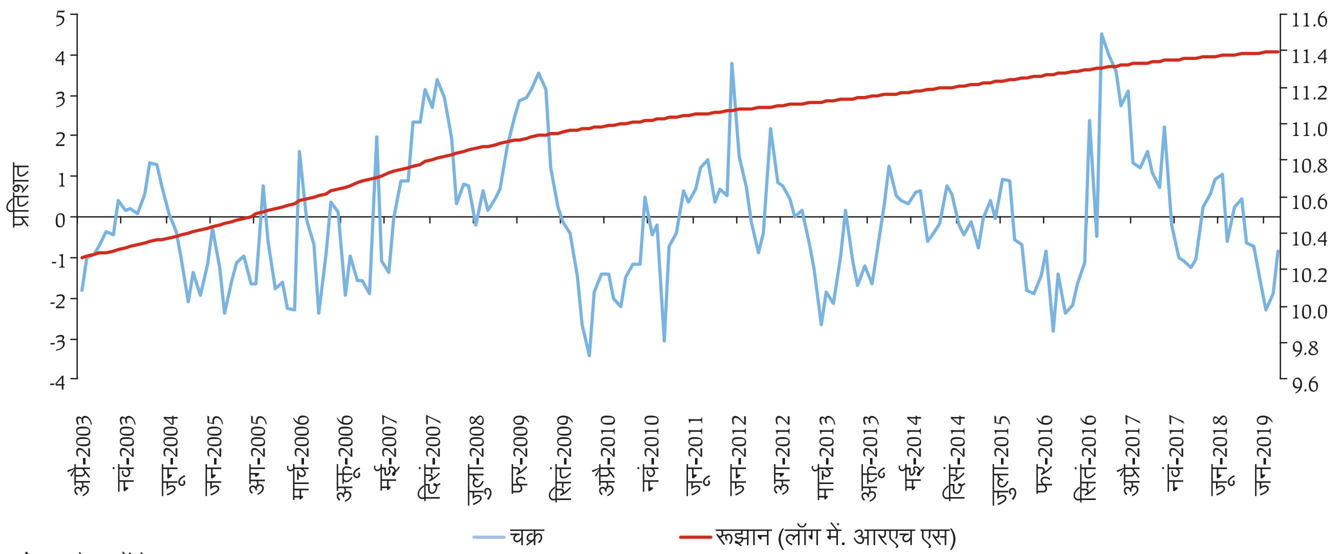

स्रोत : लेखकों के अनुमान।

के संयोजन को दर्शाता है, ऑटोरिग्रेसिव डिस्ट्रिब्यूटेड-लैग (एआरडीएल) मॉडल (पेसारन और शिन, 1998) को बैंक जमाराशियों के निकटस्थ निर्धारकों के दीर्घकालिक और अल्पकालिक गुणकों को प्राप्त करने के लिए अपनाया गया है (अनुबंध II)।

एआरडीएल मॉडल समायोजित आर-वर्ग वाले दृष्टिकोण द्वारा निर्धारित विलम्बित विस्तारमानदंड का उपयोग करता है। बाउंड्स टेस्ट के परिणाम पहले संदर्भित परिवर्तियों के बीच दीर्घकालिक संबंध होने की पुष्टि करते हैं। यद्यपि दीर्घकालिक सह-समाकलन (कोइंटीग्रेशन) जमाराशियों के दीर्घकालिक व्यवहार को स्पष्ट करने का प्रयास करता है, तथापि चक्रीय संचलनों का अध्ययन त्रुटि सुधार मॉडल (ईसीएम) के जरिए किया जा सकता है। सेंसेक्स प्रतिलाभ के अलावा सभी व्याख्यात्मक परिवर्तियां लम्बी अवधि में सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण पायी गयी। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) को जमाराशियों के साथ सकारात्मक रूप से जुड़ा हुआ पाया गया और जिसे सबसे शक्तिशाली निर्धारक के रूप में देखा गया। भारतीय अर्थव्यवस्था की अत्यधिक बचत वाली प्रवृत्ति को देखते हुए जीडीपी का यह महत्व अपेक्षा के अनुरूप है। लघु बचत संग्रहण अगले सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक के रूप में उभरता है जो यह संकेत करता है कि लम्बी अवधि में आय जमाराशियों और लघु बचत, दोनों को प्रभावित करती है, और लघु बचत के लिए कर में छूट पर सीमा से पारिवारिक इकाइयां अपनी आय से इन दोनों के लिए सक्षम होती हैं। वाणिज्यिक बैंक शाखाओं की संख्या में तिमाही दर तिमाही परिवर्तनों के रूप में परिभाषित बैंक शाखाएं जमा व्यवहार का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चालक हैं, जो दर्शाता है कि वित्तीय समावेशन का सकारात्मक प्रभाव समय के साथ बढ़ता । भारित औसत घरेलू सावधि जमा दर को जमा संग्रहण के साथ सकारात्मक रूप से जुड़ा हुआ पाया गया जो ब्याज दर में थोड़ी संवेदनशीलता का संकेत है भले ही इसका प्रभाव मामूली हो। सेंसेक्स पर प्रतिलाभ, जो अन्य वित्तीय साधनों जैसे म्यूचुअल फंड के लिए निवेशक की प्राथमिकता को नियंत्रित करने वाली परिवर्ती है, में अपेक्षित नकारात्मक संकेत पाया गया, लेकिन गुणक सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण नहीं है। अक्तूबर 2009 में संरचनात्मक विराम को नियंत्रित करने के लिए ली गई प्रतिरूपी परिवर्ती (डमी वैरिएबल) सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण है।

अल्पकालिक समीकरण में त्रुटि सुधार शब्द सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण पाया गया और जिसमें अपेक्षित नकारात्मक संकेत था। त्रुटि सुधार का पैमाना बताता है कि दीर्घकालिक संतुलन के लिए किसी आघात हेतु समायोजन और प्रतिलाभ दो तिमाहियों में पूरा हो जाता है। जमाराशि संवृद्धि की आय लोच 0.85 है, जो अल्पावधि में भी सबसे प्रासंगिक निर्धारक बन जाता है। दूसरी तरफ, लघु बचत संग्रहण प्रतिस्थापन प्रभाव के साथ जमाराशि संवृद्धि को नीचे ले जाता है। अन्य निर्धारकों में, बैंक शाखा पर गुणक में सकारात्मक संकेत होता है, लेकिन यह उसके दीर्घकालिक गुणक के मुकाबले बहुत कम परिमाण का होता है, जो लंबी अवधि की घटना के रूप में जमा संग्रहण पर वित्तीय समावेशन के प्रभाव को दर्शाता है। सेंसेक्स प्रतिलाभों का गुणक जो लम्बी अवधि में महत्वपूर्ण नहीं होता है, वह हाल के दिनों में जमाराशियों से शेयर बाजार की आस्तियों में वित्तीय बचत के विपथन की ओर इशारा करते हुए अल्पावधि में महत्वपूर्ण है। विमुद्रीकरण के लिए उपयोग किया गया प्रतिरूप सकारात्मक और सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण पाया गया जो नवंबर 2016 में निर्दिष्ट बैंक नोटों (SBNs) को परिचालन से हटाने के बाद जमाराशियों में उछाल को दर्शाता है।

अलग-अलग समय पर जमाराशि संवृद्धि के लिए विभिन्न कारकों के योगदान को समझने के लिए, एक वेक्टर ऑटोरिग्रेसन (VAR) मॉडल को अनुमानित किया जाता है जिसके लिए एआरडीएल मॉडल में पहले उपयोग की गई परिवर्तियों के वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि का उपयोग किया जाता है। सामान्यीकृत भार का उपयोग करते हुए वीएआर से जमाराशि संवृद्धि के लिए आघातों का ऐतिहासिक अपघटन इब बात का प्रमाण देता है कि जमाराशि संवृद्धि हाल के वर्षों में (विशेषकर 2013 से) मुख्य रूप से आय और जमा ब्याज दरों से संचालित होती है। लघु बचत का प्रतिस्थापन प्रभाव अक्सर पाया गया जबकि सेंसेक्स प्रतिलाभ कभी-कभी देखा गया (चार्ट 7)।

चार्ट 7: जमा ग्रोथ का ऐतिहासिक अपघटन

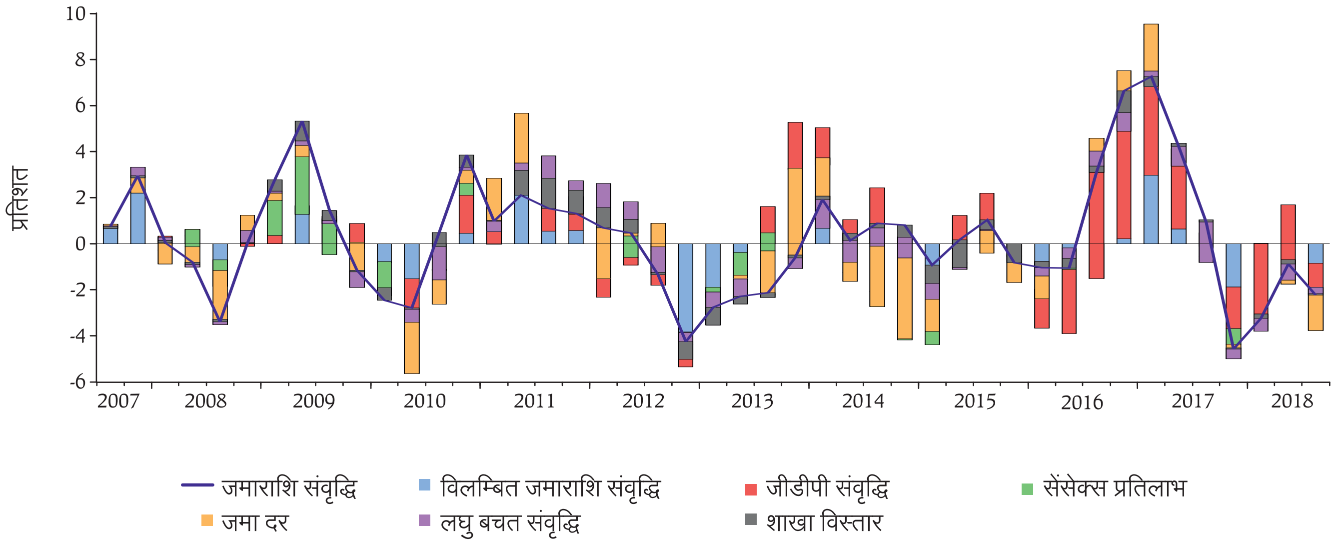

स्रोत : लेखकों के अनुमान।

IV. निष्कर्ष

बैंक जमा पारिवारिक इकाइयों की वित्तीय बचत का एक महत्वपूर्ण भाग और बैंक ऋण के वित्तपोषण की कुंजी बने हुए हैं। दिसम्बर 2018 के बाद से हाल के महीनों में जमाराशि संवृद्धि में एक चक्रीय बढ़ोतरी हो रही है, जो अक्तूबर 2009 के बाद से चल रही मंदी के रुझान को देखते हुए उत्साहजनक है। बाद में नीतियों पर विचार आवश्यक है क्योंकि जमा संग्रहण भारत की बैंक आधारित वित्तीय मध्यस्थता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अनुभवजनित साक्ष्य बैंक जमा व्यवहार के बारे में कई दिलचस्प तथ्यों को उजागर करते हैं। पहला, यह अल्पकालिक और दीर्घकालिक, दोनों ही अवधि में आय को सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक के रूप में रेखांकित करता है। दूसरा, जमा संग्रहण के लिए ब्याज दर मायने रखती है लेकिन केवल मार्जिन पर। तीसरा, जमा एकत्रीकरण के लिए बैंकरहित क्षेत्रों में बैंक शाखाओं के विस्तार के दीर्घकालिक सुझाव के मुकाबले वित्तीय समावेशन का उत्साहजनक प्रभाव पड़ता है। चौथा, जमाराशि संवृद्धि के लिए सेंसेक्स प्रतिलाभ से जुड़ा प्रतिस्थापन प्रभाव, छोटी अवधि तक ही सीमित होता है, जिसके लिए विनियामक सुधारों और कर विवाचन (टैक्स आर्बिट्राज) का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन आवश्यक है, भले ही दोनों को और अधिक बाज़ार निर्धारित बनाने के लिए प्रयासों को गंभीर करना आवश्यकता हो। और अंत में, सेंसेक्स प्रतिलाभ की तरह, छोटी अवधि में लघु बचत बैंक जमाराशियों को प्रतिस्थापित करती है लेकिन लम्बी अवधि में जमाराशियों को अनुपूरित करते हुए यह दर्शाती है कि आयकर छूट पर सीमाएं अंतत: प्रतिस्थापन प्रभाव को स्थिर करती है और लम्बी अवधि में दोनों के लिए आय को मुख्य निर्धारक तत्व बनाती है। अतएव, अंतिम विश्लेषण के रूप में अर्थव्यवस्था के विकास की दर और प्रयोज्य आय को बढ़ाना ही बैंकिंग प्रणाली के द्वारा उच्च जमा एकत्रीकरण की कुंजी है।

संदर्भ

बाई, जुशन और पियरे पेरोन (1998)। "एस्टिमेटिंग एंड टेस्टिंग लिनियर मॉडल्स विथ मल्टीपल स्ट्रक्चरल चेंजेस", इकोनोमेट्रिका, 66, 47-78

बेहरा, एच.के. और यादव, आई.एस. (2019: "एक्सप्लेनिंग इंडियाज करेंट एकाउंट डेफिसिट: ए टाइम सीरीज पर्सपेक्टिव", जर्नल ऑफ एशियन बिजनेस एंड इकोनॉमिक स्टडीज, https://doi.org/10.1108/JABES-11-2018-0089

दास आर., भोई बी.बी., कुमार पी. और बनर्जी के. (2015): "इंटर-सेक्टोरल लिंकेजेस इन द इंडियन इकोनॉमी", भारतीय रिज़र्व बैंक वर्किंग पेपर, 03/2015

हार्डिंग, डी., और पगान, ए. (2002) डिसेक्टिंग द साइकल: ए मेथोडॉलॉजिकल इंवेस्टिगेशन. जर्नल ऑफ मोनेटरी इकोनॉमिक्स, 49(2),365-381 doi:https://doi.org/10.1016/S0304-3932(01)00108-8

मशाम्बा टी., मैगविवा आर., और गुम्बो एल.सी. (2014), "एनालाइजिंग दि रिलेशनशिप बितविन बैंक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट एंड डिपाजिट मोबिलाइजेशन: इम्पिरिकल एविडेंस फ्रॉम जिम्बाब्वे कॉमर्शियल बैंक्स (1980-2006)" आईओएसआर जर्नल ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट, 16 (1): 64-75

पेसारन, एम. एच., और शिन, वाई. (1998) एन ऑटोरिग्रेसिव डिस्ट्रिब्यूटेड-लैग मॉडलिंग अप्रोच टू कोइंटीग्रेशन एनालिसिस, कोनोमेट्रिक सोसायटी मोनोग्राफ, 31, 371-413

सक्सेना टी. के. और श्रीजीत टी. बी. (2018), "पोस्ट-डिमोनेटाइजेशन पैटर्न्स ऑफ डिपाजिट्स विथ शिड्युल्ड कॉमर्शियल बैंक्स: 2016-17 और 2017-18". भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन, दिसंबर 2018

सिंह बी., बेहरा एच., राउत डी. और रॉय आई. (2017): "इम्पैक्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन ऑन दि फाइनेंशियल सेक्टर" भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन, नवंबर 2017

अनुबंध I: बचत लिखतों पर कर उपचार

बचत स्कीम	मूलधन	ब्याज आय	पूंजीगत लाभ
बैंक जमा			
1. बचत जमा	X	₹10000 तक	लागू नही
2. सावधि जमा	(≥ 5 वर्ष परिक्वता)	X ₹40000 तक का कोई टीडीएस नहीं	लागू नही
डाक बचत			
1. बचत जमा	X	₹10000 तक	लागू नही
2. सावधि जमा	√ (≥ 5 वर्ष परिक्वता)	X	
पीपीएफ	√	√	
एनएससी	√	√	
केवीपी	X	X	
सुकन्या	√	√	
एनपीएस	√	√	**40% की सीमा तक कर योग्य**
म्यूचुअल फंड ***दीर्घावधि***			
इक्विटी/संकर (>1 साल)	√ (3 साल लॉक इन सहित ईएलएसएस)		√ ₹1 लाख के बाद 10% टैक्स
ऋण (> 3 साल)	X		X (एलटीसीजी 20%)
अल्पावधि			
इक्विटी/संकर (<1 साल)	X		X (एसटीसीजी 15%)
ऋण (<3 साल) एमएमएमएफ सहित	X		X

√ : कर छूट/ प्रोत्साहन X: कोई कर छूट/प्रोत्साहन नहीं NA: लागू नहीं
ईएलएसएस: इक्विटी-लिंक्ड बचत योजना एलटीसीजी: दीर्घावधि पूंजीगत लाभ कर एसटीसीजी: अल्पावधि पूंजीगत लाभ कर
सुकन्या : सुकन्या समृद्धि खाता

अनुबंध II: प्रायोगसिद्ध परिणाम

एआरडीएल मॉडल

एआरडीएल रिग्रेशन का आकलन, पेसारन और शीन (1998) द्वारा यथा प्रस्तावित ति2: 2006 से ति3: 2018 के डेटा का उपयोग करके किया गया है।

$$\Delta deposit_t = \psi(deposit_{t-1} - \beta' x_t) + \sum_{i=1}^{p-1} \propto_i^* \Delta deposit_{t-i} + \sum_{j=0}^{q-1} \delta_j^{*'} \Delta x_{t-j} + \varepsilon_t$$

जहां जमा, मौसमी रूप से समायोजित वास्तविक सकल जमाओं का नैसर्गिक लघुगणक है और ψ त्रुटि संशोधन पद है, विवरणात्मक चरों का वेक्टर जैसे:, x_t जीडीपी, जमा दर, सेंसेक्स विवरणियां, लघु बचत संग्रह और बैंक शाखाएं। सभी चर वास्तविक अवधि के हैं।

एआरडीएल मॉडल आकलन परिणाम

परिवर्ती	(अवधि: ति2:2006 से ति3:2018)	
	गुणांक	टी आँकड़े
दीर्घावधि		
त्रुटि संशोधन पद	-0.709	-8.48***
स्थिर	-4.976	-2.80***
जीडीपी	0.958	10.99***
जमा-दर	0.005	1.98*
डीसेंसेक्स	-0.0002	-1.38
लघु-बचत	0.452	3.65***
डीब्रांच	0.066	3.31***
डी2009ति4	0.076	3.45***
अल्पावधि		
डी(एडी)	-0.363	-3.25***
डी(जीडीपी)	0.847	5.01***
डी(जीडीपी(-1))	-0.536	-3.08***
डी(डीसेंसेक्स)	-0.0003	-4.22***
डी(लघु-बचत)	0.225	1.74*
डी(लघु-बचत(-1))	0.052	0.36
डी(लघु-बचत(-2))	-0.588	-4.06***
डी(डीब्रांच)	0.001	2.33**
डीमोन	0.045	5.68***
एडीजे आर^2	0.78	
डी-डब्ल्यू आंकड़े	2.47	
एलएम(8)-पी-वैल्यू	0.14	
एआरसीएच(8)-पी- वैल्यू	0.88	

एडी : मौसमी रूप से समायोजित वास्तविक सकल जमा
जीडीपी : मौसमी रूप से समायोजित वास्तविक सकल देशी उत्पाद
जमा दर : भारित औसत सावधि जमा दर
डीसेंसेक्स : समय 'टी' और समय 'टी -1' के बीच सेंसेक्स में त्रैमासिक अंतर
लघु-बचत : मौसमी रूप से समायोजित वास्तविक लघु बचत संग्रहण का नैसर्गिक लघुगणक
डीब्रांच : बैंक शाखाओं में त्रैमासिक वृद्धि
डी2009ति4 : अक्टूबर 2009 में संरचनात्मक ब्रेक के लिए डमी
डीमोन : विमुद्रीकरण के लिए डमी

नोट : ***,**,* क्रमशः 1 प्रतिशत, 5 प्रतिशत और 10 प्रतिशत पर सांख्यिकीय महत्व के स्तर को दर्शाता है।
स्रोत : लेखक का अनुमान/गणना।

सीमा परीक्षण परिणाम

एफ- सीमा परीक्षण		शून्य परिकल्पना: किसी स्तर पर कोई संबंध नहीं		
जांच आंकड़े	**मूल्य**	**संकेत**	**आई(0)**	**आई(1)**
एफ- आंकड़े	8.88	10%	1.99	2.94
के	6	5%	2.27	3.28
		2.50%	2.55	3.61
		1%	2.88	3.99

संरचनात्मक ब्रेक जांच परिणाम

आश्रित चर : जमा वृद्धि
नमूना(समायोजित) : 1961एम01 2019एम03
सम्मिलित अवलोकन : 699 समायोजन के उपरांत
ब्रेक टाइप : बाई-पेरोन जांच का एल+1 बनाम एल क्रमिक रुप से ब्रेक का निर्धारण

ब्रेक : 2009एम09

चयन: ट्रिमिंग 0.15, सिग.लेवल 0.05

चर	गुणांक	मानक त्रुटि	टी-आंकड़े	प्रायिकता
	1961एम01 - 2009एम09 -- 585 अवलोकन			
सी	8.96	0.75	12.00	0.00
	2009एम10 - 2019एम03 -- 114 अवलोकन			
सी	4.60	0.52	8.86	0.00

वर्तमान सांख्यिकी

चुनिंदा आर्थिक संकेतक

भारतीय रिज़र्व बैंक

मुद्रा और बैंकिंग

मूल्य और उत्पादन

सरकारी खाते और खज़ाना बिल

वित्तीय बाजार

बाह्य क्षेत्र

भुगतान और निपटान प्रणालियाँ

अवसरिक श्रृंखलाएं

विषयवस्तु

संख्या	शीर्षक	पृष्ठ
1	चुनिंदा आर्थिक संकेतक	49
	भारतीय रिज़र्व बैंक	
2	भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां	50
3	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि परिचालन	51
4	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अमेरिकी डालर का क्रय/विक्रय	52
4ए	भारतीय रिज़र्व बैंक में बकाया वायदे का (अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार) परिपक्वता विश्लेषण (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	53
5	भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थायी सुविधाएं	53
	मुद्रा और बैंकिंग	
6	मुद्रा स्टॉक मात्रा	54
7	मुद्रा स्टॉक (एम$_3$) के स्रोत	55
8	मौद्रिक सर्वेक्षण	56
9	कुल चलनिधि राशियां	56
10	भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वेक्षण	57
11	आरक्षित मुद्रा- घटक और स्रोत	57
12	वाणिज्यिक बैंक सर्वेक्षण	58
13	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के निवेश	58
14	भारत में कारोबार - सभी अनुसूचित बैंक और सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	59
15	प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक ऋण का विनियोजन	60
16	सकल बैंक ऋण का उद्योग-वार विनियोजन	61
17	भारतीय रिज़र्व बैंक में खाते रखने वाले राज्य सहकारी बैंक	62
	मूल्य और उत्पादन	
18	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधारः 2012=100)	63
19	अन्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	63
20	मुंबई में सोने और चांदी का मासिक औसत मूल्य	63
21	थोक मूल्य सूचकांक	64
22	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधारः 2011-12=100)	67
	सरकारी खाते और खज़ाना बिल	
23	केन्द्र सरकार के खाते - एक नज़र में	67
24	खज़ाना बिल - स्वामित्व का स्वरूप	68
25	खज़ाना बिलों की नीलामी	68
	वित्तीय बाजार	
26	दैनिक मांग मुद्रा दरें	69
27	जमाराशि प्रमाण-पत्र	70
28	वाणिज्यिक पत्र	70
29	चुनिंदा वित्तीय बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर	70
30	गैर-सरकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के नए पूंजी निर्गम	71

संख्या	शीर्षक	पृष्ठ
	बाह्य क्षेत्र	
31	विदेशी व्यापार	72
32	विदेशी मुद्रा भंडार	72
33	अनिवासी भारतीयों की जमाराशियां	72
34	विदेशी निवेश अंतर्वाह	73
35	निवासी भारतीयों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना के अंतर्गत जावक विप्रेषण	73
36	भारतीय रुपये का वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) और सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर (एनईईआर) सूचकांक	74
37	बाह्य वाणिज्यिक उधार	74
38	भारत का समग्र भुगतान संतुलन (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	75
39	भारत का समग्र भुगतान संतुलन (बिलियन ₹)	76
40	बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण (मिलियन अमेरिकी डॉलर में)	77
41	बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण (बिलियन ₹ में)	78
42	अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति	79
	भुगतान और निपटान प्रणालियाँ	
43	भुगतान प्रणाली संकेतक	80
	अवसरिक श्रृंखलाएं	
44	लघु बचत	81
45	केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों के स्वामित्व का स्वरूप	82
46	केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियां और संवितरण	83
47	विभिन्न सुविधाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा ली गई वित्तीय सहायता	84
48	राज्य सरकारों द्वारा किए गए निवेश	85
49	राज्य सरकारों की बाज़ार उधारियां	86

टिप्पणियां: .. = उपलब्ध नहीं।

– = शून्य/नगण्य

प्रा/अ = प्रारंभिक/अनंतिम आंसं = आंशिक रूप से संशोधित

सं. 1: चुनिंदा आर्थिक संकेतक

मद	2018-19	2017-18		2018-19	
		ति2	ति3	ति2	ति3
	1	2	3	4	5
1 वस्तु क्षेत्र (% परिवर्तन)					
1.1 आधार मूल्यों पर जीवीए	6.8	6.6	7.3	6.8	6.3
1.1.1 कृषि	2.7	4.5	4.6	4.2	2.7
1.1.2 उद्योग	7.2	7.7	8.0	6.1	6.1
1.1.3 सेवाएं	7.6	6.5	8.0	7.6	7.6
1.1क अंतिम खपत व्यय	8.4	6.3	5.8	10.0	8.1
1.1ख सकल नियत पूंजी निर्माण	10.0	9.3	12.2	10.2	10.6

मद	2018-19	2018		2019	
		फरवरी	मार्च	फरवरी	मार्च
	1	2	3	4	5
1.2 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक	-	6.9	5.3	0.1	-
2 मुद्रा और बैंकिंग (% परिवर्तन)					
2.1 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक					
2.1.1 जमाराशियां	10.0	5.4	6.2	10.0	10.0
2.1.2 ऋण	13.3	10.8	10.0	14.7	13.3
2.1.2.1 गैर-खाद्यान्न ऋण	13.3	11.1	10.2	14.6	13.3
2.1.3 सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	1.8	2.7	9.5	-1.2	1.8
2.2 मुद्रा स्टॉक मात्रा					
2.2.1 आरक्षित मुद्रा (एम0)	14.5	39.3	27.3	16.5	14.5
2.2.2 स्थूल मुद्रा (एम3)	10.5	9.9	9.2	10.8	10.5
3 अनुपात (%)					
3.1 आरक्षित नकदी निधि अनुपात	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
3.2 सांविधिक चलनिधि अनुपात	19.25	19.50	19.50	19.25	19.25
3.3 नकदी-जमा अनुपात	5.1	4.8	5.1	4.7	5.1
3.4 ऋण-जमा अनुपात	77.7	74.9	75.5	78.1	77.7
3.5 वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात	99.8	166.0	117.3	123.5	99.8
3.6 निवेश-जमा अनुपात	26.9	30.8	29.0	27.6	26.9
3.7 वृद्धिशील निवेश-जमा अनुपात	5.3	147.4	43.0	3.6	5.3
4 ब्याज दरें (%)					
4.1 नीति रिपो दर	6.25	6.00	6.00	6.25	6.25
4.2 रिवर्स रिपो दर	6.00	5.75	5.75	6.00	6.00
4.3 सीमांत स्थायी सुविधा दर	6.50	6.25	6.25	6.50	6.50
4.4 बैंक दर	6.50	6.25	6.25	6.50	6.50
4.5 आधार दर	8.95/9.40	8.65/9.45	8.65/9.45	8.95/9.45	8.95/9.40
4.6 एमसीएलआर (एक दिन के लिए)	8.05/8.55	7.65/7.80	7.80/7.95	8.15/8.55	8.05/8.55
4.7 एक वर्ष से अधिक की मीयादी जमा दर	6.25/7.50	6.00/6.75	6.25/6.75	6.25/7.50	6.25/7.50
4.8 बचत जमा दर	3.50/4.00	3.50/4.00	3.50/4.00	3.50/4.00	3.50/4.00
4.9 मांग मुद्रा दर (भारित औसत)	6.35	5.94	6.15	6.29	6.35
4.10 91-दिवसीय ख़ज़ाना बिल (प्राथमिक) आय	6.31	6.36	6.11	6.40	6.31
4.11 182-दिवसीय ख़ज़ाना बिल (प्राथमिक) आय	6.35	6.50	6.33	6.48	6.35
4.12 364-दिवसीय ख़ज़ाना बिल (प्राथमिक) आय	6.39	6.66	6.49	6.55	6.39
4.13 10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों पर आय (एफबीआईएल)	7.34	7.70	7.42	7.41	7.34
5 आरबीआई संदर्भ दर और फारवर्ड प्रीमिआ					
5.1 भा.रु.-अमेरिकी डालर हाजिर दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	69.17	64.82	65.04	71.22	69.17
5.2 भा.रु.-यूरो हाजिर दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	77.70	79.76	80.62	80.75	77.70
5.3 फारवर्ड प्रीमिआ अमेरिकी डालर 1-माह (%)	6.07	4.26	4.61	4.13	6.07
3-माह (%)	4.80	4.50	4.37	4.38	4.80
6-माह (%)	4.16	4.13	4.21	4.16	4.16
6 मुद्रास्फीति (%)					
6.1 अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	2.86	4.4	4.3	2.6	2.9
6.2 औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	7.67	4.7	4.4	7.0	7.7
6.3 थोक मूल्य सूचकांक	3.18	2.7	2.7	2.9	3.2
6.3.1 प्राथमिक वस्तुएं	5.07	0.8	0.9	4.8	5.1
6.3.2 ईंधन और पावर	5.41	4.6	4.7	2.2	5.4
6.3.3 विनिर्मित उत्पाद	2.16	3.3	3.1	2.3	2.2
7 विदेशी व्यापार (% परिवर्तन)					
7.1 आयात	1.44	10.6	7.1	-4.2	1.4
7.2 निर्यात	11.02	5.3	-0.5	2.4	11.0

टिप्पणी : फाइनेंसियल बेंचमार्क इंडिया प्रा.लि. (एफबीआईएल) ने भारतीय रिजर्व बैंक के 31 मार्च 2018 के परिपत्र एफएमआरडी.डीआईआरडी.7/14.03.025/ 2017-18 के अनुसार जी सेक बेंचमार्क का प्रकाशन शुरू किया है। एफबीआईएल ने 10 जुलाई 2018 से संदर्भ दरों का प्रसार शुरू किया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक

सं. 2: भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां*

(बिलियन ₹)

मद	अंतिम शुक्रवार / शुक्रवार की स्थिति						
	2018-19	2018	2019				
		अप्रैल	मार्च 29	अप्रैल 5	अप्रैल 12	अप्रैल 19	अप्रैल 26
	1	2	3	4	5	6	7
1 निर्गम विभाग							
1.1 देयताएं							
1.1.1 संचलन में नोट	21,137.64	18,779.71	21,137.64	21,223.42	21,487.09	21,621.77	21,540.71
1.1.2 बैंकिंग विभाग में रखे गए नोट	0.11	0.12	0.11	0.09	0.12	0.12	0.12
1.1/1.2 कुल देयताएं (जारी किए गए कुल नोट) या आस्तियां	**21,137.75**	**18,779.84**	**21,137.75**	**21,223.51**	**21,487.21**	**21,621.89**	**21,540.83**
1.2 आस्तियां							
1.2.1 सोने के सिक्के और बुलियन	794.81	729.00	794.81	761.50	761.50	761.50	761.50
1.2.2 विदेशी प्रतिभूतियां	20,335.59	18,044.31	20,335.59	20,454.66	20,716.47	20,851.19	20,770.23
1.2.3 रुपया सिक्का	7.35	6.52	7.35	7.35	9.24	9.20	9.10
1.2.4 भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां	–	–	–	–	–	–	–
2 बैंकिंग विभाग							
2.1 देयताएं							
2.1.1 जमाराशियां	8,060.12	6,496.95	8,060.12	7,643.76	6,921.47	6,850.57	7,241.85
2.1.1.1 केंद्र सरकार	1.01	1.01	1.01	1.00	1.01	1.01	1.00
2.1.1.2 बाजार स्थिरीकरण योजना	–	–	–	–	–	–	–
2.1.1.3 राज्य सरकारें	0.43	0.43	0.43	0.42	0.42	0.42	0.42
2.1.1.4 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	5,657.07	4,900.62	5,657.07	5,074.67	5,047.00	5,404.21	5,229.44
2.1.1.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	41.97	42.50	41.97	38.61	38.44	38.08	41.55
2.1.1.6 गैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	34.94	20.63	34.94	26.08	26.27	25.23	26.19
2.1.1.7 अन्य बैंक	320.36	281.01	320.36	297.82	295.52	302.62	307.44
2.1.1.8 अन्य	1,997.34	1,250.76	1,997.34	2,191.06	1,498.98	1,079.00	1,608.02
2.1.1.9 भारत के बाहर के वित्तीय संस्थान	7.00	–	7.00	14.10	13.83	–	27.79
2.1.2 अन्य देयताएं	10,876.86	9,801.78	10,876.86	10,980.84	11,094.73	11,093.08	11,314.65
2.1/2.2 कुल देयताएं या आस्तियां	**18,936.98**	**16,298.72**	**18,936.98**	**18,624.60**	**18,016.20**	**17,943.65**	**18,556.50**
2.2 आस्तियां							
2.2.1 नोट और सिक्के	0.11	0.12	0.11	0.09	0.12	0.12	0.13
2.2.2 विदेश में रखे शेष	6,466.40	8,584.90	6,466.40	6,499.95	6,332.84	6,184.33	6,855.16
2.2.3 ऋण और अग्रिम							
2.2.3.1 केन्द्र सरकार	–	–	–	–	–	–	–
2.2.3.2 राज्य सरकारें	0.10	–	0.10	73.82	60.34	50.37	0.66
2.2.3.3 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	1,806.88	475.76	1,806.88	1,368.11	983.47	1,067.72	1,054.78
2.2.3.4 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	–	–	–	–	–	–	–
2.2.3.5 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	–	–	–	–	–	–	–
2.2.3.6 नाबार्ड	–	–	–	–	–	–	–
2.2.3.7 एक्जिम बैंक	–	–	–	–	–	–	–
2.2.3.8 अन्य	134.63	58.97	134.63	124.82	71.01	71.02	67.67
2.2.3.9 भारत के बाहर की वित्तीय संस्थाएं	7.00	–	7.00	–0.14	–	–	3.40
2.2.4 खरीदे और भुनाए गए बिल							
2.2.4.1 आंतरिक	–	–	–	–	–	–	–
2.2.4.2 सरकारी खज़ाना बिल	–	–	–	–	–	–	–
2.2.5 निवेश	9,230.80	6,290.30	9,230.80	9,294.23	9,294.64	9,295.04	9,295.35
2.2.6 अन्य आस्तियां	1,291.06	888.68	1,291.06	1,263.72	1,273.78	1,275.05	1,279.35
2.2.6.1 सोना	871.69	670.18	871.69	845.06	850.42	850.42	850.42

* डाटा अनंतिम है।

सं. 3: भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि परिचालन

(बिलियन ₹)

दिनांक	चलनिधि समायोजन सुविधा				एमएसएफ	स्थायी चलनिधि सुविधाएं	बाज़ार स्थिरीकरण योजना	ओएमओ (एकमुश्त)		निवल अंतर्वेशन (+)/ अवशोषण (-) (1+3+5+6+9-2-4-7-8)
	रिपो	रिवर्स रिपो	परिवर्तन-शील रिपो दर	परिवर्तन-शील रिवर्स रिपो दर				विक्रय	क्रय	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
मार्च 1, 2019	32.25	551.66	240.01	242.52	17.25	–	–	–	125.00	–379.67
मार्च 2, 2019	116.70	87.19	–	–	–	–	–	–	–	29.51
मार्च 4, 2019	–	131.96	–	–	3.72	–	–	–	–	–128.24
मार्च 5, 2019	47.91	188.66	37.65	495.90	7.25	–	–	–	–	–591.75
मार्च 6, 2019	35.16	138.80	250.02	427.61	9.35	–2.00	–	–	–	–273.88
मार्च 7, 2019	30.56	163.89	–	200.56	2.83	2.32	–	0.10	0.10	–328.74
मार्च 8, 2019	42.59	365.56	116.55	104.66	1.50	–	–	–	125.00	–184.58
मार्च 11, 2019	28.11	372.84	250.01	218.44	3.00	–	–	–	–	–310.16
मार्च 12, 2019	29.91	349.13	240.01	699.74	1.30	–0.89	–	–	–	–778.54
मार्च 13, 2019	79.21	127.26	–	849.90	4.88	4.84	–	–	–	–888.23
मार्च 14, 2019	30.53	223.04	250.03	852.44	20.01	0.33	–	0.10	0.10	–774.58
मार्च 15, 2019	39.40	411.65	75.00	–	14.41	1.23	–	–	125.00	–156.61
मार्च 16, 2019	143.60	37.46	–	–	108.50	–	–	–	–	214.64
मार्च 18, 2019	36.61	238.02	–	326.42	–	–	–	–	–	–527.83
मार्च 19, 2019	62.61	94.44	186.33	747.67	1.25	1.32	–	–	–	–590.60
मार्च 20, 2019	50.16	114.53	111.75	373.04	0.03	1.91	–	–	0.10	–323.62
मार्च 21, 2019	–	75.07	–	–	16.80	–	–	–	–	–58.27
मार्च 22, 2019	62.44	482.13	152.30	472.64	–	–1.91	–	0.05	0.15	–741.84
मार्च 25, 2019	58.19	559.32	–	310.04	2.01	1.91	–	–	–	–807.25
मार्च 26, 2019	38.81	508.49	195.60	425.38	–	–	–	–	–	–699.46
मार्च 27, 2019	108.88	409.66	–	531.70	1.70	–	–	–	–	–830.78
मार्च 28, 2019	64.61	469.84	–	698.23	39.40	–	–	0.05	0.15	–1,063.96
मार्च 29, 2019	146.85	782.58	243.00	–	128.82	–0.23	–	–	–	–264.14
मार्च 30, 2019	106.19	410.74	–	–	194.43	–	–	–	–	–110.12
मार्च 31, 2019	4.25	163.58	–	–	619.38	–	–	–	–	460.05

सं. 4: भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अमेरिकी डालर का क्रय/विक्रय

i) ओटीसी सेगमेन्ट में परिचालन

मद	2017-18	2018	2019	
		मार्च	फरवरी	मार्च
	1	2	3	4
1 विदेशी मुद्रा का निवल क्रय/विक्रय (मिलियन अमेरिकी डालर) (1.1-1.2)	33,689.00	996.00	825.00	9,408.00
1.1 क्रय (+)	52,068.00	3,328.00	2,086.00	10,306.00
1.2 विक्रय (-)	18,379.00	2,332.00	1,261.00	898.00
2 संविदा दर पर ₹ के बराबर (बिलियन ₹)	2,228.28	71.10	54.04	649.65
3 संचयी (मार्च के अंत से) (मिलियन अमेरिकी डालर)	33,689.00	33,689.00	–24,785.00	–15,377.00
(बिलियन ₹)	2,228.27	2,228.27	–1,769.10	–1,119.45
4 माह के अंत में बकाया निवल वायदा विक्रय (-)/क्रय (+) (मिलियन अमेरिकी डालर)	20,853.00	20,853.00	–4,372.00	–13,774.00

ii) मुद्रा फ्यूचर्स सेगमेन्ट में परिचालन

मद	2017-18	2018	2019	
		मार्च	फरवरी	मार्च
	1	2	3	4
1 विदेशी मुद्रा का निवल क्रय/विक्रय (मिलियन अमेरिकी डालर) (1.1-1.2)	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1 क्रय (+)	3,935.00	1,005.00	233.00	300.00
1.2 विक्रय (-)	3,935.00	1,005.00	233.00	300.00
2 माह के अंत में बकाया निवल मुद्रा वायदा विक्रय (-)/क्रय (+) (मिलियन अमेरिकी डालर)	0.00	0.00	–300.00	0.00

सं. 4ए: भारतीय रिज़र्व बैंक में बकाया वायदे का (अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार) परिपक्वता विश्लेषण (मिलियन अमेरिकी डॉलर)

(अमेरिकी मिलियन डालर)

मद	31 मार्च 2019 तक		
	दीर्घ (+)	अल्प (-)	निवल (1-2)
	1	2	3
1. 1 माह तक	2,115	2,377	-262
2. 1 माह से अधिक और 3 माह तक	3,138	3,895	-757
3. 3 माह से अधिक और 1 वर्ष तक	200	7,070	-6,870
4. 1 वर्ष से अधिक	0	5,885	-5,885
कुल (1+2+3+4)	**5,453**	**19,227**	**-13,774**

सं. 5: भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थायी सुविधाएं

(बिलियन ₹)

मद	नियत अंतिम शुक्रवार की स्थिति							
	2018-19	2018			2019			
		अप्रैल 27	नवंबर 23	दिसंबर 21	जनवरी 18	फरवरी 15	मार्च 29	अप्रैल 26
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 सीमांत स्थायी सुविधा	128.8	31.2	7.5	32.1	5.0	10.9	128.8	10.0
2.1 सीमा	–	–	–	–	–	–	–	–
2.2 बकाया	–	–	–	–	–	–	–	–
3.1 सीमा	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0	28.0
3.2 बकाया	26.8	23.5	21.2	20.8	17.0	17.9	26.8	23.5
4.1 सीमा	–	–	–	–	–	–	–	–
4.2 बकाया	–	–	–	–	–	–	–	–
5 कुल बकाया (1+2.2+3.2+4.2)	155.6	54.7	28.7	52.9	22.1	28.8	155.6	33.5

मुद्रा और बैंकिंग

सं. 6: मुद्रा स्टॉक मात्रा

(बिलियन ₹)

मद	मार्च 31 /माह के नियत अंतिम शुक्रवार/नियत शुक्रवार की बकाया स्थिति				
	2018-19	2018	2019		
		मार्च 30	फरवरी 15	मार्च 15	मार्च 29
	1	2	3	4	5
1 जनता के पास मुद्रा (1.1 + 1.2 + 1.3 - 1.4)	20,522.3	17,604.4	20,294.6	20,638.1	20,550.7
1.1 संचलन में नोट	21,108.8	18,044.2	20,798.9	21,156.9	21,137.6
1.2 रुपये सिक्के का संचलन	251.4	249.1	250.8	251.0	251.0
1.3 छोटे सिक्कों का संचलन	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
1.4 बैंकों के पास नकदी	845.4	696.4	762.6	777.2	845.4
2 जनता की जमाराशियां	16,580.5	15,103.2	14,274.7	14,324.3	16,667.4
2.1 बैंकों के पास मांग जमाराशियां	16,263.1	14,837.1	14,012.7	14,046.7	16,263.1
2.2 रिजर्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशियां	317.4	266.0	262.0	277.6	404.3
3 एम$_1$ (1+2)	**37,102.8**	**32,707.5**	**34,569.3**	**34,962.4**	**37,218.1**
4 डाकघर बचत बैंक जमाराशियां	1,348.6	1,092.1	1,256.2	1,348.6	1,348.6
5 एम$_2$ (3+4)	**38,451.5**	**33,799.6**	**35,825.5**	**36,311.1**	**38,566.7**
6 बैंकों के पास मीयादी जमाराशियां	117,205.9	106,952.6	114,829.0	115,896.7	117,205.9
7 एम$_3$ (3+6)	**154,308.7**	**139,660.1**	**149,398.3**	**150,859.1**	**154,424.0**
8 कुल डाकघर जमाराशियां	3,579.5	3,008.1	3,372.6	3,579.5	3,579.5
9 एम$_4$ (7+8)	**157,888.3**	**142,668.1**	**152,770.9**	**154,438.6**	**158,003.5**

सं. 7: मुद्रा स्टॉक (एम$_3$) का स्रोत

(बिलियन ₹)

स्रोत	मार्च 31 / माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/ नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2018-19	2018	2019		
		मार्च 30	फरवरी 15	मार्च 15	मार्च 29
	1	2	3	4	5
1 सरकार को निवल बैंक ऋण	**43,877.9**	**39,909.8**	**44,334.5**	**45,211.4**	**44,315.8**
1.1 आरबीआई का सरकार को निवल ऋण (1.1.1-1.1.2)	8,019.5	4,655.5	8,730.5	9,213.3	8,457.4
1.1.1 सरकार पर दावे	9,296.9	6,350.3	8,755.5	9,234.8	9,218.6
1.1.1.1 केन्द्र सरकार	9,281.7	6,342.9	8,714.6	9,217.9	9,218.5
1.1.1.2 राज्य सरकारें	15.2	7.4	40.9	16.9	0.1
1.1.2 आरबीआई के पास सरकार की जमाराशियां	1,277.4	1,694.8	25.0	21.6	761.2
1.1.2.1 केन्द्र सरकार	1,276.9	1,688.3	24.6	21.1	760.8
1.1.2.2 राज्य सरकारें	0.4	6.5	0.4	0.4	0.4
1.2 सरकार को अन्य बैंक ऋण	35,858.4	35,254.4	35,604.0	35,998.1	35,858.4
2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण	**103,801.8**	**92,137.2**	**100,387.5**	**101,543.1**	**103,801.9**
2.1 आरबीआई का वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	153.6	140.3	80.7	88.1	153.8
2.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को अन्य बैंकों द्वारा दिया गया ऋण	103,648.2	91,996.9	100,306.8	101,455.0	103,648.2
2.2.1 वाणिज्यिक बैंकों द्वारा बैंक ऋण	97,691.9	86,254.2	94,403.6	95,537.1	97,691.9
2.2.2 सहकारी बैंकों द्वारा बैंक ऋण	5,859.3	5,666.0	5,817.2	5,835.8	5,859.3
2.2.3 वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों द्वारा अन्य प्रतिभूतियों में निवेश	97.0	76.7	86.0	82.1	97.0
3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (3.1 + 3.2)	**29,778.6**	**29,211.9**	**29,642.9**	**29,365.2**	**29,759.1**
3.1 आरबीआई की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (3.1.1-3.1.2)	28,485.9	27,596.8	28,350.2	28,072.5	28,466.4
3.1.1 सकल विदेशी आस्तियां	28,488.0	27,598.8	28,352.4	28,074.8	28,468.5
3.1.2 विदेशी देयताएं	2.1	2.1	2.3	2.3	2.1
3.2 अन्य बैंकों की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	1,292.7	1,615.1	1,292.7	1,292.7	1,292.7
4 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	**258.9**	**256.5**	**258.2**	**258.4**	**258.4**
5 बैंकिंग क्षेत्र की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं	**23,408.4**	**21,855.3**	**25,224.8**	**25,519.0**	**23,711.2**
5.1 आरबीआई की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं	10,588.0	8,982.0	11,466.8	10,819.0	10,506.0
5.2 अन्य बैंकों की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं (अवशिष्ट)	12,820.4	12,873.4	13,758.0	14,700.1	13,205.2
एम$_3$ (1+2+3+4-5)	**154,308.7**	**139,660.1**	**149,398.3**	**150,859.1**	**154,424.0**

सं. 8: मौद्रिक सर्वेक्षण

(बिलियन ₹)

मद	मार्च 31/माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/ नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2018-19	2018	2019		
		मार्च 30	फरवरी 15	मार्च 15	मार्च 29
	1	2	3	4	5
मौद्रिक समुच्चय					
एन एम$_1$ (1.1 + 1.2.1+1.3)	37,102.4	32,707.5	34,569.3	34,962.4	37,218.1
एन एम$_2$ (एन एम$_1$ + 1.2.2.1)	89,108.3	80,176.3	85,542.9	86,414.3	89,224.0
एन एम$_3$ (एन एम$_2$ + 1.2.2.2 + 1.4 = 2.1 + 2.2 + 2.3 - 2.4 - 2.5)	156,451.6	141,850.9	151,455.6	153,032.0	156,567.4
1 घटक					
1.1 जनता के पास मुद्रा	20,521.9	17,604.4	20,294.6	20,638.1	20,550.7
1.2. निवासियों की कुल जमाराशियां	131,831.8	120,323.4	127,287.5	128,384.1	131,831.8
1.2.1 मांग जमाराशियां	16,263.1	14,837.1	14,012.7	14,046.7	16,263.1
1.2.2 निवासियों की सावधि जमाराशियां	115,568.7	105,486.3	113,274.8	114,337.4	115,568.7
1.2.2.1 अल्पावधि सावधि जमाराशियां	52,005.9	47,468.8	50,973.7	51,451.8	52,005.9
1.2.2.1.1 जमा प्रमाण-पत्र	2,849.9	1,931.1	2,173.1	2,552.6	2,849.9
1.2.2.2 दीर्घावधि सावधि जमाराशियां	63,562.8	58,017.4	62,301.2	62,885.6	63,562.8
1.3 भा.रि.बैं. के पास 'अन्य' जमाराशियां	317.4	266.0	262.0	277.6	404.3
1.4 वित्तीय संस्थाओं से मांग/सावधि निधीयन	3,780.5	3,657.1	3,611.5	3,732.2	3,780.5
2 स्रोत					
2.1 देशी ऋण	156,561.0	139,837.2	153,425.0	155,940.3	156,999.0
2.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	43,877.9	39,909.8	44,334.5	45,211.4	44,315.8
2.1.1.1 सरकार को निवल भा.रि.बैं. ऋण	8,019.5	4,655.5	8,730.5	9,213.3	8,457.4
2.1.1.2 बैंकिंग प्रणाली द्वारा सरकार को ऋण	35,858.4	35,254.4	35,604.0	35,998.1	35,858.4
2.1.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण	112,683.1	99,927.3	109,090.5	110,729.0	112,683.2
2.1.2.1 वाणिज्यिक क्षेत्र को भा.रि.बैंक ऋण	153.6	140.3	80.7	88.1	153.8
2.1.2.2 बैंकिंग प्रणाली द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	112,529.4	99,787.1	109,009.8	110,640.9	112,529.4
2.1.2.2.1 अन्य निवेश (गैर-एसएलआर प्रतिभूतियां)	8,798.5	7,728.5	8,581.7	9,078.2	8,798.5
2.2 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	258.4	256.5	258.2	258.4	258.4
2.3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	28,017.3	26,920.6	27,553.6	27,314.1	27,997.7
2.3.1 भा.रि.बैं. की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	28,485.9	27,596.8	28,350.2	28,072.5	28,466.4
2.3.2 बैकिंग प्रणाली की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	–468.6	–676.2	–796.6	–758.4	–468.6
2.4 पूंजी खाता	23,467.4	20,717.1	23,877.9	23,450.8	23,538.1
2.5 अन्य मदें (निवल)	4,917.6	4,446.3	5,903.3	7,030.0	5,149.7

सं. 9: कुल चलनिधि राशियां

(बिलियन ₹)

समुच्चय	2018-19	2018	2019		
		मार्च	जनवरी	फरवरी	मार्च
	1	2	3	4	5
1 एन एम$_3$	**156,451.6**	**141,816.7**	**149,656.6**	**151,455.6**	**156,451.6**
2 डाकघर जमाराशियां	3,579.5	3,008.1	3,529.2	3,579.5	3,579.5
3 एल$_1$ (1 + 2)	**160,031.2**	**144,824.7**	**153,185.8**	**155,035.1**	**160,031.2**
4 वित्तीय संस्थाओं की देयताएं	29.3	29.3	29.3	29.3	29.3
4.1 सावधि मुद्रा उधार	26.6	26.6	26.6	26.6	26.6
4.2 जमा प्रमाण-पत्र	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
4.3 सावधि जमाराशियां	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
5 एल$_2$ (3 + 4)	**160,060.5**	**144,854.0**	**153,215.1**	**155,064.4**	**160,060.5**
6 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पास जनता की जमाराशियां	319.1	319.1	..	..	319.1
7 एल$_3$ (5 + 6)	**160,379.5**	**145,173.1**	..	..	**160,379.5**

सं. 10: भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वेक्षण

(बिलियन ₹)

मद	मार्च 31/माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/ नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2018-19	2018	2019		
		मार्च 30	फरवरी 15	मार्च 15	मार्च 29
	1	2	3	4	5
1 घटक					
1.1 संचलन में मुद्रा	21,367.7	18,300.7	21,057.2	21,415.3	21,396.1
1.2 भा.रि.बैं. के पास बैंकरों की जमाराशियां	6,019.7	5,636.3	5,262.4	5,951.7	6,054.3
1.2.1 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	5,585.0	5,256.9	4,918.4	5,599.9	5,657.1
1.3 भा.रि.बैं. के पास 'अन्य' जमाराशियां	317.4	266.0	262.0	277.6	404.3
आरक्षित मुद्रा (1.1+1.2+1.3=2.1+2.2+2.3-2.4-2.5)	27,704.4	24,203.0	26,581.6	27,644.6	27,854.7
2 स्रोत					
2.1 भा.रि.बैं.के देशी ऋण	9,548.0	5,331.7	9,439.9	10,132.6	9,636.0
2.1.1 सरकार को निवल भा.रि.बैं. ऋण	8,019.5	4,655.5	8,730.5	9,213.3	8,457.4
2.1.1.1 केन्द्र सरकार को निवल भा.रि.बैं. ऋण (2.1.1.1.1+2.1.1.1.2+2.1.1.1.3+2.1.1.1.4-2.1.1.1.5)	8,004.7	4,654.6	8,690.0	9,196.8	8,457.8
2.1.1.1.1 केन्द्र सरकार को ऋण और अग्रिम	–	–	–	–	–
2.1.1.1.2 खज़ाना बिलों में निवेश	–	–	–	–	–
2.1.1.1.3 दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	9,274.3	6,336.1	8,706.7	9,210.3	9,211.2
2.1.1.1.3.1 केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां	9,274.3	6,336.1	8,706.7	9,210.3	9,211.2
2.1.1.1.4 रुपया सिक्के	7.4	6.8	7.9	7.6	7.4
2.1.1.1.5 केन्द्र सरकार की जमाराशियां	1,276.9	1,688.3	24.6	21.1	760.8
2.1.1.2 राज्य सरकारों को निवल भा.रि.बैं. ऋण	14.8	0.9	40.5	16.5	-0.3
2.1.2 बैंकों पर भा.रि.बैं. के दावे	1,374.9	536.0	628.8	831.3	1,024.8
2.1.2.1 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को ऋण और अग्रिम	1,374.9	535.7	628.8	831.3	1,024.8
2.1.3 वाणिज्यिक क्षेत्र को भा.रि.बैं. के ऋण	153.6	140.3	80.7	88.1	153.8
2.1.3.1 प्राथमिक व्यापारियों को ऋण और अग्रिम	26.8	25.4	17.9	23.8	26.8
2.1.3.2 नाबार्ड को ऋण और अग्रिम	–	–	–	–	–
2.2 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	258.4	256.5	258.2	258.4	258.4
2.3 भा.रि.बैं. की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	28,485.9	27,596.8	28,350.2	28,072.5	28,466.4
2.3.1 सोना	1,595.9	1,407.2	1,617.1	1,666.5	1,666.5
2.3.2 विदेशी मुद्रा आस्तियां	26,890.2	26,189.8	26,733.3	26,406.2	26,800.0
2.4 पूंजी खाता	9,702.7	8,596.1	10,529.4	9,865.6	9,773.3
2.5 अन्य मदें (निवल)	885.3	385.8	937.4	953.4	732.7

सं. 11: आरक्षित मुद्रा - घटक और स्रोत

(बिलियन ₹)

मद	2018-19	मार्च 31/माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया						
		2018	2019					
		मार्च 30	फरवरी 22	मार्च 1	मार्च 8	मार्च 15	मार्च 22	मार्च 29
	1	2	3	4	5	6	7	8
आरक्षित मुद्रा (1.1 + 1.2 + 1.3 = 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 - 2.6)	27,704.8	24,203.0	26,718.3	26,655.0	26,769.4	27,644.6	27,004.4	27,854.7
1 घटक								
1.1 संचलन में मुद्रा	21,367.7	18,300.7	21,074.2	21,060.5	21,318.4	21,415.3	21,479.6	21,396.1
1.2 भा.रि.बैं. के पास बैंकरों की जमाराशियां	6,019.7	5,636.3	5,381.0	5,318.4	5,179.0	5,951.7	5,255.1	6,054.3
1.3 भा.रि.बैं. के पास 'अन्य' जमाराशियां	317.4	266.0	263.0	276.1	272.0	277.6	269.7	404.3
2 स्रोत								
2.1 सरकार को निवल रिजर्व बैंक ऋण	8,019.5	4,655.5	8,280.3	9,140.6	9,109.5	9,213.3	8,792.1	8,457.4
2.2 बैंकों को रिज़र्व बैंक ऋण	1,374.9	536.0	1,205.8	188.5	244.7	831.3	573.6	1,024.8
2.3 वाणिज्यिक क्षेत्र को रिज़र्व बैंक ऋण	153.6	140.3	78.8	78.7	82.0	88.1	96.2	153.8
2.4 भा.रि.बैं. की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	28,485.9	27,596.8	28,404.0	28,457.4	28,131.4	28,072.5	27,908.5	28,466.4
2.5 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	258.9	256.5	258.4	258.4	258.4	258.4	258.4	258.4
2.6 भा.रि.बैं. की निवल गैर मौद्रिक देयताएं	10,588.0	8,982.0	11,509.1	11,468.6	11,056.6	10,819.0	10,624.4	10,506.0

सं. 12: वाणिज्यिक बैंक सर्वेक्षण

(बिलियन ₹)

मद	माह के नियत अंतिम शुक्रवार / माह के नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2018-19	2018	2019		
		मार्च 30	फरवरी 15	मार्च 15	मार्च 29
	1	2	3	4	5
1 घटक					
1.1 निवासियों की कुल जमाराशियां	124,088.4	112,794.2	119,640.5	120,703.3	124,088.4
1.1.1 मांग जमाराशियां	15,110.8	13,702.8	12,877.2	12,907.8	15,110.8
1.1.2 निवासियों की सावधि जमाराशियां	108,977.5	99,091.4	106,763.3	107,795.5	108,977.5
1.1.2.1 अल्पावधि सावधि जमाराशियां	49,039.9	44,591.1	48,043.5	48,508.0	49,039.9
1.1.2.1.1 जमा प्रमाण-पत्र	2,849.9	1,931.1	2,173.1	2,552.6	2,849.9
1.1.2.2 दीर्घावधि सावधि जमाराशियां	59,937.6	54,500.3	58,719.8	59,287.5	59,937.6
1.2 वित्तीय संस्थाओं से मांग/सावधि निधीयन	3,780.5	3,657.1	3,611.5	3,732.2	3,780.5
2 स्रोत					
2.1 देशी ऋण	140,289.7	127,142.0	136,568.6	138,568.6	140,289.7
2.1.1 सरकार को ऋण	33,783.0	33,174.1	33,537.0	33,922.6	33,783.0
2.1.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	106,506.7	93,967.9	103,031.6	104,646.0	106,506.7
2.1.2.1 बैंक ऋण	97,691.9	86,254.2	94,403.6	95,537.1	97,691.9
2.1.2.1.1 गैर-खाद्यान्न ऋण	97,275.8	85,834.4	93,786.2	95,010.3	97,275.8
2.1.2.2 प्राथमिक व्यापारियों को निवल ऋण	85.4	64.3	123.9	110.3	85.4
2.1.2.3 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश	20.5	10.5	12.0	10.1	20.5
2.1.2.4 अन्य निवेश (गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में)	8,708.9	7,638.9	8,492.1	8,988.6	8,708.9
2.2 वाणिज्यिक बैंकों की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (2.2.1-2.2.2-2.2.3)	–468.6	–676.2	–796.6	–758.4	–468.6
2.2.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	2,623.8	2,018.0	2,099.2	2,222.3	2,623.8
2.2.2 अनिवासी विदेशी मुद्रा प्रत्यावर्तनीय मीयादी जमाराशियां	1,637.2	1,466.3	1,554.2	1,559.3	1,637.2
2.2.3 समुद्रपार विदेशी मुद्रा उधार	1,455.3	1,227.9	1,341.6	1,421.5	1,455.3
2.3 निवल बैंक रिज़र्व (2.3.1+2.3.2-2.3.3)	5,380.8	5,321.8	4,955.9	5,449.2	5,380.8
2.3.1 भा.रि.बैं. के पास शेष	5,657.1	5,256.9	4,918.4	5,599.9	5,657.1
2.3.2 उपलब्ध नकदी	748.5	600.6	666.3	680.7	748.5
2.3.3 भा.रि.बैं. से ऋण और अग्रिम	1,024.8	535.7	628.8	831.3	1,024.8
2.4 पूंजी खाता	13,523.1	11,879.3	13,106.9	13,343.6	13,523.1
2.5 अन्य मदें (निवल) (2.1+2.2+2.3-2.4-1.1-1.2)	3,809.9	3,457.1	4,369.1	5,480.3	3,809.9
2.5.1 अन्य मांग और मीयादी देयताएं (2.2.3 का निवल)	3,979.8	4,360.8	3,825.3	4,558.4	3,979.8
2.5.2 निवल अंतर-बैंक देयताएं (प्राथमिक व्यापारियों से इतर)	–484.5	–268.2	–524.5	–524.0	–484.5

सं. 13: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के निवेश

(बिलियन ₹)

मद	29 मार्च, 2019 की स्थिति	2018	2019		
		मार्च 30	फरवरी 15	मार्च 15	मार्च 29
	1	2	3	4	5
1 एसएलआर प्रतिभूतियां	33,803.6	33,184.5	33,548.6	33,932.6	33,803.5
2 वाणिज्यिक पत्र	903.6	1,159.4	964.7	976.3	903.6
3 निम्नलिखित द्वारा जारी शेयर					
3.1 सरकारी उद्यम	115.4	118.7	115.8	117.5	115.4
3.2 निजी कारपोरेट क्षेत्र	695.9	745.3	720.7	708.2	695.9
3.3 अन्य	63.8	42.1	62.1	59.9	63.8
4 निम्नलिखित द्वारा जारी बांड / डिबेंचर					
4.1 सरकारी उद्यम	1,348.2	1,399.7	1,194.6	1,346.1	1,348.2
4.2 निजी कारपोरेट क्षेत्र	2,687.8	2,222.3	2,534.1	2,579.9	2,687.8
4.3 अन्य	1,700.5	994.6	1,393.6	1,655.8	1,700.5
5 निम्नलिखित द्वारा जारी लिखत					
5.1 म्यूचुअल फंड	209.9	177.3	569.6	549.2	209.9
5.2 वित्तीय संस्थाएं	983.8	895.8	936.5	995.6	983.8

सं. 14: भारत में कारोबार - सभी अनुसूचित बैंक और सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

(बिलियन ₹)

मद	नियत अंतिम शुक्रवार (मार्च के संबंध में) / नियत शुक्रवार की स्थिति							
	सभी अनुसूचित बैंक				सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक			
	2018-19	2018	2019		2018-19	2018	2019	
		मार्च	फरवरी	मार्च		मार्च	फरवरी	मार्च
	1	2	3	4	5	6	7	8
सूचना देने वाले बेंकों की संख्या	220	223	222	220	146	149	148	146
1 बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं	**2,755.5**	**2,344.9**	**2,550.9**	**2,755.5**	**2,706.2**	**2,282.0**	**2,505.7**	**2,706.2**
1.1 बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां	1,809.8	1,667.5	1,609.5	1,809.8	1,761.5	1,615.6	1,565.8	1,761.5
1.2 बैंकों से उधार राशि	793.6	611.7	851.3	793.6	793.4	601.2	850.7	793.4
1.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	152.1	65.7	90.1	152.1	151.3	65.2	89.3	151.3
2 अन्य के प्रति देयताएं	**138,343.1**	**126,658.9**	**132,933.9**	**138,343.1**	**134,941.1**	**123,506.3**	**129,637.4**	**134,941.1**
2.1 कुल जमाराशियां	129,003.4	117,285.4	124,094.7	129,003.4	125,725.5	114,260.5	120,932.9	125,725.5
2.1.1 मांग	15,422.7	13,994.8	12,941.9	15,422.7	15,110.8	13,702.8	12,653.1	15,110.8
2.1.2 मीयादी	113,580.7	103,290.6	111,152.9	113,580.7	110,614.7	100,557.7	108,279.8	110,614.7
2.2 उधार	3,816.6	3,693.9	3,689.9	3,816.6	3,780.5	3,657.1	3,647.2	3,780.5
2.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	5,523.1	5,679.7	5,149.3	5,523.1	5,435.0	5,588.7	5,057.3	5,435.0
3 रिज़र्व बैंक से उधार	**1,806.9**	**2,740.1**	**1,474.0**	**1,806.9**	**1,806.9**	**2,739.8**	**1,474.0**	**1,806.9**
3.1 मीयादी बिल / वचन पत्रों की जमानत पर	–	–	–	–	–	–	–	–
3.2 अन्य	1,806.9	2,740.1	1,474.0	1,806.9	1,806.9	2,739.8	1,474.0	1,806.9
4 उपलब्ध नकदी और रिज़र्व बैंक के पास शेष	6,575.3	6,029.2	5,884.4	6,575.3	6,405.6	5,857.5	5,744.2	6,405.6
4.1 उपलब्ध नकदी	765.3	616.3	727.8	765.3	748.52	600.6	710.8	748.5
4.2 रिज़र्व बैंक के पास शेष	5,810.0	5,412.9	5,156.5	5,810.0	5,657.1	5,256.9	5,033.4	5,657.1
5 बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां	**3,722.5**	**3,011.8**	**3,706.8**	**3,722.5**	**3,276.1**	**2,614.6**	**3,180.8**	**3,276.1**
5.1 अन्य बैंकों के पास शेष	2,447.1	2,041.9	2,381.2	2,447.1	2,230.1	1,860.5	2,170.4	2,230.1
5.1.1 चालू खाते में	167.4	156.0	139.7	167.4	133.0	123.1	112.4	133.0
5.1.2 अन्य खातों में	2,279.7	1,885.9	2,241.5	2,279.7	2,097.2	1,737.4	2,058.1	2,097.2
5.2 मांग और अल्पसूचना पर मुद्रा	478.0	360.5	548.9	478.0	320.9	182.4	312.1	320.9
5.3 बैंकों को अग्रिम	329.5	284.1	348.6	329.5	296.4	282.0	305.5	296.4
5.4 अन्य आस्तियां	467.9	325.3	428.2	467.9	428.8	289.6	392.9	428.8
6 निवेश	**34,749.0**	**34,124.7**	**34,365.8**	**34,749.0**	**33,803.5**	**33,184.5**	**33,427.0**	**33,803.5**
6.1 सरकारी प्रतिभूतियां	34,671.4	34,067.4	34,300.5	34,671.4	33,783.0	33,174.1	33,416.3	33,783.0
6.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	77.6	57.3	65.2	77.6	20.5	10.5	10.7	20.5
7 बैंक ऋण	**100,555.4**	**88,785.3**	**97,295.4**	**100,555.4**	**97,691.9**	**86,254.2**	**94,497.4**	**97,691.9**
7क खाद्यान्न ऋण	646.4	611.4	823.4	646.4	416.1	419.9	593.1	416.1
7.1 ऋण, नकदी-ऋण और ओवरड्राफ्ट	98,007.1	86,451.5	94,948.8	98,007.1	95,194.6	83,984.8	92,200.4	95,194.6
7.2 देशी बिल - खरीदे गए	276.4	230.3	240.8	276.4	262.2	203.9	226.1	262.2
7.3 देशी बिल- भुनाए गए	1,609.8	1,417.3	1,489.2	1,609.8	1,583.0	1,387.5	1,463.4	1,583.0
7.4 विदेशी बिल - खरीदे गए	249.1	266.0	231.2	249.1	245.8	263.0	228.0	245.8
7.5 विदेशी बिल - भुनाए गए	413.0	420.3	385.3	413.0	406.2	415.0	379.5	406.2

सं. 15: प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक ऋण का विनियोजन

(बिलियन ₹)

मद	बकाया स्थिति				वृद्धि (%)	
	मार्च 30, 2018	2018	2019		वित्तीय वर्ष में अब तक	वर्ष-दर-वर्ष
		मार्च 30	फरवरी 15	मार्च 29	2018-19	2019
	1	2	3	4	5	6
1 सकल बैंक ऋण	**77,303**	**77,303**	**83,681**	**86,749**	**12.2**	**12.2**
1.1 खाद्यान्न ऋण	**419**	**419**	**615**	**415**	**–0.9**	**-0.9**
1.2 गैर-खाद्यान्न ऋण	**76,884**	**76,884**	**83,065**	**86,334**	**12.3**	**12.3**
1.2.1 कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां	**10,302**	**10,302**	**10,928**	**11,113**	**7.9**	**7.9**
1.2.2 उद्योग	**26,993**	**26,993**	**27,743**	**28,858**	**6.9**	**6.9**
1.2.2.1 सूक्ष्म और लघु	3,730	3,730	3,727	3,755	0.7	0.7
1.2.2.2 मझौले	1,037	1,037	1,034	1,064	2.6	2.6
1.2.2.3 बड़े	22,226	22,226	22,982	24,039	8.2	8.2
1.2.3 सेवाएं	**20,505**	**20,505**	**22,762**	**24,156**	**17.8**	**17.8**
1.2.3.1 परिवहन परिचालक	1,213	1,213	1,349	1,385	14.2	14.2
1.2.3.2 कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	186	186	192	185	–0.4	-0.4
1.2.3.3 पर्यटन, होटल और रेस्तरां	365	365	386	390	6.9	6.9
1.2.3.4 नौवहन	63	63	74	77	22.8	22.8
1.2.3.5 पेशेवर सेवाएं	1,554	1,554	1,781	1,715	10.4	10.4
1.2.3.6 व्यापार	4,669	4,669	5,047	5,282	13.1	13.1
1.2.3.6.1 थोक व्यापार	2,052	2,052	2,243	2,505	22.1	22.1
1.2.3.6.2 खुदरा व्यापार	2,618	2,618	2,804	2,776	6.1	6.1
1.2.3.7 वाणिज्यिक स्थावर संपदा	1,858	1,858	1,988	2,023	8.9	8.9
1.2.3.8 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसी)	4,964	4,964	5,754	6,412	29.2	29.2
1.2.3.9 अन्य सेवाएं	5,633	5,633	6,191	6,686	18.7	18.7
1.2.4 व्यक्तिगत ऋण	**19,085**	**19,085**	**21,633**	**22,207**	**16.4**	**16.4**
1.2.4.1 उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	197	197	45	63	–68.0	-68.0
1.2.4.2 आवास	9,746	9,746	11,349	11,601	19.0	19.0
1.2.4.3 मीयादी जमाराशि की जमानत पर अग्रिम	725	725	706	829	14.3	14.3
1.2.4.4 शेयरों और बाडों की जमानत पर व्यक्तियों को अग्रिम	56	56	59	63	12.8	12.8
1.2.4.5 क्रेडिट कार्ड बकाया	686	686	834	883	28.6	28.6
1.2.4.6 शिक्षा	697	697	689	680	–2.5	-2.5
1.2.4.7 वाहन ऋण	1,898	1,898	2,005	2,022	6.5	6.5
1.2.4.8 अन्य व्यक्तिगत ऋण	5,080	5,080	5,946	6,068	19.4	19.4
1.2अ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	**25,532**	**25,532**	**26,829**	**27,390**	**7.3**	**7.3**
1.2अ.1 कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां	10,216	10,216	10,863	11,050	8.2	8.2
1.2अ.2 सूक्ष्म और लघु उद्यम	9,964	9,964	10,266	10,672	7.1	7.1
1.2अ.2.1 विनिर्माण	3,730	3,730	3,727	3,755	0.7	0.7
1.2अ.2.2 सेवाएं	6,234	6,234	6,540	6,917	11.0	11.0
1.2अ.3 आवास	3,756	3,756	4,332	4,327	15.2	15.2
1.2अ.4 माइक्रो क्रेडिट	264	264	243	241	–8.5	-8.5
1.2अ.5 शिक्षा ऋण	607	607	563	540	–11.1	-11.1
1.2अ.6 अजा/अजजा के लिए राज्य प्रायोजित संस्थाएं	3	3	4	4	34.1	34.1
1.2अ.7 कमजोर वर्ग	5,690	5,690	6,149	6,626	16.4	16.4
1.2अ.8 निर्यात ऋण	283	283	165	156	–45.0	-45.0

सं. 16: सकल बैंक ऋण का उद्योग-वार विनियोजन

(बिलियन ₹)

उद्योग	बकाया स्थिति				वृद्धि (%)	
	मार्च 30, 2018	2018	2019		वित्तीय वर्ष में अब तक	वर्ष-दर-वर्ष
		मार्च 30	फरवरी 15	मार्च 29	2018-19	2019
	1	2	3	4	5	6
1 उद्योग	**26,993**	**26,993**	**27,743**	**28,858**	**6.9**	**6.9**
1.1 खनन और उत्खनन (कोयला सहित)	**413**	**413**	**415**	**418**	**1.1**	**1.1**
1.2 खाद्य प्रसंस्करण	**1,554**	**1,554**	**1,547**	**1,571**	**1.1**	**1.1**
1.2.1 चीनी	290	290	284	297	2.6	2.6
1.2.2 खाद्य तेल और वनस्पति	211	211	214	213	1.1	1.1
1.2.3 चाय	45	45	50	50	11.6	11.6
1.2.4 अन्य	1,008	1,008	999	1,010	0.2	0.2
1.3 पेय पदार्थ और तंबाकू	**156**	**156**	**146**	**147**	**–5.9**	**–5.9**
1.4 वस्त्र	**2,099**	**2,099**	**2,013**	**2,035**	**–3.0**	**–3.0**
1.4.1 सूती वस्त्र	1,057	1,057	963	977	–7.6	–7.6
1.4.2 जूट से बने वस्त्र	22	22	21	21	–3.9	–3.9
1.4.3 मानव - निर्मित वस्त्र	243	243	266	267	10.0	10.0
1.4.4 अन्य वस्त्र	776	776	762	770	–0.9	–0.9
1.5 चमड़ा और चमड़े से बने उत्पाद	**113**	**113**	**110**	**111**	**–2.1**	**–2.1**
1.6 लकड़ी और लकड़ी से बने उत्पाद	**109**	**109**	**118**	**120**	**10.2**	**10.2**
1.7 काग़ज़ और काग़ज़ से बने उत्पाद	**306**	**306**	**302**	**303**	**–1.0**	**–1.0**
1.8 पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद और आण्विक इंधन	**651**	**651**	**557**	**631**	**–3.1**	**–3.1**
1.9 रसायन और रासायनिक उत्पाद	**1,630**	**1,630**	**1,830**	**1,915**	**17.5**	**17.5**
1.9.1 उवर्रक	306	306	283	400	30.9	30.9
1.9.2 औषधि और दवाइयां	484	484	507	505	4.4	4.4
1.9.3 पेट्रो केमिकल्स	387	387	509	467	20.7	20.7
1.9.4 अन्य	453	453	531	542	19.7	19.7
1.10 रबड़, प्लास्टिक और उनके उत्पाद	**424**	**424**	**452**	**458**	**8.1**	**8.1**
1.11 कांच और कांच के सामान	**85**	**85**	**100**	**99**	**17.0**	**17.0**
1.12 सीमेन्ट और सीमेन्ट से बने उत्पाद	**526**	**526**	**550**	**557**	**5.9**	**5.9**
1.13 मूल धातु और धातु उत्पाद	**4,160**	**4,160**	**3,707**	**3,716**	**–10.7**	**–10.7**
1.13.1 लोहा और स्टील	3,262	3,262	2,851	2,829	–13.3	–13.3
1.13.2 अन्य धातु और धातु से बने उत्पाद	898	898	856	887	–1.3	–1.3
1.14 सभी अभियांत्रिकी	**1,553**	**1,553**	**1,632**	**1,686**	**8.6**	**8.6**
1.14.1 इलेक्ट्रानिक्स	344	344	375	379	10.1	10.1
1.14.2 अन्य	1,210	1,210	1,257	1,308	8.1	8.1
1.15 वाहन, वाहन के पुर्जे और परिवहन उपस्कर	**787**	**787**	**799**	**799**	**1.4**	**1.4**
1.16 रत्न और आभूषण	**727**	**727**	**711**	**720**	**–0.9**	**–0.9**
1.17 निर्माण	**901**	**901**	**959**	**995**	**10.4**	**10.4**
1.18 इन्फ्रास्ट्रक्चर	**8,909**	**8,909**	**9,866**	**10,559**	**18.5**	**18.5**
1.18.1 पावर	5,196	5,196	5,544	5,690	9.5	9.5
1.18.2 दूरसंचार	846	846	915	1,156	36.7	36.7
1.18.3 सड़क	1,665	1,665	1,892	1,869	12.2	12.2
1.18.4 अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर	1,202	1,202	1,515	1,845	53.5	53.5
1.19 अन्य उद्योग	**1,890**	**1,890**	**1,930**	**2,020**	**6.8**	**6.8**

सं. 17: भारतीय रिज़र्व बैंक में राज्य सहकारी बैंकों के खाते

(बिलियन ₹)

मद	नियत अंतिम शुक्रवार (मार्च के संबधं में)/अंतिम शुक्रवार/नियत शुक्रवार की स्थिति								
	2017-18	2018		2019					
		फरवरी 23	दिसंबर 28	जनवरी 04	जनवरी 18	जनवरी 25	फरवरी 01	फरवरी 15	फरवरी 22
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
सूचना देने वाले बैंकों की संख्या	31	31	31	32	32	31	32	32	31
1 कुल जमाराशियां (2.1.1.2+2.2.1.2)	**540.9**	**540.3**	**553.5**	**576.0**	**572.6**	**552.7**	**573.8**	**587.8**	**610.2**
2 मांग और मीयादी देयताएं									
2.1 मांग देयताएं	**158.0**	**149.1**	**172.7**	**176.2**	**180.4**	**174.1**	**180.6**	**199.7**	**182.0**
2.1.1 जमाराशियां									
2.1.1.1 अंतर-बैंक	41.7	41.8	50.2	51.0	49.9	48.7	48.1	51.3	44.6
2.1.1.2 अन्य	89.9	84.4	90.4	93.8	93.1	90.2	93.9	95.4	100.8
2.1.2 बैंकों से उधार	1.2	0.0	2.5	3.1	8.6	8.7	3.7	4.4	4.6
2.1.3 अन्य मांग देयताएं	25.2	23.0	29.6	28.2	28.7	26.5	34.9	48.6	31.9
2.2 मीयादी देयताएं	**797.9**	**880.0**	**862.5**	**892.2**	**891.4**	**883.5**	**896.4**	**926.6**	**939.5**
2.2.1 जमाराशियां									
2.2.1.1 अंतर-बैंक	336.5	417.0	392.6	403.0	405.0	408.5	408.5	426.1	423.1
2.2.1.2 अन्य	451.0	455.9	463.1	482.2	479.5	462.4	479.9	492.4	509.4
2.2.2 बैंकों से उधार	3.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.4
2.2.3 अन्य मीयादी देयताएं	7.3	7.1	6.8	6.9	6.9	12.6	8.1	7.1	6.5
3 रिज़र्व बैंक से उधार	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4 अधिसूचित बैंक/राज्य सरकार से उधार	404.8	448.5	516.0	512.8	510.4	512.3	511.1	503.4	506.8
4.1 मांग	112.3	136.7	169.1	172.2	167.2	168.8	172.4	167.1	174.7
4.2 मीयादी	292.5	311.9	346.9	340.6	343.2	343.5	338.7	336.3	332.1
5 उपलब्ध नकदी और रिज़र्व बैंक के पास शेष	**55.6**	**45.0**	**45.9**	**45.7**	**46.0**	**46.4**	**48.2**	**48.2**	**48.9**
5.1 उपलब्ध नकदी	2.8	3.1	3.0	3.0	3.1	2.9	3.0	3.1	2.9
5.2 रिज़र्व बैंक के पास शेष	52.8	41.9	42.9	42.7	42.9	43.5	45.2	45.1	46.0
6 चालू खाते में अन्य बैंकों के पास शेष	**15.0**	**7.4**	**12.8**	**8.8**	**9.2**	**8.5**	**11.6**	**11.2**	**12.1**
7 सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	**295.6**	**286.2**	**309.1**	**316.6**	**318.5**	**313.0**	**317.3**	**312.3**	**307.3**
8 मांग और अल्प सूचना पर मुद्रा	**208.8**	**186.4**	**232.9**	**166.6**	**165.2**	**174.0**	**169.6**	**168.7**	**252.0**
9 बैंक ऋण (10.1+11)	**434.4**	**502.4**	**561.8**	**564.1**	**576.9**	**579.5**	**574.3**	**593.0**	**590.3**
10 अग्रिम									
10.1 ऋण, नकदी-ऋण और ओवरड्राफ्ट	**434.4**	**502.3**	**561.8**	**564.0**	**576.8**	**579.5**	**574.2**	**593.0**	**590.2**
10.2 बैकों से प्राप्य राशि	668.5	731.0	817.8	815.6	812.8	812.7	804.5	806.6	810.9
11 खरीदे और भुनाए गए बिल	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

मूल्य और उत्पादन

सं. 18: उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधारः 2012=100)

समूह/उप समूह	2018-19			ग्रामीण			शहरी			मिश्रित		
	ग्रामीण	शहरी	मिश्रित	मार्च 18	फर. 19	मार्च 19	मार्च 18	फर. 19	मार्च 19	मार्च 18	फर. 19	मार्च 19
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 खाद्य और पेय पदार्थ	**139.5**	**138.4**	**139.1**	**138.6**	**137.2**	**137.3**	**134.8**	**138.0**	**139.6**	**137.2**	**137.5**	**138.1**
1.1 अनाज और उत्पाद	137.8	137.2	137.6	136.8	136.8	137.0	135.0	139.4	139.7	136.2	137.6	137.9
1.2 मांस और मछली	149.5	147.5	148.8	143.8	153.0	154.1	143.1	150.1	151.1	143.6	152.0	153.0
1.3 अंडा	137.3	137.3	137.3	140.0	139.1	138.7	135.5	145.3	142.9	138.3	141.5	140.3
1.4 दूध और उत्पाद	142.7	141.3	142.2	142.0	142.5	142.5	139.9	141.7	141.9	141.2	142.2	142.3
1.5 तेल और चर्बी	124.0	117.6	121.6	123.2	124.1	124.1	116.5	118.4	118.4	120.7	122.0	122.0
1.6 फल	146.8	143.4	145.2	152.9	135.8	136.1	138.5	137.0	139.4	146.2	136.4	137.6
1.7 सब्जी	141.4	142.1	141.6	138.0	128.7	128.2	128.0	131.6	141.2	134.6	129.7	132.6
1.8 दाल और उत्पाद	124.1	115.3	121.1	129.3	121.5	122.3	115.5	119.9	120.7	124.6	121.0	121.8
1.9 चीनी और उत्पाद	111.9	110.8	111.5	117.1	108.3	108.3	114.2	110.4	110.4	116.1	109.0	109.0
1.10 मसाले	138.8	140.7	139.4	136.3	139.2	138.9	140.7	140.8	140.7	137.8	139.7	139.5
1.11 गैर नशीले पेय पदार्थ	134.9	127.5	131.8	131.2	137.4	137.5	126.2	128.3	128.5	129.1	133.6	133.7
1.12 तैयार भोजन, नाश्ता, मिठाई	155.3	151.3	153.5	152.8	156.2	156.5	147.6	153.5	153.9	150.4	154.9	155.3
2 पान, तंबाकू और मादक पदार्थ	**159.4**	**162.9**	**160.4**	**155.1**	**162.8**	**162.9**	**159.7**	**164.9**	**165.3**	**156.3**	**163.4**	**163.5**
3 कपड़ा और जूते	**150.3**	**139.3**	**145.9**	**148.3**	**149.9**	**150.2**	**135.2**	**141.4**	**141.6**	**143.1**	**146.5**	**146.8**
3.1 कपड़ा	151.2	141.0	147.2	149.2	150.5	150.8	136.7	143.3	143.5	144.3	147.7	147.9
3.2 जूते	145.2	129.5	138.7	143.0	146.1	146.1	126.7	130.8	131.2	136.2	139.7	139.9
4 आवास	**--**	**145.6**	**145.6**	**--**	**--**	**--**	**142.0**	**148.5**	**149.0**	**142.0**	**148.5**	**149.0**
5 ईंधन और लाइट	**147.0**	**129.3**	**140.3**	**142.6**	**145.3**	**146.5**	**126.4**	**127.1**	**128.8**	**136.5**	**138.4**	**139.8**
6 विविध	**138.6**	**131.1**	**134.9**	**133.3**	**142.2**	**142.4**	**127.1**	**132.4**	**132.8**	**130.3**	**137.4**	**137.7**
6.1 घरेलू सामान और सेवा	145.9	134.8	140.6	139.9	150.1	150.1	130.8	136.6	136.8	135.6	143.7	143.8
6.2 स्वास्थ्य	143.5	135.5	140.5	136.7	149.9	150.4	130.5	138.5	139.2	134.3	145.6	146.2
6.3 परिवहन और संचार	128.5	120.3	124.2	124.6	129.2	129.9	117.8	119.2	119.9	121.0	123.9	124.6
6.4 मनोरंजन	140.4	130.3	134.7	135.1	143.4	143.8	126.8	132.2	133.0	130.4	137.1	137.7
6.5 शिक्षा	149.4	144.5	146.5	142.7	155.5	155.6	137.8	146.6	146.7	139.8	150.3	150.4
6.6 व्यक्तिगत देखभाल और प्रभाव	132.6	129.9	131.5	129.3	134.9	134.0	126.7	133.0	132.5	128.2	134.1	133.4
सामान्य सूचकांक (सभी समूह)	**141.3**	**137.7**	**139.6**	**138.7**	**141.0**	**141.2**	**134.0**	**138.6**	**139.5**	**136.5**	**139.9**	**140.4**

स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

सं. 19: अन्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

मद	आधार वर्ष	योजक कारक	2018-19	2018	2019	
				मार्च	फरवरी	मार्च
	1	2	3	4	5	6
1 औद्योगिक कामगार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	2001	4.63	300	287	307	309
2 कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	1986-87	5.89	907	887	917	924
3 ग्रामीण श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	1986-87	–	915	894	925	932

स्रोत : श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार।

सं. 20: मुंबई में सोने और चांदी का मासिक औसत मूल्य

मद	2018-19	2018	2019	
		मार्च	फरवरी	मार्च
	1	2	3	4
1 मानक स्वर्ण (₹ प्रति 10 ग्राम)	31,193	30,420	33,217	32,036
2 चांदी (₹ प्रति किलोग्राम)	38,404	38,332	40,059	38,044

स्रोत : मुंबई में सोने और चांदी के मूल्य के लिए इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन लि. मुंबई।

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक

(आधारः 2011-12=100)

पण्य	भारांक	2018-19	2018	2019		
			मार्च	जनवरी	फरवरी (अ)	मार्च (अ)
	1	2	3	4	5	6
1 सभी पण्य	**100.000**	**119.8**	**116.3**	**119.2**	**119.5**	**120.0**
1.1 प्राथमिक वस्तुएं	**22.618**	**134.2**	**128.2**	**133.8**	**134.2**	**134.7**
1.1.1 खाद्य वस्तुएं	**15.256**	**143.7**	**137.3**	**144.2**	**143.8**	**145.1**
1.1.1.1 खाद्यान्न (अनाज+दाल)	3.462	146.7	140.5	151.8	153.9	153.4
1.1.1.2 फल और सब्जियाँ	3.475	147.6	132.3	140.5	136.2	144.4
1.1.1.3 दूध	4.440	143.1	140.7	143.4	142.9	143.2
1.1.1.4 अंडा, मांस और मछली	2.402	138.0	133.1	142.6	143.8	140.9
1.1.1.5 मसाले	0.529	129.6	128.0	129.1	127.7	125.5
1.1.1.6 अन्य खाद्य वस्तुएं	0.948	144.4	143.4	146.1	147.7	147.7
1.1.2 खाद्येतर वस्तुएं	**4.119**	**123.4**	**120.1**	**123.4**	**126.8**	**123.5**
1.1.2.1 फाइबर	0.839	127.0	119.1	127.2	125.3	127.6
1.1.2.2 तिलहन	1.115	140.5	138.7	144.1	146.9	145.5
1.1.2.3 अन्य खाद्येतर वस्तुएं	1.960	107.9	107.6	102.9	109.2	102.2
1.1.2.4 फूल	0.204	164.0	143.7	191.4	193.0	190.4
1.1.3 खनिज	**0.833**	**136.0**	**138.3**	**136.7**	**139.3**	**136.7**
1.1.3.1 धात्विक खनिज	0.648	122.3	126.1	123.4	126.2	123.4
1.1.3.2 अन्य खनिज	0.185	183.7	180.8	183.3	185.0	183.3
1.1.4 कच्चा तेल और नैसर्गिक गैस	**2.410**	**92.0**	**81.2**	**84.7**	**84.8**	**87.6**
1.2 ईंधन और बिजली	**13.152**	**104.2**	**98.0**	**99.3**	**101.0**	**103.3**
1.2.1 कोल	**2.138**	**123.3**	**122.6**	**123.6**	**123.6**	**123.6**
1.2.1.1 कुकिंग कोल	0.647	132.9	131.7	133.9	133.9	133.9
1.2.1.2 नॉन-कुकिंग कोल	1.401	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0
1.2.1.3 लिग्नाइट	0.090	120.3	113.5	120.0	120.0	121.2
1.2.2 खनिज तेल	**7.950**	**96.7**	**88.5**	**88.4**	**91.3**	**95.0**
1.2.3 बिजली	**3.064**	**110.1**	**105.4**	**110.7**	**110.7**	**110.7**
1.3 विनिर्मित उत्पाद	**64.231**	**117.9**	**115.8**	**118.1**	**118.1**	**118.3**
1.3.1 खाद्य उत्पादों का विनिर्माण	**9.122**	**128.6**	**127.9**	**128.4**	**128.7**	**128.5**
1.3.1.1 मांस का परिरक्षण और प्रसंस्करण	0.134	136.7	136.4	135.3	134.3	133.9
1.3.1.2 मछली, क्रस्टेशियस, मोलस्क और उनके उत्पादों का प्रसंस्करण एवं परिरक्षण	0.204	132.2	123.4	135.7	134.0	130.3
1.3.1.3 फल और सब्जियों का परिरक्षण और प्रसंस्करण	0.138	114.3	117.6	112.4	113.1	111.2
1.3.1.4 सब्जियां और पशु तेल एवं चर्बी	2.643	117.6	117.0	114.8	115.4	114.2
1.3.1.5 डेयरी उत्पाद	1.165	136.1	139.7	134.6	134.4	134.2
1.3.1.6 अनाज मिल के उत्पाद	2.010	141.7	137.7	144.4	144.6	144.2
1.3.1.7 स्टार्च और स्टार्च के उत्पाद	0.110	116.5	112.7	124.7	128.4	131.7
1.3.1.8 बेकरी उत्पाद	0.215	129.2	127.4	130.0	130.5	131.3
1.3.1.9 चीनी, गुड़ और शहद	1.163	111.3	115.4	111.4	112.0	112.3
1.3.1.10 कोक, चॉकलेट और चीनी कन्फेक्शनरी	0.175	126.7	127.1	127.7	127.4	126.6
1.3.1.11 मैक्रोनी, नूडल्स, और कूसकूस और उसके जैसे मैदे से बने उत्पाद	0.026	134.5	129.2	136.4	142.6	135.1
1.3.1.12 चाय और कॉफी उत्पाद	0.371	137.7	132.1	131.1	128.1	131.7
1.3.1.13 प्रसंस्कृत मसाले और नमक	0.163	122.1	122.5	124.9	125.3	124.4
1.3.1.14 प्रसंस्कृत तैयार खाद्य पदार्थ	0.024	127.0	127.9	128.4	128.2	129.1
1.3.1.15 स्वास्थ्य पूरक	0.225	143.5	140.0	148.2	154.0	156.6
1.3.1.16 पशु के लिए तैयार खाद्य	0.356	157.4	152.9	159.1	159.2	161.4
1.3.2 पेय पदार्थों का विनिर्माण	**0.909**	**120.7**	**119.7**	**121.9**	**121.6**	**121.9**
1.3.2.1 शराब और स्पिरीट	0.408	113.8	112.8	115.3	114.6	114.5
1.3.2.2 माल्ट लिकर और माल्ट	0.225	120.5	119.2	121.6	121.4	122.1
1.3.2.3 शीतल पेय, मिनरल वॉटर और बोतलबन्द पानी के अन्य उत्पाद	0.275	131.2	130.5	131.9	132.0	132.8
1.3.3 विनिर्मित तंबाकू उत्पाद	**0.514**	**150.1**	**150.3**	**150.7**	**148.9**	**153.7**
1.3.3.1 तंबाकू के उत्पाद	0.514	150.1	150.3	150.7	148.9	153.7
1.3.4 वस्त्र विनिर्माण	**4.881**	**117.9**	**114.2**	**119.0**	**119.0**	**118.7**
1.3.4.1 धागों की कताई और वस्त्र तैयार करना	2.582	110.6	106.8	111.3	110.8	110.4
1.3.4.2 बुनाई और तैयार वस्त्र	1.509	127.3	123.2	128.4	129.5	129.6
1.3.4.3 बुने हुए और क्रॉचिडेट फेब्रिक्स	0.193	112.9	110.6	112.8	112.5	111.2
1.3.4.4 कपड़ों को छोड़कर निर्मित वस्त्र सामग्री	0.299	130.3	124.9	134.5	134.2	135.1
1.3.4.5 डोरियाँ, रस्सी, सुतली और नेटिंग	0.098	138.8	137.8	140.2	139.3	135.6
1.3.4.6 अन्य वस्त्र	0.201	118.4	118.6	119.4	119.0	116.8
1.3.5 विनिर्मित तैयार वस्त्र	**0.814**	**138.9**	**137.7**	**138.3**	**139.2**	**138.0**
1.3.5.1 फर से बने वस्त्रों को छोड़कर वुलन के तैयार वस्त्र	0.593	139.7	137.5	139.3	140.9	139.2
1.3.5.2 बुने हुए क्रॉस्चिटेड वस्त्र	0.221	136.8	138.2	135.7	134.6	134.6

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक (जारी)

(आधारः 2011-12=100)

पण्य	भारांक	2018-19	2018	2019		
			मार्च	जनवरी	फरवरी (अ)	मार्च (अ)
	1	2	3	4	5	6
1.3.6 चमड़ा और उससे बने हुए उत्पाद का विनिर्माण	**0.535**	**121.8**	**120.4**	**121.3**	**120.6**	**120.2**
1.3.6.1 चमड़े की टैनिंग और ड्रेसिंग; ड्रेसिंग और फर की रंगायी	0.142	111.1	108.7	107.7	106.8	103.9
1.3.6.2 सामान, हैंडबैग, काठी और दोहन	0.075	135.1	131.2	135.7	135.5	135.4
1.3.6.3 जूते चप्पल	0.318	123.5	123.1	124.0	123.3	123.9
1.3.7 लकड़ी के विनिर्माण और लकड़ी और कॉर्क के उत्पाद	**0.772**	**133.5**	**131.4**	**134.2**	**134.6**	**135.7**
1.3.7.1 आरा मिलिंग और लकड़ी के उत्पाद	0.124	124.2	120.0	125.5	125.2	124.5
1.3.7.2 विनियर शीट, प्लायवुड का विनिर्माण, लॅमिन बोर्ड, पार्टिकल बोर्ड और अन्य पॅनल और बोर्ड	0.493	136.2	133.2	137.2	138.3	137.4
1.3.7.3 बिल्डरों की बढ़ईगीरी	0.036	158.7	158.3	157.0	157.0	171.2
1.3.7.4 लकड़ी के डिब्बे	0.119	124.2	128.1	124.0	122.1	129.9
1.3.8 कागज़ और कागज़ के उत्पाद का विनिर्माण	**1.113**	**123.4**	**120.3**	**124.9**	**124.5**	**124.3**
1.3.8.1 लुगदी, कागज़ और कागज़ बोर्ड	0.493	129.4	123.5	131.5	131.2	130.9
1.3.8.2 लहरदार कागज़ और पेपर बोर्ड और कागज़ के पात्र और पेपर बोर्ड	0.314	116.7	115.9	117.9	117.8	116.5
1.3.8.3 कागज़ की अन्य सामग्री और पेपर बोर्ड	0.306	120.6	119.5	121.3	120.6	121.8
1.3.9 मुद्रण और रिकार्डेड मीडिया का पुनरुत्पादन	**0.676**	**146.5**	**144.5**	**145.4**	**145.6**	**145.8**
1.3.9.1 मुद्रण	0.676	146.5	144.5	145.4	145.6	145.8
1.3.10 रसायन और रासायनिक उत्पाद का विनिर्माण	**6.465**	**119.0**	**115.5**	**119.6**	**119.5**	**119.7**
1.3.10.1 मूल रसायन	1.433	125.0	118.3	125.5	125.7	125.4
1.3.10.2 उर्वरक और नाइट्रोजन यौगिक	1.485	121.0	118.9	122.7	122.7	122.9
1.3.10.3 प्लास्टिक और सिथेंटिक रबड़ प्राथमिक रूप में	1.001	117.6	114.6	115.7	115.3	115.6
1.3.10.4 कीटनाशक और अन्य एग्रोकेमिकल उत्पाद	0.454	120.2	117.0	122.5	122.0	124.2
1.3.10.5 पेन्ट, वार्निश और समान कोटिंग, मुद्रण स्याही और मैस्टिक्स	0.491	112.7	108.3	113.9	114.4	113.7
1.3.10.6 साबुन और डिटर्जेंट, सफाई और चमकाने की सामग्री, इत्र और शौचालय सफाई की सामग्री	0.612	116.8	114.8	118.8	118.6	119.2
1.3.10.7 अन्य रासायनिक उत्पाद	0.692	116.6	114.7	116.4	116.1	115.9
1.3.10.8 मानव निर्मित फाइबर	0.296	104.0	101.8	102.3	102.8	102.7
1.3.11 फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पाद का विनिर्माण	**1.993**	**123.4**	**120.7**	**126.1**	**125.9**	**125.7**
1.3.11.1 फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पाद	1.993	123.4	120.7	126.1	125.9	125.7
1.3.12 रबड़ और प्लास्टिक उत्पाद का विनिर्माण	**2.299**	**109.5**	**107.6**	**110.1**	**109.4**	**109.9**
1.3.12.1 रबड़ टायर और ट्यूब, रबड़ टायर की रीट्रीडिंग और पुनर्निर्माण	0.609	98.9	97.9	100.1	99.6	99.5
1.3.12.2 रबड़ के अन्य उत्पाद	0.272	91.8	91.0	92.8	92.4	92.7
1.3.12.3 प्लास्टिक उत्पाद	1.418	117.5	115.0	117.7	116.9	117.6
1.3.13 अन्य अधात्विक खनिज उत्पादों का विनिर्माण	**3.202**	**115.9**	**114.0**	**116.3**	**117.5**	**116.6**
1.3.13.1 कांच और कांच उत्पाद	0.295	121.4	118.0	124.5	125.5	125.5
1.3.13.2 आग रोधक उत्पाद	0.223	111.1	109.8	112.3	111.1	110.5
1.3.13.3 मिट्टी से बनी भवन निर्माण सामग्री	0.121	98.2	97.6	98.8	100.9	99.0
1.3.13.4 चीनी मिट्टी के बर्तन और चीनी मिट्टी	0.222	112.7	112.4	112.3	114.4	114.4
1.3.13.5 सीमेन्ट, चूना और प्लास्टर	1.645	114.3	113.6	115.2	116.9	117.2
1.3.13.6 कंक्रीट, सीमेन्ट और प्लास्टर से बनी वस्तुएं	0.292	121.5	120.1	122.5	122.8	121.9
1.3.13.7 पत्थरों को काटना, आकार देना और संवारना	0.234	118.9	117.0	118.9	118.5	120.2
1.3.13.8 अन्य अधात्विक खनिज उत्पाद	0.169	130.7	116.2	122.2	123.3	105.2
1.3.14 मूल धातुओं का विनिर्माण	**9.646**	**112.2**	**109.6**	**110.1**	**110.5**	**111.0**
1.3.14.1 स्टील तैयार करने में प्रयुक्त सामग्री	1.411	113.0	109.8	108.8	108.5	108.5
1.3.14.2 मेटेलिक आयरन	0.653	117.9	116.1	115.5	114.2	114.3
1.3.14.3 नरम इस्पात - अर्ध निर्मित इस्पात	1.274	99.5	98.1	97.9	97.9	98.1
1.3.14.4 नरम इस्पात - लंबे उत्पाद	1.081	110.2	105.9	109.5	109.7	110.1
1.3.14.5 नरम इस्पात - चपटे उत्पाद	1.144	119.6	117.8	115.6	115.2	117.1
1.3.14.6 स्टेनलेस स्टील के अतिरिक्त एलॉय स्टील-आकार	0.067	111.7	108.9	109.3	111.6	111.3
1.3.14.7 स्टेनलेस स्टील अर्ध निर्मित	0.924	112.7	109.8	107.4	112.5	109.9
1.3.14.8 पाइप और ट्यूब	0.205	126.6	124.8	127.8	128.6	128.2
1.3.14.9 कीमती धातु सहित अलौह धातु	1.693	112.1	110.8	109.6	109.8	110.5
1.3.14.10 कास्टिंग	0.925	109.5	107.0	110.3	109.9	113.8
1.3.14.11 स्टील से गढ़ी वस्तुएं	0.271	126.8	116.8	137.5	140.2	139.0
1.3.15 मशीनरी और उपकरणों को छोड़कर गढ़े हुए धातु उत्पादों का विनिर्माण	**3.155**	**115.0**	**112.0**	**116.4**	**115.7**	**116.2**
1.3.15.1 इमारती धातु उत्पाद	1.031	112.8	109.8	114.2	114.2	115.2
1.3.15.2 धातु से बने टैंक, जलाशय और डिब्बे	0.660	127.1	125.2	127.6	123.1	123.8
1.3.15.3 बाष्प चालित जनरेटर, सेंट्रल हीटिंग हॉट वाटर बॉयलरर्स को छोड़कर	0.145	105.9	109.1	104.8	104.8	104.8
1.3.15.4 धातु की फोर्जिंग, दबाना, स्टैपिंग और रोल फॉरमिंग, पाउडर धातुकर्म	0.383	96.0	90.3	98.7	101.5	102.5
1.3.15.5 कटलरी, हस्त चालित उपकरण और सामान्य हार्डवेयर	0.208	99.7	99.1	99.6	99.9	100.1
1.3.15.6 अन्य गढ़े हुए धातु उत्पाद	0.728	123.1	118.8	125.7	125.2	125.0
1.3.16 कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल उत्पादों का विनिर्माण	**2.009**	**111.8**	**110.6**	**111.5**	**111.8**	**111.3**
1.3.16.1 इलेक्ट्रॉनिक पुरजे	0.402	100.9	102.3	99.5	98.5	98.4
1.3.16.2 कंप्यूटर और संबंधित उपकरण	0.336	132.5	127.4	135.0	135.0	135.0

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक (समाप्त)

(आधारः 2011-12=100)

पण्य	भारांक	2018-19	2018	2019		
			मार्च	जनवरी	फरवरी (अ)	मार्च (अ)
	1	2	3	4	5	6
1.3.16.3 संचार उपकरण	0.310	116.8	114.0	116.5	116.6	116.6
1.3.16.4 उपभोक्ता इलेक्ट्रानिक्स	0.641	103.9	103.4	103.8	103.9	102.4
1.3.16.5 मापने, जांचने, नेविगेशन और नियंत्रण उपकरण	0.181	109.2	109.1	105.3	108.9	109.0
1.3.16.6 हाथ घडी और दीवार घडी	0.076	137.8	137.1	135.6	138.7	136.6
1.3.16.7 विभासन, विद्युत चिकित्सकीय एवं विद्युत उपचारात्मक उपकरण	0.055	103.4	100.3	104.4	104.2	106.6
1.3.16.8 ऑप्टिकल उपकरण और फोटोग्राफिक उपकरण	0.008	108.7	112.6	107.3	107.3	107.5
1.3.17 इलेक्ट्रिकल उपकरण का विनिर्माण	**2.930**	**111.7**	**110.1**	**112.1**	**112.0**	**112.1**
1.3.17.1 विद्युत मोटर्स, जनरेटर, ट्रांसफार्मर और बिजली वितरण और नियंत्रण संबंधी उपकरण	1.298	107.6	106.1	108.2	108.2	108.5
1.3.17.2 बैटरी और एक्युम्युलेटर	0.236	117.7	117.2	117.3	116.6	116.8
1.3.17.3 डेटा संचरण या छवियों के सजीव प्रसारण के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल	0.133	126.4	112.4	128.8	127.7	126.2
1.3.17.4 अन्य इलेक्ट्रानिक और बिज़ली के वायर और केबल	0.428	111.3	109.2	111.4	111.4	111.4
1.3.17.5 वायरिंग संबंधी चीजें और बिजली के प्रकाश और सजावट के उपकरण	0.263	108.6	109.7	108.5	109.4	109.9
1.3.17.6 घरेलू उपकरण	0.366	121.6	121.5	120.9	120.8	120.1
1.3.17.7 अन्य इलेक्ट्रिकल उपकरण	0.206	108.7	108.2	110.1	110.1	110.2
1.3.18 मशीनरी और उपकरणों का विनिर्माण	**4.789**	**111.3**	**109.9**	**111.8**	**111.5**	**112.3**
1.3.18.1 इंजन और टर्बाइन, एयरक्राफ्ट, वाहन और दुपहिया वाहनों के इंजन को छोड़कर	0.638	103.0	102.9	103.8	103.7	105.1
1.3.18.2 तरल बिजली उपकरण	0.162	118.2	116.2	118.6	119.1	119.2
1.3.18.3 अन्य पंप, कंप्रेसर, नल और वाल्व	0.552	108.9	109.5	109.5	109.5	109.9
1.3.18.4 बेयरिंग, गियर्स, गेयरिंग और ड्राइविंग उपकरण	0.340	111.1	111.3	109.1	109.6	108.8
1.3.18.5 ओवन, फर्नेस और फर्नेस बर्नर भट्टियां	0.008	78.2	79.3	78.0	78.0	78.0
1.3.18.6 माल उठाने एवं चढ़ाने – उतारने वाले उपकरण	0.285	110.4	107.7	112.3	111.5	111.9
1.3.18.7 कार्यालय मशीनरी और उपकरण	0.006	130.2	130.2	130.2	130.2	130.2
1.3.18.8 सामान्य प्रयोजन के अन्य उपकरण	0.437	129.7	129.7	129.1	128.6	129.7
1.3.18.9 कृषि और वानिकी मशीनरी	0.833	116.9	113.9	118.7	118.5	118.9
1.3.18.10 धातु निर्माण करनेवाली मशीनरी और मशीन टूल्स	0.224	101.8	96.7	103.6	103.6	106.0
1.3.18.11 खनन, उत्खनन और निर्माण के लिए मशीनरी	0.371	75.5	73.9	75.7	75.5	76.9
1.3.18.12 खाद्य, पेय और तंबाकू प्रसंस्करण के लिए मशीनरी	0.228	124.7	122.8	126.9	123.4	124.5
1.3.18.13 कपड़ा, परिधान और चमड़े के उत्पादन से जुड़ी मशीनरी	0.192	120.0	120.2	119.1	119.2	120.2
1.3.18.14 अन्य विशेष प्रयोजनों के लिए मशीनरी	0.468	123.4	121.3	122.8	123.0	124.2
1.3.18.15 अक्षय ऊर्जा उत्पादन मशीनरी	0.046	67.3	68.8	67.0	67.0	67.0
1.3.19 मोटर वाहन, ट्रेलरों और अर्ध-ट्रेलरों का विनिर्माण	**4.969**	**112.8**	**111.1**	**113.3**	**113.3**	**113.5**
1.3.19.1 मोटर वाहन	2.600	113.4	111.5	113.6	113.6	113.6
1.3.19.2 मोटर वाहन पुरजे और सहायक उपकरण	2.368	112.3	110.6	113.0	113.1	113.3
1.3.20 अन्य परिवहन उपकरणों का विनिर्माण	**1.648**	**111.7**	**110.4**	**112.9**	**112.9**	**113.2**
1.3.20.1 जहाजों और तैरने वाली – वस्तुओं का निर्माण	0.117	158.8	158.8	158.8	158.8	158.8
1.3.20.2 रेलवे इंजन और रोलिंग स्टाक	0.110	104.8	105.2	105.8	105.8	105.8
1.3.20.3 मोटर साइकल	1.302	106.6	105.2	107.9	107.9	108.3
1.3.20.4 साइकल और अवैध गाडी	0.117	127.7	124.9	129.3	129.2	129.7
1.3.20.5 अन्य परिवहन उपकरण	0.002	123.6	121.2	125.0	125.1	124.7
1.3.21 फर्नीचर का विनिर्माण	**0.727**	**127.4**	**124.6**	**130.9**	**129.7**	**129.4**
1.3.21.1 फर्नीचर	0.727	127.4	124.6	130.9	129.7	129.4
1.3.22 अन्य विनिर्माण	**1.064**	**107.1**	**104.4**	**106.9**	**106.4**	**108.7**
1.3.22.1 आभूषण और संबंधित सामग्री	0.996	104.0	101.4	103.7	103.2	105.6
1.3.22.2 संगीत उपकरण	0.001	174.1	180.0	172.1	177.0	177.5
1.3.22.3 खेल के सामान	0.012	127.6	125.5	129.4	128.3	126.4
1.3.22.4 खेल और खिलौने	0.005	132.2	128.9	135.1	135.6	133.0
1.3.22.5 चिकित्सा और दंत चिकित्सा उपकरण और सामग्री	0.049	159.2	155.9	160.8	160.5	160.9
2 खाद्य सूचकांक	**24.378**	**138.1**	**133.7**	**138.3**	**138.1**	**138.9**

स्रोत : आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।

सं. 22: औदयोगिक उत्पादन का सूचकांक (आधारः 2011-12=100)

उद्योग	भारांक	2016-17	2017-18	अप्रैल-फरवरी		फरवरी	
				2017-18	2018-19	2018	2019
	1	2	3	4	5	6	7
सामान्य सूचकांक	100.00	120.0	125.3	123.9	128.8	127.4	127.5
1 क्षेत्रवार वर्गीकरण							
1.1 खनन	14.37	102.5	104.9	102.5	105.6	110.1	112.3
1.2 विनिर्माण	77.63	121.0	126.6	125.4	130.2	129.7	129.3
1.3 बिजली	7.99	141.6	149.2	148.5	156.6	136.1	137.7
2 उपयोग आधारित वर्गीकरण							
2.1 मूल वस्तुएं	34.05	117.5	121.8	120.5	124.8	119.5	120.9
2.2 पूंजीगत माल	8.22	101.5	105.6	103.3	107.7	118.8	108.3
2.3 मध्यवर्ती माल	17.22	122.3	125.1	124.0	123.6	124.8	118.7
2.4 बुनियादी/निर्माण वस्तुएं	12.34	125.0	132.0	130.6	140.7	138.5	141.8
2.5 उपभोक्ता टिकाऊ माल	12.84	122.6	123.6	122.5	130.3	124.0	125.5
2.6 उपभोक्ता गैर-टिकाऊ माल	15.33	126.5	139.9	138.5	144.2	146.6	152.9

स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

सरकारी खाते और खज़ाना बिल

सं. 23: केन्द्र सरकार के खाते - एक नज़र में

(राशि बिलियन ₹ में)

मद	वित्तीय वर्ष	अप्रैल - फरवरी			
	2018-19 (बज़ट अनुमान)	2018-19 (वर्तमान)	2017-18 (वर्तमान)	बज़ट अनुमान का प्रतिशत	
				2018-19	2017-18
	1	2	3	4	5
1 राजस्व प्राप्तियां	**17,296.8**	**12,656.8**	**11,776.8**	**73.2**	**78.2**
1.1 कर राजस्व (निवल)	14,844.1	10,939.2	10,355.5	73.7	81.6
1.2 करेतर राजस्व	2,452.8	1,717.6	1,421.3	70.0	60.2
2 पूंजीगत प्राप्तियां	**7,275.5**	**9,231.6**	**8,214.9**	**126.9**	**115.3**
2.1 ऋण की वसूली	131.6	150.4	133.0	114.3	76.1
2.2 अन्य प्राप्तियां	800.0	566.2	924.9	70.8	92.5
2.3 उधारियां और अन्य देयताएं	6,344.0	8,515.0	7,157.0	134.2	120.3
3 कुल प्राप्तियां (1+2)	**24,572.4**	**21,888.4**	**19,991.7**	**89.1**	**90.1**
4 राजस्व व्यय	21,406.1	19,153.0	17,020.9	89.5	87.5
4.1 ब्याज भुगतान	5,875.7	5,011.6	4,507.3	85.3	84.9
5 पूंजी व्यय	3,166.2	2,735.4	2,970.9	86.4	108.6
6 कुल व्यय (4+5)	**24,572.4**	**21,888.4**	**19,991.7**	**89.1**	**90.1**
7 राजस्व घाटा (4-1)	**4,109.3**	**6,496.3**	**5,244.1**	**158.1**	**119.5**
8 राजकोषीय घाटा {6-(1+2.1+2.2)}	**6,344.0**	**8,515.0**	**7,157.0**	**134.2**	**120.3**
9 सकल प्राथमिक घाटा [8-4.1]	**468.3**	**3,503.4**	**2,649.7**	**748.1**	**414.0**

स्रोत : महालेखानियंत्रक, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार और यूनियन बज़ट 2018-19।

सं. 24: खज़ाना बिल - स्वामित्व का स्वरूप

(बिलियन ₹)

मद	2017-18	2018	2019					
		मार्च 30	फरवरी 22	मार्च 1	मार्च 8	मार्च 15	मार्च 22	मार्च 29
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 91-दिवसीय								
1.1 बैंक	680.0	680.0	262.2	245.1	216.4	186.1	200.6	185.2
1.2 प्राथमिक व्यापारी	134.3	134.3	105.8	110.1	120.9	122.2	141.5	178.8
1.3 राज्य सरकारें	335.2	335.2	480.9	392.9	370.9	370.9	316.4	270.0
1.4 अन्य	221.3	221.3	426.0	408.6	396.6	393.4	328.8	277.5
2 182-दिवसीय								
2.1 बैंक	313.7	313.7	384.8	364.2	334.5	322.8	336.4	319.5
2.2 प्राथमिक व्यापारी	273.2	273.2	389.4	412.4	426.1	396.1	367.9	387.4
2.3 राज्य सरकारें	158.6	158.6	336.3	295.7	285.7	285.7	280.4	280.4
2.4 अन्य	116.9	116.9	173.7	155.9	161.3	193.0	198.0	185.7
3 364-दिवसीय								
3.1 बैंक	330.8	330.8	468.3	497.4	525.8	517.1	511.6	488.1
3.2 प्राथमिक व्यापारी	700.4	700.4	747.1	711.6	700.6	704.4	704.2	741.7
3.3 राज्य सरकारें	127.3	127.3	189.4	189.4	189.4	189.4	189.4	188.9
3.4 अन्य	407.0	407.0	645.5	647.2	618.2	620.0	628.9	623.9
4 14-दिवसीय मध्यवर्ती								
4.1 बैंक	–	–	–	–	–	–	–	–
4.2 प्राथमिक व्यापारी	–	–	–	–	–	–	–	–
4.3 राज्य सरकारें	2,124.1	2,124.1	1,570.8	1,614.9	1,265.1	1,439.6	1,728.3	1,656.1
4.4 अन्य	1.7	1.7	3.2	4.2	3.5	2.1	3.3	2.5
कुल खज़ाना बिल (14 दिवसीय मध्यवर्ती खज़ाना बिल को छोड़कर)#	3,798.8	3,798.8	4,609.3	4,430.5	4,346.6	4,301.2	4,204.1	4,127.0

14 दिवसीय मध्यवर्ती खज़ाना बिल बिक्री योग्य नहीं है, ये बिल 91 दिवसीय, 182 दिवसीय और 364 दिवसीय खज़ाना बिलों जैसे नहीं है। यह बिल स्वरूप के अनुसार मध्यवर्ती हैं क्योंकि राज्य सरकारों के दैनिक न्यूनतम नकदी शेष में कमी को पूरा करने के लिए परिसमाप्त किए जाते हैं।

सं. 25: खज़ाना बिलों की नीलामी

(राशि बिलियन ₹ में)

नीलामी की तारीख	अधिसूचित राशि	प्राप्त बोलियां			स्वीकृत बोलियां			कुल निर्गम (6+7)	कट-ऑफ मूल्य	कट-ऑफ मूल्य पर निहित प्रतिफल (प्रतिशत)
		संख्या	कुल अंकित मूल्य		संख्या	कुल अंकित मूल्य				
			प्रतियोगी	गैर-प्रतियोगी		प्रतियोगी	गैर-प्रतियोगी			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
91-दिवसीय खज़ाना बिल										
2018-19										
फरवरी 27	40	52	143.53	60.01	28	39.99	60.01	100.00	98.43	6.3977
मार्च 6	40	54	227.20	8.01	31	39.99	8.01	48.00	98.43	6.3977
मार्च 13	40	53	293.27	12.12	20	39.88	12.12	52.00	98.44	6.3563
मार्च 20	40	61	152.26	13.51	41	39.99	13.51	53.50	98.45	6.3149
मार्च 27	40	63	157.79	10.41	44	39.99	10.41	50.40	98.45	6.3149
182-दिवसीय खज़ाना बिल										
2018-19										
फरवरी 27	30	40	93.33	0.07	19	29.93	0.07	30.00	96.87	6.4800
मार्च 6	30	44	122.14	0.00	17	30.00	0.00	30.00	96.88	6.4587
मार्च 13	30	49	126.39	0.18	26	29.82	0.18	30.00	96.89	6.4373
मार्च 20	30	49	124.88	0.18	17	29.82	0.18	30.00	96.92	6.3732
मार्च 27	30	40	122.09	0.00	12	30.00	0.00	30.00	96.93	6.3519
364-दिवसीय खज़ाना बिल										
2018-19										
फरवरी 27	30	56	102.16	0.00	28	30.00	0.00	30.00	93.87	6.5482
मार्च 6	30	56	131.36	0.00	15	30.00	0.00	30.00	93.90	6.5141
मार्च 13	30	59	129.93	0.00	28	30.00	0.00	30.00	93.92	6.4914
मार्च 20	30	65	138.25	0.00	22	30.00	0.00	30.00	93.98	6.4232
मार्च 27	30	50	107.34	0.00	11	30.00	0.00	30.00	94.01	6.3892

वित्तीय बाजार

सं. 26: दैनिक मांग मुद्रा दरें

(वार्षिक प्रतिशत)

स्थिति के अनुसार		दरों का दायरा	भारित औसत दरें
		उधार लेना/उधार देना	उधार लेना/उधार देना
		1	2
मार्च	1, 2019	4.80-6.35	6.18
मार्च	2, 2019	4.80-6.35	6.07
मार्च	5, 2019	4.80-6.50	6.15
मार्च	6, 2019	4.80-6.30	6.18
मार्च	7, 2019	4.80-6.25	6.14
मार्च	8, 2019	4.80-6.30	6.15
मार्च	11, 2019	4.80-6.30	6.16
मार्च	12, 2019	4.80-6.30	6.14
मार्च	13, 2019	4.80-6.27	6.17
मार्च	14, 2019	4.80-6.30	6.15
मार्च	15, 2019	4.80-6.85	6.23
मार्च	16, 2019	4.90-6.55	6.25
मार्च	18, 2019	4.80-6.35	6.20
मार्च	19, 2019	4.80-6.30	6.20
मार्च	20, 2019	4.80-6.30	6.20
मार्च	22, 2019	4.80-6.28	6.19
मार्च	25, 2019	4.80-7.25	6.19
मार्च	26, 2019	4.80-7.25	6.16
मार्च	27, 2019	4.80-7.35	6.23
मार्च	28, 2019	4.80-7.35	6.24
मार्च	29, 2019	5.00-9.75	7.02
मार्च	30, 2019	5.00-9.50	8.19
अप्रैल	2, 2019	4.80-6.50	6.19
अप्रैल	3, 2019	4.80-7.00	6.22
अप्रैल	4, 2019	4.80-6.25	6.13
अप्रैल	5, 2019	4.50-6.25	5.99
अप्रैल	8, 2019	4.40-6.25	5.98
अप्रैल	9, 2019	4.40-6.10	5.97
अप्रैल	10, 2019	4.40-6.25	5.99
अप्रैल	11, 2019	4.60-6.40	6.02
अप्रैल	12, 2019	4.40-6.15	6.05
अप्रैल	15, 2019	4.40-6.15	6.05

टिप्पणी : नोटिस मुद्रा सहित।

सं. 27: जमा प्रमाणपत्र

मद	2018	2019			
	मार्च 30	फरवरी 15	मार्च 1	मार्च 15	मार्च 29
	1	2	3	4	5
1 बकाया राशि (बिलियन ₹)	1,857.3	2,002.5	2,088.7	2,204.6	2,722.6
1.1 पखवाड़े के दौरान जारी (बिलियन ₹)	331.3	333.8	292.0	472.4	524.1
2 ब्याज दर (प्रतिशत)	6.65-8.50	6.44-8.90	6.45-8.79	7.22-8.95	7.09-8.45

सं. 28: वाणिज्यिक पत्र

मद	2018	2019			
	मार्च 31	फरवरी 15	फरवरी 28	मार्च 15	मार्च 31
	1	2	3	4	5
1 बकाया राशि (बिलियन ₹)	3,725.8	5,242.3	5,208.1	5,309.5	4,830.8
1.1 पखवाड़े के दौरान रिपोर्ट किए गए (बिलियन ₹)	999.2	1,035.5	900.8	1,240.6	1,013.0
2 ब्याज दर (प्रतिशत)	6.49-14.00	6.41-13.40	6.36-11.74	6.44-9.98	6.54-12.60

सं. 29: चुनिंदा वित्तीय बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर

(बिलियन ₹)

मद	2017-18	2018	2019				
		मार्च 30	मार्च 1	मार्च 8	मार्च 15	मार्च 22	मार्च 29
	1	2	3	4	5	6	7
1 मांग मुद्रा	245.5	395.8	411.4	388.6	342.2	445.0	602.5
2 नोटिस मुद्रा	36.6	45.3	93.7	2.7	125.2	5.5	51.1
3 मीयादी मुद्रा	9	18.4	9.7	3.6	6.7	3.6	4.8
4 सीबीएलओ	2,130.1	2,226.0	3,290.1	2,443.8	3,039.6	2,225.1	2,697.9
5 बाजार रिपो	1,921.8	1,587.9	2,281.6	1,577.2	2,043.5	1,591.0	1,757.4
6 कार्पोरेट बांड में रिपो	3.8	3.8	19.4	27.4	18.7	37.7	87.8
7 फोरेक्स (यूएस मिलियन डॉलर)	55,345	105,617	81,741	71,888	69,677	83,911	98,933
8 भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां	808.7	790.6	563.7	473.6	649.7	720.1	654.7
9 राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां	45.3	60.3	44.0	60.3	75.6	79.9	84.2
10 खज़ाना बिल							
10.1 91-दिवसीय	35.5	34.1	22.8	23.5	15.0	35.9	35.5
10.2 182-दिवसीय	10.2	2.5	7.7	10.8	17.1	15.9	9.5
10.3 364-दिवसीय	10.3	16.9	7.7	43.0	20.3	32.3	18.1
10.4 नकदी प्रबंधन बिल	13	–	56.0	27.0	22.2	–	–
11 कुल सरकारी प्रतिभूतियां (8+9+10)	923.0	904.2	701.9	638.2	799.9	884.1	801.9
11.1 भारतीय रिज़र्व बैंक	–	2.0	26.2	31.3	25.2	9.9	7.7

टिप्पणी : मुद्रा बाजार के संपार्श्विक उधार और ऋण दायित्व (सीबीएलओ) खंड को समाप्त किया गया तथा उसके स्थान पर 5 नवंबर 2018से त्रिपक्षीय रिपो लाया गया।

सं. 30: गैर-सरकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के नए पूंजी निर्गम

(राशि बिलियन ₹ में)

प्रतिभूति और निर्गम का प्रकार	2018-19		2017-18 (अप्रैल-मार्च)		2018-19 (अप्रैल-मार्च)*		मार्च 2018		मार्च 2019 *	
	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 इक्विटी शेयर	**129**	**167.5**	**214**	**679.9**	**129**	**167.5**	**35**	**103.8**	**9**	**1.5**
1ए प्रीमियम	124	160.8	211	657.8	124	160.8	35	99.0	9	1.2
1.1 पब्लिक	119	146.1	193	466.0	119	146.1	33	102.3	8	1.3
1.1.1 प्रीमियम	115	141.2	190	448.7	115	141.2	33	97.6	8	1.0
1.2 राइट्स	10	21.5	21	213.9	10	21.5	2	1.5	1	0.3
1.2.1 प्रीमियम	9	19.6	21	209.1	9	19.6	2	1.5	1	0.2
2 अधिमान शेयर	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
2.1 पब्लिक	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2.2 राइट्स	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3 डिबेंचर	**21**	**337.2**	**7**	**49.5**	**21**	**337.2**	**1**	**4.9**	**–**	**–**
3.1 परिवर्तनीय	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.1.1 पब्लिक	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.1.2 राइट्स	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3.2 अपरिवर्तनीय	21	337.2	7	49.5	21	337.2	1	4.9	–	–
3.1.1 पब्लिक	21	337.2	7	49.5	21	337.2	1	4.9	–	–
3.1.2 राइट्स	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4 बांड	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**
4.1 पब्लिक	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
4.2 राइट्स	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5 कुल (1+2+3+4)	**150**	**504.7**	**221**	**729.5**	**150**	**504.7**	**36**	**108.7**	**9**	**1.5**
5.1 पब्लिक	140	483.2	200	515.6	140	483.2	34	107.2	8	1.3
5.2 राइट्स	10	21.5	21	213.9	10	21.5	2	1.5	1	0.3

* : आंकड़े अनंतिम है।

टिप्पणी : अप्रैल 2018 से मासिक डाटा का समेकन निर्गम की समाप्ति की तारीख के आधार पर की जाती है जबकि पूर्व में समेकन का कार्य निर्गम चालू होने की तारीख के आधार पर किया जाता था।

स्रोत : भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)।

बाह्य क्षेत्र

सं. 31: विदेशी व्यापार

मद	इकाई	2018-19	2018			2019		
			मार्च	नवंबर	दिसंबर	जनवरी	फरवरी	मार्च
		1	2	3	4	5	6	7
1 निर्यात	बिलियन ₹	23,039.0	1,906.2	1,876.9	1,974.1	1,862.9	1,900.7	2,261.4
	अमेरिकी मिलियन डालर	329,536.2	29,316.4	26,121.6	27,909.9	26,337.3	26,687.6	32,548.0
1.1 तेल	बिलियन ₹	3,245.0	215.4	344.6	294.8	226.0	217.8	245.2
	अमेरिकी मिलियन डालर	46,350.8	3,312.7	4,795.4	4,167.4	3,195.7	3,058.1	3,529.8
1.2 तेल से इतर	बिलियन ₹	19,794.0	1,690.8	1,532.4	1,679.3	1,636.9	1,682.9	2,016.1
	अमेरिकी मिलियन डालर	283,185.3	26,003.7	21,326.2	23,742.5	23,141.6	23,629.5	29,018.2
2 आयात	बिलियन ₹	35,876.8	2,784.4	3,140.5	2,992.1	2,906.6	2,582.8	3,018.1
	अमेरिकी मिलियन डालर	513,085.9	42,823.1	43,706.0	42,302.9	41,092.9	36,264.5	43,439.9
2.1 तेल	बिलियन ₹	9,860.2	723.6	975.1	759.5	796.0	667.7	816.1
	अमेरिकी मिलियन डालर	140,883.8	11,128.6	13,570.5	10,737.4	11,252.9	9,375.6	11,746.0
2.2 तेल से इतर	बिलियन ₹	26,016.6	2,060.8	2,165.4	2,232.7	2,110.7	1,915.1	2,202.0
	अमेरिकी मिलियन डालर	372,202.1	31,694.5	30,135.4	31,565.6	29,840.0	26,888.9	31,693.9
3 व्यापार शेष	बिलियन ₹	–12,837.9	–878.2	–1,263.5	–1,018.0	–1,043.7	–682.1	–756.8
	अमेरिकी मिलियन डालर	–183,549.7	–13,506.7	–17,584.3	–14,393.0	–14,755.7	–9,576.9	–10,891.9
3.1 तेल	बिलियन ₹	–6,615.2	–508.2	–630.5	–464.7	–569.9	–449.9	–570.9
	अमेरिकी मिलियन डालर	–94,532.9	–7,815.9	–8,775.1	–6,570.0	–8,057.3	–6,317.5	–8,216.2
3.2 तेल से इतर	बिलियन ₹	–6,222.7	–370.0	–633.0	–553.3	–473.8	–232.1	–185.9
	अमेरिकी मिलियन डालर	–89,016.8	–5,690.8	–8,809.2	–7,823.0	–6,698.4	–3,259.5	–2,675.7

स्रोत : वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय तथा वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय।

सं. 32: विदेशी मुद्रा भंडार

मद	इकाई	2018	2019					
		अप्रैल 20	मार्च 15	मार्च 22	मार्च 29	अप्रैल 5	अप्रैल 12	अप्रैल 19
		1	2	3	4	5	6	7
1 कुल भंडार	**बिलियन ₹**	**27,935**	**28,122**	**27,981**	**28,539**	**28,632**	**28,758**	**28,744**
	अमेरिकी मिलियन डालर	**423,583**	**405,638**	**406,668**	**411,905**	**413,781**	**414,886**	**414,147**
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	**बिलियन ₹**	26,299	26,147	26,009	26,566	26,718	26,812	26,798
	अमेरिकी मिलियन डालर	398,486	377,774	378,805	384,054	386,116	386,762	386,034
1.2 स्वर्ण	**बिलियन ₹**	1,397	1,667	1,667	1,667	1,607	1,612	1,612
	अमेरिकी मिलियन डालर	21,484	23,408	23,408	23,408	23,226	23,303	23,303
1.3 एसडीआर	एसडीआरएस मिलियन	1,059	1,049	1,049	1,049	1,049	1,049	1,049
	बिलियन ₹	102	101	100	101	101	101	101
	अमेरिकी मिलियन डालर	1,538	1,461	1,460	1,457	1,456	1,459	1,456
1.4 आईएमएफ में आरक्षित भाग की स्थिति	**बिलियन ₹**	137	207	206	207	207	233	233
	अमेरिकी मिलियन डालर	2,075	2,995	2,994	2,986	2,984	3,362	3,355

सं. 33: अनिवासी भारतीयों की जमाराशियां

(अमेरिकी मिलियन डालर)

योजना	बकाया				प्रवाह	
	2018-19	2018	2019		2017-18	2018-19
		मार्च	फरवरी	मार्च	अप्रैल-मार्च	अप्रैल-मार्च
	1	2	3	4	5	6
1 एनआरआई जमाराशियां	**130,416**	**126,182**	**125,599**	**130,416**	**9,676**	**10,381**
1.1 एफसीएनआर (बी)	23,170	22,026	21,623	23,170	1,024	1,144
1.2 एनआर (ई) आरए	92,015	90,035	89,183	92,015	7,132	7,306
1.3 एनआरओ	15,231	14,121	14,792	15,231	1,520	1,930

सं. 34: विदेशी निवेश अंतर्वाह

(अमेरिकी मिलियन डालर)

मद	2018-19	2017-18	2018-19	2018	2019	
		अप्रैल-मार्च	अप्रैल-मार्च	मार्च	फरवरी	मार्च
	1	2	3	4	5	6
1.1 निवल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (1.1.1-1.1.2)	**34,600**	**30,286**	**34,600**	**2,051**	**2,370**	**3,724**
1.1.1 भारत में प्रत्यक्ष निवेश (1.1.1.1-1. 1.1.2)	**47,200**	**39,431**	**47,200**	**3,214**	**3,091**	**6,295**
1.1.1.1 सकल अंतर्वाह/सकल निवेश	**64,374**	**60,974**	**64,374**	**4,711**	**4,317**	**7,520**
1.1.1.1.1 ईक्विटी	45,059	45,521	45,059	3,377	2,925	3,661
1.1.1.1.1.1 सरकारी (एसआईए/एफआईपीबी)	2,429	7,797	2,429	56	22	277
1.1.1.1.1.2 भारतीय रिज़र्व बैंक	36,315	29,569	36,315	3,053	2,490	2,528
1.1.1.1.1.3 शेयरों की अधिप्राप्ति	5,622	7,491	5,622	208	353	796
1.1.1.1.1.4 अनिगमित निकायों की ईक्विटी पूंजी	693	664	693	60	60	60
1.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	13,570	12,542	13,570	1,131	1,131	1,131
1.1.1.1.3 अन्य पूंजी	5,746	2,911	5,746	203	261	2,729
1.1.1.2 प्रत्यावर्तन /विनिवेश	**17,175**	**21,544**	**17,175**	**1,497**	**1,226**	**1,226**
1.1.1.2.1 ईक्विटी	16,954	21,325	16,954	1,486	1,223	1,223
1.1.1.2.2 अन्य पूंजी	221	219	221	11	3	3
1.1.2 भारत द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (1.1.2.1+1.1.2.2+ 1.1.2.3-1.1.2.4)	**12,599**	**9,144**	**12,599**	**1,162**	**721**	**2,571**
1.1.2.1 ईक्विटी पूंजी	6,863	5,254	6,863	590	427	894
1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	2,972	2,853	2,972	238	238	238
1.1.2.3 अन्य पूंजी	5,018	4,525	5,018	583	242	1,624
1.1.2.4 प्रत्यावर्तन/विनिवेश	2,253	3,487	2,253	248	185	185
1.2 निवल संविभागीय निवेश (1.2.1+1.2.2+1.2.3-1.2.4)	**–2,056**	**22,115**	**–2,056**	**–1,390**	**–25**	**8,575**
1.2.1 जीडीआर/एडीआर	1,820	–	1,820	–	–	–
1.2.2 एफआईआई	–3,587	22,165	–3,587	–1,357	974	9,574
1.2.3 अपतटीय निधियां और अन्य	–	–	–	–	–	–
1.2.4 भारत द्वारा संविभागीय निवेश	290	50	290	33	999	999
1 विदेशी निवेश अंतर्वाह	**32,544**	**52,401**	**32,544**	**661**	**2,345**	**12,299**

सं. 35: वैयक्तिक निवासियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के अंतर्गत जावक विप्रेषण

(मिलियन अमेरिकी डालर)

मद	2018-19	2018	2019		
		मार्च	जनवरी	फरवरी	मार्च
	1	2	3	4	5
1 एलआरएस के अंतर्गत जावक विप्रेषण	**13,787.6**	**1,120.8**	**1,336.4**	**1,046.5**	**1,476.8**
1.1 जमाराशियां	455.9	81.0	29.6	33.2	100.6
1.2 अचल संपत्ति की खरीद	84.5	13.9	4.9	4.6	10.5
1.3 इक्विटी / डेट में निवेश	422.9	69.4	26.9	24.5	74.4
1.4 उपहार	1,370.2	139.1	106.1	103.6	161.0
1.5 दान	8.7	0.6	0.6	0.6	0.3
1.6 यात्रा	4,803.8	334.7	506.1	366.4	429.2
1.7 निकट संबंधियों का रखरखाव	2,800.9	318.6	242.8	199.8	322.9
1.8 चिकित्सा उपचार	28.6	2.4	3.0	1.6	2.5
1.9 विदेश में शिक्षा	3,569.9	134.1	400.3	296.7	333.8
1.10 अन्य	242.2	26.9	16.2	15.4	41.6

सं. 36: भारतीय रुपये का वास्तविक प्रभावी विनिमय दर सूचकांक (रीर) और सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर सूचकांक (नीर)

	2017-18	2018-19	2018	2019	
			अप्रैल	मार्च	अप्रैल
मद	1	2	3	4	5
36-मुद्रा निर्यात और व्यापार आधारित भारांक (आधार: 2004-05=100)					
1 व्यापार आधारित भारांक					
1.1 नीर	76.94	72.63	74.44	73.52	73.75
1.2 रीर	119.71	113.99	116.26	115.00	115.37
2 निर्यात आधारित भारांक					
2.1 नीर	78.89	74.17	76.32	75.11	75.35
2.2 रीर	121.94	116.30	118.98	117.42	117.81
6-मुद्रा व्यापार आधारित भारांक					
1 आधार : 2004-05 (अप्रैल-मार्च) =100					
1.1 नीर	67.91	63.07	64.53	63.88	64.07
1.2 रीर	129.19	121.70	123.47	123.30	123.33
2 आधार : 2017-18 (अप्रैल-मार्च) =100					
2.1 नीर	100.00	92.88	95.02	94.06	94.35
2.2 रीर	100.00	94.20	95.57	95.44	95.46

सं. 37: बाह्य वाणिज्यिक उधार — पंजीकरण

(राशि अमेरिकी मिलियन डालर में)

मद	2017-18	2018	2019	
		मार्च	फरवरी	मार्च
	1	2	3	4
1 स्वचालित मार्ग				
1.1 संख्या	769	91	88	130
1.2 राशि	20,397	3,575	2,812	4,894
2 अनुमोदन मार्ग				
2.1 संख्या	38	6	-	7
2.2 राशि	8,471	1,500	-	7,831
3 कुल (1+2)				
3.1 संख्या	807	97	88	137
3.2 राशि	28,868	5,075	2,812	12,725
4 भारित औसत परिपक्वता (वर्षों में)	6.10	5.70	5.80	5.10
5 ब्याज दर (प्रतिशत)				
5.1 6 महीने के लिबॉर पर भारित औसत मार्जिन या अस्थिर दर के ऋणों के लिए संदर्भ दर	1.34	1.08	1.56	1.29
5.2 सावधि दर के ऋणों के लिए ब्याज दर की सीमा	0.00-12.25	0.00-12.05	1.20-10.50	0.00-11.65

सं. 38: भारत का समग्र भुगतान संतुलन

(मिलियन अमेरिकी डालर)

मद	अक्तूबर-दिसंबर 2017 (आं.सं)			अक्तूबर-दिसंबर 2018 (प्रा.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
समग्र भुगतान शेष (1+2+3)	**320,203**	**310,768**	**9,434**	**286,966**	**291,262**	**–4,296**
1 चालू खाता (1.1+1.2)	**150,254**	**163,970**	**–13,716**	**164,437**	**181,351**	**–16,914**
1.1 पण्य	**77,541**	**121,564**	**–44,022**	**83,082**	**132,573**	**–49,491**
1.2 अदृश्य मदें (1.2.1+1.2.2+1.2.3)	**72,712**	**42,406**	**30,306**	**81,355**	**48,778**	**32,577**
1.2.1 सेवाएं	50,179	29,467	20,712	55,250	33,951	21,299
1.2.1.1 यात्रा	7,441	4,606	2,836	7,372	4,863	2,510
1.2.1.2 परिवहन	4,388	4,419	–31	4,807	5,231	–424
1.2.1.3 बीमा	611	435	176	689	419	271
1.2.1.4 जीएनआईई	203	193	11	144	289	–145
1.2.1.5 विविध	37,536	19,815	17,721	42,237	23,149	19,088
1.2.1.5.1 सॉफ्टवेयर सेवाएं	19,532	1,333	18,199	21,103	1,254	19,849
1.2.1.5.2 कारोबार सेवाएं	9,859	9,360	499	9,978	10,131	–152
1.2.1.5.3 वित्तीय सेवाएं	983	1,574	–591	1,324	992	332
1.2.1.5.4 संचार सेवाएं	414	239	175	673	284	390
1.2.2 अंतरण	17,685	1,623	16,062	18,795	1,552	17,243
1.2.2.1 आधिकारिक	96	202	–105	102	237	–134
1.2.2.2 निजी	17,589	1,422	16,167	18,693	1,316	17,377
1.2.3 आय	4,848	11,316	–6,468	7,310	13,274	–5,964
1.2.3.1 निवेश आय	3,693	10,745	–7,052	5,946	12,683	–6,736
1.2.3.2 कर्मचारियों को क्षति पूर्ति	1,155	572	584	1,363	591	772
2 पूंजी खाता (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	**169,329**	**146,799**	**22,530**	**122,529**	**108,922**	**13,608**
2.1 विदेशी निवेश (2.1.1+2.1.2)	**93,973**	**84,329**	**9,645**	**73,262**	**67,850**	**5,412**
2.1.1 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	15,270	10,947	4,323	16,155	8,633	7,523
2.1.1.1 भारत में	14,301	8,315	5,985	15,530	5,139	10,391
2.1.1.1.1 इक्विटी	10,755	8,287	2,468	11,005	5,101	5,904
2.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	3,182	–	3,182	3,504	–	3,504
2.1.1.1.3 अन्य पूंजी	364	29	335	1,022	38	984
2.1.1.2 विदेश में	969	2,631	–1,662	625	3,494	–2,869
2.1.1.2.1 इक्विटी	969	1,190	–221	625	1,719	–1,094
2.1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	0	713	–713	–	753	–753
2.1.1.2.3 अन्य पूंजी	0	728	–728	0	1,021	–1,021
2.1.2 संविभाग निवेश	78,703	73,382	5,322	57,107	59,218	–2,111
2.1.2.1 भारत में	78,576	73,145	5,430	56,733	58,921	–2,188
2.1.2.1.1 एफआईआई	78,576	73,145	5,430	56,733	58,921	–2,188
2.1.2.1.1.1 इक्विटी	63,467	61,246	2,221	45,530	47,949	–2,419
2.1.2.1.1.2 ऋण	15,109	11,900	3,209	11,203	10,972	231
2.1.2.1.2 एडीआर /जीडीआर	0	0	0	0	0	0
2.1.2.2 विदेश में	127	236	–109	374	297	77
2.2 ऋण (2.2.1+2.2.2+2.2.3)	**38,158**	**32,247**	**5,911**	**20,355**	**17,463**	**2,892**
2.2.1 बाह्य सहायता	1,947	1,201	746	2,960	1,278	1,682
2.2.1.1 भारत द्वारा	14	31	–17	11	29	–18
2.2.1.2 भारत को	1,934	1,170	764	2,949	1,249	1,700
2.2.2 वाणिज्यिक उधार	10,761	10,378	383	10,331	8,375	1,955
2.2.2.1 भारत द्वारा	2,755	2,623	132	3,337	3,346	–9
2.2.2.2 भारत को	8,006	7,755	251	6,993	5,029	1,964
2.2.3 भारत को अल्पावधि	25,449	20,667	4,782	7,064	7,809	–745
2.2.3.1 आपूर्तिकर्ता का ऋण >180 दिन तथा खरीदार का ऋण	24,456	20,667	3,789	4,433	7,809	–3,377
2.2.3.2 आपूर्तिकर्ता का 180 दिन तक का ऋण	993	0	993	2,631	0	2,631
2.3 बैंकिंग पूंजी (2.3.1+2.3.2)	**25,355**	**20,775**	**4,580**	**21,193**	**16,279**	**4,913**
2.3.1 वाणिज्यिक बैंक	25,107	20,775	4,332	21,193	16,095	5,098
2.3.1.1 आस्तियां	8,245	8,721	–475	5,964	1,763	4,202
2.3.1.2 देयताएं	16,861	12,054	4,807	15,228	14,332	896
2.3.1.2.1 अनिवासी जमाराशियां	14,489	11,398	3,091	13,298	13,159	139
2.3.2 अन्य	248	0	248	0	185	–185
2.4 रुपया ऋण चुकौती	–	0	0	0	0	0
2.5 अन्य पूंजी	11,843	9,449	2,394	7,720	7,329	391
3 भूल-चूक	**621**	**–**	**621**	**–**	**989**	**–989**
4 मौद्रिक गतिविधियां (4.1+4.2)	0	**9,434**	**–9,434**	**4,296**	0	**4,296**
4.1 आईएमएफ	0	0	0	–	–	–
4.2 विदेशी मुद्रा भंडार (वृद्धि -/ कमी +)	0	9,434	–9,434	4,296	0	4,296

सं. 39: भारत का समग्र भुगतान संतुलन

(बिलियन ₹)

मद	अक्तूबर-दिसंबर 2017 (आं.सं)			अक्तूबर-दिसंबर 2018 (प्रा.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
समग्र भुगतान शेष (1+2+3)	**20,726**	**20,116**	**611**	**20,682**	**20,992**	**–310**
1 चालू खाता (1.1+1.2)	**9,726**	**10,614**	**–888**	**11,851**	**13,070**	**–1,219**
1.1 पण्य	**5,019**	**7,869**	**–2,850**	**5,988**	**9,555**	**–3,567**
1.2 अदृश्य मदें (1.2.1+1.2.2+1.2.3)	**4,707**	**2,745**	**1,962**	**5,863**	**3,516**	**2,348**
1.2.1 सेवाएं	3,248	1,907	1,341	3,982	2,447	1,535
1.2.1.1 यात्रा	482	298	184	531	350	181
1.2.1.2 परिवहन	284	286	–2	346	377	–31
1.2.1.3 बीमा	40	28	11	50	30	20
1.2.1.4 जीएनआईई	13	12	1	10	21	–10
1.2.1.5 विविध	2,430	1,283	1,147	3,044	1,668	1,376
1.2.1.5.1 सॉफ्टवेयर सेवाएं	1,264	86	1,178	1,521	90	1,431
1.2.1.5.2 कारोबार सेवाएं	638	606	32	719	730	–11
1.2.1.5.3 वित्तीय सेवाएं	64	102	–38	95	71	24
1.2.1.5.4 संचार सेवाएं	27	15	11	49	20	28
1.2.2 अंतरण	1,145	105	1,040	1,355	112	1,243
1.2.2.1 आधिकारिक	6	13	–7	7	17	–10
1.2.2.2 निजी	1,138	92	1,046	1,347	95	1,252
1.2.3 आय	314	732	–419	527	957	–430
1.2.3.1 निवेश आय	239	695	–456	429	914	–485
1.2.3.2 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	75	37	38	98	43	56
2 पूंजी खाता (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	**10,960**	**9,502**	**1,458**	**8,831**	**7,850**	**981**
2.1 विदेशी निवेश (2.1.1+2.1.2)	6,083	5,458	624	5,280	4,890	390
2.1.1 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	988	709	280	1,164	622	542
2.1.1.1 भारत में	926	538	387	1,119	370	749
2.1.1.1.1 इक्विटी	696	536	160	793	368	425
2.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	206	0	206	253	0	253
2.1.1.1.3 अन्य पूंजी	24	2	22	74	3	71
2.1.1.2 विदेश में	63	170	–108	45	252	–207
2.1.1.2.1 इक्विटी	63	77	–14	45	124	–79
2.1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	0	46	–46	0	54	–54
2.1.1.2.3 अन्य पूंजी	0	47	–47	0	74	–74
2.1.2 संविभाग निवेश	5,094	4,750	344	4,116	4,268	–152
2.1.2.1 भारत में	5,086	4,735	351	4,089	4,247	–158
2.1.2.1.1 एफआईआई	5,086	4,735	351	4,089	4,247	–158
2.1.2.1.1.1 इक्विटी	4,108	3,964	144	3,281	3,456	–174
2.1.2.1.1.2 ऋण	978	770	208	807	791	17
2.1.2.1.2 एडीआर /जीडीआर	0	0	0	0	0	0
2.1.2.2 विदेश में	8	15	–7	27	21	6
2.2 ऋण (2.2.1+2.2.2+2.2.3)	**2,470**	**2,087**	**383**	**1,467**	**1,259**	**208**
2.2.1 बाह्य सहायता	126	78	48	213	92	121
2.2.1.1 भारत द्वारा	1	2	–1	1	2	–1
2.2.1.2 भारत को	125	76	49	213	90	122
2.2.2 वाणिज्यिक उधार	697	672	25	745	604	141
2.2.2.1 भारत द्वारा	178	170	9	241	241	–1
2.2.2.2 भारत को	518	502	16	504	362	142
2.2.3 भारत को अल्पावधि	1,647	1,338	310	509	563	–54
2.2.3.1 आपूर्तिकर्ता का ऋण >180 दिन तथा खरीदार का ऋण	1,583	1,338	245	319	563	–243
2.2.3.2 आपूर्तिकर्ता का 180 दिन तक का ऋण	64	0	64	190	0	190
2.3 बैंकिंग पूंजी (2.3.1+2.3.2)	**1,641**	**1,345**	**296**	**1,527**	**1,173**	**354**
2.3.1 वाणिज्यिक बैंक	1,625	1,345	280	1,527	1,160	367
2.3.1.1 आस्तियां	534	564	–31	430	127	303
2.3.1.2 देयताएं	1,091	780	311	1,098	1,033	65
2.3.1.2.1 अनिवासी जमाराशियां	938	738	200	958	948	10
2.3.2 अन्य	16	0	16	0	13	–13
2.4 रुपया ऋण चुकौती	0	0	0	0	0	0
2.5 अन्य पूंजी	767	612	155	556	528	28
3 भूल-चूक	**40**	0	**40**	0	**71**	**–71**
4 मौद्रिक गतिविधियां (4.1+4.2)	0	**611**	**–611**	**310**	0	**310**
4.1 आईएमएफ	–	–	–	0	0	0
4.2 विदेशी मुद्रा भंडार (वृद्धि - / कमी +)	0	611	–611	310	0	310

सं. 40: बीपीएम6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण

(मिलियन अमेरिकी डालर)

मद	अक्तूबर-दिसंबर 2017 (आं.सं)			अक्तूबर-दिसंबर 2018 (प्रा.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
1 चालू खाता (1.अ+1आ+1.इ)	**150,247**	**163,950**	**–13,704**	**164,430**	**181,330**	**–16,900**
1.अ माल और सेवाएं (1.अ.क.+ 1अ.ख.)	**127,720**	**151,030**	**–23,310**	**138,332**	**166,524**	**–28,193**
1.अ.क. माल (1.अ.क.1 से 1अ.क.3)	**77,541**	**121,564**	**–44,022**	**83,082**	**132,573**	**–49,491**
1.अ.क.1 बीओपी आधार पर सामान्य वाणिज्यिक वस्तुएं	77,848	111,951	–34,103	82,438	125,486	–43,048
1.अ.क.2 वाणिज्यिक के अंतर्गत माल का निवल निर्यात	–307	0	–307	643	–	643
1..अ.क.3 गैर-मौद्रिक स्वर्ण	–	9,612	–9,612	–	7,087	–7,087
1.अ.ख सेवाएं (1.अ.ख.1 से 1.अ.ख.13)	**50,179**	**29,467**	**20,712**	**55,250**	**33,951**	**21,299**
1.अ.ख.1 अन्य के स्वामित्ववाले भौतिक इनपुट पर विनिर्माण सेवाएं	34	13	21	99	13	87
1.अ.ख.2 अन्यत्र शामिल न की गई रखरखाव व मरम्मत सेवाएं	43	129	–87	64	376	–313
1.अ.ख.3 परिवहन	4,388	4,419	–31	4,807	5,231	–424
1.अ.ख.4 यात्रा	7,441	4,606	2,836	7,372	4,863	2,510
1.अ.ख.5 निर्माण	529	327	201	865	618	247
1.अ.ख.6 बीमा और पेंशन सेवाएं	611	435	176	689	419	271
1.अ.ख.7 वित्तीय सेवाएं	983	1,574	–591	1,324	992	332
1.अ.ख.8 अन्यत्र शामिल न किए गए बौद्धिक संपत्ति के उपयोग के लिए प्रभार	215	1,929	–1,714	182	2,173	–1,990
1.अ.ख.9 दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं	20,071	1,662	18,409	21,862	1,629	20,233
1.अ.ख.10 अन्य कारोबारी सेवाएं	9,859	9,360	499	9,978	10,131	–152
1.अ.ख.11 वैयक्तिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन संबंधी सेवाएं	366	501	–135	459	583	–124
1.अ.ख.12 अन्यत्र शामिल न की गई सरकारी माल और सेवाएं	203	193	11	144	289	–145
1.अ.ख.13 अन्य जो अन्यत्र शामिल नहीं है	5,437	4,320	1,117	7,403	6,635	768
1.आ प्राथमिक आय (1.आ.1 से 1.आ.3)	**4,848**	**11,316**	**–6,468**	**7,310**	**13,274**	**–5,964**
1.आ.1 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	1,155	572	584	1,363	591	772
1.आ.2 निवेश आय	3,068	10,626	–7,558	5,089	12,516	–7,427
1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश	1,508	4,743	–3,235	1,663	6,548	–4,885
1.आ.2.2 संविभाग निवेश	19	2,618	–2,599	35	2,311	–2,277
1.आ.2.3 अन्य निवेश	332	3,257	–2,925	204	3,642	–3,438
1.आ.2.4 रिज़र्व आस्तियां	1,209	8	1,201	3,187	14	3,174
1.आ.3 अन्य प्राथमिक आय	625	119	506	857	167	690
1.इ द्वितीयक आय (1.इ.1+1.इ.2)	**17,678**	**1,604**	**16,074**	**18,789**	**1,532**	**17,257**
1.इ.1 वित्तीय निगम, वित्तेतर निगम, परिवार और एनपीआईएसएच	17,589	1,422	16,167	18,693	1,316	17,377
1.इ.1.1 वैयक्तिक अंतरण (निवासी और / अनिवासी परिवारों के बीच चालू अंतरण)	17,011	1,083	15,928	18,019	987	17,032
1.इ.1.2 अन्य चालू अंतरण	578	339	239	674	329	345
1.इ.2 सामान्य सरकार	89	182	–93	96	216	–120
2. पूँजी खाता (2.1+2.2)	**131**	**97**	**33**	**71**	**147**	**–76**
2.1 अनुत्पादित वित्तेतर आस्तियों का सकल अधिग्रहण (नामे) / निस्तारण (जमा)	47	19	28	5	42	–36
2.2 पूँजी अतंरण	84	78	5	66	106	–40
3. वित्तीय खाता (3.1 से 3.5)	**169,205**	**156,155**	**13,050**	**126,760**	**108,795**	**17,965**
3.1 प्रत्यक्ष निवेश (3.1अ+3.1आ)	**15,270**	**10,947**	**4,323**	**16,155**	**8,633**	**7,523**
3.1अ भारत में प्रत्यक्ष निवेश	14,301	8,315	5,985	15,530	5,139	10,391
3.1.अ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	13,937	8,287	5,650	14,509	5,101	9,408
3.1.अ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश से इतर इक्विटी	10,755	8,287	2,468	11,005	5,101	5,904
3.1.अ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	3,182	–	3,182	3,504	–	3,504
3.1.अ.2 ऋण लिखत	364	29	335	1,022	38	984
3.1.अ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	364	29	335	1,022	38	984
3.1.आ. भारत द्वारा प्रत्यक्ष निवेश	969	2,631	–1,662	625	3,494	–2,869
3.1.आ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	969	1,903	–934	625	2,472	–1,847
3.1.आ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश को छोड़कर इक्विटी	969	1,190	–221	625	1,719	–1,094
3.1.आ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	–	713	–713	–	753	–753
3.1.आ.2 ऋण लिखत	0	728	–728	0	1,021	–1,021
3.1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	–	728	–728	–	1,021	–1,021
3.2 संविभाग निवेश	**78,703**	**73,382**	**5,322**	**57,107**	**59,218**	**–2,111**
3.2अ भारत में संविभाग निवेश	78,576	73,145	5,430	56,733	58,921	–2,188
3.2.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	63,467	61,246	2,221	45,530	47,949	–2,419
3.2.2 ऋण प्रतिभूतियां	15,109	11,900	3,209	11,203	10,972	231
3.2आ. भारत द्वारा संविभाग निवेश	127	236	–109	374	297	77
3.3 वित्तीय डेरिवेटिव (रिज़र्व निधियों को छोड़कर) और कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन	**5,402**	**5,905**	**–503**	**5,859**	**5,362**	**497**
3.4 अन्य निवेश	**69,829**	**56,487**	**13,342**	**43,343**	**35,583**	**7,760**
3.4.1 अन्य इक्विटी (एडीआर/जीडीआर)	0	0	0	0	0	0
3.4.2 मुद्रा और जमाराशियां	14,738	11,398	3,340	13,298	13,343	–46
3.4.2.1 केंद्रीय बैंक (रूपी डेट मूवमेंट; एनआरजी)	248	0	248	0	185	–185
3.4.2.2 केंद्रीय बैंक को छोड़कर जमाराशियां लेनेवाले निगम (अनिवासी भारतीय जमाराशियां)	14,489	11,398	3,091	13,298	13,159	139
3.4.2.3 सामान्य सरकार	–	–	–	–	–	–
3.4.2.4 अन्य क्षेत्र	–	–	–	–	–	–
3.4.3 ऋण (बाह्य सहायता, ईसीबी और बैंकिंग पूँजी)	23,326	20,956	2,370	21,186	12,590	8,596
3.4.3अ भारत को ऋण	20,557	18,301	2,255	17,837	9,214	8,623
3.4.3आ भारत द्वारा ऋण	2,769	2,654	114	3,348	3,376	–27
3.4.4 बीमा, पेंशन, और मानकीकृत गारंटी योजनाएं	21	58	–37	29	207	–179
3.4.5 व्यापार ऋण और अग्रिम	25,449	20,667	4,782	7,064	7,809	–745
3.4.6 अन्य खाते प्राप्य /देय-अन्य	6,296	3,407	2,889	1,767	1,633	134
3.4.7 विशेष आहरण अधिकार	–	–	–	0	0	0
3.5 आरक्षित आस्तियां	0	**9,434**	**–9,434**	**4,296**	0	**4,296**
3.5.1 मौद्रिक स्वर्ण	–	–	–	–	–	–
3.5.2 विशेष आहरण अधिकार एन.ए	–	–	–	–	–	–
3.5.3 आईएमएफ में रिज़र्व निधियों की स्थिति एन.ए	–	–	–	–	–	–
3.5.4 अन्य रिज़र्व आस्तियां (विदेशी मुद्रा आस्तियां)	0	9,434	–9,434	4,296	0	4,296
4. कुल आस्तियां / देयताएं	**169,205**	**156,155**	**13,050**	**126,760**	**108,795**	**17,965**
4.1 इक्विटी तथा निवेश निधि शेयर	83,924	77,636	6,288	66,925	61,388	5,537
4.2 ऋण लिखत	78,985	65,678	13,308	53,772	45,774	7,998
4.3 अन्य वित्तीय आस्तियां और देयताएं	6,296	12,842	–6,546	6,063	1,633	4,430
5. निवल भूल-चूक	**621**	–	**621**	–	**989**	**–989**

सं. 41: बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण

(बिलियन ₹)

मद	अक्तूबर-दिसंबर 2017 (आं.सं)			अक्तूबर-दिसंबर 2018 (प्रा.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
1. चालू खाता (1.अ+1.आ+1.इ)	**9,725**	**10,612**	**–887**	**11,851**	**13,069**	**–1,218**
1.अ माल और सेवाएं (1.अ.क.+ 1अ.ख.)	**8,267**	**9,776**	**–1,509**	**9,970**	**12,002**	**–2,032**
1.अ.क. माल (1.अ.क.1 से 1अ.क.3)	**5,019**	**7,869**	**–2,850**	**5,988**	**9,555**	**–3,567**
1.अ.क.1 बीओपी आधार पर सामान्य वाणिज्यिक वस्तुएं	5,039	7,246	–2,207	5,942	9,044	–3,103
1.अ.क.2 वाणिज्यिक के अंतर्गत माल का निवल निर्यात	–20	0	–20	46	–	46
1..अ.क.3 गैर-मौद्रिक स्वर्ण	0	622	–622	0	511	–511
1.अ.ख सेवाएं (1.अ.ख.1 से 1.अ.ख.13)	**3,248**	**1,907**	**1,341**	**3,982**	**2,447**	**1,535**
1.अ.ख.1 अन्य के स्वामित्ववाले भौतिक इनपुट पर विनिर्माण सेवाएं	2	1	1	7	1	6
1.अ.ख.2 अन्यत्र शामिल न की गई रखरखाव व मरम्मत सेवाएं	3	8	–6	5	27	–23
1.अ.ख.3 परिवहन	284	286	–2	346	377	–31
1.अ.ख.4 यात्रा	482	298	184	531	350	181
1.अ.ख.5 निर्माण	34	21	13	62	45	18
1.अ.ख.6 बीमा और पेंशन सेवाएं	40	28	11	50	30	20
1.अ.ख.7 वित्तीय सेवाएं	64	102	–38	95	71	24
1.अ.ख.8 अन्यत्र शामिल न किए गए बौद्धिक संपत्ति के उपयोग के लिए प्रभार	14	125	–111	13	157	–143
1.अ.ख.9 दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं	1,299	108	1,192	1,576	117	1,458
1.अ.ख.10 अन्य कारोबारी सेवाएं	638	606	32	719	730	–11
1.अ.ख.11 वैयक्तिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन संबंधी सेवाएं	24	32	–9	33	42	–9
1.अ.ख.12 अन्यत्र शामिल न की गई सरकारी माल और सेवाएं	13	12	1	10	21	–10
1.अ.ख.13 अन्य जो अन्यत्र शामिल नहीं है	352	280	72	534	478	55
1.आ प्राथमिक आय (1.आ.1 से 1.आ.3)	**314**	**732**	**–419**	**527**	**957**	**–430**
1.आ.1 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	75	37	38	98	43	56
1.आ.2 निवेश आय	199	688	–489	367	902	–535
1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश	98	307	–209	120	472	–352
1.आ.2.2 संविभाग निवेश	1	169	–168	2	167	–164
1.आ.2.3 अन्य निवेश	22	211	–189	15	263	–248
1.आ.2.4 रिज़र्व आस्तियां	78	1	78	230	1	229
1.आ.3 अन्य प्राथमिक आय	40	8	33	62	12	50
1.इ द्वितीयक आय (1.इ.1+1.इ.2)	**1,144**	**104**	**1,040**	**1,354**	**110**	**1,244**
1.इ.1 वित्तीय निगम, वित्तेतर निगम, परिवार और एनपीआईएसएच	1,138	92	1,046	1,347	95	1,252
1.इ.1.1 वैयक्तिक अंतरण (निवासी और / अनिवासी परिवारों के बीच चालू अंतरण)	1,101	70	1,031	1,299	71	1,228
1.इ.1.2 अन्य चालू अंतरण	37	22	15	49	24	25
1.इ.2 सामान्य सरकार	6	12	–6	7	16	–9
2. पूँजी खाता (2.1+2.2)	**8**	**6**	**2**	**5**	**11**	**–6**
2.1 अनुत्पादित वित्तेतर आस्तियों का सकल अधिग्रहण (नामे) / निस्तारण (जमा)	3	1	2	0	3	–3
2.2 पूँजी अंतरण	5	5	0	5	8	–3
3. वित्तीय खाता (3.1 से 3.5)	**10,952**	**10,108**	**845**	**9,136**	**7,841**	**1,295**
3.1 प्रत्यक्ष निवेश (3.1अ+3.1आ)	**988**	**709**	**280**	**1,164**	**622**	**542**
3.1अ भारत में प्रत्यक्ष निवेश	926	538	387	1,119	370	749
3.1.अ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	902	536	366	1,046	368	678
3.1.अ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश से इतर इक्विटी	696	536	160	793	368	425
3.1.अ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	206	0	206	253	0	253
3.1.अ.2 ऋण लिखत	24	2	22	74	3	71
3.1.अ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	24	2	22	74	3	71
3.1.आ. भारत द्वारा प्रत्यक्ष निवेश	63	170	–108	45	252	–207
3.1.आ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	63	123	–60	45	178	–133
3.1.आ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश को छोड़कर इक्विटी	63	77	–14	45	124	–79
3.1.आ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	0	46	–46	0	54	–54
3.1.आ.2 ऋण लिखत	0	47	–47	0	74	–74
3.1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	0	47	–47	0	74	–74
3.2 संविभाग निवेश	**5,094**	**4,750**	**344**	**4,116**	**4,268**	**–152**
3.2अ भारत में संविभाग निवेश	5,086	4,735	351	4,089	4,247	–158
3.2.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	4,108	3,964	144	3,281	3,456	–174
3.2.2 ऋण प्रतिभूतियां	978	770	208	807	791	17
3.2आ. भारत द्वारा संविभाग निवेश	8	15	–7	27	21	6
3.3 वित्तीय डेरिवेटिव (रिज़र्व निधियों को छोड़कर) और कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन	**350**	**382**	**–33**	**422**	**386**	**36**
3.4 अन्य निवेश	**4,520**	**3,656**	**864**	**3,124**	**2,565**	**559**
3.4.1 अन्य इक्विटी (एडीआर/जीडीआर)	0	0	0	0	0	0
3.4.2 मुद्रा और जमाराशियां	954	738	216	958	962	–3
3.4.2.1 केंद्रीय बैंक (रूपी डेट मूवमेंट; एनआरजी)	16	0	16	0	13	–13
3.4.2.2 केंद्रीय बैंक को छोड़कर जमाराशियां लेनेवाले निगम (अनिवासी भारतीय जमाराशियां)	938	738	200	958	948	10
3.4.2.3 सामान्य सरकार	–	–	–	–	–	–
3.4.2.4 अन्य क्षेत्र	–	–	–	–	–	–
3.4.3 ऋण (बाह्य सहायता, ईसीबी और बैंकिंग पूँजी)	1,510	1,356	153	1,527	907	620
3.4.3अ भारत को ऋण	1,331	1,185	146	1,286	664	621
3.4.3आ भारत द्वारा ऋण	179	172	7	241	243	–2
3.4.4 बीमा, पेंशन, और मानकीकृत गारंटी योजनाएं	1	4	–2	2	15	–13
3.4.5 व्यापार ऋण और अग्रिम	1,647	1,338	310	509	563	–54
3.4.6 अन्य खाते प्राप्य/देय-अन्य	408	221	187	127	118	10
3.4.7 विशेष आहरण अधिकार	–	–	–	0	0	0
3.5 आरक्षित आस्तियां	**0**	**611**	**–611**	**310**	**0**	**310**
3.5.1 मौद्रिक स्वर्ण	–	–	–	–	–	–
3.5.2 विशेष आहरण अधिकार एन.ए	–	–	–	–	–	–
3.5.3 आईएमएफ में रिज़र्व निधियों की स्थिति एन.ए	–	–	–	–	–	–
3.5.4 अन्य रिज़र्व आस्तियां (विदेशी मुद्रा आस्तियां)	0	611	–611	310	0	310
4. कुल आस्तियां / देयताएं	**10,952**	**10,108**	**845**	**9,136**	**7,841**	**1,295**
4.1 इक्विटी तथा निवेश निधि शेयर	5,432	5,025	407	4,823	4,424	399
4.2 ऋण लिखत	5,113	4,251	861	3,876	3,299	576
4.3 अन्य वित्तीय आस्तियां और देयताएं	408	831	–424	437	118	319
5. निवल भूल-चूक	**40**	**–**	**40**	**–**	**71**	**–71**

सं. 42: अंतरराष्ट्रीय निवेश की स्थिति

(मिलियन अमेरिकी डालर)

मद	वित्तीय वर्ष / समाप्त तिमाही की स्थिति							
	2017-18		2017		2018			
			दिसंबर		सितंबर		दिसंबर	
	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 विदेश/भारत में प्रत्यक्ष निवेश	157,373	378,957	155,176	377,478	163,325	362,162	166,193	386,354
1.1 इक्विटी पूंजी और पुनर्निवेशित अर्जन	103,734	363,190	102,500	361,451	107,808	346,320	109,655	369,706
1.2 अन्य पूंजी	53,640	15,767	52,676	16,026	55,517	15,842	56,538	16,648
2 संविभाग निवेश	3,577	272,146	2,939	267,497	2,641	237,865	2,666	245,817
2.1 इक्विटी	2,054	155,106	1,975	155,675	1,804	135,249	1,386	138,091
2.2 ऋण	1,524	117,040	964	111,822	837	102,616	1,280	107,727
3 अन्य निवेश	48,235	401,046	46,281	390,267	41,530	395,402	39,394	403,366
3.1 व्यापार ऋण	1,696	103,155	1,572	98,442	904	104,333	252	103,650
3.2 ऋण	8,225	159,699	5,577	155,927	7,073	157,447	6,542	160,329
3.3 मुद्रा और जमाराशियां	20,790	126,456	20,769	123,546	16,628	122,137	17,211	125,997
3.4 अन्य आस्तियां/देयताएं	17,524	11,736	18,363	12,351	16,925	11,486	15,388	13,390
4 रिज़र्व्स	424,545	–	409,072	–	400,525	–	395,591	–
5 कुल आस्तियां/देयताएं	633,731	1,052,150	613,094	1,035,241	608,022	995,429	603,844	1,035,537
6 आईआईपी (आस्तियां - देयताएं)		–418,419		–421,428		–387,408		–431,693

भुगतान और निपटान प्रणाली

सं. 43: भुगतान प्रणाली संकेतक

प्रणाली	मात्रा (मिलियन)				मूल्य (बिलियन ₹)			
	2018-19	2019			2018-19	2019		
		जनवरी	फरवरी	मार्च		जनवरी	फरवरी	मार्च
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 आरटीजीएस	**136.63**	**11.78**	**11.09**	**13.64**	**1,715,520.61**	**156,570.32**	**146,468.19**	**190,693.10**
1.1 ग्राहक लेनदेन	133.30	11.50	10.84	13.35	1,184,368.12	106,991.92	94,576.26	125,551.00
1.2 अंतरबैंक लेनदेन	3.31	0.27	0.25	0.29	172,513.75	17,805.11	18,183.59	23,178.34
1.3 अंतरबैंक समाशोधन	0.027	0.001	0.002	0.003	358,638.74	31,773.29	33,708.34	41,963.75
2 सीसीआईएल परिचालित प्रणाली	**3.62**	**0.31**	**0.27**	**0.28**	**1,165,510.38**	**100,832.13**	**98,962.53**	**103,147.77**
2.1 सीबीएलओ	0.130	–	–	–	181,404.63	–	–	–
2.2 सरकारी प्रतिभूतियों का समाशोधन	1.11	0.11	0.10	0.09	509,315.87	62,249.17	59,795.85	53,731.05
2.2.1 एकमुश्त	0.81	0.08	0.06	0.06	93,550.07	8,773.42	7,912.97	7,361.13
2.2.2 रिपो	0.216	0.018	0.017	0.017	271,249.89	21,206.86	21,154.91	18,540.59
2.3 विदेशी समाशोधन	0.09	0.02	0.02	0.02	144,515.90	32,268.89	30,727.96	27,829.33
3 पेपर समाशोधन	2.38	0.20	0.17	0.19	474,789.88	38,582.95	39,166.68	49,416.73
3.1 चेक ट्रंकेशन प्रणाली	**1,123.76**	**94.43**	**86.99**	**99.76**	**82,460.65**	**6,867.63**	**6,414.49**	**7,658.15**
3.2 एमआईसीआर समाशोधन	1,111.67	93.60	86.27	99.16	81,535.92	6,804.43	6,369.68	7,610.47
3.2.1 आरबीआई के केन्द्र	–	–	–	–	–	–	–	–
3.2.2 अन्य केन्द्र	–	–	–	–	–	–	–	–
3.3 गैर-एमआईसीआर समाशोधन	–	–	–	–	–	–	–	–
	12.09	0.83	0.72	0.60	924.73	63.20	44.81	47.68
4 खुदरा इलेक्ट्रानिक समाशोधन	**7,113.25**	**621.96**	**633.61**	**727.32**	**258,745.44**	**22,415.03**	**22,026.20**	**28,878.55**
4.1 ईसीएस नामे	0.93	0.03	0.03	0.02	12.60	0.12	0.15	0.09
4.2 ईसीएस जमा (एनईसीएस शामिल है)	5.36	0.40	0.37	0.25	132.35	9.07	14.40	10.48
4.3 ईएफटी/एनईएफटी	2,318.89	205.13	201.10	242.39	227,936.08	19,662.62	19,214.30	25,470.01
4.4 तुरंत भुगतान सेवाएं (आईएमपीएस)	1,752.91	171.51	166.37	190.18	15,902.57	1,522.97	1,493.43	1,762.89
4.5 राष्ट्रीय स्वचलित समाशोधन गृह (एनएसीएच)	3,035.17	244.89	265.73	294.47	14,761.84	1,220.26	1,303.92	1,635.08
5 कार्ड	**16,046.26**	**1,414.44**	**1,306.53**	**1,462.26**	**45,121.45**	**3,720.32**	**3,537.98**	**4,000.60**
5.1 क्रेडिट कार्ड	1,772.36	160.43	142.13	163.27	6,078.81	553.39	488.59	580.49
5.1.1 एटीएम का प्रयोग	9.77	0.86	0.79	0.86	45.33	3.94	3.70	3.98
5.1.2 पीओएस का प्रयोग	1,762.59	159.57	141.34	162.41	6,033.48	549.45	484.89	576.51
5.2 डेबिट कार्ड	14,273.90	1,254.01	1,164.40	1,298.99	39,042.64	3,166.92	3,049.40	3,420.10
5.2.1 एटीएम का प्रयोग	9,859.61	880.48	817.92	891.42	33,107.89	2,661.24	2,594.31	2,889.99
5.2.2 पीओएस का प्रयोग	4,414.28	373.53	346.48	407.57	5,934.75	505.68	455.09	530.11
6 प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआई)	**4,604.34**	**443.58**	**384.85**	**427.24**	**2,128.76**	**187.03**	**164.97**	**185.99**
6.1 एम-वॉलेट	4,139.28	395.83	345.03	384.89	1,836.55	158.58	142.79	159.90
6.2 पीपीआई कार्ड	465.00	47.75	39.82	42.35	291.34	28.45	22.18	26.09
6.3 पेपर वाउचर	0.05	0.00	0.00	0.00	0.87	–	–	–
7 मोबाइल बैंकिंग	**6,194.80**	**710.90**	**739.41**	**867.41**	**29,577.05**	**2,959.74**	**3,047.25**	**4,394.51**
8 कार्ड बकाया	**971.72**	**976.43**	**990.61**	**971.72**	–	–	–	–
8.1 क्रेडिट कार्ड	47.09	45.17	46.06	47.09	–	–	–	–
8.2 डेबिट कार्ड	924.63	931.26	944.55	924.63	–	–	–	–
9 एटीएम की संख्या (वास्तव में)	**221703**	**221848**	**221786**	**221703**	–	–	–	–
10 पीओएस की संख्या (वास्तव में)	**3722229**	**3657596**	**3636851**	**3722229**	–	–	–	–
11 कुल जोड़ (1.1+1.2+2+3+4+5+6)	**29,027.83**	**2,586.50**	**2,423.34**	**2,730.50**	**2,910,848.56**	**258,819.17**	**243,866.03**	**292,600.42**

टिप्पणी : पिछले 12 माह अवधि का डाटा अनंतिम है।
मोबाइल बैंकिंग - जुलाई 2017 के आंकड़ों में मोबाइल उपकरण का प्रयोग करते हुए प्रारंभ, संसाधित और अधिकृत किए गए वैयक्तिक और कारपोरेट भुगतानों को ही शामिल किया गया है। अन्य कारपोरेट भुगतान जो मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए प्रारंभ, संसाधित और प्राधिकृत नहीं किए गए हैं उन्हें इसमें शामिल नहीं किया गया है।
2.1: 5 नवंबर 2018 से सीसीआईएल ने सीबीएलओ को समाप्त कर दिया है।
2.2.3: 5 नवंबर 2018 से सिक्युरिटीज़ सेगमेन्ट के अंतर्गत त्रिपक्षीय रिपो की शुरुआत की गई है।

अवसरिक श्रृंखलाएं

सं. 44: लघु बचत

(बिलियन ₹)

योजना		2017-18	2017	2018		
			अगस्त	जून	जुलाई	अगस्त
		1	2	3	4	5
1. लघु बचत	**प्राप्तियां**	**728.98**	**60.31**	**80.18**	**88.92**	**80.33**
	बकाया	**8,039.71**	**7,559.02**	**8,276.45**	**8,366.80**	**8,447.96**
1.1 कुल जमाराशियां	**प्राप्तियां**	**583.32**	**47.19**	**71.19**	**77.75**	**70.63**
	बकाया	**5,273.10**	**4,892.47**	**5,482.77**	**5,560.52**	**5,631.15**
1.1.1 डाक घर बचत बैंक जमाराशियां	प्राप्तियां	171.45	9.96	23.55	24.35	20.21
	बकाया	1,092.10	968.84	1,162.02	1,186.37	1,206.58
1.1.2 एमजीएनआरईजी	प्राप्तियां	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	बकाया	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3 राष्ट्रीय बचत योजना, 1987	प्राप्तियां	–1.62	–0.21	–0.59	–0.29	–0.36
	बकाया	31.38	31.57	30.08	29.79	29.43
1.1.4 राष्ट्रीय बचत योजना, 1992	प्राप्तियां	0.05	1.07	–0.05	0.60	–0.06
	बकाया	–0.43	0.40	–0.60	0.00	–0.06
1.1.5 मासिक आय योजना	प्राप्तियां	16.25	0.35	7.73	9.92	10.08
	बकाया	1,816.91	1,794.83	1,840.89	1,850.81	1,860.89
1.1.6 वरिष्ठ नागरिक योजना, 2004	प्राप्तियां	122.64	11.79	10.51	12.08	11.20
	बकाया	417.18	348.45	450.86	462.94	474.14
1.1.7 डाक घर मीयादी जमाराशियां	प्राप्तियां	196.33	15.88	17.39	19.80	19.83
	बकाया	992.92	868.84	1,046.58	1,066.38	1,086.21
1.1.7.1 1 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	598.18	547.75	622.45	631.29	640.25
1.1.7.2 2 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	45.97	41.25	48.68	49.91	51.06
1.1.7.3 3 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	61.40	54.70	64.06	64.97	65.91
1.1.7.4 5 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	287.37	225.14	311.39	320.21	328.99
1.1.8 डाक घर आवर्ती जमाराशियां	प्राप्तियां	78.68	8.35	12.65	11.29	9.73
	बकाया	923.20	879.24	953.10	964.39	974.12
1.1.9 डाक घर सावधि मीयादी जमाराशियां	प्राप्तियां	–0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
	बकाया	–0.37	0.08	–0.37	–0.37	–0.37
1.1.10 अन्य जमाराशियां	प्राप्तियां	–0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
	बकाया	0.21	0.22	0.21	0.21	0.21
1.2 बचत प्रमाणपत्र	**प्राप्तियां**	**79.43**	**10.60**	**7.78**	**9.03**	**7.89**
	बकाया	**2,066.76**	**2,023.36**	**2,092.57**	**2,103.03**	**2,111.75**
1.2.1 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VIII निर्गम	प्राप्तियां	–0.65	–2.83	3.62	4.08	5.42
	बकाया	871.74	848.71	880.87	884.95	890.37
1.2.2 इंदिरा विकास पत्र	प्राप्तियां	–9.56	–0.01	0.95	1.19	0.01
	बकाया	–0.71	8.81	1.41	2.60	2.61
1.2.3 किसान विकास पत्र	प्राप्तियां	–155.92	–11.99	–12.99	–14.41	–15.65
	बकाया	379.81	477.38	342.38	327.97	312.32
1.2.4 किसान विकास पत्र-2014	प्राप्तियां	245.88	25.49	16.11	18.08	18.01
	बकाया	706.12	577.17	758.14	776.22	794.23
1.2.5 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VI निर्गम	प्राप्तियां	–0.29	–0.05	0.09	0.09	0.10
	बकाया	–1.40	–1.26	–1.34	–1.25	–1.15
1.2.6 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VII निर्गम	प्राप्तियां	–0.03	–0.01	0.00	0.00	0.00
	बकाया	–0.64	–0.63	–0.80	–0.80	–0.80
1.2.7 अन्य प्रमाणपत्र	बकाया	111.84	113.18	111.91	113.34	114.17
1.3 लोक भविष्य निधि	**प्राप्तियां**	**66.23**	**2.52**	**1.21**	**2.14**	**1.81**
	बकाया	**699.85**	**643.19**	**701.11**	**703.25**	**705.06**

टिप्पणी : अप्रैल 2017 से प्राप्तियों पर प्राप्त डाटा निवल प्राप्तियां अर्थात् सकल भुगतानों और सकल प्राप्तियों का अंतर हैं।

स्रोत : महालेखाकार, डाक और तार।

सं. 45: केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों के स्वामित्व का स्वरूप

(प्रतिशत)

केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां

श्रेणी	2017	2018			
	दिसंबर	मार्च	जून	सितंबर	दिसंबर
	1	2	3	4	5
(क) कुल (₹ बिलियन में)	**52813.50**	**53967.78**	**54556.81**	**56028.30**	**57581.03**
1. वाणिज्यिक बैंक	41.40	42.68	41.84	41.41	40.51
2. गैर-बैंक प्राथमिक डीलर्स	0.33	0.29	0.33	0.37	0.33
3. बीमाकृत कंपनियां	23.63	23.49	24.24	24.61	24.57
4. म्यूच्युअल फंड	1.33	1.00	1.13	1.41	0.64
5. सहकारी बैंक	2.69	2.57	2.59	2.51	2.38
6. वित्तीय संस्थाएं	0.82	0.90	0.93	0.97	1.01
7. कॉरपोरेट	1.09	0.91	1.09	1.01	1.05
8. विदेशी संस्थागत निवेशक	4.53	4.35	3.84	3.65	3.60
9. भविष्य निधियां	5.32	5.88	5.79	5.71	5.54
10. भारतीय रिज़र्व बैंक	11.94	11.62	11.63	11.76	13.81
11. अन्य	6.92	6.30	6.58	6.58	6.55
11.1 राज्य सरकार	1.91	1.91	1.97	1.99	1.97

राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां

श्रेणी	2017	2018			
	दिसंबर	मार्च	जून	सितंबर	दिसंबर
	1	2	3	4	5
(ख) कुल (₹ बिलियन में)	**23329.53**	**24288.29**	**24954.61**	**25668.33**	**26693.93**
1. वाणिज्यिक बैंक	38.13	35.79	35.02	34.66	34.00
2. गैर-बैंक प्राथमिक डीलर्स	0.51	0.51	0.75	0.58	0.60
3. बीमाकृत कंपनियां	33.35	34.13	34.24	33.74	33.90
4. म्यूच्युअल फंड	1.68	1.64	1.20	1.05	1.23
5. सहकारी बैंक	4.78	4.78	4.79	4.75	4.67
6. वित्तीय संस्थाएं	0.22	0.35	0.35	0.43	0.37
7. कॉरपोरेट	0.13	0.15	0.16	0.17	0.22
8. विदेशी संस्थागत निवेशक	0.21	0.23	0.15	0.10	0.09
9. भविष्य निधियां	17.05	19.67	20.34	21.04	21.29
10. भारतीय रिज़र्व बैंक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11. अन्य	3.94	2.76	2.99	3.48	3.64
11.1 राज्य सरकार	0.01	0.05	0.06	0.07	0.07

खज़ाना बिल

श्रेणी	2017	2018			
	दिसंबर	मार्च	जून	सितंबर	दिसंबर
	1	2	3	4	5
(ग) कुल (₹ बिलियन में)	**5102.82**	**3798.76**	**5280.07**	**5657.50**	**5298.26**
1. वाणिज्यिक बैंक	48.40	60.74	55.30	47.84	53.76
2. गैर-बैंक प्राथमिक डीलर्स	1.67	2.17	1.41	1.86	2.06
3. बीमाकृत कंपनियां	5.22	4.17	3.66	4.55	4.74
4. म्यूच्युअल फंड	10.40	2.27	7.03	10.69	5.65
5. सहकारी बैंक	2.05	2.42	1.29	1.20	1.21
6. वित्तीय संस्थाएं	3.97	3.55	2.36	1.67	1.88
7. कॉरपोरेट	2.12	2.45	1.88	6.67	1.86
8. विदेशी संस्थागत निवेशक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
9. भविष्य निधियां	0.02	0.11	0.21	0.01	0.02
10. भारतीय रिज़र्व बैंक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11. अन्य	26.17	22.12	26.87	25.50	28.72
11.1 राज्य सरकार	21.81	16.35	23.11	21.36	24.04

सं. 46: केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियां और संवितरण

(बिलियन ₹)

मद	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (स.अ.)	2018-19 (ब.अ.)
	1	2	3	4	5	6
1. कुल वितरण	**30,002.99**	**32,852.10**	**37,606.11**	**42,659.69**	**48,579.90**	**53,611.81**
1.1 गतिविधियां	17,142.21	18,720.62	22,012.87	25,379.05	29,324.08	32,025.64
1.1.1 राजस्व	13,944.26	14,830.18	16,682.50	18,784.17	22,525.73	24,390.87
1.1.2 पूंजी	2,785.08	3,322.62	4,120.69	5,012.13	5,857.77	6,745.79
1.1.3 ऋण	412.88	567.82	1,209.68	1,582.75	940.58	888.98
1.2 गैर गतिविधियां	12,427.83	13,667.69	15,108.10	16,726.46	18,542.53	20,762.79
1.2.1 राजस्व	11,413.65	12,695.20	13,797.27	15,552.39	17,684.36	19,839.32
1.2.1.1 ब्याज भुगतान	5,342.30	5,845.42	6,480.91	7,244.48	8,166.36	8,851.50
1.2.2 पूंजी	990.37	946.87	1,273.06	1,157.75	844.41	909.08
1.2.3 ऋण	23.81	25.63	37.77	16.32	13.76	14.40
1.3 अन्य	432.95	463.79	485.14	554.17	713.29	823.38
2. कुल प्राप्तियां	**30,013.72**	**31,897.37**	**37,780.49**	**42,884.32**	**47,718.59**	**52,780.35**
2.1 राजस्व प्राप्तियां	22,114.75	23,876.93	27,483.74	31,322.01	35,923.82	41,185.41
2.1.1 कर प्राप्तियां	18,465.45	20,207.28	22,971.01	26,221.45	30,132.23	34,941.02
2.1.1.1 पण्य और सेवाओं पर कर	11,257.81	12,123.48	14,409.52	16,523.77	18,296.56	22,138.76
2.1.1.2 आय और संपत्ति पर कर	7,176.34	8,051.76	8,522.71	9,656.22	11,802.47	12,775.14
2.1.1.3 संघशासित क्षेत्र (बिना विधान मंडल के) के कर	31.30	32.04	38.78	41.46	33.20	27.12
2.1.2 गैर-कर प्राप्तियां	3,649.30	3,669.65	4,512.72	5,100.56	5,791.59	6,244.38
2.1.2.1 ब्याज प्राप्तियां	401.62	396.22	357.79	332.20	316.10	368.35
2.2 गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां	391.13	609.55	598.27	690.63	1,651.83	1,428.43
2.2.1 ऋण और अग्रिम की वसूली	93.85	220.72	165.61	209.42	648.80	616.50
2.2.2 विनिवेश से प्राप्त राशि	297.28	388.83	432.66	481.22	1,003.03	811.93
3. सकल वित्तीय घाटा [1-(2.1+2.2)]	**7,497.11**	**8,365.63**	**9,524.10**	**10,647.04**	**11,004.25**	**10,997.97**
3क वित्तपोषण के स्रोत : संस्था-वार						
3क.1 घरेलू वित्तपोषण	7,424.19	8,236.30	9,396.62	10,467.08	10,980.08	11,023.86
3क.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	3,358.58	–374.76	2,310.90	6,171.23	1,447.92	..
3क.1.1.1 सरकार को निवल भा.रि. बैंक का ऋण	1,081.30	–3,341.85	604.72	1,958.16	–1,448.47	..
3क.1.2 सरकार को गैर-बैंक ऋण	4,065.61	8,611.06	7,085.72	4,295.85	9,532.16	..
3क.2 बाह्य वित्तपोषण	72.92	129.33	127.48	179.97	24.18	–25.89
3ख वित्तपोषण के स्रोत : लिखत-वार						
3ख.1 घरेलू वित्तपोषण	7,424.19	8,236.30	9,396.62	10,467.08	10,980.08	11,023.86
3ख.1.1 बाज़ार उधार (निवल)	6,391.99	6,640.58	6,732.98	6,898.21	7,951.99	8,398.36
3ख.1.2 लघु बचत (निवल)	–142.81	–565.80	–785.15	–1,050.38	–1,653.29	–1,434.61
3ख.1.3 राज्य भविष्य निधियां (निवल)	312.90	343.39	352.61	456.88	406.13	474.19
3ख.1.4 आरक्षित निधियां	34.63	51.09	–33.22	–64.36	6.70	31.14
3ख.1.5 जमाराशियां और अग्रिम	255.45	275.45	134.70	177.92	168.45	159.10
3ख.1.6 नकद शेष	–10.72	954.74	–174.38	–224.63	861.31	831.46
3ख.1.7 अन्य	582.75	536.84	3,169.08	4,273.43	3,238.79	2,564.21
3ख.2 बाह्य वित्तपोषण	72.92	129.33	127.48	179.97	24.18	–25.89
4. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर कुल वितरण	*26.7*	*26.3*	*27.3*	*27.8*	*28.4*	*28.1*
5. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर कुल प्राप्तियां	*26.7*	*25.6*	*27.4*	*27.9*	*27.9*	*27.7*
6. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर राजस्व प्राप्तियां	*19.7*	*19.2*	*20.0*	*20.4*	*21.0*	*21.6*
7. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर कर प्राप्तियां	*16.4*	*16.2*	*16.7*	*17.1*	*17.6*	*18.3*
8. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर सकल वित्तीय घाटा	*6.7*	*6.7*	*6.9*	*6.9*	*6.4*	*5.8*

स्रोत : केन्द्रीय और राज्य सरकारों का बजट दस्तावेज।
...: उपलब्ध नहीं।   आरईः संशोधित अनुमान;   बीईः बजट अनुमान

सं.47: विभिन्न सुविधाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा ली गई वित्तीय सहायता

(बिलियन ₹)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	मार्च 2019 के दौरान					
		विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ)		अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए)		ओव्हरड्राफ्ट (ओडी)	
		प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या	प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या	प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या
	1	2	3	4	5	6	7
1	आंध्र प्रदेश	11.90	5	9.71	19	5.43	28
2	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-
3	असम	-	-	-	-	-	-
4	बिहार	-	-	-	-	-	-
5	छत्तीसगढ़	-	-	-	-	-	-
6	गोवा	-	-	0.83	17	0.41	18
7	गुजरात	-	-	-	-	-	-
8	हरियाणा	-	-	-	-	-	-
9	हिमाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-
10	जम्मू और कश्मीर	1.35	1	4.51	17	-	-
11	झारखंड	2.52	5	4.53	18	-	-
12	कर्नाटक	-	-	-	-	-	-
13	केरल	-	-	4.40	11	0.73	11
14	मध्य प्रदेश	-	-	-	-	-	-
15	महाराष्ट्र	-	-	-	-	-	-
16	मणिपुर	1.61	3	1.28	15	-	-
17	मेघालय	-	-	-	-	-	-
18	मिज़ोरम	-	-	-	-	-	-
19	नगालैंड	-	-	0.66	4	0.32	7
20	उड़ीसा	-	-	-	-	-	-
21	पुदुचेरी	-	-	-	-	-	-
22	पंजाब	3.11	5	5.52	12	0.07	13
23	राजस्थान	-	-	-	-	-	-
24	तमिलनाडु	-	-	-	-	-	-
25	तेलंगाना	2.17	5	7.40	12	3.72	18
26	त्रिपुरा	-	-	-	-	-	-
27	उत्तरप्रदेश	-	-	-	-	-	-
28	उत्तराखंड	0.90	1	2.40	12	0.00	1
29	पश्चिम बंगाल	-	-	9.60	1	3.20	2

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक।

सं. 48: राज्य सरकारों द्वारा किए गये निवेश

(बिलियन ₹)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	मार्च 2019 के दौरान			
		समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ)	गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ)	सरकारी प्रतिभूतियाँ	निलामी खज़ाना बिल (एटीबी)
	1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	74.59	7.35	0.02	0
2	अरुणाचल प्रदेश	10.27	0.01	--	0
3	असम	37.32	0.47	--	0
4	बिहार	63.71	--	--	0
5	छत्तीसगढ़	37.43	--	0.01	0
6	गोवा	5.39	2.70	--	0
7	गुजरात	123.46	4.28	--	0
8	हरियाणा	18.79	10.74	--	0
9	हिमाचल प्रदेश	--	--	--	0
10	जम्मू और कश्मीर	--	--	--	0
11	झारखंड	--	--	--	0
12	कर्नाटक	34.66	--	--	0
13	केरल	19.42	--	--	0
14	मध्य प्रदेश	--	8.32	--	0
15	महाराष्ट्र	333.88	2.67	--	260.00
16	मणिपुर	3.39	0.90	--	0
17	मेघालय	5.51	0.27	0.09	0
18	मिज़ोरम	4.97	0.29	--	0
19	नगालैंड	13.36	0.29	--	0
20	उड़ीसा	120.53	13.01	0.76	151.00
21	पुदुचेरी	2.89	--	--	8.88
22	पंजाब	--	--	0.08	0
23	राजस्थान	--	--	1.29	37.92
24	तमिलनाडु	59.73	--	0.45	273.47
25	तेलंगाना	48.31	8.28	0.01	0
26	त्रिपुरा	2.95	0.04	--	8.00
27	उत्तरप्रदेश	--	--	1.80	0
28	उत्तराखंड	27.09	0.71	--	0
29	पश्चिम बंगाल	99.38	4.79	2.14	0
	कुल	**1147.01**	**65.14**	**6.64**	**739.27**

सं. 49: राज्य सरकारों की बाज़ार उधारियां

(बिलियन ₹)

क्र.सं.	राज्य	2016-17		2017-18		2018-19							
						जनवरी		फरवरी		मार्च		2018-19 में अब तक कुल राशि उठाई गई है	
		सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल	निवल
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	आंध्र प्रदेश	195.00	177.06	228.00	189.22	30.40	15.04	25.00	17.93	-	-12.19	302.00	238.24
2	अरुणाचल प्रदेश	4.53	2.87	8.88	7.03	-	-	-	-	3.19	2.93	7.19	6.93
3	असम	30.90	19.94	77.60	67.97	15.00	15.00	10.00	10.00	21.95	-3.11	105.95	80.89
4	बिहार	177.00	168.15	100.00	89.08	80.00	72.69	20.00	20.00	43.00	23.84	143.00	109.03
5	छत्तीसगढ़	42.00	38.98	81.00	81.00	35.00	35.00	30.00	30.00	39.00	39.00	129.00	129.00
6	गोवा	13.20	11.71	18.00	14.00	1.00	1.00	3.00	1.00	4.50	3.50	23.50	18.50
7	गुजरात	247.20	209.44	240.00	157.85	39.00	7.75	52.00	37.01	82.00	65.60	369.71	274.57
8	हरियाणा	158.00	153.59	166.40	158.40	15.00	15.00	45.00	32.05	42.40	27.40	212.65	179.70
9	हिमाचल प्रदेश	34.00	21.63	46.00	25.51	5.00	-	8.00	6.00	4.10	-2.90	42.10	21.08
10	जम्मू और कश्मीर	27.90	18.99	62.00	39.74	8.00	8.00	13.84	13.84	3.00	-4.81	66.84	49.27
11	झारखंड	51.54	47.25	60.00	48.07	-	-2.48	25.00	21.00	10.09	3.67	55.09	40.23
12	कर्नाटक	280.07	240.26	220.98	173.48	70.00	55.00	45.00	45.00	70.00	10.83	396.00	313.83
13	केरल	173.00	146.86	205.00	162.03	-	-8.12	27.00	19.00	5.00	-2.69	195.00	147.84
14	मध्य प्रदेश	161.00	145.51	150.00	131.25	10.00	-7.85	40.00	40.00	32.00	0.85	204.96	149.71
15	महाराष्ट्र	400.00	364.72	450.00	364.80	50.00	17.05	30.00	-	-	-94.57	208.69	31.17
16	मणिपुर	6.30	4.78	5.25	2.78	-	-1.03	2.00	2.00	2.70	2.70	9.70	6.67
17	मेघालय	10.01	7.18	11.16	9.20	-	-	1.00	1.00	3.72	2.33	11.22	8.63
18	मिज़ोरम	1.70	-0.35	4.24	2.77	-	-	-	-	-	-0.97	-	-1.23
19	नगालैंड	10.70	7.33	11.35	7.66	-	-	1.50	0.50	1.72	-0.35	8.22	3.55
20	उड़ीसा	76.20	69.90	84.38	84.38	-	-	10.00	-	-	-	55.00	45.00
21	पुदुचेरी	5.25	5.25	8.25	4.88	1.50	1.50	1.50	1.50	1.75	-0.75	8.25	4.75
22	पंजाब	136.00	121.44	174.70	133.49	18.08	11.41	15.00	11.46	27.26	18.88	221.15	170.53
23	राजस्थान	160.54	143.25	249.14	167.77	20.00	20.00	22.56	10.82	23.22	-40.21	331.78	201.86
24	सिक्कीम	7.44	5.74	9.95	7.45	0.92	0.92	-	-	2.71	2.71	10.88	7.95
25	तमिलनाडु	372.50	349.94	409.65	360.23	46.41	26.41	60.00	38.00	25.95	-3.03	431.25	322.78
26	तेलंगाना	218.61	205.79	246.00	218.28	20.00	9.03	27.50	22.45	20.22	11.51	267.40	221.83
27	त्रिपुरा	9.90	7.53	11.37	11.37	2.00	2.00	2.00	2.00	-	-1.56	15.43	13.87
28	उत्तरप्रदेश	410.50	369.05	416.00	371.78	80.00	69.01	90.00	90.00	60.00	4.06	460.00	333.07
29	उत्तराखंड	54.50	50.81	66.60	58.30	4.00	4.00	-	-2.52	5.50	4.56	63.00	52.89
30	पश्चिम बंगाल	344.31	312.30	369.11	253.04	60.00	60.00	70.45	60.45	88.00	66.43	428.28	304.31
	कुल	**3819.79**	**3426.92**	**4191.00**	**3402.81**	**611.31**	**426.33**	**677.35**	**530.50**	**622.98**	**123.66**	**4783.23**	**3486.43**

- : शून्य

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक।

वर्तमान सांख्यिकी की व्याख्यात्मक टिप्पणियां

सारणी सं. 1

1.2 और 6: वार्षिक आंकड़े महीनों के औसत हैं।

3.5 और 3.7: वित्त वर्ष में अब तक वृद्धि के अनुपात से संबंधित है।

4.1 से 4.4, 4.8, 4.9 और 5 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम शुक्रवार से संबंधित है।

4.5, 4.6 और 4.7 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम शुक्रवार को पांच प्रमुख बैंकों से संबंधित है।

4.10 से 4.12 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम निलामी दिन से संबंधित है।

4.13 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम दिन से संबंधित है।

7.1 और 7.2: विदेशी व्यापार यूएस डॉलर से संबंधित है।

सारणी सं. 2

2.1.2 : चुकता पूंजी, आरक्षित निधि और दीर्घावधि परिचालनगत निधि शामिल है।

2.2.2 : नकदी, सावधि जमाराशियों और अल्पावधि प्रतिभूतियों/बांडों सहित *जैसे* - आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी।

सारणी सं. 4

http://nsdp.rbi.org.in के 'रिज़र्व टैम्पलेट' के अंतर्गत परिपक्वतावार बकाया फॉर्वर्ड संविदा की स्थिति दर्शायी गयी है।

सारणी सं. 5

अन्य को विशेष पुर्नवित्त सुविधा, अर्थात् एक्ज़िम बैंक को 31 मार्च 2013 से बंद है।

सारणी सं. 6

अनुसूचित बैंकों के लिए, मार्च की समाप्ति के आंकडे सूचना देने के लिए नियत अंतिम शुक्रवार से संबंधित हैं।

2.2 : आईएमएफ खाता सं.1 की शेष राशि, आरबीआई कर्मचारी भविष्य निधि, पेंशन निधि, उपदान और अधिवर्षिता निधि शामिल नहीं हैं।

सारणी सं. 7 और 11

सारणी 7 में 3.1 और सारणी 11 में 2.4: आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट बांड शामिल हैं।

सारणी सं. 8

एनएम2 और एनएम3 में एफसीएनआर (बी) जमाराशियां शामिल नहीं हैं।

2.4: चुकता पूंजी और आरक्षित राशि शामिल हैं।

2.5 : बैंकिंग प्रणाली की अन्य मांग और मीयादी देयताएं शामिल हैं।

सारणी सं. 9

वित्तीय संस्थाओं में एक्जिम बैंक, सिडबी, नाबार्ड और एनएचबी शामिल हैं।

एल1 और एल2 मासिक आधार पर और एल3 तिमाही आधार पर संकलित किए जाते हैं।

जहां आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं वहां अंतिम उपलब्ध आंकड़े पुनः दिए गए हैं।

सारणी सं. 13

कालम सं. (4) और (5) में दर्शाए गए आंकड़े अनंतिम हैं।

सारणी सं. 14

कालम सं. (4) और (8) में दर्शाए गए आंकडें अनंतिम हैं।

सारणी सं. 15 और 16

डाटा अनंतिम है और चुनिंदा 41 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से संबंधित है जिसमें सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (आईएनजी वैश्य को छोड़कर जिसे अप्रैल 2015 को कोटक महिंद्रा के साथ विलय किया गया है) द्वारा कुल दिये गये कुल खाद्येतर ऋण के 90 प्रतिशत शामिल है।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत निर्यात ऋण केवल विदेशी बैंक से संबंधित है।

मद 2.1 के अंतर्गत माइक्रो और लघु में विनिर्माण क्षेत्र में माइक्रो और लघु उद्योग को ऋण शामिल है।

मद 5.2 के अंतर्गत माइक्रो और लघु उद्यमों में विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र में माइक्रो तथा लघु उद्यमों को ऋण शामिल है।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र पुरानी परिभाषा के अनुसार है और दि. 23 अप्रैल 2015 के एफआईडीडी परिपत्र एफआईडीडी.केका.प्लान. बीसी.54/ 04.09.01/2014-15 के अनुरूप नहीं है।

सारणी सं. 17

2.1.1: राज्य सहकारी बैंकों में सहकारी सोसाइटियों द्वारा अनुरक्षित आरक्षित निधि शामिल नहीं है।
2.1.2 : आरबीआई, एसबीआई, आईडीबीआई, नाबार्ड, अधिसूचित बैंकों और राज्य सरकारों से लिए गए ऋण शामिल नहीं है।
4. : आईडीबीआई और नाबार्ड से लिए गए ऋण शामिल हैं।

सारणी सं. 24

प्राथमिक व्यापारियों में, प्राथमिक व्यापारी का कारोबार करने वाले बैंक शामिल हैं।

सारणी सं. 30

प्राइवेट प्लेसमेंट और बिक्री के प्रस्ताव शामिल नहीं हैं।
1: बोनस शेयर शामिल नहीं हैं।
2: संचयी परिवर्तनीय अधिमान शेयर और इक्वी - अधिमान शेयर शामिल हैं।

सारणी सं. 32

आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट बांडों में निवेश तथा सार्क स्वैप व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त विदेशी मुद्रा और भारत सरकार द्वारा रिज़र्व बैंक को अतंरित एसडीआर शामिल नहीं हैं। अमेरिकी डॉलर में दिखाई गई विदेशी मुद्रा आस्तियों में रिज़र्व में रखी गैर यूएस मुद्राओं (जैसे यूरो, स्टर्लिंग, येन और ऑस्ट्रेलिया डॉलर) के मूल्यवृद्धि/मूल्यह्रास को शामिल किया गया है। विदेशी मुद्रा धारिता को रूपी-अमेरिकी डॉलर आरबीआई धारिता दरों में परिवर्तित किया गया है।

सारणी सं. 34

1.1.1.1.2 और 1.1.1.1.1.4 : अनुमान
1.1.1.2 : नवीनतम माह के लिए अनुमान
'अन्य पूंजी' एफडीआई उद्यम की मूल और अनुषंगी संस्थाओं/शाखाओं के बीच के ऋण संबंधी लेनदेन से संबंधित है।
हो सकता है कि सूचना देने में हुए समय-अंतराल के कारण ये आँकड़े भुगतान-संतुलन के आंकड़ो से मेल न खाएं।

सारणी सं. 35

1.10 : जर्नलों के लिए अभिदान, विदेश में किए गए निवेशों का अनुरक्षण, छात्र ऋण चुकौती और क्रेडिट कार्ड भुगतान जैसी मदें शामिल हैं।

सारणी सं. 36

सूचकांकों में वृद्धि रुपये की मूल्यवृद्धि या मूल्यह्रास का संकेतक। 6-मुद्राओं वाले सूचकांक के लिए, आधार वर्ष 2016-17 अस्थिर है जिसे प्रत्येक वर्ष अद्यतन किया जाता है। रीर के आंकड़े उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) पर आधारित है। इससे संबंधित कार्यपद्धति का विवरण बुलेटिन के दिसंबर 2005 और अप्रैल 2014 अंक में दिया गया है।

सारणी सं. 37

ईसीबी/विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों के लिए आवेदनों पर आधारित जिन्हें उस अवधि के दौरान ऋण पंजीकरण संख्या दी गई है।

सारणी सं. 38, 39, 40 और 41

इन सारणियों के संबंध में व्याख्यात्मक टिप्पणियां आरबीआई बुलेटिन 2012 के दिसंबर अंक में उपलब्ध हैं।

सारणी सं. 43

1.3: बहुपक्षीय निवल निपटान समूहों से संबंधित है।

3.1: मुंबई, नई दिल्ली और चेन्नै - तीन केन्द्रों से संबंधित है।

3.3: 21 बैंकों द्वारा प्रबंधित समाशोधन गृहों से संबंधित है।

6: दिसंबर 2010 से उपलब्ध।

7: आईएमपीएस लेनदेन शामिल हैं।

9: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा खोले गए एटीएम और व्हाइट लेबल एटीएम शामिल है। अप्रैल 2014 से व्हाइट लेबल एटीएम शामिल किए गए है।

मोबाइल बैंकिंग - जुलाई 2017 के आंकड़ों में मोबाइल उपकरण का प्रयोग करते हुए प्रारंभ, संसाधित और अधिकृत किए गए वैयक्तिक और कारपोरेट भुगतानों को ही शामिल किया गया है। अन्य कारपोरेट भुगतान जो मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए प्रारंभ, संसाधित और प्राधिकृत नहीं किए गए हैं उन्हें इसमें शामिल नहीं किया गया है।

सारणी सं. 45

(-): नगण्य को दर्शाता है।

जून 2016 से टेबल फार्मेट संशोधित किया है, जिसमें केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों सहित राज्य सरकारों की स्वामित्ववाली प्रतिभूतियाँ और खज़ाना बिलों सहित शामिल है।

राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में उज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (यूडीएवाई) के अंतर्गत जारी विशेष बान्ड शामिल हैं।

वाणिज्यिक बैंकों के अंतर्गत बैंक के प्राथमिक डीलरों को शामिल किया गया है। तथापि, कुल बकाया प्रतिभूतियों में इसका हिस्सा बहुत कम है।

"अन्य" श्रेणी में राज्य सरकारों, पेंशन निधियां न्यास, संस्थाएं, हिंदू अविभक्त परिवार / वैयक्तिक आदि. शामिल है।

सारणी सं. 46

2011-12 से जीडीपी डाटा 2011-12 के आधार पर हैं। वर्ष 2015-16 का डाटा 29 राज्यों से संबंधित हैं।

2015-16 से जीडीपी डाटा 28 फरवरी 2018 को केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी राष्ट्रीय आय के दूसरे अग्रिम से संबंधित है।

जीडीपी के लिए 2016-17 (आरई) और 2017-18 के लिए केंद्रीय बजट 2017-18 से लिए गए है।

राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि व्यय को छोड़कर कुल प्राप्तियां और कुल व्यय।

1 और 2: आंकड़े केंद्र सरकार (एनएसएसएफ की पुन:चुकौती सहित) और राज्य सरकार के निवल चुकौती से संबंधित है।

1.3: राज्य द्वारा स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थानों को दिये गये मुआवजे और कार्य से संबंधित है।

2: यह डाटा केंद्र और राज्य सरकारों को दिये गये उधार प्राप्तियों सहित केंद्र और राज्य सरकारों के नकदी शेष में हुए घटबढ़ से संबंधित निवल को दर्शाते है।

3ए.1.1: आंकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक के अभिलेख के अनुसार है।

3बी.1.1: दिनांकित प्रतिभूतियों और 364 दिन के खज़ाना बिलों के माध्यम से प्राप्त उधारियों सहित।

3बी.1.2: राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा विशेष प्रतिभूतियों में किये गये निवल निवेश को दर्शाते है।

3बी.1.6: केंद्र द्वारा राज्य सरकारों को दिये गये अर्थोपाय अग्रिमों सहित।

3बी.1.7: वित्तीय संस्थानों, बीमा और पेंशन निधि, प्रेषण, नकदी शेष निवेश लेखा से लिये गये ऋण, खज़ाना बिलों (364-दिन के खज़ाना बिलों को छोड़कर) सहित।

सारणी सं. 47

राज्य सरकारों द्वारा समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ), गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) और निलामी खज़ाना बिल (एटीबी) के शेषों तथा सरकारी प्रतिभूतियों में किए गए अन्य निवेशों को संपाश्विक के तौर पर रखते हुए विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) प्राप्त की जाती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा राज्य सरकारों को उनके अल्प कालिक नकदी असंतुलन से निपटने के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) दिया जाता है।

राज्य सरकारों को उनकी अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) सीमा से अधिक की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आग्रिम के तौर पर ओवरड्राफ्ट दिया जाता है।

प्राप्त कुल सहायता (एसडीएफ/डब्ल्यूएमए/ओडी) को उन दिनों की संख्या से भाग देने पर, जिनके लिए माह के दौरान सहायता प्राप्त हुई, औसत राशि प्राप्त होती है।

-: नगण्य

सारणी सं. 48

समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ), गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) वे आरक्षित निधियाँ हैं जो कुछ राज्य सरकारों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखी जाती हैं।

नीलामी खज़ाना बिलों (एटीबी) में राज्य सरकारों द्वारा प्राथमिक बाज़ारो में निवेश किए गए 91 दिवसीय,182 दिवसीय तथा 364 दिनों की खज़ाना बिल शामिल हैं।

--: लागू नहीं (इस योजना का सदस्य नहीं है)।

वर्तमान सांख्यिकी संबंधी अवधारणाएं एवं कार्यप्रणालियां भारतीय रिज़र्व बैंक मासिक बुलेटिन के वर्तमान सांख्यिकी संबंधी व्यापक मार्गदर्शिका (**https://rbi.org.in/scripts/publicationsview.aspx?id=17618**) में उपलब्ध हैं।

विस्तृत टिप्पणियां भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी संबंधित प्रेस विज्ञप्तियों और बैंक के अन्य प्रकाशनों (जैसे **भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकीय हैंडबुक**) में उपलब्ध हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक के हाल के प्रकाशन

प्रकाशन का नाम	मूल्य	
	भारत में	विदेश में
1. भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन 2019	₹300 एक प्रति (कांउटर पर) ₹350 एक प्रति (डाक प्रभार सहित) ₹4,200 (डाक प्रभार सहित एक वर्ष का सदस्यता शुल्क) ₹3,150 (एक वर्ष का रियायती दर*) ₹3,360 (एक वर्ष का सदस्यता शुल्क - डाक प्रभार सहित@) ₹2,520 (एक वर्ष का रियायती दर@)	15 अमरीकी डॉलर एक प्रति (डाक प्रभार सहित) 180 अमरीकी डॉलर (एक वर्ष का सदस्यता शुल्क) (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
2. भारतीय राज्यों से संबंधित सांख्यिकीय हैंड बुक 2018-19	₹650 (सामान्य) ₹700 (डाक प्रभार सहित)	24 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
3. भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकीय हैंड बुक 2017-18	₹700 (सामान्य) ₹750 (डाक प्रभार सहित) ₹525 (रियायती) ₹575 (रियायती डाक प्रभार सहित)	50 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
4. राज्य वित्त: 2017-18 और 2018-19 के बजटों का अध्ययन	₹600 एक प्रति (काउंटर पर) ₹650 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	24 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
5. रिपोर्ट ऑफ दि कमिटी ऑन फुलर कैपिटल अकांउट कन्वर्टिबिलिटी (तारापोर समिति की रिपोर्ट II)	₹140 एक प्रति (काउंटर पर) ₹170 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	25 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
6. बैंकिंग शब्दावली (2012)	₹80 एक प्रति (कांउटर पर) ₹120 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	
7. अनुवाद के विविध आयाम (हिंदी)	₹165 एक प्रति (कांउटर पर) ₹205 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	
8. बैंक में राजभाषा नीति का कार्यान्वयनः दशा और दिशा (हिंदी)	₹150 एक प्रति (कांउटर पर) ₹200 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	
9. भारतीय रिज़र्व बैंक सामयिक पेपर खंड 37, 2016	₹200 एक प्रति (कांउटर पर) ₹250 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	18 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
10. भारतीय रिज़र्व बैंक सामयिक पेपर खंड 38, 2017	₹200 एक प्रति (कांउटर पर) ₹250 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	18 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
11. भारतीय रिज़र्व बैंक सामयिक पेपर खंड 39, 2018	₹200 एक प्रति (कांउटर पर) ₹250 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	18 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
12. Perspectives on Central Banking Governors Speak (1935-2010) Platinum Jubilee	₹1400 एक प्रति (कांउटर पर)	50 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)

टिप्पणियाः

1. उपर्युक्त प्रकाशनों में से कई प्रकाशन आरबीआई की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर उपलबध हैं।
2. टाइम सीरीज़ डेटा भारतीय अर्थव्यवस्था के डेटाबेस में उपलब्ध हैं (http://dbie.rbi.org.in)।
3. भारतीय रिज़र्व बैंक का इतिहास 1935-1997 (4 खंड), वित्तीय संकट के संदर्भ में केन्द्रीय बैंकिंग की चुनौतियां और भारत की क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था: वृद्धि और वित्त भारत के प्रमुख पुस्तक भंडारों में उपलब्ध हैं।

* भारत में छात्रों, अध्यापकों / व्याख्याताओं, अकादमिक और शैक्षिक संस्थाओं, सार्वजनिक पुस्तकालयों और पुस्तक विक्रेताओं को 25 प्रतिशत रियायत दी जाएगी बशर्ते उन्हें संबंधित संस्था से पात्रता प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

@ इलेक्ट्रानिक भुगतान को बढ़ावा देने हेतु, घरेलू ग्राहक जो एनईएफटी के माध्यम से भुगतान करना चाहते है, उन्हें 20 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया गया है।

सामान्य अनुदेशः

1. बिकी हुई प्रतियां वापस नहीं ली जाएंगी।
2. प्रकाशन कन्साइनमेंट वीपीपी आधार पर नहीं भेजा जाएगा।
3. जहां कहीं रियायती मूल्य का उल्लेख नहीं है, वहां भारत में छात्रों, अध्यापकों/व्याख्याताओं, अकादमिक और शैक्षिक संस्थाओं, सार्वजनिक पुस्तकालयों और पुस्तक विक्रेताओं को 25 प्रतिशत की रियायत दी जाएगी, बशर्ते उन्हें संबंधित संस्था से पात्रता प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। सामान्यतः प्रकाशन के पिछले अंक उपलब्ध नहीं है।
4. प्रकाशनों की (सोमवार से शुक्रवार) तक बिक्री तथा वितरण प्रभाग, कॉर्पोरेट सेवा विभाग, भारिबैं, अमर बिल्डिंग, तल मंज़िल, सर पी.एम. रोड, फोर्ट, पोस्ट बॉक्स संख्या 1036, मुंबई - 400 001 पर उपलब्ध हैं। बिक्री अनुभाग का संपर्क नं. 022-2260 3000, विस्तार 4002, ई-मेलः spsdcs@rbi.org.in है।
5. सदस्यता शुल्क मुख्यतः एनईएफटी द्वारा किया जाना चाहिए और अग्रेषणपत्र, जिसके साथ एनईएफटी विवरण संलग्न हो, मुख्य महाप्रबंधक, कॉर्पोरेट सेवा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, दूसरी मंज़िल, मुख्य भवन, मुम्बई - 400 001 को संबोधित होना चाहिए।
   एनईएफटी फार्म में निम्नलिखित जानकारी भरना अपेक्षित है :

लाभार्थी का नाम	कॉर्पोरेट सेवा विभाग, भारिबैं
बैंक का नाम	भारतीय रिज़र्व बैंक
शाखा तथा पता	फोर्ट, मुंबई
बैंक शाखा का आईएफएससी	RBIS0MBPA04
खाते का प्रकार	चालू खाता
खाता संख्या	41-8691632-86
प्रेषक से प्राप्तकर्ता की जानकारी	अभिदाता का नाम.......... अभिदाता सं.........

6. प्रकाशनों को शीघ्रातिशीघ्र भेजने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। तथापि मांग अधिक होने पर 'पहले आओ, पहले पाओ' आधार पर प्रकाशनों की आपूर्ति की जाएगी। औपचारिकताएं पूरा करने और उसके बाद उपलब्ध प्रकाशनों को भेजने में न्यूनतम एक महीने का समय लगेगा। 'प्रकाशन प्राप्त न होने की शिकायत' 2 महीने के अंदर भेजी जाए।
7. **कृपया अपनी अंशदान संख्या, नाम, पता तथा ई-मेल आईडी spsdcs@rbi.org.in पर मेल करें ताकि हम आपसे संपर्क कर सकें।**